भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षको, शिक्षक-प्रशिक्षको, शैक्षिक प्रशासको तथा शोधकर्ताओ को एक मंच प्रदान करना, शिक्षा के विभिन्न आयामो जैसे शिक्षादर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की समकालीन समस्याएं, पाठ्यक्रम एव प्रविधि सबंधी नवीन विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्वरूप, विभिन्न राज्यों मे शिक्षा की स्थिति आदि पर मौलिक तथा आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के सुधार और विकास को बढ़ावा देना। लेखको द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार परिषद् की नीतियो को प्रस्तुत नहीं करते इसलिए इस सबध में परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

पूरन चन्द — *प्रधान अकादमिक संपादक*
राजकुमार गुप्त — *संपादक*
डी. साई प्रसाद — *उत्पादन अधिकारी*

आवरण कर्ण चड्ढा

मूल्य एक प्रति : 8.50 रुपए   वार्षिक : 34.00 रुपए

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष . 21 | अक . 2 | अक्तूबर 2002

इस अंक में

भारत के अध्यापक
सशक्त एवं गतिशील परम्परा के उत्तराधिकारी

❑ जगमोहन सिंह राजपूत

अध्यापकों के कार्य निष्पादन में जो परिवर्तन महत्वपूर्ण है उसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक और तकनीकी शामिल हैं। आज शिक्षा प्रणाली तथा अध्ययन-अध्यापन में नई तकनीकी का प्रयोग करने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हमारे अध्यापकों को इसका प्रशिक्षण लेना है और व्यवस्थापकों को इसकी व्यवस्था करनी है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के विकास के नए आयाम खुल रहे हैं। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्नों और परिप्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अध्यापकों के साथ मिलकर करें और बिना किसी हिचक के अपने चिंतन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताओं का विकास करें। प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थी को ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे एक साथ मिलकर सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके।

किसी भी समाज में परिवर्तन को समझने के लिए और सामाजिक सामंजस्य तथा समरसता को बढ़ाने मे अध्यापको ने सदा ही योगदान किया है। सदियों से अध्यापक भावी समाज के निर्माण में अपना योगदान करते आए है। मानव विकास के इतिहास, उसकी प्रगति के विभिन्न सोपान अध्यापको के द्वारा ही विकसित और निर्मित होते रहे हैं। हमारे देश मे अध्यापकों का स्थान बहुत ही ऊंचा रहा है या यों कहे कि सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था मे सर्वोपरि रहा है। हमारे प्राचीन ग्रन्थ और उनमे निहित चिंतन तथा ज्ञान के भडार अध्यापको के योगदान, उनके त्याग, ज्ञानार्जन के लिए की गई तपस्या और मानव हित के लिए किए गए उनके प्रयत्नो के ही परिणाम हैं। अपने विद्यार्थियों को उन्नति की ओर अग्रसर करना, उनकी प्रगति से संवेदनात्मक स्तर पर जुड़ना और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत् प्रयत्न करते रहना भारतीय शिक्षा परंपरा का एक अत्यत सुदृढ़ पक्ष रहा है। भारत में गुरुकुलो और आश्रमों की परपरा अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंची और यही सर्वोत्कृष्ट ज्ञानार्जन के केंद्र बने। बहुधा लोग इन स्थानों पर अध्ययन के लिए एकत्र होते थे। मानव सभ्यता के विकास मे भारत का योगदान अनेक क्षेत्रों में अत्यत उच्च स्तर तक हजारों वर्षो पहले ही पहुच गया था। विज्ञान, गणित, रसायनशास्त्र, आयुर्वेद, जहाजरानी, योगा इत्यादि क्षेत्रों में हमारी महान उपलब्धियों के जनक इस देश के कर्मठ अध्यापक ही रहे है।

बीसवी शताब्दी मे उपनिवेशवाद का अंत हुआ और मानव चिंतन में जो नए आयाम निकले उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का हर व्यक्ति तक पहुंचना विश्व स्तर पर स्वीकृत हुआ। आज के समय मे यह चुनौती भारत के सामने भी खड़ी है। हमारे साधन सीमित है और उन सीमित साधनों के रहते हुए भी शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना

है और उसकी उपयोगिता के द्वारा हर स्तर पर उसकी स्वीकार्यता को भी आगे ले जाना है। इस कार्य को करने का बीड़ा भी इस देश के अध्यापकों के समक्ष रखा गया है। अपने कर्तव्य का वह उसी कर्मठता से आज भी पालन कर रहे है जिसकी विरासत उन्हे हजारों सालों से मिली हुई है।

विश्व के धनाढ्य देशों के लोग जो भारत की स्थितियों से परिचित हैं, आश्चर्यचकित होकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय विद्यार्थी आज विश्व स्तर पर सुविधा सपन्न देशों और स्कूलो के विद्यार्थियों के साथ कैसे बराबरी का कार्य करने की क्षमता रखते है, और किस प्रकार वे सभी से आगे निकल जाते है। उदाहरण के लिए संचार तकनीकी और डाक्टरी अध्ययन के क्षेत्र ऐसे है जहां भारतीय विद्यार्थियों का लोहा सारा विश्व मानता है। अध्यापकों के सामने जो नई चुनौतिया आती रहती हैं उनके परिमाण आज अत्यंत अधिक बढ़ गए है। आज कहा जाता है कि सारा विश्व कक्षा के अंदर सिमट गया है। संचार तकनीकी ने इसे संभव बनाया है। आज सूचना अत्यत अधिक मात्रा और सख्या में उपलब्ध है और आवश्यकता यह है कि जो नए परिवर्तन द्रुत गति के साथ हो रहे है उन्हे समझा जाए। सूचनाओं के क्षेत्रों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें से उपयोगी को निकालने का कौशल सीखा जाए और शिक्षा एक ज्ञान-समाज की ओर ले जाने के लिए हर विद्यार्थी को प्रेरित कर सके। अपने आप मे यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सामना करने के लिए हमारे अध्यापकों को स्वाध्याय और स्व-निर्देषित अध्ययन को जीवन का अग बनाना होगा। यहां पर मैं भी यह कहना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा में आचार्य और अध्यापक वही होता है जो सतत् अध्ययन करता रहता है और अपने आचरण से नई पीढ़ी के सामने ही नहीं बल्कि समाज के सामने स्वीकार्य आचरण प्रस्तुत करता है।

आचार्य केवल स्वयं अनुकरणीय आचरण करे और शिष्य उसका अनुसारण करे, इतना ही पूर्ण रूप से आचार्य शब्द की व्याख्या नही करता है। आचार्य स्वयं जैसा आचरण करता है वैसा ही दूसरों से भी कराता है। स्वयं लगातार पढ़ता रहता है और दूसरो को भी पढ़ने को प्रेरित करता है और उनसे अपनी ही भांति पढ़वाता है। आज के संदर्भ में शिक्षाशास्त्री बहुधा कहते हैं कि पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया 'पार्टनरशिप बेस्ड' यानी शिक्षक-विद्यार्थी की भागीदारी की होनी चाहिए। समानता स्पष्ट है। अध्यापक भी तैयारी करे, विद्यार्थी भी करें फिर दोनों साथ-साथ मिलकर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रश्न-परिप्रश्न इस प्रक्रिया को गहन बनाते हैं और सीखने वाले के क्षितिज को विस्तार देते है। अब यदि शिक्षक का अपना अध्ययन और अनुशीलन का क्षेत्र ही सीमित होगा तो वह विद्यार्थी का क्षितिज कैसे बढ़ा पाएगा? ज्ञान के अथाह सागर में से लगातार कुछ प्राप्त करते रहने का एक ही उपाय है– स्वाध्याय, चिंतन, मनन, उपयोग जो कुछ मिले उसे और परिष्कृत करते रहने की इच्छा। यह इच्छा धीरे-धीरे अपने आप ही बढ़ती जाती है और खोजने वाला असीम आनद और उपलब्धि का सुख पाने लगता है। फिर जब वह इसे अपने शिष्यों के साथ बांटता है तो यह अत्यंत आनद बोध की स्थिति होती है जिसकी उपयोगिता असीम होती है।

इसी प्रकार की सुदृढ़ परंपराओं से अत्यंत ओजस्वी, गहन तथा शास्वत सत्य को मुखरित करने वाला ज्ञान भंडार भारत के प्राचीन ग्रंथों मे समाहित है और इसे समझने वाले इसकी गहनता को और अधिक पहचानने और जानने का प्रयास करते हैं। **'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'** इसी प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को परख कर कहा गया है– शुद्ध ज्ञान सत्य का प्रतिरूप है। वह आशंकाओ का निवारण करता है। इसे पाने में ज्ञानवान तथा लगनशील अध्यापक की सहायता की आवश्यकता होती है। शुद्ध ज्ञान को और शुद्ध तथा समृद्ध बनाने में अध्यापक ही प्रेरणा का स्रोत होता है और साथी-शोधक भी होता है। सदियों से अध्यापन की योग्यता के लिए तीन गुण आवश्यक माने जाते रहे हैं। सबसे प्रथम है ज्ञान मे अभिरुचि। सीखता रहे और उसमें उपलब्धि तथा आनंद का अनुभव करे अन्यथा शृंखला स्वय ही टूट जाएगी, जितना सीखा है उससे

संतुष्ट न होकर और सीखने की आवश्यकता उसके सामने लगातार उभरती रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है चरित्र निर्माण के प्रति समर्पित भाव से प्रयत्नशील होना। ऐसा वही कर सकेगा जो स्वयं संयत जीवन जी रहा होगा, जिसे अपने चरित्र पर विश्वास होगा और जिसने ऐसा ही विश्वास औरो से भी अर्जित कर लिया होगा। ऐसा अध्यापक ही नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण मे अपना सार्थक और सफल योगदान कर सकेगा। इसी से उसके व्यक्तित्व का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम उभरता है— अध्यापक का विनीत होना। अपने ज्ञान पर उसे कभी घमंड नही होता है। आज भी अध्यापन के कार्य में लगे लगभग 50 लाख अध्यापक स्कूल शिक्षा में इन्हीं भावनाओं, विचारो तथा परम्पराओं से प्रेरणा लेकर विषम परिस्थितियो में भी अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं।

अध्यापकों के कार्य निष्पादन में जो परिवर्तन महत्वपूर्ण है उसमे मानव जीवन के सभी पक्ष, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक और तकनीकी शामिल है। आज शिक्षा प्रणाली तथा अध्ययन-अध्यापन मे नई तकनीकी का प्रयोग करने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हमारे अध्यापकों को इसका प्रशिक्षण लेना है और व्यवस्थापको को इसकी व्यवस्था करनी है। विद्यार्थियो मे सृजनात्मकता के विकास के नए आयाम खुल रहे है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्नों और परिप्रश्नो के द्वारा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अध्यापको के साथ मिल कर करें और बिना किसी हिचक के अपने चिंतन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताओं का विकास करे। प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थी को ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे एक साथ मिलकर सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके।

आज स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता पहले से अत्यंत अधिक मानी जाती है। सभी आवश्यक परिवर्तनों से जुड़े विभिन्न पहलू पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार लाए जाने चाहिए। अध्यापको को पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। हमारे बहुत से बच्चे कक्षा एक और दो मे स्कूल छोड़ देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि कक्षा एक और दो के पाठ्यक्रम ऐसे हों जो बच्चे के सपूर्ण पर्यावरण से जुडे हो। उसके आसपास जो हो रहा है उसी की चर्चा उसमे हो, ऐसी संस्तुति एन.सी.ई.आर.टी. ने अपने नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा मे की है और यह एक अत्यंत उत्साहजनक सस्तुति है। इसे अध्यापकों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। यदि यह सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकी तो निश्चित ही स्कूल छोडने वाले बच्चों का प्रतिशत आगे आने वाले वर्षो में काफी कम हो जाएगा। इस प्रकार के कई सुझाव परीक्षा प्रणाली के सवध में भी दिए गए हैं। अध्यापको को नई जिम्मेदारियो को निभाने के लिए सतत् रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की कई नई योजनाए भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा एन सी.ई आर.टी ने देश के सामने प्रस्तुत की हैं।

समाज में मूल्यो का निर्धारण और उन्हे जीवन में उतारने की प्रेरणा अध्यापको से ही मिलती है। इस समय मानव मूल्यो का जो ह्रास हो रहा है और विश्व के हर देश में इन मूल्यो को लेकर जो समस्याएं उठ रही हैं उन्होंने इस बात की आवश्यकता को दोहराया है कि मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण योगदान करना है। सारे पाठ्यक्रम में प्रत्येक अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा मूल्यो को आत्मसात् करने और उन्हे व्यवहार मे लाने का प्रयत्न प्रत्यक्ष रूप से लगातार करता रहे। हमारा देश अनेक विभिन्नताओं का देश है। यही हमारी एकता का महत्वपूर्ण सूत्र है— विविधता मे एकता। भारत जैसा उदाहरण और कहीं उपलब्ध नही है। इस देश को जो प्राकृतिक सपदाए, सास्कृतिक धरोहरे तथा भाषाओं की विभिन्नताएं और धार्मिक अंतराल मिले है वे सब अपने आप में अद्वितीय हैं। यही सब मिलकर भारत को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायता करते है। हमारे अध्यापक इन तथ्यो को बच्चो के सामने अपनी योग्यता, समझ, अनुभव के आधार पर अच्छे ढंग से रख सकते हैं।

भारतवर्ष का अध्यापक अनेक कठिनाइयो और कमियों में भी अपने कार्य का निर्वाह प्रतिबद्धता से

करता है। उनके कार्य करने की स्थिति में सुधार लाने का हर सभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र का और सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्हें प्रशिक्षण के अवसर, पढ़ने-लिखने की सामग्री और नई तकनीकी से परिचित कराने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। बहुत-सी नई योजनाए इन दिशाओं में बन रही है। अध्यापको की सेवकालीन स्थिति को सुधारने के प्रयत्न भी पिछले कुछ वर्षो मे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह होगा कि अध्यापकों और समाज के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान बढ़े और एक-दूसरे की आवश्यकताओं और अपेक्षाओ को सही ढंग से समझा जा सके। यही इस देश में एक सुदृढ़ समाज की स्थापना के लिए भारत तथा भारतीय संस्कृति और भारतीयता में विश्व के लिए आवश्यक कड़ी होगी। इसमे सबसे बड़ा योग(अध्यापकों का ही होगा। हमारा देश 5 सितंबर को (वर्ष अध्यापको का सम्मान करता है। यह एक प्रतीकात्(प्रक्रिया होते हुए भी अध्यापको के प्रति राष्ट्र के सम(को दर्शाती है। हमें इसको पूरी तरह व्यावहारिक (पर ले जाना चाहिए और डा. राधाकृष्णन जैसे म(अध्यापकों के विचारों के अनुसार शिक्षा को बाहरी ज(के लिए ही नही बल्कि मानव के अंतर्मन को भी स(करने के लिए गतिमान बनाना चाहिए। अध्यापकों अतिरिक्त और कोई इस कार्य को नहीं कर सक(देश उन्हीं की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प(
श्री अरविन्द मार्ग, नई दि(

शैक्षिक समस्याएं एवं सुधार : एक विश्लेषण

❑ स्मिता भवालकर

देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए पचास से अधिक वर्ष बीत गए हैं। स्वतन्त्र देश में जन्मी मेरी पीढ़ी भी आज इस दौर में है कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हमने लगभग बीस-पच्चीस वर्षो से भी अधिक बिता दिए हैं। अर्थात् हमने अपनी आयु के कई कीमती वर्ष इस देश की भूमि और वातावरण में व्यतीत किए हैं। न केवल सांस ली है अपितु एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क प्राप्त किया और जीवन के लिए आवश्यक अनेक सुख-सुविधाओं का उपभोग भी किया है। पर आज देश के सामने चुनौतियों को देखें तो लगता है कि स्वर्णिम सम्पदा वाला मेरा देश आज भी कहीं मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। चुनौतियों की सूची लम्बी है– सीमाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि से होते हुए हम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तक आ पहुंचते हैं। इन चुनौतियों पर विचार करें तो विश्लेषण अत्यन्त व्यापक रूप से करना होगा।

समस्याओं का विस्तार इस लेख का विषय नही है। इस लम्बी काल-यात्रा मे जहां हमने चिकित्सा, यान्त्रिकी, आण्विक शोध, सगणक जैसे जटिल क्षेत्रो में उच्च मानदण्ड स्थापित किए हैं वही यह भी प्रश्न उठता है कि क्या हमने सभ्य, सुसस्कृत जिम्मेदार, जागरूक व सयमित व्यवहार वाले नागरिक तैयार किए हैं? क्या हमारे देश के नागरिक अपने देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यो का निर्वहन भली प्रकार करते हैं?

अपने आसपास की स्थितियों में लोगों के सामान्य दैनिक व्यवहारो को देखें तो हमे उपरोक्त प्रश्नो के सकारात्मक उत्तर नहीं मिलते।

नागरिको का निर्माण करने का दायित्व किसका है, इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानते है। प्रत्येक युग में यह कार्य 'शिक्षा व्यवस्था' का होता है। 'शिक्षा' ही वह साधन है जिससे किसी देश व समाज के नागरिक 'सुयोग्य एवं सुसंस्कृत' नागरिक बनाए जा सकते है। शिक्षा को यदि 'प्रणाली उपागम' की दृष्टि से देखें और इस प्रणाली या 'तन्त्र' का विश्लेषण करे तो ज्ञात होता है कि जितना 'अदा' (input) हमने इसमे लगाया उसके अनुपात में 'प्रदा' (output) हमको नही मिल रहा है। इस 'अदा' में समस्त भौतिक ससाधन व शिक्षक, विद्यार्थी सहित अन्य मानवीय ससाधन सम्मिलित है। 'प्रदा' के रूप मे हमें विद्यार्थियो में, जो कि भविष्य के नागरिक हैं, 'अपेक्षित परिवर्तन' नही दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति मे हमें यह विचार करने पर बाध्य होना पड़ेगा कि दोष कहा है? इसके लिए अग्रलिखित विश्लेषण पर विचार करें–

स्वतन्त्रता-पूर्व से लेकर अब तक की दीर्घ कालावधि में विविध स्तरो पर 'शिक्षा' के सन्दर्भ मे अनेक आयोग, समितिया गठित हुए। उनके प्रतिवेदनो के आधार पर अनेक संशोधन भी हुए, परन्तु 'शिक्षा' को लेकर आम आदमी, राजनेता, अभिभावक, स्वयं शिक्षक व विद्यार्थी,

शिक्षा व्यवस्था

- **उद्देश्य**
  - व्यक्ति–
    - स्वयं का जीवन-यापन सुव्यवस्थित रूप से कर सके
    - अपना व परिवार का भरण पोषण व्यवस्थित कर सके
    - स्वयं के हित-अहित को पहचान कर उचित निर्णय ले सके
    - स्वय के हित-अहित का चिन्तन करते हुए समाज व राष्ट्र के विकास मे अपनी भागीदारी का दायित्व निभा सके
- **अदा**
  - विद्यार्थी
  - पाठ्यक्रम
  - शिक्षक
  - अभिभावक
  - अन्य मानवीय व भौतिक ससाधन
- **प्रक्रिया**
  - शिक्षण
  - अधिगम
  - शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य अन्त क्रिया
  - भौतिक ससाधनों का उचित प्रबन्धन
- **प्रदा**
  - विद्यार्थी में उद्देश्यो के अनुरूप परिवर्तन

शिक्षाशास्त्री व अन्य विचारक सभी असन्तुष्ट है। अर्थात् यदि हम वाणिज्य की भाषा में देखे तो लगाई गई 'पूंजी' की तुलना में 'प्राप्ति' नहीं है। अत यह आवश्यक लगता है कि हम वास्तविक शैक्षिक समस्याओ व शैक्षिक सुधारों का विश्लेषण करे।

उद्देश्य व पाठ्यक्रम– शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम परस्पर निर्भर तत्व हैं। किसी देश व समाज के जीवन-दर्शन व तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप उद्देश्य निर्धारित होते है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट पाठ्य-वस्तु निर्धारित होती है जिसे पढ़ाना हमारा तात्कालिक उद्देश्य होता है। अत. कुछ तात्कालिक उद्देश्य होते है जो अन्तिम उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए आज के समय के अनुरूप 'सगणक' की शिक्षा देना हमे आवश्यक लगा तो हमने उसे पाठ्यक्रम का अंग बना लिया। परन्तु 'सगणक-संचालन' मे आयु के अनुरूप निपुणता प्राप्त करना तात्कालिक उद्देश्य रहेगा व अन्तिम उद्देश्य उस निपुणता के माध्यम से स्वय का व राष्ट्र का विकास करना ही होगा। आज की स्थिति को देखें तो–

- हमने तात्कालिक उद्देश्य को अन्तिम उद्देश्य मान लिया है फलस्वरूप उद्देश्यो की अपूर्ण प्राप्ति होती है जैसे–'संगणक-संचालन' में निपुण सभी विद्यार्थी अपने राष्ट्र की प्रगति में सतत् व वास्तविक योगदान दे रहे हैं ऐसा हमे नही दिखता। उल्टे अधिकतम लोग विदेश जाकर अर्थार्जन करने को अन्तिम उद्देश्य मान लेते हैं। उसमें सफल हुए तो भी वे असन्तुष्ट रहते हैं क्योकि भौतिक सुखों की एक सीमा है यह भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण सीख उन्होंने भुला दी।
- दूसरी त्रुटि जो हम आज देख रहे हैं वह मनोविज्ञान के "वैयक्तिक विभेद" के सिद्धान्त को नजरअन्दाज करने की है। जैसे सगणक संचालन को देखें तो 'संगणक' की सामान्य समझ सभी विद्यार्थियों को हो यह तो ठीक है परन्तु सभी माता-पिता विचार करे कि उनके बच्चे संगणक विशेषज्ञ बनकर 'बिल गेट्स' की तरह अथाह धन अर्जित करने लग जाएंगे तो यह उन बच्चो के साथ अन्याय ही होगा क्योंकि सभी बच्चों की रुचि व क्षमताए भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार तात्कालिक या गौण उद्देश्यों में कालानुसार सशोधन किए जाए तो भी हमारे अन्तिम

उद्देश्यों को हमें भुलाना नहीं है।

व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास— शिक्षा का सामान्य अर्थ 'व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास' माना जाता है परन्तु आज देखा जा रहा है कि शालेय व महाविद्यालयीय शिक्षा के लगभग बीस-बाईस वर्ष बिताने के बाद भी परीक्षा में पर्याप्त अक लाने वाले विद्यार्थी को भी अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु 'पर्सनालिटी डवलपमेन्ट' के संस्थानों की शरण में जाना पड़ रहा है। उस पर विडम्बना यह कि जो कार्य शैक्षणिक संस्थाओ व अभिभावको ने दीर्घ अवधि में नहीं किया उसे यह विशुद्ध व्यावसायिक संस्थान मात्र चार से छह माह की सक्षिप्त अवधि मे करने का दावा कर रहे हैं। ये संस्थान क्या कर रहे है कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते है। जो यह केन्द्र सिखा रहे हैं वह होता है—

- आत्मविश्वासपूर्वक बातचीत करना,
- निर्णय लेना इत्यादि।

इससे स्पष्ट होता है कि पिछले बीस-बाईस वर्षो में हम कोई विशिष्ट पाठ्य-वस्तु तो विद्यार्थियों को सिखाते रहे परन्तु यह पाठ्य-वस्तु हमारे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन मात्र होती है, यह तथ्य हमने भुला दिया। परिणामस्वरूप विशद व समृद्ध पाठ्यक्रम होने के उपरान्त भी हमें वांछित परिवर्तन या उद्देश्य प्राप्त नही होते। अत· हमे पाठ्यक्रम में सुधार करने के साथ ही यह सदैव स्मरण रखना होगा कि शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य क्या है।

प्रक्रिया— शिक्षाशास्त्र मे शिक्षण विधियों, पद्धतियो के सन्दर्भ मे अनेक अनुसंधान हो रहे है व अनेक प्रभावी शिक्षण पद्धतियां विकसित की गई है। अनेक नवाचार अपनाए जा रहे है। परन्तु इन नवाचारों के बावजूद शिक्षण के ऐसे कुछ सामान्य परन्तु आधारभूत व महत्वपूर्ण आयाम है जिनका विचार आज के सन्दर्भ में अप्रासंगिक व कालबाह्य नहीं है। इस आधार पर प्रक्रिया के विश्लेषण से स्पष्ट होने वाले तथ्य इस प्रकार है।

व्यावहारिक परिवर्तनों का विचार— हम देखते है कि नागरिकशास्त्र विषय कई वर्ष पढकर भी पढ़े-लिखे लोग यातायात के नियमो का पालन नहीं करते। पर्यावरण सरक्षण सम्बन्धी पर्याप्त विषय-वस्तु पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के बावजूद वास्तविक जीवन मे लोग पर्यावरण सरक्षण के प्रति पर्याप्त रूप से सचेत नही हैं। देशभक्ति की कविताएं पढ़कर भी देश के प्रति निष्ठा की जिम्मेदारी मात्र सीमा पर तैनात सिपाही की है, ऐसा लगता है! अर्थात् शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई गई विषय-वस्तु में अनुभूति के स्तर या भावात्मक स्तर पर परिवर्तन के प्रयास गम्भीरता से किए ही नही गए। प्रत्येक विषय के शिक्षण के द्वारा व्यावहारिक स्तर पर अनेक भावात्मक परिवर्तन सम्भव होते हैं, इतना ही नहीं वे भावात्मक परिवर्तन उस विषय के शिक्षण के 'प्राप्य उद्देश्य' होते है। अतः दोष अधिगमकर्ता का नहीं बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का है। निर्धारित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विषय के शिक्षण को व्यावहारिक परिवर्तनों के स्तर तक ले जाना होगा। अध्यापक को मात्र तथ्य-सम्प्रेषण से आगे बढकर 'ब्लूम' की भाषा मे व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक (cognitive), भावात्मक (effective), क्रियात्मक (psychomotor) तीनो पक्षों तक अनिवार्यत· ले जाना होगा। भारतीय संस्कृति में सर्वागीण विकास की इस अवधारणा को पंचकोषो के रूप में कहा गया है— ● अन्नमय कोष अर्थात् अन्न से शरीर का पोषण, ● प्राणमय कोष अर्थात् श्वास-प्रश्वास से शरीर का पोषण, ● मनोमय कोष अर्थात् मन और भावों का विकास, ● विज्ञानमय कोष अर्थात् बुद्धि का विकास, ● आनन्दमय कोष अर्थात् आन्तरिक आनन्द जो 'स्व' की वास्तविक उच्च्य पहचान से आता है। आनन्दमय कोष के विकास के लिए नैतिक व आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसे हम टाल नही सकते। 'सर्वागीण विकास' की अवधारणा पूर्ण करने के लिए हमे इस ओर ध्यान देना ही होगा।

शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य अन्तर्क्रिया— शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य विषय-वस्तु के तथ्य सम्प्रेषित करने के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी अन्तर्क्रिया होती है। यह अन्तर्क्रिया भी विद्यार्थी पर विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती है। यह प्रभाव विद्यार्थी व शिक्षक के समायोजन

आवश्यक भौतिक ससाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। देश के अनेक विद्यालय व महाविद्यालय अच्छे भवन व आवश्यक शैक्षणिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, उच्च उपाधिधारी मानवीय संसाधन भी आज उपलब्ध हैं फिर भी शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यो की प्राप्ति में अपूर्णता दिखाई दे रही है। अतः मात्र संसाधनों के अभाव को हम शिक्षा के गिरते स्तर का कारण मानकर दोषमुक्त नही हो सकते। जहा 'प्रबन्धन' चौकस है वहां भी 'परीक्षा-परिणाम' तो अच्छे आते हैं परन्तु विद्यार्थी में अपेक्षित वास्तविक परिवर्तन के स्तर पर वहा भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। अतः हमें अदा के व प्रक्रिया के उन तत्वो पर विचार करना ही होगा जिनका उल्लेख यहा पूर्व में किया गया है।

आधी शताब्दी से भी अधिक की अवधि बीत जाए और हम अब भी अंग्रेजों को दोष देते रहें तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हम निरन्तर शिक्षा पद्धति मे परिवर्तन तो करते चले जा रहे हैं, सुधार की स्वाभाविक प्रक्रिया में उनकी आवश्यकता भी है परन्तु एक दृष्टि हमे वास्तविक समस्याओ पर डालनी ही होगी। इस दृष्टि से अन्य अनेक शैक्षिक सुधारों के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें यहा प्रस्तुत विश्लेषण का विचार करना ही होगा तभी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति मे वास्तविक उद्देश्यो के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तनो की हम आशा कर सकते हैं। ☐☐

सी-4/24-25 ऋषिनगर
उज्जैन, मध्य प्रदेश

वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा का महत्व

❒ ज्योति बहल

वर्तमान में समस्त विश्व में विशेषकर विकासशील देशों की विशिष्ट परिस्थितियों के सन्दर्भ में इस विषय के अन्तर्गत जनजीवन को समृद्ध बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अतएव इसी से संबंधित अनेक पहलुओं का अध्ययन इसकी विषय-सामग्री बन जाता है जैसे– जनसंख्या का इतिहास, स्थिति, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक सम्पत्ति व राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सम्पत्ति व पर्यावरण पर कुप्रभाव, प्रजनन क्रिया को नियन्त्रण में लाने के लिए जातीय ज्ञान, जनसंख्या नीति आदि। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं जैसे– आवास, जल, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व असामाजिक तत्वों की समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है।

जन से जन परस्पर मिलकर निर्मित जन समुदाय का आकार जब निरन्तर बढता ही गया तो उसे जनसंख्या के नाम से गिनने की आवश्यकता हुई। सामुदायिक जीवन के प्रारम्भ से ही मानव इस बात का अनुभव करता आ रहा है कि समाज में जनसंख्या की वृद्धि और कमी से तत्कालीन समाज की संरचना, स्वरूप, आकार और प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। समूह की सदस्य संख्या अधिक हो जाने पर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओ– भोजन, वस्त्र, आवास तथा यौन सन्तुष्टि की मांग बढ़ जाती है और जब उस मांग की पूर्ति उचित मात्रा में समय पर नही हो पाती तो हर सदस्य का जीवन अभाव ग्रस्त और सघर्षमय बन जाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक ढाचे मे अनेक परिवर्तन होते चले जाते हैं। अतः जनसख्या वृद्धि से जनसंख्या की लघुतम इकाई व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, देश एवं सम्पूर्ण विश्व की प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया प्रभावित होती है। जिसकी उपेक्षा स्वयं जनसंख्या के लिए घातक तथा विनाशक रूप धारण कर विकराल, विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर लेती है। वह स्थिति जब जन ही जन का जनक नही बल्कि स्वय भक्षक बन जाएगा। प्रकृति के संतुलन नियम के अनुसार कई जीव-जन्तु स्वयं की तीव्र गति से बढ़ती हुई संख्या को नियत्रित करने के लिए, ताकि स्वय के जीवन की रक्षा हो सके, स्वय के अश से उत्पादित सतति का भक्षण कर लेते हैं और अपनी सुख-सुविधा के अनुसार अपनी सख्या के संतुलन को बनाए रखते हैं। परन्तु यह 'संतुलन नियम' मानव जाति और उसकी सतति पर लागू नही हो सकता। कारण– मानव कभी भी अपनी सतति का भक्षण नहीं कर सकता। अतएव आवश्यकता है कि मानव अपनी सख्या के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन को नियंत्रित कर ले इसके लिए 'जनसंख्या शिक्षण' का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए।

एक अनुमान के अनुसार 2005 तक सबसे अधिक जनसख्या वाले 50 शहरो में से जो 40 शहर विकासशील देशो में होंगे। उन महानगरों मे से अधिकतम नगर भारत मे होगे, जिनमे कुछ की आबादी डेढ़ से ढाई करोड

तक होने की सम्भावना है। एशियाई-पेसिफिक देशो की एस्केप कांफ्रेंस, कोलम्बो 1982 के विचारकों तथा सेक्रेटरी एस.एस. किबिया ने इस बढ़ती हुई विकट जनसंख्या समस्या को सीधे तथा तुरन्त प्रभावित कर अंकुश में लाने वाले कुछ कठोरतम एवं अनिवार्य उपायों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया जिस पर हमे विशेष रूप से न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि तुरन्त ही जनसख्या वृद्धि को नियत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। कारण– हमे यह नही भूलना चाहिए कि विश्व की मात्र 1/2 प्रतिशत भूमि पर बसे हमारे देश भारत मे विश्व की कुल जनसख्या का छठा भाग सांसें ले रहा होगा। अत' जनसख्या शिक्षण का अध्ययन नई पीढ़ी के लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए। देश की अप्रत्याशित बढती हुई जनसंख्या की समस्याओं का सामना करने के लिए जनसंख्या शिक्षण विषय एक महत्वपूर्ण गहन-गम्भीर दीर्घकालीन भूमिका अदा कर सकेगा।

जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो विश्व, देश तथा राज्य की जनसंख्या के सभी पक्षों का ज्ञान दे। जनसख्या और उसकी समस्याओ के प्रति ऐसी धारणाओं तथा व्यवहार का विकास करने मे सहायक हो जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हितकारी हो। परन्तु इसका अर्थ यौन शिक्षा से एकदम भिन्न है। इस संबंध मे जनसंख्या शिक्षा के प्रथम परिचायक कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स कालेज के प्रोफेसर स्लान आर. वेलेड ने स्पष्ट रूप मे कहा भी है कि "There should be no confusion in understanding the meaning of population education as it is quite different from sex education or "Education for family living"

शिक्षण के कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या शिक्षा न तो परिवार नियोजन संबधी कार्यक्रम है, न यौन शिक्षा है और न ही प्रचार या विशिष्ट दीक्षा संबंधी कार्यक्रम। यह एक शैक्षिक प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र-छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य मे देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसख्या की स्थिति, ज के प्रमुख तत्वो, जनसंख्या का बोध कराया जा साथ ही जनसंख्या वृद्धि से जागरूक समस्या जनसाधारण के जीवन-स्तर पर पड़ने वाले प्र विषय में भी जागरूक कराया जा सकेगा।

जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या प्रक्रिया की प्रवृत्ति एव अर्थ, जनस विशेषताओं, जनसंख्या परिवर्तन के कारण एव तथा इन परिवर्तनों का अपने परिवार, अपने सम विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे मे ज्ञ करता है।

अतः जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो से अथवा मानव शक्ति से, संसाधन से संब इस शिक्षा मे जनसख्या के आकार, जनसख्या ह्रास, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या मे लैंगिक विवाह की आयु आदि विषयो का ज्ञान करा है। यह वह शिक्षा है जिससे न केवल आकड पता चलता है बल्कि जनसख्या वृद्धि या ह्रास द तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर पडने वाले प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त सकती है। इसी अनुक्रम मे यदि जनसंख्या गति तीव्र है और उसके फलस्वरूप मानव त विभिन्न पहलुओं पर कुप्रभाव पड़ रहा है तो भी जानकारी कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए।

सक्षेप मे जनसख्या शिक्षण अत्यधिक जनस से उत्पन्न समस्याओ के विषय में गहन ज्ञा एवं जागरूकता प्रदान करता है, जिसे प्राप्त कर स्वयं अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश उ के जीवन-स्तर को उच्च एव समृद्ध बना स

"राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश" ने शिक्षा की परिभाषा को इस प्रकार समझाया है– शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है जिसके द्वारा विभि विशेषकर छात्र-छात्राओ की विश्व के पर देश-प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसख्या स्थिति, के प्रमुख तत्वो, जनसंख्या और पर्यावरण के

सबध, जनसख्या वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव आदि का बोध कराया जा सकेगा। साथ ही जनसख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओ और जनसाधारण के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय मे भी जागरूक कराया जा सकेगा।

1970 में बैकॉक मे यूनेस्को द्वारा आयोजित एक गोष्ठी "जनसख्या तथा पारिवारिक जीवन शिक्षण" में व्याख्या इस प्रकार की गई कि "जनसख्या शिक्षण एक ऐसा शैक्षणिक कार्य है जो शिक्षार्थियों को परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समग्र विश्व की आबादी की परिस्थिति के विषय में स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है तथा इस सन्दर्भ मे स्वयं के और देश के प्रति अपने कर्तव्य, व्यवहार और उत्तरदायित्व की समझ व अनुभूति विकसित करता है।

"अगस्त 1969 मे बम्बई मे राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिससे जनसंख्या शिक्षण के विषय मे इस प्रकार स्पष्टता की गई कि जनसख्या शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी भली प्रकार समझ जाए कि परिवार के आकार को नियन्त्रण में रखा जा सकता है। जनसख्या नियन्त्रण से देश के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने और समृद्ध बनाने में सहयोग मिलता है। जनसख्या शिक्षण से यह जागरूकता भी उत्पन्न की जा सकती है कि परिवार के सदस्यो के सर्वाग सुखो, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, युवा पीढी के आशामय भविष्य के लिए आज भारतीय परिवार को दो या तीन बच्चों के जन्म से ही समझौता करना चाहिए।"

व्यक्ति, देश, समाज का कल्याण इसी मे निहित है कि कुटुम्ब का स्वरूप छोटा हो। उपरोक्त सभी व्याख्याओ के गहन, गम्भीर अध्ययन के पश्चात् निम्न बाते स्पष्ट होती हैं–

- ☐ जनसख्या एक शैक्षणिक प्रक्रिया है।
- ☐ जनसख्या शिक्षण विद्यार्थियो को जनसख्या व उसकी गतिविधियो के विषय मे जागरूक बनाता है।
- ☐ जनसंख्या शिक्षण जनवृद्धि के कारणों एव उससे उद्‌भुत होने वाले भयंकर परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- ☐ विद्यार्थियो को गृहस्थ आश्रम मे प्रवेश करने के बाद परिवार के सन्दर्भ में विवेकपूर्ण समझदारीपूर्वक निर्णय लेने मे उचित मार्गदर्शन करता है।
- ☐ जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन-स्तर पर पडने वाले कुप्रभाव को दर्शाता है।
- ☐ जनसख्या शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों मे यह आत्मसात् कराना है कि वर्तमान काल में कम सतति देश भक्ति ही नही वरन् आने वाली पीढ़ी के प्रति नैतिक कर्तव्य भी है।

जनसंख्या शिक्षण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जनवृद्धि से हमारे देश के लिए क्या-क्या नवीन समस्याए उत्पन्न होंगी तथा व्यक्तिगत जीवन स्तर पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी तथा कल की आने वाली पीढी को इस बात के लिए पहले से ही तैयार करना है कि वे अपने परिवार व संतान के विषय में उचित ढग से विचार कर सकें, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।

जनसंख्या शिक्षण का क्षेत्र एवं विषय-सामग्री

'हौसर (Houser) के पॉपुलेशन गैप इन दि कुरीकुलम मे एक लेख मे जनसख्या शिक्षण के अध्ययन क्षेत्र के लिए निम्न विषयो को व्यक्त किया–

- ☐ जनसंख्या वृद्धि इतिहास– भूतकाल से लेकर आधुनिक समय तक।
- ☐ जनसंख्या वृद्धि– प्रवृत्ति, भविष्य के लिए दृष्टिकोण, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या का सक्रमण सिद्धान्त।
- ☐ जनसंख्या वितरण।
- ☐ जनसंख्या संयोजन– प्रवृत्ति, भविष्य के लिए दृष्टिकोण, लिंग, आयु, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताए।
- ☐ जैविक और जातीय ज्ञान।
- ☐ जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथ्यों के सन्दर्भ मे ज्ञान।
- ☐ जनसख्या अनुसंधान की पद्धतियां।

एन.सी.ई.आर.टी. ने 1970 में दिल्ली मे एक कार्यशाला का आयोजन किया, उसमें जनसख्या शिक्षण

के विषयों की स्पष्टता इस प्रकार की गई–

- ☐ जनसंख्या वृद्धि
- ☐ जनसंख्या और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास
- ☐ स्वास्थ्य पोषण और जनसख्या
- ☐ जैविक तथ्य– पारिवारिक जीवन और जनसख्या

इन विषयों का समावेश स्कूल स्तरीय शिक्षण के लिए बताया गया था।

उपरोक्त बातो को लक्ष्य मे रखते हुए यही स्पष्ट होता है कि जनसख्या शिक्षण का मुख्य विषय जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है। आज जनसख्या शिक्षण की विषय-सामग्री मे निम्न तथ्यों का समावेश किया जाता है–

- ☐ जनसख्या वृद्धि का इतिहास– विश्व के सन्दर्भ मे सामान्य ज्ञान और भारत के सन्दर्भ मे विशिष्ट ज्ञान, जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रवृत्ति और समस्या।
- ☐ भारतीय जनांकिकी का परिचय– जनसख्या वृद्धि– जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
- ☐ जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पहलुओ और राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव।
- ☐ जनसंख्या वृद्धि गति का पर्यावरण, खाद्यान्न, प्राकृतिक स्रोतो व जीवन स्तर पर प्रभाव।
- ☐ जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति का व्यक्ति, उसके पारिवारिक जीवन व जीवन स्तर पर प्रभाव।
- ☐ प्रजनन क्रिया का पूर्व-प्राथमिक ज्ञान।
- ☐ जनसख्या नीति– विश्व के सदर्भ मे सामान्य ज्ञान एव भारत के सन्दर्भ में विशिष्ट ज्ञान।

वर्तमान में समस्त विश्व में विशेषकर विकासशील देशों की विशिष्ट परिस्थितियो के सन्दर्भ में इस विषय के अन्तर्गत जनजीवन को समृद्ध बनाने के लिए जनसख्या शिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया गया है, अतएव इसी से सबंधित अनेक पहलुओं का अध्ययन इसकी विषय-सामग्री बन जाता है जैसे– जनसंख्या का इतिहास, स्थिति, जनसख्या विस्फोट, जनसख्या वृद्धि का सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक सम्पत्ति व राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सम्पत्ति व पर्यावरण पर कुप्रभाव, प्रजनन क्रिया को नियन्त्रण में लाने के लिए जातीय ज्ञान, जनसख्या नीति आदि। जनसख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओ जैसे– आवास, जल, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व असामाजिक तत्वो की समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है।

व्यक्ति का आचरण सामाजिक, जैविक वातावरणीय परिस्थितियो से उद्भूत एक संकलन है अर्थात् व्यक्तित्व है जो तैयार होने पर स्वयं व्यक्ति, उसके परिवार, समाज व साथ ही समग्र जगत को प्रभावित करता है। व्यक्ति स्वय को समाज का अभिन्न अंग मानते हुए स्वय अपने परिवार एव अपने देश के भविष्य के सन्दर्भ में तर्क-सगत और उत्तरदायित्व पूर्ण निर्णय ले सके, इसके लिए उसमें समझ शक्ति, विवेक, चतुरता, सवेदनशीलता होना परमावश्यक है। जनसख्या शिक्षण मात्र छोटे या बड़े प्रकार के परिवार का स्वरूप निश्चित करने का आयोजन नही है। वास्तव मे यह व्यक्ति को इस बात के लिए जागरूक एव शिक्षित बनाने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि जनसख्या की वृद्धि जीवन स्तर एवं वातावरण– इन तीनो का निकट सम्बन्ध है। अर्थात् जनसख्या वृद्धि वातावरण व जीवन स्तर दोनों को ही बुरी तरह प्रभावित करती है। जीवन स्तर का अवलम्बन विशेष रूप से खाद्य सामग्री, पर्याप्त वस्त्र, शुद्ध पेय जल, शुद्ध वायु शक्ति के साधन एवं भूमि आदि जीवन के अनेक स्रोतों पर आधारित है। इसी प्रकार शिक्षण की सुविधाए, रोजगार, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाए एवं आर्थिक विकास आदि जीवन स्तर को बनाने मे आधार स्तम्भ बनते हैं, जब जनवृद्धि अति तीव्र गति से बढ़ती है तो उपरोक्त जीवन स्रोतो की कमी होती जाती है क्योंकि सभी स्रोतों में अधिक से अधिक भागीदारी के अधिकारी बढ़ते जाते है, परिणामस्वरूप जीवन स्तर निम्न से निम्नतर बनता चला जाता है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण देश मे अपेक्षाकृत अधिक खाद्य सामग्री, वस्त्र, आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाए, यातायात के साधन, अधिकाधिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता खड़ी होती जाती है अर्थात्

जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह समझ, ज्ञान उन किशोर बच्चों को देना है जो भविष्य में इस दुर्घटना का शिकार होने जा रहे है।

जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य

जनसंख्या शिक्षा मनुष्य को उसी प्रकार शक्ति प्रदान करती है जिससे वह चिन्तन मनन कर अपने स्वास्थ्य, समाज एव देश के हित को समझ सके। आज हमारा देश जनसंख्या वृद्धि की विकराल समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा के विषय की उपयोगिता सिद्ध करने की ऐसी आवश्यकता नही है। भारत में प्राचीन समय से ही जनसख्या शिक्षा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न केवल सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति मे सम्मिलित रही है बल्कि विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों, पुस्तको में भी इसके उदाहरण मिलते है। जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जा सकते हैं–

- ☐ जनसख्या शिक्षण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एव सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जनसख्या का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन एवं स्पष्टीकरण करती है। जनसख्या शिक्षण जनसंख्या की प्रक्रिया और उसकी वृद्धि के परिणामो का अभ्यास कराता है।
- ☐ व्यक्ति व कुटुम्ब पर बढ़ती हुई जनसख्या के प्रभाव को समझना एव पारस्परिक सहकार और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है।
- ☐ जनसंख्या शिक्षा में जनांकिकी के सिद्धान्त, परिवर्तन एवं कार्यकलापों का संज्ञान जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर आदि की विस्तृत जानकारी, इन दरों की कैसे गणना की जाती है और क्या आवश्यकता है आदि विषयो का ज्ञान करना।
- ☐ युवा-वर्ग में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि, उसकी स्थिति एवं कारणों की जानकारी देना।
- ☐ मानव जीवन के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एव सांस्कृतिक पहलुओ पर बढती जनसंख्या के कुप्रभाव की जानकारी कराना तथा विकास के कार्यक्रमों की महत्ता बताना।
- ☐ बढती हुई जनसंख्या की विषम परिस्थिति का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट करना।
- ☐ जन-शक्ति एवं अन्य ससाधन मे असामंजस्यपूर्ण स्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक ज्ञान कराना तथा समाधान के बिन्दु स्पष्ट करना।
- ☐ जिम्मेदार दम्पत्ति के कर्तव्यो को बताते हुए परिवार में उच्च स्तर के मातृत्व एवं पितृत्व की भावना का विकास करना।
- ☐ स्वास्थ्य, मातृ शिशु कल्याण, परिवार नियोजित करने के कार्यक्रम, पुष्टाहार एव विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिवार के बच्चे पर्याप्त हो सकें आदि के विषयों पर विस्तृत जानकारी देना ताकि समाज मे रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति ऊंचे स्तर का जीवन व्यतीत कर सके।
- ☐ विभिन्न परिस्थितियो में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य एव जनसंख्या सम्बन्धी नीति का ज्ञान कराना।
- ☐ मनुष्य के आपसी सम्बन्धों, पति-पत्नी के नाजुक रिश्ते एव समाज मे इन सम्बन्धो की मान्यता को ऊंचे स्तर पर रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान देना।
- ☐ विवाह के पवित्र बन्धन को स्वीकार करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर पर बनाए रखना क्यो आवश्यक है, और इससे अच्छे राष्ट्र का कैसे निर्माण हो सकता है, इसकी जानकारी देना।

1969 में जनसंख्या शिक्षण का एक परिसंवाद मुम्बई में आयोजित किया गया था, जिसमे जनसंख्या शिक्षण के हितों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि–

- ☐ परिवार के कद को इच्छानुसार नियन्त्रित किया जा सकता है, इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए।

- ☐ उनमें ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना कि जनसख्या शिक्षण जीवन को समृद्ध बनाने मे सहायक, मार्गदर्शक बनता है।
- ☐ छोटे क़द के परिवार एव व्यक्तिगत जीवन इन दोनो के बीच सीधा सम्बन्ध है, इसका स्पष्टीकरण करना है।
- ☐ परिवार के सदस्यो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए छोटे कुटुम्ब का महत्व बताना है।
- ☐ भावी पीढ़ी का भविष्य उज्वल बनाने के लिए जो अवसर प्रदान करना है, उस अवसर के सन्दर्भ में छोटा कुटुम्ब कितना उपयोगी है इसके विषय मे ज्ञान देना है।

संक्षेप के जनसंख्या शिक्षण का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न खतरों का ज्ञान नई पीढ़ी को कराना है जिससे वे अपने भविष्य को उन्नत बना सकें। यह तभी सम्भव है जब उन्हें जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं व प्रजनन नियन्त्रण सम्बन्धी ज्ञान हो। यह समस्त ज्ञान आज के युवा-वर्ग को कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास के उन समस्त आंकडों एवं घटकों का ज्ञान देना है, जो मानव जीवन के बहुमुखी विकास मे सहायक हो सकें।

जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता

जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, अंग एव विभिन्न अंगों के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनसख्या शिक्षा का भारतवर्ष के सन्दर्भ मे अत्यधिक महत्व है। हमारे देश में अनुमानत· लगभग एक अरब व्यक्ति निवास करते हैं और दुनिया के नक्शे में इसका स्थान चीन के पश्चात् द्वितीय है। हमारे देश मे जनसख्या वृद्धि विस्फोटजनक स्थिति मे है। अतः यह आवश्यक है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा अथवा बूढ़ा, जनसंख्या शिक्षा अवश्य प्राप्त करे। इस प्रकार के ज्ञान से दोहरा लाभ होगा— आत्मोत्थान एवं भावी पीढ़ी का कल्याण। यदि हम वास्तव में देश की उन्नति चाहते हैं और देश का स्थान विकसित देशो में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें यह नारा अपनाना होगा—

"हर एक, सीख एक, सिखाए एक"

भारत में जनसख्या शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत कम थी और क्षेत्रीय विस्तार की सम्भावनाए अत्यधिक थीं, इसलिए इस युग की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसख्या बढ़ाने के लिए भारतीय पूर्वज विवाह के समय बहु विवाह के साथ-साथ बच्चो की कामना करते थे।

जैसे-जैसे समाज का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई तथा उत्पादन और जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगी, वैसे-वैसे धार्मिक विचारों में भी परिवर्तन आए, तत्काल परिस्थितियो के अनुकूल वैदिक ऋषियो ने भी विवाह संस्था तथा सतानोत्पत्ति की अवधारणा को जन्म दिया और यह व्रत लिया कि पुरुष आजीवन पत्नी का साथ दे। परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि या ह्रास की नीति मे वैदिक काल से ही परिवर्तन होते रहे हैं और जनसंख्या शिक्षा किसी न किसी रूप में दी जाती रही है। भारतीय संस्कृति और परम्परा में जहां एक ओर जनमानस में अपने शाश्वत मानवीय मूल्यों से विचलित न होने का गुण है वहीं दूसरी ओर निरन्तर बदलते हुए समाज में परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने और सामंजस्य स्थापित करने का गुण सन्निहित दिखाई देता है। यह लचीलेपन का ही परिणाम है कि सहस्र वर्षो के उतार-चढ़ाव के बावजूद हमारी परम्पराए एवं संस्कृति अभी तक अक्षुण्ण बनी हुई है और मानवता के विकास मार्ग को सदैव प्रशस्त करती आई है।

परिस्थितियों के अनुरूप भारत में ऋषियों, मनीषियों, विचारको आदि ने आदर्श जीवन के लिए अपना सन्देश समय-समय पर दिया है। अत· जनसख्या शिक्षा कोई नई शिक्षा नही है, यह विभिन्न कालो मे विभिन्न प्रकार से विभिन्न उद्देश्यो को लेकर दी जाती रही है। वर्तमान परिस्थिति और माग के अनुसार यह नितान्त आवश्यक है कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न कुप्रभावों को रोकने, जनता के बहुमुखी विकास एव देश को विकसित देशो की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा को

देश के जन-जन और कोने-कोने तक पहुंचाया जाए।

किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एव सास्कृतिक विकास में जनसख्या की अति वृद्धि बाधक बनती है। किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का विकास जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता को स्वीकृत किए बिना नहीं हो सकता। जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता के अनेक कारण है—

जनसंख्या विस्फोट—सम्पूर्ण विश्व मे, विशेष रूप से विकासशील देशों मे जनसख्या वृद्धि की गति अति तीव्र है। मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या को नियन्त्रित नही किया जा पा रहा है। विकासशील देश जनसंख्या को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से जन्म दर नियन्त्रित करने के लिए परिवार नियोजन अपना रहे है। इसका सीधा संबंध उन दम्पत्तियो से होता है जो अभी एक सन्तान के जनक हैं और अपनी उत्पादन आयु के अन्दर हैं, उन्हे अपने परिवार का नियोजन करना होगा अन्यथा बहुत विलम्ब हो जाएगा। दूसरी ओर इसका सबंध उन किशोरों से है जो विवाह की आयु की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान प्रदान करना है कि—

- प्रजनन एक अनिच्छित व अनियन्त्रित प्रक्रिया नहीं है, पहले ऐसा माना जाता था कि संतान का जन्म एक सयोग है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अकुश मे नहीं लाया जा सकता इस पुरानी मान्यता से युवको को मुक्त करना है।
- जनसंख्या समस्या का सम्बन्ध मात्र प्रौढ़ पीढ़ी से नही है। पहले यह भी मान्यता थी कि युवको के पास करने के लिए अन्य बहुत से कार्य हैं जो रुचिकर एवं महत्वपूर्ण हैं। अत. जनसंख्या समस्या का ज्ञान उनके योग्य नही है। आज यह मान्यता उचित नहीं है। किशोर मन में ही यह सस्कार डालना है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में आने वाली है।

जनसंख्या और विश्व के प्राकृतिक साधनों में बढ़ता हुआ असन्तुलन—प्राकृतिक सम्पदा प्रकृति की अमूल्य देन है जो सीमित है, उसमें वृद्धि नही की जा सकती। लेकिन आज जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ती जा रही है इस कारण प्रकृति एवं मानव के बीच एक असन्तुलन पैदा हो गया है। लोगों को इस सन्दर्भ में ज्ञान कराना है कि जनसंख्या वृद्धि से भयंकर सर्वनाश हो सकता है। अतः जनसंख्या को नियन्त्रित करना होगा। आज यह बात भी सर्वविदित है कि जनसख्या अनिच्छित रूप से नही बढ़ती।

परिवार नियोजन का आम प्रचार-प्रसार—बहुत से विकासशील देशो ने जनसंख्या नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय नीति, जन्म दर नियन्त्रण, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम अपनाए हैं। इन आयोजनों को जन-जन तक पहुचाने के लिए पोस्टर, पेंटिंग्स, पम्फलेट, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, टी.वी. एव सिनेमा आदि की मदद ली जाती है। इन सामूहिक माध्यमों से प्रेक्षकों व श्रोताओ को प्रभावशील ढंग से नियन्त्रित नही किया जा सकता, विशेष तौर पर युवक इस ओर ध्यान नही देते और ध्यान भी दें तो उसे उचित रूप में ग्रहण नही कर पाते जिससे लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना अधिक है। अतएव इस बात की जरूरत है कि जनसख्या समस्या के विषय में सूचना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एवं व्यवस्थित परिवार नियोजन शिक्षण के द्वारा दी जानी चाहिए।

वर्तमान परिवार नियोजन कार्यक्रम को तीव्र बनाने की आवश्यकता—शिक्षण संस्थाओ में जनसख्या शिक्षण देने की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई है कि जनसंख्या समस्या गम्भीर रूप धारण न करे, साथ ही वर्तमान में जन्म दर कम करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। परन्तु जनसंख्या वृद्धि की समस्या इतनी जटिल और विविध रूपी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने मे अथवा जनसंख्या को नियन्त्रित करने मे बहुत समय लगेगा। भारत मे परिवार कल्याण का उद्देश्य जन्म दर जो 1969-70 मे 38 प्रति हजार थी, जिसे कम करके 20 प्रति हजार तक लाने का प्रयास है, अथवा अनेक नवीन समस्याएं जन्म लेगी। यह बड़ी तीव्रता, गम्भीरता से अनुभव किया गया है कि इसके लिए दीर्घकालीन व विविधलक्षी आयोजन की आवश्यकता होगी। इसी कार्य की पूर्ति हेतु जनसख्या शिक्षण की

आवश्यकता अनुभव की गई है।

जनसंख्या आयु संरचना—आयु आधार पर जनसख्या वितरण की समस्या का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे श्रम शक्ति के अनुपात का ज्ञान प्राप्त होता है। साधारण रूप से 15-45 वर्ष की आयु संतानोत्पत्ति की अवस्था मानी जाती है। आज वर्तमान में विकासशील देशो मे लगभग चालीस से पैतालिस प्रतिशत जनसख्या का भाग सोलह वर्ष की आयु-सीमा के अन्दर है। भावी दो दशको मे वह प्रौढ़ जनसंख्या का रूप धारण कर लेगी। अतएव प्रजनन के प्रति इस आयु समूह का जैसा भी दृष्टिकोण होगा, वही महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसलिए स्कूलों में जनसंख्या शिक्षण अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है।

भावी जनपीढ़ी की सफलता हेतु जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता—परिवार नियोजन का सम्बन्ध मात्र वर्तमान की पुनरुत्पादन वाली जनसंख्या से नहीं है, इसका सबंध तो प्रत्येक उस समूह के हर सदस्य से है जो पुनरुत्पादन आयु समूह में प्रवेश कर रहा है। इसलिए परिवार नियोजन के प्रयत्न निरन्तर चलते रहने चाहिए। जनसंख्या समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है और इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को इसका ज्ञान कराया जाए। इस प्रकार जनसख्या शिक्षण प्रत्येक नई आने वाली पीढी को अपने परिवार मे परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरणा देगा।

जनसंख्या शिक्षण उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक एवं प्रभावशाली जीवन शैली तैयार करने का एक माध्यम—विद्यालयों में जनसख्या शिक्षण देने का महत्वपूर्ण कारण है— अति जन वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओ से युवको को परिचित कराना। नि.सन्देह वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार से अनेक अनिष्टों के संकेत प्राप्त हो रहे है। अतएव आज कोई भी इस शिक्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता। कुछ शिक्षाविद् इस पर जोर दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए जनसख्या शिक्षण को शिक्षण प्रवृत्तियों का एक अग बना दिया जाए। परन्तु वास्तव में जनसख्या शिक्षण का अध्ययन समाज विधाओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

आर्थिक विकास तथा व्यवस्थित जनसंख्या वृद्धि का शिक्षा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तथा एक-दूसरे पर आधारित होने के कारण हमारी "राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली" के निर्धारकों एव निर्माताओं ने, जनसंख्या की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए, सामान्य शिक्षा मे, जनसंख्या शिक्षण के महत्व को समझा और 1969 में हुए पॉपुलेशन एजुकेशन के नेशनल सेमिनार, मुम्बई में एक विशेष पॉपुलेशन एजुकेशन सेल अर्थात् "जनसंख्या शिक्षण कक्ष" की स्थापना की नीव— एन.सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत रखी गई। नवम्बर 1973 में "पॉपुलेशन ग्रोथ एण्ड ह्यूमन डवलपमेन्ट" विषय पर भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कान्फ्रेंस में जनसंख्या शिक्षण कक्षा के प्रमुख प्रो. टी. एस. मेहता ने "जनसख्या शिक्षण" का महत्व समझाते हुए जनसख्या शिक्षण को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षण में आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाने की जोरदार सिफारिश की, जिससे कि अधिक से अधिक युवा-वर्ग जो कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी का निर्माता है, जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली समस्याओ के प्रति जागरूक रह कर अपने परिवार के नियन्त्रण के बारे मे उचित निर्णय ले सके। केन्द्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को तीव्र गति देने के लिए एक विशेष कार्यनीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार स्कूलो व कालेजों के छात्रो के साथ न पढ़ने वाले युवकों को भी जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा दी जाएगी। इस कार्य को सरकारी विभागो, एजेन्सियों व सगठित क्षेत्रो द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के लिए चलाए जाने वाले शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो में लागू किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को शीघ्र साक्षर बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएगे, अधिक सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी ताकि महिला वर्ग जनसंख्या नियन्त्रण में पूरा योग दे सके।

सन् 1962 मे शिक्षाशास्त्री 'श्री वारेन थॉम्पसन' ने अपनी रिपोर्ट (टीचर्स-कालेज रिपोटे) मे, सामान्य शिक्षा के बारे में मत व्यक्त करते हुए जनसख्या शिक्षण के बारे में भी उल्लेख किया जिसका सारांश यह है कि 'शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक सरकार में अपने नागरिको

को आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं, परिस्थितियो से अवगत कराना है और उन समस्याओं को हल करने के लिए एक पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। आज अनेकानेक समस्याओ का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है जो व्यक्ति, समाज व देश को बाह्य एवं आन्तरिक रूप से प्रभावित करती है। इस समस्या को दूर करने के लिए युवकों को सामाजिक, आर्थिक नीतियो से अवश्य अवगत कराना होगा, नही तो ऊपर से थोपी गई कोई भी नीति सफल नहीं हो सकेगी।

फिलिप एस होसर ने इस बात पर जोर दिया है कि आज भी विश्व के विभिन्न जनसमूहों में जनसंख्या शिक्षण, शिक्षण का अंग नहीं बन पाया है जबकि वर्तमान जनसख्या के सन्दर्भ मे इसे शाला में अध्ययन का एक आवश्यक अग बनाना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में—

"Information about population should be regarded as an essential part of general education."

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने जनसख्या की समस्या को महत्वपूर्ण समस्या समझकर यह सिफारिश की— 'शिक्षा को, राष्ट्रीय योजनाओ को सफल बनाने हेतु, एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि व्यक्ति, समाज व देश का कल्याण हो। गुजरात मे सरदार पटेल विश्वविद्यालय को इस बात का श्रेय जाता है कि सर्वप्रथम इसने 'जनसंख्या शिक्षण' को 'को-ऑपरेशन कोर्स' के रूप मे अपनाया। यह कोर्स कालेज के तीनो वर्षो में जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा और इसे अनुस्नातक कक्षा तक ले जाने की सम्भावना पर आशा व्यक्त की गई है।

विकासशील देशो मे जनवृद्धि के अनेक कारण हैं जैसे— बाल-विवाह, अशिक्षा, भाग्यवादी दृष्टिकोण, धार्मिक अंधविश्वास, परम्परागत निरर्थक मान्यताए आदि जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक समाज मे पहुंच गई हैं, जिनके अनेक सामाजिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आधार है। उन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकने का एक ही सही सशक्त उपाय है, और वह है— 'जनसंख्या शिक्षा'।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'जनसंख्या शिक्षा' आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार करती है कि वे जीवन व समाज की वास्तविकताओं, सघर्षो का सामना करने मे समर्थ बन सके। साथ ही वे 20वी सदी की जनवृद्धि से उत्पन्न होने वाली भयंकर स्थिति से अवगत हो सके और जनसंख्या मर्यादा के विषय मे जागरूक बन सके। इसके द्वारा आज की शिक्षण संस्थाएं इस समय की जनवृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए युवको को तैयार करेंगी। उन्हें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जिसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो, अपना निजी व्यक्तित्व हो, अपनी दृष्टि हो, अपना बनाया हुआ उन्नत रास्ता हो एवं उनका जीवन सभी सुख-सुविधाओ से सम्पन्न उच्च स्तर का हो। 'जनसख्या शिक्षा' द्वारा आज का युवा वर्ग स्वय का तथा आने वाली पीढ़ियो का जीवन सुखी, समृद्ध, सुव्यवस्थित, उच्चस्तरीय एवं संवरा हुआ बना सकता है।

जनसंख्या शिक्षा– आवश्यक आधार एवं नीति

हमारे देश में पिछले चार दशकों की लगातार योजना के बावजूद हम अपनी सर्वाधिक गम्भीर समस्या— जनसंख्या को नियन्त्रित करना— को हल नहीं कर सके; पर वास्तव में इस दिशा में किए गए हमारे समस्त प्रयास खोखले साबित हुए हैं। यद्यपि जनसख्या वृद्धि नियन्त्रित होने के विभिन्न स्तरो पर विभिन्न विद्वानों द्वारा कई कारण बताए जाते रहे हैं। किन्तु इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि हम अपने देश मे आम जनता को उचित रूप से जनसंख्या शिक्षा प्रदान नही कर सके।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या शिक्षा आम मनुष्य को एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जिससे वह चिन्तन एव मनन कर अपने स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित को समझ सकेगा। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश में प्राचीन समय से ही यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न केवल सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति मे सम्मिलित रही है, बल्कि विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थो एव पुस्तको में भी इसके उदाहरण मिलते हैं।

आधुनिक समय मे भी विभिन्न शिक्षाविद् एवं जनसख्या विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते है, कि जनसंख्या समस्या को हल करने के लिए आम जनता को जनसंख्या शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है। परन्तु यह शिक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाए? शिक्षा के किस स्तर से यह शिक्षण आरम्भ किया जाए? शिक्षा के किस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के किस अंग का शिक्षण किया जाए? जनसंख्या शिक्षण का माध्यम कैसा हो? इत्यादि के सम्बन्ध में इन विद्वानों में मतभेद रहे हैं। वास्तव मे जिस प्रकार बिना किसी ठोस आधार एव सोची-समझी रणनीति के अभाव में हमारे जनसंख्या नियन्त्रित करने के अब तक के प्रयास असफल रहे हैं उसी प्रकार यदि जनसख्या शिक्षण के लिए भी यदि पहले कोई आधार नही बनाया गया एवं सोच-समझ कर नीति तैयार नही की गई तो सम्भवतया यह उपाय भी कारगर सिद्ध नहीं हो सके।

वास्तव में जनसख्या शिक्षा किसी एक विषय़ अथवा जीवन के किसी एक पहलू को ध्यान मे रखकर नहीं दी जाती बल्कि मानव के बहुमुखी विकास को दृष्टि मे रखते हुए दी जाती है। अत. जनसख्या शिक्षण का उचित आधार तभी तैयार हो सकेगा जब पहले से यह निश्चित हो सके कि इस शिक्षण के अन्तर्गत किन-किन बातों का समावेश होना चाहिए।

जनसख्या शिक्षण के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बिन्दुओ को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए—

जनसंख्या सम्बन्धी आकड़े— देश, प्रदेश, जिला, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल कितनी जनसंख्या है, किस गति से वह बढ़ रही है, कब से बढ रही है, ऐसी बातें जनसंख्या के आंकड़ों से जानी जानी चाहिए। जनसंख्या आंकड़ों सम्बन्धी विषय को 'डेमोग्राफी', 'पापुलेशन स्टडी' आदि की भी संज्ञा दी जाती है। इस विज्ञान द्वारा हम यह जानकारी कर सकते हैं कि किसी विशेष समय देश की जन्मदर क्या है, मृत्युदर क्या है, शिशु-दर क्या है, शुद्ध पुनरुत्पादन की क्या महत्ता है, यह कैसे निकाला जाता है, आदि की जानकारी इसी ज्ञान से प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर भारत वर्ष की जनसख्या 1901 मे 24 करोड़ थी, जो 1981 में 68 करोड़ हो गयी यह जानकारी हमें इसी विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। जनसख्या के आंकड़े 10 वर्षीय जनगणना द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनो से प्राप्त कर सकते है।

स्वास्थ्य एवं हाइजीन—जनसख्या के स्वास्थ्य का क्या स्तर है, हाइजीन का कितना ज्ञान है इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा का अंग मानी जाती है। स्वास्थ्य का स्तर जानने के लिए देश, प्रदेश के विभिन्न भागों में कितने अस्पताल है, कितने चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत है, कितने चिकित्सक प्राइवेट तौर पर सुविधाए दे रहे है, आदि का ज्ञान लाभकारी होता है। युवा पीढ़ी के सदस्यो को व्यक्तिगत 'हाइजीन' जैसे—शरीर की सफाई, दांतो की सफाई, शरीर की विभिन्न जरूरतो का ज्ञान आदि भी इसमें सम्मिलित रहता है। अस्पतालों मे कितनी शैय्याएं उपलब्ध हैं। एक शैय्या पर कितने रोगी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। एक चिकित्सक कितने रोगियों को देखने के लिए उपलब्ध है आदि की जानकारी भी इसी विज्ञान से प्राप्त होती है।

सफाई, स्वच्छता एवं पर्यावरण—वातावरण की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान भी जनसंख्या शिक्षा के अंग हैं। पर्यावरण कैसे स्वच्छ बनाया जाना चाहिए, इसकी क्यों आवश्यकता है? दूषित पर्यावरण से मानव के जीवन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानकारी भी जनसख्या शिक्षा द्वारा दी जानी चाहिए। पेड़-पौधों से किस प्रकार आक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जनसख्या के बढ़ने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जनसख्या की अत्यधिक वृद्धि से पेड़-पौधों का ह्रास होता है इसीलिए वन सम्पदा मानव के सुख सौभाग्य के लिए आवश्यक है।

प्रजनन एवं पारिवारिक जीवन—स्त्री एवं पुरुष के शरीर में प्रजनन के कौन-कौन से अंग है इसकी जानकारी जनसख्या शिक्षा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, इसका परिवार मे बच्चो

की संख्या से क्या सम्बन्ध होता है आदि विषय भी जनसख्या शिक्षा में सम्मिलित किए जाते है, शिशु के गर्भकाल एवं प्रसव के बाद माताओ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि बाते भी जनसख्या शिक्षा द्वारा सिखाई जानी चाहिए।

खाद्य एव पौष्टिक आहार—मनुष्य की मूलभूत तीन आवश्यकताओ में भोजन एक है। किस आयु-वर्ग के लिए किस प्रकार के और कितनी मात्रा मे भोजन की आवश्यकता है, प्रतिदिन मनुष्य को कितनी मात्रा मे और कौन-कौन-सा भोजन खाना चाहिए यह जानकारी इसी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होती है। पौष्टिक आहार किन-किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और क्या पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता है, इस विषय को लेकर भी जनसंख्या शिक्षा में चर्चा की जाती है। उदाहरणस्वरूप अमरूद के तत्व किसी भी अर्थ में सेब के तत्वों से न्यून नहीं होते। किन्तु सेब की अपेक्षा अमरूद बहुत सस्ता उपलब्ध है, जिसे सीमित साधन वाला व्यक्ति भी खा सकता है। अतः धन की कमी की हालत में अमरूद का सेवन करके भी व्यक्ति सेब के बराबर पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता है।

परिवार परिसीमन—परिवार मे यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और ससाधनो की कमी है तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा ही देती है। परिवार सीमित करने के क्या-क्या स्थाई, अस्थाई साधन हैं, किस साधन मे क्या अच्छाई, बुराई है, कहा से चिकित्सको एवं साधनों की सेवा सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, यदि परिवार में दम्पत्ति को बच्चा नहीं प्राप्त हो रहा है तो चिकित्सक द्वारा पूर्ण परीक्षण, दवाई अथवा शल्यक्रिया से दम्पत्ति की सहायता करना। मौटे तौर पर परिवार परिसीमन का कार्यक्रम कम बच्चो का ही नहीं है, बल्कि बच्चे न होने की दशा में सहायता करना भी है।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम—समाज में गर्भवती माताओं एवं शिशुओं का विशेष स्थान है। क्योंकि माता ही परिवार में सब प्रकार की शिक्षा देती है और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती है। यदि माता का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे वांछित पौष्टिक भोजन उपलब्ध नही हो पाता, रोगों से बचने के लिए जिन टीकों और दवाइयों की आवश्यकता है वे नहीं प्राप्त होतीं, तो परिवार का स्तर कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसी प्रकार नवजात शिशुओं के लिए प्रथम एक वर्ष तक विशेष तौर पर और उसके बाद भी लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि शिशुओं को रोगों से बचाया जा सके, और ऊची मृत्युदर मे कमी लाई जा सके। साथ ही माताओ की प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय एव प्रसवोपरान्त किस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए आदि बातों की जानकारी मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से दी जा सकती है। इस कार्यक्रम को भली-भांति क्रियान्वित करके माताओं की प्रसव के समय सभावित मृत्यु से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।

जनसंख्या शिक्षण के लिए ठोस आधार की तैयारी में जनसंख्या शिक्षण के अंगों के निश्चितीकरण के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह निश्चित करना भी रहती है कि शिक्षण के इन विभिन्न अंगो में से किस-किस अंग को शिक्षा के किस स्तर पर पढ़ाया जाए। यद्यपि इस संबंध मे भी विद्वानों में बड़े विवाद है। कुछ के विचार मे जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इस स्तर पर ही छात्रों की संख्या सर्वाधिक होती है और इस समय वे किसी भी तथ्य को ग्रहण करने के लिए संवेदनशील भी होते है। इसके अतिरिक्त इस समय जो सस्कार पड़ जाएंगे वे ही भविष्य के व्यवहार की आधारशिला बनेंगे। परन्तु कुछ लोग इसका विरोध करते है और कहते हैं कि इससे एक ओर तो बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ जरूरत से ज्यादा हो जाएगा दूसरी ओर उम्र के इस दौर मे ही जनसख्या वृद्धि और उसके परिणामों को बताकर अन्धकार मे भविष्य की कल्पना कराकर उनके मन में निराशा और डर की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। इन विद्वानों के विचार में जनसंख्या शिक्षा निम्न माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर आरम्भ की जानी चाहिए चूंकि

विश्वविद्यालय के स्तर तक भारत मे बहुत ही कम लोग पहुंचते है। अतः इसे उस स्तर के पाठ्यक्रम मे स्थान देने की आवश्यकता नही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह दोनों ही विचार एकदम ठीक प्रतीत होते हैं। आवश्यकता यहा पर पुनः नियोजन करने की है। वास्तव में जनसख्या शिक्षण के कई अंग हैं जिनमे से कुछ जैसे स्वास्थ्य एव हाइजीन, सफाई, स्वच्छता एवं पर्यावरण, खाद्य एव पौष्टिक आहार इत्यादि का शिक्षण बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही प्रारम्भ कराया जा सकता है, क्योकि इससे न तो बच्चो पर अतिरिक्त पाठयक्रम का कोई बोझ पडेगा और न ही उन्हे प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन एवं पारिवारिक जीवन तथा जनसंख्या वृद्धि के भयकर परिणामो की जानकारी अभी न देकर भविष्य के प्रति आशावान बनाया जा सकेगा। इसमे सन्देह नही है कि प्राथमिक स्तर मे बच्चा जिस उम्र में होता है वह बहुत अधिक सवेदनशील होता है। अत' इस समय उसे जनसंख्या शिक्षण के समस्त अगों से परिचित कराना उचित भी नहीं होगा। परन्तु जहां प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत हो रही है वहां इसी स्तर पर प्रौढ़ विद्यार्थियो को जनसख्या शिक्षण के समस्त अगो एव उद्देश्यों से अवश्य ही परिचित कराया जाना चाहिए। सक्षेप में जनसख्या शिक्षण का प्रारम्भ बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर सीमित एवं चयनित रूप में तथा प्रौढ़ो के लिए विस्तृत एव सम्पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। जब बच्चे निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर आते जाए वैसे-वैसे उन्हें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अधिकाधिक परिचित कराया जाना चाहिए। यह सोचना आज गलत है कि विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम छात्र पहुचते है। वास्तव मे, आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के पजीकरण की स्थिति देखी जाए, वहा पर भी स्थिति गम्भीर होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र वयस्क होने के कारण बात को अधिक समझने लगता है। अत' इस स्तर पर भी जनसंख्या शिक्षण का विशिष्ट अध्ययन ठीक उसी प्रकार कराया जाना चाहिए जैसा कि अन्य विषयों का कराया जाता है।

जनसख्या शिक्षण को व्यापक स्तर पर आरम्भ करने से पहले उसके लिए किए जाने वाली आवश्यक तैयारी में यह बात भी आवश्यक है कि यह निश्चित किया जाए कि जनसंख्या शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर अन्य विषयों में इसे जोड कर न पढ़ाया जाए बल्कि इसे एक अलग विषय के रूप में स्थान दिया जाए। इसका कारण यह है कि यदि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों को इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान अथवा जीवविज्ञान इत्यादि विषयों के साथ जोड़ कर पढाया जाता है तो मुख्य विषय के महत्व के आगे इन प्रकरणों का महत्व गौण हो जाता है और इसीलिए न तो उन्हें ठीक से पढ़ाया जाता है और न ही विद्यार्थी एवं अभिभावक इन्हे अधिक महत्व देते है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या शिक्षा को, भले ही बहुत छोटे पाठ्यक्रम के साथ, एक पृथक विषय के रूप में पढाया जाए, हर स्तर पर उसकी पृथक परीक्षा भी हो, जैसी कि अन्य विषयो की होती है तो न केवल विद्यार्थी की दृष्टि में बल्कि शिक्षक एव अभिभावक की दृष्टि में भी जनसख्या शिक्षा अन्य विषयो की भांति महत्वपूर्ण हो जाएगी और तब इसका पठन एवं पाठन दोनों ही गम्भीरता के साथ किए जाएगे और तब विद्यार्थी अपने जीवन मे कुछ न कुछ तो अवश्य ही ग्रहण करेगा। इस सम्बन्ध मे यह भी आवश्यक है कि शिक्षण प्रशिक्षण स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को अवश्य ही रखा जाए क्योंकि जब तक शिक्षकों को ही जनसंख्या शिक्षा सबंधी विषय सामग्री और उसके पढ़ाने के तौर-तरीके मालूम नही होगे तब तक वह ठीक से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकेगे। जनसंख्या शिक्षण के लिए आवश्यक आधार तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि जनसख्या शिक्षण के लिए एक उचित नीति बनाकर क्रियान्वित भी की जाए। इसके अन्तर्गत समाज में शिक्षको, विभिन्न ऐच्छिक सामाजिक संगठनों एव सरकार आदि सभी की बडी गम्भीर भूमिका की आवश्यकता होगी।

वास्तव में जनसंख्या शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में स्थान देने पर ही उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकती

इसके लिए पहले तो शिक्षक को हृदय से इस उत्तरदायित्व को स्वीकारना होगा। तत्पश्चात् दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होगा। पहली भूमिका तो उनकी यह है कि अपने विद्यालय के बच्चों को जनसख्या शिक्षा दें। उनके शैक्षिक स्तर के अनुकूल ही उनको समस्या से अवगत कराया जाए। विषय की रोचकता बनाए रखने के लिए विभिन्न भाषा, वाद-विवाद और नाटक, प्रदर्शन आदि जैसे पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। विद्यालय में जब कभी भी कोई प्रदर्शनी लगे तो उसमें एक भाग जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित हो। इस सबध मे निरतर शिक्षा सर्वाधिक प्रभावी होगी। शिक्षकों की दूसरी भूमिका यह होनी चाहिए कि वे विद्यालय के बाहर के युवकों को भी जनसख्या शिक्षा दें। इसके लिए शिक्षक विद्यालयों में इन युवको को अपने तत्संबधी कार्यो मे भाग लेने का अवसर दे। जब कभी भी वियालयो मे जनसंख्या शिक्षा संबंधी भाषा, वाद-विवाद, प्रदर्शनी अथवा चलचित्र आदि का आयोजन हो तो इन युवकों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को जनसेवा कार्यो के अन्तर्गत नगर और ग्रामीण जनता के पास पहुंचकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

शिक्षकों के आतिरिक्त समाज में विद्यमान विभिन्न समाजसेवी एवं ऐच्छिक संगठनों को भी जनसख्या शिक्षण के कार्य के लिए आगे आना चाहिए। ये संगठन अपने कार्यकर्ताओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्र विशेष में इस शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को विभिन्न प्रदर्शनियो, मेले, भाषणों आदि के माध्यम से विभिन्न उपायों से आम जनता की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण प्रदान करना चाहिए।

जन-शिक्षा के सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है—पोस्टर, पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, नाटक और चलचित्र। जनसंख्या शिक्षा सबधी केन्द्रीय और प्रान्तीय विभागों को इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड देना चाहिए और प्रौढ़ों को लिखने, पढ़ने, सामान्य जीवन की जानकारी, अपने अधिकार एव कर्तव्यो की जानकारी के साथ-साथ उन्हे जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके लिए 'छोटा परिवार सुखी परिवार' के पोस्टर लगवाने चाहिए, पत्र, पत्रिकाओं में जनसंख्या शिक्षा संबंधी सामग्री प्रकाशित की जानी चाहिए, रेडियो पर वार्ताएं एव नाटक प्रसारित करने चाहिए, टेलीविजन पर नाटक और चलचित्रो द्वारा विचारो को जीवित रूप दिया जाना चाहिए। इससे स्कूल के बच्चे और स्कूल के बाहर के व्यक्ति सभी लाभान्वित होंगे व हमारा पूरा समाज, देश व विश्व भी लाभान्वित होगा। ▢▢

3 एम.आई.जी., अशोक विहार
डब्ल्यू-1 साकेत नगर, कानपुर
उत्तर प्रदेश

शैक्षिक सुधार – दायित्व या व्यापार

❐ सत्यनारायण त्रिपाठी

शिक्षा राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र का व्यक्तित्व उसके नागरिकों के व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। कोठारी आयोग (1964-66) ने शायद इसीलिए कहा है कि भारत का भाग्य उसके कक्षा-कक्ष में संवर रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत पहले ही भांप लिया था इसीलिए संविधान की धारा-45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाने के लिए कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने तो संविधान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो उसके जीने के अधिकार से व्युत्पन्न है। अतः शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन क्या राष्ट्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर को सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कर सकता है?

प्रत्येक राष्ट्र सभावनाओं की सर्वोच्चता की तरफ अग्रसर एव भावनात्मक दृष्टि से आबद्ध व्यक्तियो का अद्‌भुत संगठन है। राष्ट्र की समुन्नतता एवं प्रगतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक अपनी सभावनाओं की सर्वोच्चता के कितने निकट है। नागरिकों को अपनी संभावनाओ की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित करना समुचित शैक्षिक परिवेश का कार्य है। समुचित शैक्षिक परिवेश व्यष्टिगत न होकर समष्टिगत है जिसे राष्ट्र जैसी समष्टिगत संस्था ही उपलब्ध करा सकती है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय दर्शन के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्रीय शैक्षिक तत्र सृजित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक तत्र जितना ही सुदृढ एवं आधुनिकतम प्रणाली उपागमों पर आधारित होगा उतना ही वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक तत्र मे सतत् परिमार्जन एव सशोधन की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्र अपने शैक्षिक तंत्र को सुदृढ एव पुनर्गठन का प्रयास करता है तो उसे शैक्षिक सुधार की संज्ञा दी जाती है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं उसका सशोधित स्वरूप (1992) इसका नवीनतम उदाहरण है। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय जनतत्रात्मक मूल्यों की कसौटी पर शिक्षा मे जो संशोधन की दिशा सुनिश्चित की है क्या वह राष्ट्रीय दायित्व है अथवा राष्ट्रीय आय बढ़ाने हेतु व्यापार का साधन है? यह अत्यन्त विचारणीय विषय है जिस पर शिक्षाशास्त्रियों व मनीषियों का गंभीर चिंतन आवश्यक है।

शिक्षा ही मनुष्य को सृष्टि का अप्रतिम प्राणी बनाए हुए है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न सस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा के तीनो पक्षो का समन्वित विकास कर समाज एव राष्ट्र का उपयोगी नागरिक बनता है। व्यक्ति ही राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पक्षों में प्रशासक, विशेषज्ञ एव कार्मिक बनाता है। इसलिए राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति को शिक्षा द्वारा उसके वैयक्तिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास को ऐसी दिशा

प्रदान करना जिससे वह राष्ट्र का महत्वपूर्ण प्राणी बन सके। भारत एक जनतंत्रात्मक देश है जिसका वैयक्तिकता का पूर्ण सम्मान करना मूलभूत सिद्धान्त है। समानता, स्वतत्रता एव भ्रातृत्व भाव हमारे शासन का आधार हैं। वैज्ञानिक एव तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति ने लोगों के आत्म विश्वास को बढ़ाया है। जिससे हमारे जनतत्रात्मक मूल्य और अधिक प्रगाढ हुए हैं। इसलिए आज हमारी मान्यता है कि व्यक्ति अपने पर शासन कर सकता है और वह स्वतंत्रता, शक्ति एव जिम्मेदारी पूर्ण कार्यो का अधिकारी है। हमारे जीवन का तरीका एवं गुण ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तो पर आधारित हैं जो व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार को निर्देशित एवं नियत्रित करते है। अतः हमारी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को उसकी अस्मिता को प्रभावित किए बिना सामाजिक मूल्यो एवं आदर्शो के प्रति आकर्षित करना है। यही कारण है कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) मे अब तक के संचित साधनो को इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फायदा पहुचने की बात कही गई है। इस दृष्टि से शैक्षिक सुधार राष्ट्रीय दायित्व है जिससे समाज एव राष्ट्र निरन्तर प्रभावी एवं दक्ष ढंग से अपने लक्ष्यो की प्राप्ति कर सके। चूंकि शिक्षा भौतिक एवं आध्यात्मिक (सा विद्या या विमुक्तये) विकास की बुनियाद है इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा की सकल्पना को सत्य करने की आवश्यकता है। आज सर्वत्र व्यक्ति के उन्नयन हेतु जीने की कला, कुछ करने की कला तथा कुछ बनने की कला निरन्तर सीखते रहने पर बल दिया जा रहा है। सीखते समाज का निर्माण राष्ट्र की परमावश्यकता हो गई है। इसलिए वर्तमान समय मे किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती। राष्ट्र को अपनी शैक्षिक प्रणाली को गतिशील बनाए रखना अत्यावश्यक ही नहीं उसके अस्तित्व की आधारशिला है।

शैक्षिक सुधार दायित्व या व्यापार है पर निर्णय करने के पूर्व हमे अपनी वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 की मशा को पूरा करना होगा। इस नीति मे शिक्षा का सार एव भूमिका निम्नलिखित बताई गई है–

- ☐ हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 'सबके लिए शिक्षा' हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है।
- ☐ शिक्षा सुसस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीको के अमल की सभावना बढ़ती है और समझ एव चिंतन की स्वतत्रता आती है। साथ ही हमारे सविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति मे अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है।
- ☐ शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान एवं विकास को सम्बल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है।
- ☐ कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। इसी सिद्धान्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित उपर्युक्त शिक्षा के सार एवं भूमिका को देखने से स्पष्ट है कि व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के भविष्य एव वर्तमान के निर्माण हेतु, राष्ट्रीय मूल्यो के प्रचार-प्रसार हेतु, राष्ट्रीय जनशक्ति के विकास हेतु शिक्षा में वाछित सुधार हमारा परम् दायित्व है। यदि हम इस दायित्व को पूरा नही करते तो राष्ट्र का सूक्ष्म स्तर से लेकर व्यापक स्तर पर क्षरण अवश्यम्भावी है। शैक्षिक सुधार व्यापार न होकर दायित्व है यह बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) (6 20) से भी स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि तकनीकी एव व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत यह नीति रखी गई है कि शिक्षा के प्रमाणों को बनाए रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का व्यापारीकरण रोका जाएगा। इसके विकल्प के रूप में स्वीकृत मानदण्डों और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप इन क्षेत्रो में निजी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने की एक नई पद्धति तैयार की जाएगी। शैक्षिक सुधार की मंशा निश्चित रूप से राष्ट्रीय दायित्व बोध है। इसके

लिए निजी प्रयासो का उपयोग साधन है न कि साध्य। इसका अद्यतन उदाहरण 1995 में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से व्यापारीकरण को रोकने हेतु हमारी संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के गठन हेतु विधान पारित किया।

शिक्षा राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योकि राष्ट्र का व्यक्तित्व उसके नागरिको के व्यक्तित्व मे परिलक्षित होता है। कोठारी आयोग (1964-66) ने शायद इसीलिए कहा है कि भारत का भाग्य उसके कक्षा-कक्ष में सवर रहा है। हमारे सविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत पहले ही भाप लिया था इसीलिए सविधान की धारा-45 में सविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाने के लिए कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने तो सविधान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो उसके जीने के अधिकार से व्युत्पन्न है। अतः शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन क्या राष्ट्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर को सभी नागरिको के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कर सकता है? सरकार की क्षमता इसी से आकी जा सकती है कि उसने संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर की बात तो दूर रही वह तो उसके लागू होने के 50 वर्ष के अन्दर भी अपनी सवैधानिक जिम्मेदारी कि– 14 वर्ष तक की आयु के बच्चो को निःशुल्क एव अनिवार्य शिक्षा दे सके– नही निभा सकी। अत. प्रत्येक स्तर की शिक्षा को नि शुल्क एवं अनिवार्य बनाने की हम कल्पना नहीं कर सकते। परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय निवेश है। इसलिए राष्ट्र को प्रारम्भिक शिक्षा को निवेश मानकर सभी नागरिकों को देना नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार की निरन्तर नीतियां इस तरफ उसे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रारम्भिक शिक्षा मे भी निजी प्रयास हो रहे है जिससे शिक्षा का तो प्रसार हो रहा है परन्तु सरकारी प्रयास उत्तम न होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर भी शिक्षा में व्यापारीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है जिससे नागरिकों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उच्च शिक्षा का लक्ष्य व्यापक है। इस स्तर पर छात्र अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए समाज, राष्ट्र एव विश्व के हितों का भी ध्यान रख सकता है। इस सदर्भ में पी.आर. दुभाषी (उ. शि. प. 212, 1994 पृष्ठ 214) कहते हैं–

"उच्च शिक्षा का उद्देश्य युवकों को तैयार करना है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उपरान्त समाज की प्रगति में योगदान करें।"

उन्होने स्नातक शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को ज्ञान के सीमान्त तथा अनुसंधान जगत की देहली पर पहुचाना बताया है। आज भूमण्डलीकरण के युग में ज्ञान का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। हमारे यहा ज्ञान का महत्व बहुत ही पहले समझा गया था इसीलिए कहा गया है– ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं अर्थात् ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। यही नहीं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं अर्थात् ज्ञान सभी का नेत्र है, ज्ञानी मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है– विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पीटर एफ. ड्रकर ने अपनी पुस्तक "पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी" में आज की समाज की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा है सबसे बड़ी चुनौती "ज्ञान सम्बन्धी काम और ज्ञान सबंधी कार्यकर्ता की उत्पादकता" है। आज ज्ञान की सब जगह पूजा होगी यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अतः आज आवश्यकता है कि अधिसंख्य छात्रों में ज्ञान की समृद्धि हो, पर्याप्त सम्प्रेषण की क्षमता हो, दृष्टि की व्यापकता हो तथा वे सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हों। अतः राष्ट्र का परम दायित्व है कि अपने नागरिकों को ज्ञान पिपासु बनाने वाली शैक्षिक प्रणाली का सृजन करे।

परन्तु आज उच्च शिक्षा में छात्रो द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति क्या है? हमारे यहा प्रचलित परीक्षा प्रणाली 35 प्रतिशत अंक पाने पर छात्रो को उत्तीर्ण घोषित करती है जबकि वे 65 प्रतिशत ज्ञान से अछूते रहते हैं। इसलिए हम आज की परीक्षा प्रणाली को अनुग्रह प्रणाली कह सकते हैं जिसे किसी प्रवीणता पर आधारित परीक्षा प्रणाली से स्थानापन्न करने की आवश्यकता है। शिक्षा की चुनौतियां–1985 नामक दस्तावेज में शिक्षा

के विभिन्न स्तरों पर समस्याओ का विषद् विवेचन किया गया है। उसमें कहा गया है कि छात्रो से अपेक्षा की जाती है कि वे विषय को समझें अथवा न समझें, बस पाठ्यपुस्तक में दी गई सामग्री को रट डाले। कदाचित वे इतना भी नहीं करते। वे कक्षाओ मे लिखवाए गए नोटो, कुंजियों मे दी गई खिचड़ी सामग्री अथवा प्राइवेट कोचिंग क्लासो, जो उच्च शिक्षातंत्र के समानान्तर चल रही हैं, पर निर्भर करते हैं। अपने आप अध्ययन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं कि अधिसंख्य छात्रो में ज्ञान सीमित होता है, इनमें सम्प्रेषण की कमी, दृष्टि सकुचित तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय दायित्व की भावना शून्य होती है। अत· हम कह सकते है कि आज उच्च शिक्षा उच्च नहीं रह गई है। यह दीर्घकालिक होने के कारण बेरोजगार युवकों की शरण स्थली बन कर रह गई है। उच्च शिक्षा प्रायः नि·शुल्क (रुपए के अवमूल्यन के कारण) होने के कारण छात्रों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को रोजगार प्राप्तकर्ता के स्थान पर रोजगार प्रदाता होना चाहिए परन्तु आज का शिक्षित बेरोजगार तो रोजगार के योग्य ही नही है क्योकि वह सस्ती एवं मुफ्त डिग्री पाने का आदी हो गया है।

जनसंख्या बढ़ने से उच्च शिक्षा पर व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस व्यय को कहां से जुटाया जाए तथा शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बनाई जाए? यह ज्वलत समस्या है। इस समस्या को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुल्ट्ज के शिक्षण एव अधिगम प्रक्रिया के सम्प्रत्यय से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षण एवं अधिगम को उत्पादन की सरल प्रक्रिया माना है। उनकी परिकल्पना के अनुसार अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रियाओं से नई उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण होता है जिसे मानव पूंजी की संज्ञा दी जा सकती है। मानव पूंजी मानवीय एवं भौतिक संसाधनो की उपलब्ध निधि मे सवृद्धि करती है। इसीलिए शिक्षा को पूंजी या उत्पादक विनियोग माना जा सकता है। अत· शिक्षा में सुधार हेतु प्रतिछात्र लागत व्यय के आधार पर शैक्षिक तंत्र को समझने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिछात्र लागत व्यय कला एवं विज्ञान विषयों मे क्रमशः 22,250 रुपए एव 32,210 रुपए हैं। राज्य विश्वविद्यालय में यह व्यय अत्यन्त कम है। इसलिए पुनैया समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार पर बहुत अधिक निर्भर न रहकर अपने स्वयं के संसाधनों को सृजित करना चाहिए। इसी स्वय के संसाधनों के सृजित करने के प्रयास को शिक्षा का वाणिज्यीकरण या व्यापारीकरण की सज्ञा दी गई।

अब उच्च शिक्षा में शिक्षा के व्यय का 15 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा रहा है जबकि उच्च शिक्षा के लाभार्थी (उच्च आय-वर्ग के 30 प्रतिशत) बहुत कम हैं और थोड़े लोगो के लाभार्थ सामान्य वर्ग के लोगों की कमाई का हिस्सा नही लगाया जा सकता। अत उच्च शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस प्रकार करनी होगी कि जो इसके लाभार्थी हैं वे अपने लाभ के लिए शिक्षा पर व्यय करें। इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट और इनफोर्मेशन टैक्नोलॉजी के लोग शिक्षा प्राप्त कर बहुत ऊंची कमाइया करते हैं। इन संस्थाओं में पढ़ने हेतु छात्रों को बहुत सारी कम्पनियां ऋण एवं वित्तीय सहायता स्वत· प्रदान करती है। इन सस्थाओं के विशेषज्ञ अपनी शर्त पर शिक्षण कार्य करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण संस्थाओं में पूंजी सरकार या निजी क्षेत्र के लोग लगाएं तथा उसमें अध्यापक अपनी शर्तो पर अध्यापन कार्य करे तथा उनके अध्यापन के जो लाभार्थी हैं वे उनके खर्च को वहन करे। छात्रो को अपने द्वारा चुने गए अध्यापकों एवं संस्थाओ मे पढ़ने का अधिकार हो। संस्थाओं पर किसी का वर्चस्व न हो। वे केवल छात्रों एवं अध्यापकों को क्रमश· अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा प्रदान करने का अभिकरण हों। इसमें छात्रों और अध्यापकों में आत्म-विश्वास की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा उनमें स्वतंत्र चितन का विकास होगा। उच्च शिक्षा कीमतशुदा होगी और उच्च शिक्षा हेतु वांछित व्यक्ति को उसके लिए व्यय करना होगा। यद्यपि शिक्षा में यह प्रवृत्ति व्यापारीकरण जैसी दिख रही है परन्तु यदि इस तरह की प्रणाली विकसित हो गई तो शिक्षण संस्थाओ, शिक्षको व छात्रों मे प्रतिस्पर्धा

की भावना का उदय होगा जो कि उनके विकास का परिचायक होगा। इस प्रणाली से कुछ विषय जिनका व्यावसायिक मूल्य होगा उनका महत्व निश्चित रूप से बढेगा परन्तु कुछ विषय जिनका बौद्धिक मूल्य है उनका महत्व पहले जैसा नहीं रह सकेगा। ऐसे विषयों को सरकार व अन्य संस्थाओ को संरक्षण प्रदान करना पडेगा। ऐसे विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीमित संस्थाएं बनानी होंगी जिससे उन पर व्यय को कम किया जा सके। इसी प्रकार कमजोर तबको के लोगो को नेशनल बैंक ऑफ एजुकेशन की स्थापना करके योग्य लोगों को ऋण देना होगा तथा कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए ऋण सहायता के रूप में देना होगा। इस व्यवस्था से उच्च शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से उठेगा तथा उस पर अनावश्यक रूप से उच्च शिक्षा लेने वाले लोगों की संख्या में भी ह्रास होगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा निवेश के रूप में राष्ट्र का दायित्व है परन्तु उच्च शिक्षा लाभार्थियों की मदद से बिना लाभ लिए संरक्षित एव संवंर्धित करना भी सरकार का दायित्व है। इस स्तर पर सरकार शिक्षा में व्यापारिक दृष्टिकोण रख सकती है परन्तु इसे व्यापार नही बना सकती। व्यापारिक दृष्टिकोण शिक्षा में जिम्मेदारी की प्रवृत्ति को बढावा देगा तभी तात्रिक उपागम के फलस्वरूप शिक्षा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। ▢▢

शिक्षा विभाग
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

शिक्षा में सम्प्रेषण

❑ आशा भन्साली

"शिक्षा जीवन में तैयार करती है, युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य दायित्वों के लिए, उनके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है अच्छे तथा बुरे में अन्तर समझने के लिए, उनमें विकसित करती है, निष्ठा तथा आत्मविश्वास, उनके मस्तिष्क को स्वतन्त्र करती है– भय से, घृणा से, ईर्ष्या से तथा उनके व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम अंश को सम्मुख लाती है।"

शिक्षा के इन प्रयोजनों की प्राप्ति सम्प्रेषण से होती है। अतः शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित शिक्षण तथा अधिगम के कार्यो में सम्प्रेषण का अत्यधिक महत्व है। सम्प्रेषण शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में सम्प्रेषक विचारों, मतों, तथ्यों एवं भावनाओं को दूसरों तक सम्प्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों जैसे लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य, का प्रयोग करता है और संग्राहक तक पहुंचता है। सम्प्रेषण हमारा विकास करने, सिखाने, जागरूक रखने और समायोजन योग्य बनाता है। विचारों के सम्प्रेषण से ही आपसी समझ व आपसी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं।

शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित शिक्षण तथा अधिगम के कार्यो मे सम्प्रेषण एव गुरु-शिष्य के मध्य अन्योंयाश्रय अन्त.क्रिया समावेशित होती है। यह अन्तःक्रिया शिक्षा के उद्देश्यो की पूर्ति के माध्यमों के रूप में होती है। इस प्रकार सम्प्रेषण अन्य लोगों के साथ सामान्य अनुभव प्राप्त करना है।

सम्प्रेषण मानवीय अन्त क्रिया का एक सही अर्थ मे चुनौतीपूर्ण एव उत्तेजक क्षेत्र है। वर्तमान समय में सम्प्रेषण कौशल अध्ययन आकर्षित कर देने वाला है।

सम्प्रेषण कौशल के पाच प्रमुख अंग होते हैं– ● बोलना, ● सुनना, ● लिखना, ● पठनीयता या पठनीय लेखन, ● अशाब्दिक सकेत।

आज की औपचारिक शिक्षा मे प्रत्यक्षत. उन सभी अंगों की पूर्णत. उपेक्षा की गई है। आज सर्वप्रथम यह आवश्यकता है कि बालक को किसी भी एक भाषा में इतना निष्णात कर दिया जाए कि वह उस भाषा में बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सके, उस भाषा को सुनकर समझ सके, अपने विचार उस भाषा में लिख सके तथा स्वय उस भाषा सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन कर सके तथा उस भाषा में रचना कर सके। ये सभी सम्प्रेषण के अग प्राथमिक स्तर पर ही पूर्णत सिखा दिए जाने चाहिए किन्तु इनका सर्वत्र अभाव ही परिलक्षित होता है।

वास्तव मे सम्प्रेषण का प्रयोग रोचकतापूर्वक तथ्यों, भावनाओं, आकड़ों, सवेगों, विचारों और दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान द्वारा अन्त.क्रिया द्वारा किया जाना चाहिए इसे बोझिल अथवा कठिन नहीं बनाना चाहिए।

अध्यापक पाठ्य-वस्तु को इतने रोचक ढग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे कि छात्र सहजता से ही उस ज्ञान का अधिगम कर ले।

आज बदलते हुए सामाजिक परिवेश की आवश्यक आवश्यकता है कि आज का प्रत्येक व्यक्ति सम्प्रेषण के इन पांचो तत्वो में निष्णात हो। जिस प्रकार छात्र में किसी भी विषय या क्षेत्र से सम्बन्धित कुशलता का विकास करना आवश्यक माना जा रहा है उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्प्रेषण कला का ज्ञान भी आवश्यक हो गया है।

सम्प्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी सूचना को समुचित रीति से प्रदान किया जा सकता है तथा एक साझे प्रतीकात्मक संकेत मे अनुदित कर प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जा सकता है। सम्प्रेषण इस प्रकार किया जाए कि किसी भी जानकारी को प्राप्तकर्ता अच्छी तरह समझ ले।

सम्प्रेषण के आधार – सम्प्रेषण तथ्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, भावनाओ तथा अभिवृत्तियों का अन्त क्रियात्मक प्रेषण है। सम्प्रेषण एक अन्तःवैषर्यिक अवधारणा है क्योकि सैद्धान्तिक रूप से यह विभिन्न विषयो जैसे गणित, मनोविज्ञान, लेखाशास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, पर्यावरणीय ज्ञान आदि तक पहुंचने का एक तरीका है।

सचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतीकों को छांटना, चयन तथा सम्प्रेषण इस प्रकार समावेशित होते हैं जिससे सुनने वाला भेजने वाले के मस्तिष्क मे निहित अर्थो को पुनर्रचित कर विषय का बोध करता है। सूचना तथा सहस्रों सम्भावित उद्दीपनों का हस्तान्तरण सम्प्रेषण मे समावेशित है अर्थात् सूचना भेजने वाला यदि यह कहता है कि– "नौ बज गए है" तब सूचना प्राप्त करने वाले को "नौ बजना" यह कहना उसके लिए उद्दीपन का कार्य करता है और यह उद्दीपन सुनने वाले को निर्दिष्ट समय का बोध कराते हुए वाच्छित क्रिया करने को बाध्य करता है। सम्प्रेषण ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह के बीच ही सम्भव है जो समान भाषा या समान बोली जानता हो।

केवल मनुष्य ही शब्दो द्वारा दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, गन्ध तथा स्वाद को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ये गन्ध रसादि साधन सदेशों के आदान-प्रदान के विभिन्न प्रकार है। सम्प्रेषण ही एक ऐसा माध्यम है जिसने मानव के विकास की सीढियों का ज्ञान कराया और उसे आदिम मानव से सभ्य मानव में बदल दिया।

सम्प्रेषण की परिभाषा – अमरीकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिग डायरेक्टर्स के अनुसार – "सम्प्रेषण वह तत्व है जो विचारों और सूचनाओ के हस्तांतरण से मानव मे आपसी समझ, भ्रातृत्व की भावना, सहयोग और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है।"

न्यूमेन एवं समर के अनुसार – "सम्प्रेषण एक अथवा अनेक लोगों के मध्य तथ्यों का, विचारों का, दृष्टिकोणों का और सवेगों का आदान-प्रदान करता है। सम्प्रेषण को शब्दों, पत्रों, सकेतों और सदेशों के द्वारा किए जाने वाले समागम के रूप मे भी परिभाषित किया जा सकता है, और यह एक शैली है जिसके द्वारा एक संगठन के सदस्य परस्पर अर्थ और अभिप्राय को आपस मे एक साथ समझते है।

लेलेंड ब्राउन के अनुसार– "सम्प्रेषण तथ्यों, विचारों *अथवा कार्य की दिशा का अन्तःपरिवर्तन और प्रसारण है।"*

एम.टी.मेयर्स एवं जी.ई.मेयर्स के अनुसार – "सम्प्रेषण से अभिप्राय एक विशेष प्रकार का प्रारूप बनाने से है। ऐसा प्रारूप जिसे प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसमूह के मध्य सम्प्रेषण के लिए दो आवश्यक शर्ते हैं– ● *सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतीकात्मक प्रणाली* को समान रूप से ग्रहण किया जाए। ● सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा समान भाषा व बोली का प्रयोग आवश्यक है। प्रतीको और संदर्भों के मध्य साहचर्य को भी समान रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए।

सम्प्रेषण का क्षेत्र – सम्प्रेषण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। यह एक ऐसा अन्तर्शास्त्रीय विषय है जिसका क्षेत्र असीमित है। सम्प्रेषण प्रेषक और सग्राहक इन दो के मध्य निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जिससे प्रेषक और संग्राहक अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों की अन्तःक्रिया कर सके। अन्तःक्रिया की इस प्रक्रिया मे कई प्रकार के सकेतो का उपयोग होता है। ये सकेत शब्द, क्रिया, चित्र, संख्या आदि हो सकते हैं।

सम्प्रेषण का अभिप्राय निर्देशों, आदेशो, अनुदेशो

को निचले स्तरों तक भेजना कदापि नहीं है क्योंकि ऐसा करना तो केवल एक दिशा में ही सम्प्रेषण होगा। द्विपक्षीय सम्प्रेषण उच्च स्तरीय होता है–

सम्प्रेषण दो प्रकार का होता है–

● आन्तरिक सम्प्रेषण, ● बाह्य सम्प्रेषण

आन्तरिक सम्प्रेषण भावो के मध्य होता है जैसे किसी नेता का जनता के मध्य प्रतिष्ठा बनाना। आन्तरिक सम्प्रेषण प्रबन्धन के कार्यो जैसे निर्देशन, समन्वयन, नियोजन, व्यवस्थापन, प्रेरणा आदि के निष्पादन में सहायक होता है।

बाह्य सम्प्रेषण सगठन से बाहर सन्देशो को भेजने से सम्बन्धित होता है। ऐसा बाह्य सम्प्रेषण शिक्षा, सरकार, उसके विभागों, उसकी व्यवस्था करने आदि से सम्बन्धित होता है।

तकनीकी के विकसित होने से मौखिक सम्प्रेषण एव लिखित सम्प्रेषण के अनेक साधन उपलब्ध हो गए है। आज बड़ी से बड़ी कम्पनियां, शैक्षिक सगठन अपने प्रबंधन को चलाने एव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कई प्रकार के मौखिक, शाब्दिक, लिखित माध्यमो का चुनाव करती हैं जैसे – लिखित साधनो में पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट, हैन्डबुक, जरनल, मैनुअल आदि। शाब्दिक माध्यमों में जैसे आमने-सामने वार्तालाप, व्याख्यान, गोष्ठिया, बैठके, साक्षात्कार, परामर्श प्रदान करने के सत्र आदि। शाब्दिक माध्यमों में प्रयुक्त उपकरण जैसे माइक, टेलीफोन आदि।

सम्प्रेषण की प्रकृति – वर्तमान समय में संगठनो को सम्प्रेषण प्रणालियों के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाछित, समान लक्ष्यो की प्राप्ति की जाती है। यह व्यक्तियो, समूहो, विभागो आदि के बीच सूचना का आदान-प्रदान है। प्रत्येक सगठन की अपनी एक उपप्रणाली होती है और लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए उपप्रणालियों के बीच सदैव अन्त.क्रिया होती है। सम्प्रेषण उपप्रणालियों व उनके साथ सम्पूर्ण प्रणाली को सूचना तथा आंकड़े प्रेषित करता है।

प्रभावी रूप से सम्प्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि सम्प्रेषक विभिन्न सम्प्रेषण कौशलो जैसे वक्तव्य, लेखन, सुनकर समझना, पठन-कौशल आदि मे दक्ष हो। यही कारण है कि सफल एवं प्रभावी सम्प्रेषण निर्मित किए जाते हैं जन्म नही लेते हैं। इसीलिए यह विषय मनुष्य द्वारा सम्प्रेषण कौशल प्राप्ति और उसके लिए किए गए प्रयासो की कथा है।

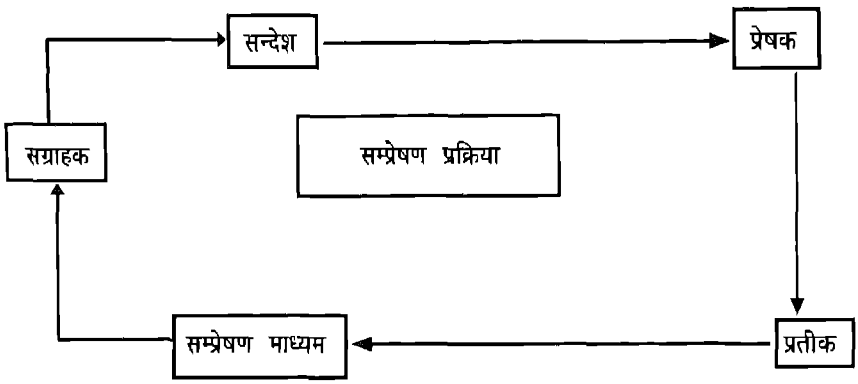
प्रागैतिहासिक मानव ध्वनियों, धूएं के संकेत प्रेषित करता था जिससे अपनी भावनाओं को दूसरो तक पहुंचाता था। जैसे-जैसे वह सभ्य एवं सुसंस्कृत होता गया सम्प्रेषण की विधाओ मे भी परिष्करण होता चला गया।

सम्प्रेषण की प्रक्रिया– सम्प्रेषण एक संगठन मे व्यक्तियो और समूह के लिए एक गतिशील माध्यम है। इस प्रक्रिया में सम्प्रेषक विचारों, मतों, तथ्यों एवं भावनाओं को दूसरों तक सम्प्रेषित करने के लिए एक विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमो का प्रयोग करता है। यह माध्यम लिखित, मौखिक, दृश्य-श्रव्य हो सकते है। दृश्य संचार माध्यम में स्लाइड्स, नियोन होर्डिंग्स, पोस्टर आदि सम्मिलित है। टेलीविजन तथा फिल्मे श्रव्य-दृश्य सम्प्रेषण माध्यम है।

सगठन का लक्ष्य विभिन्न सचार माध्यमों की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे सक्रिय बनाया जाता है। सम्प्रेषक कब और क्या सम्प्रेषित करना चाहता है इसका चयन करता है और सम्प्रेषण के लिए उनके माध्यम निर्धारित करता है। सग्राहक सन्देश ग्रहण करता है, विश्लेषण करता है, बोध करता है और उसका प्रत्युतर देता है। यह सम्पूर्ण क्रम संचार प्रक्रिया है। प्रक्रिया के रूप मे यह नित्य घटित होता है और निरन्तर जारी रहता है।

सम्प्रेषण प्रक्रिया के तत्व– सम्प्रेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व समावेशित होते हैं–

- ☐ सन्देश
- ☐ प्रेषक
- ☐ संकेतन
- ☐ माध्यम
- ☐ सग्राहक
- ☐ विसकेतन।



सन्देश– संदेश कथित या लिखित जानकारी का अंश है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करना होता है। यह सम्प्रेषण की विषय-वस्तु होता है। इसमे कोई तथ्य, विचार, राय, आंकड़ा, प्रवृति या कार्य की दिशा जिसमें सूचना सम्मिलित हो समावेशित हो सकती है। इसका अस्तित्व सम्प्रेषक के मस्तिष्क में होता है।

सम्प्रेषक– यह संदेश का प्रेषक या प्रसारक होता है। यह एक व्यक्ति होता है जो संदेश को सम्प्रेषित करता है। यान्त्रिक युक्तियों की दशा में जिनका प्रयोग सम्प्रेषण मे किया जाता है। उपसम्प्रेषक (पैरा ट्रान्समीटर) एक चालक होता है। वह व्यक्ति जो सदेश देता है सम्प्रेषक या भेजने वाला कहलाता है।

संकेतनः सम्प्रेषण प्रतीक– प्रतीक में विषय-वस्तु स्थापित करने की प्रक्रिया संकेतन कहलाती है। किसी भी सम्प्रेषण का संदेश या विषय-वस्तु सदैव अमूर्त (ऐब्स्ट्रक्ट) होती है और उसका आर्थिक मूल्य नहीं आंका जा सकता। सन्देश के सम्प्रेषण के लिए कुछ प्रतीकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। सम्प्रेषक अपने विचारों को, प्रतीकों, चिन्हों आदि के समूहों में नियोजित तथा सगठित करता है। सकेतन क्रिया विचारों, तथ्यो, भावनाओं तथा मतों का अनुवाद प्रतीको, चिन्हों, शब्दो, कार्यो, चित्रों तथा श्रव्य-दृश्य साधनों आदि मे करती है। यह सम्प्रेषक पर निर्भर करता है कि वह निर्दिष्ट श्रोता या सग्राहक तक प्रभावी सम्प्रेषण हेतु जिस माध्यम को ठीक समझे उसका चयन करे।

सम्प्रेषण माध्यम– सम्प्रेषण माध्यम (चैनल) से अभिप्राय उन माध्यमो से है जिनसे होकर सन्देश भेजा जाता है। चयनित शब्दों, प्रतीकों या चिन्हों को किसी निश्चित माध्यम द्वारा श्रोता या संग्राहक तक सम्प्रेषित किया जाना चाहिए।

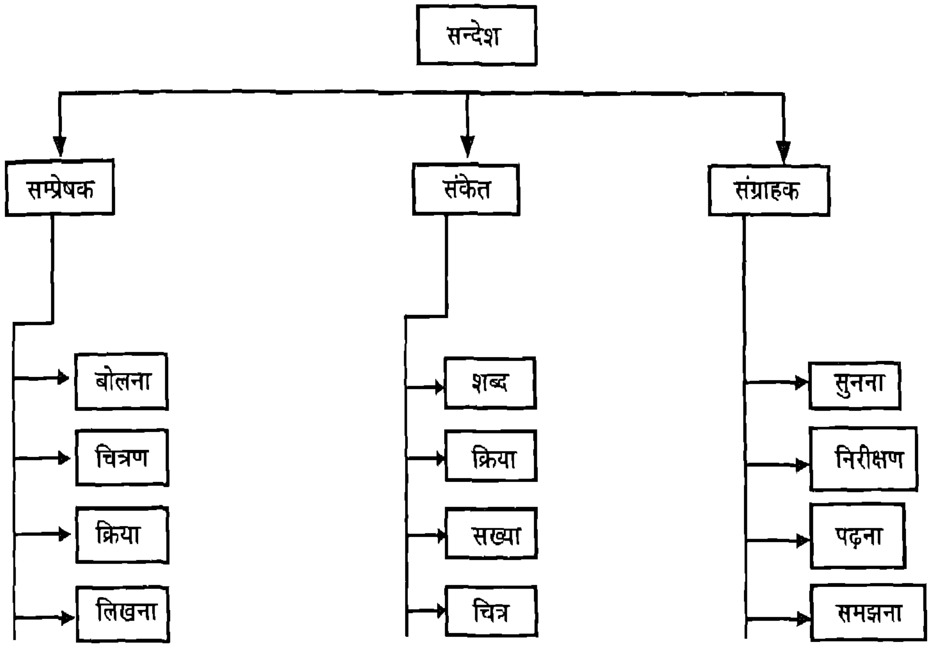
संग्राहक– सग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसे सन्देश प्रेषित करना प्रेषक को अभीष्ट होता है। वह व्यक्ति जो सदेश ग्रहण करता है, सग्राहक कहलाता है।

विसंकेतन– विसंकेतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सांकेतिक सन्देश को साधारण रूप से समझे जाने वाली भाषा में अनुदित किया जाता है। सग्राहक प्रेषक से प्राप्त प्रतीकों, शब्दो या चिन्हों को परिवर्तन करके सन्देश का अर्थ प्राप्त करता है।

कार्य करना– संदेश द्वारा समझे गए अर्थ के अनुसार संग्राहक कार्य करता है। यह संदेश को क्रियान्वित करता है।

पृष्ठ-पोषण– प्रेषक को सन्देश के विषय में ज्ञान को वापिस भेजना पृष्ठ-पोषण कहलाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सग्राहक ने सन्देश प्राप्त कर लिया है और उसे उसी अर्थ में समझा है जिसमें प्रेषक ने भेजा है।

सम्प्रेषण प्रक्रिया, मॉडल तथा सिद्धान्त– सम्प्रेषण के मूलभूत मॉडल में सूचना परक अथवा विश्लेषणात्मक क्रिया समावेशित है। जिसमे सन्देश, सूचना या सूचना के प्रति प्रतिक्रिया प्रेषक से सग्राहक तक सम्प्रेषण चैनल



नामक पथ से पहुंचती है।

शिक्षक या शैक्षणिक माध्यम द्वारा सम्प्रेषित सन्देश मौखिक या दृश्य हो सकता है और संग्राहक सुनकर, देखकर या परखकर तथा अन्य तरीको से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। कक्षा मे प्रयुक्त सम्प्रेषण चैनल को सन्देश तथा प्रतिसन्देश दोनों को आदर्श तरीके से समाहित करना चाहिए। इसमे प्रारम्भ करना, सग्रहण करना तथा प्रत्युतर देना समावेशित है जो कि पृष्ठ-पोषण का कार्य करता है।

हैरॉल्ड डी. लॉसवेल मॉडल—लॉसवेल की सम्प्रेषण प्रक्रिया अपने व्यापक विश्लेषण के अन्तर्गत चार मूलभूत तथा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। ये प्रश्न निम्नलिखित हैं—

★ कौन? ★ क्या? ★ किसे? ★ कौन सा?

सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक के व्यवहारगत पक्षों को लॉसवेल द्वारा भली-भाति स्थापित किया गया है। लेकिन इनका मॉडल सम्प्रेषण के कार्य से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उठाकर इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख तत्वो की ओर इंगित करता है। ये प्रश्न इस प्रकार हैं—

★ कौन ? ★ क्या कहता है ? ★ किस माध्यम से ? ★ किसे कहता है ? ★ क्या प्रभाव पडता है?

★ क्यों?— हम सम्प्रेषण क्यों करना चाहते है?

★ सम्प्रेषण का क्या प्रयोजन है?

★ क्या ये प्रेरित करने के लिए है या सूचित करने के लिए?

★ क्या किसी विशेष कार्य के किए जाने की आवश्यकता है?

★ क्या? — हम क्या सम्प्रेषित करना चाहते है?

(सन्देश) एक आदेश ? एक विचार ? एक प्रवृत्ति ? या एक भावना ?

कैसे ? — किस प्रकार के शब्द या सम्भावित कार्य सबसे अच्छी तरह से आवश्यकता की पूर्ति करते हैं?

(माध्यम)

कौन ? — हम किससे सम्प्रेषण करते हैं?

(संग्राहक)

कब ? – इस संदेश को प्राप्त करने का सही समय कब है?

(प्रभाव सहित)

सिद्धान्त

☐ लक्ष्यभेद सिद्धान्त (बुल्स आई)

☐ पिंगपोग सिद्धान्त (पिंग-पोंग)

☐ स्पाइरल सिद्धान्त (स्पाइरल)

सम्प्रेषण के लाभ

● सहकर्मी से बेहतर तालमेल।

● अध्यापक का छात्र के साथ व्यवहार।

● अभीवर्धित मान्यता तथा अप्रभावी सम्प्रेषण शैलियो को बदलने की क्षमता।

● अन्तर्वैयक्तिक विवादों को समझाने के लिए नए कौशल।

● प्रबंधन तथा कर्मचारियों के परस्पर आमुखन द्वारा उच्चतर कार्य निष्पादन मानको की स्थापना।

● विपरीत परिस्थितियो मे भी उत्पादकता में वृद्धि।

● साक्षात्कार तथा परामर्श की बेहतर तकनीकें।

● सगठन मे आधार प्रदान करने तथा विश्वास अर्जित करने का परिवेश उत्पन्न करने की क्षमता।

● विभिन्न संकुलों के सहकर्मियो के प्रति समझ विकसित करने में लचीलापन।

● सुनने की सक्रिय तथा परिशुद्ध आदतें।

● टीम की भावना, साहचर्य, गौरव तथा लक्ष्य की एकरूपता उत्पन्न करने के प्रति उत्साह।

● सूचना सीमाओं के परे सम्प्रेषण की क्षमता जैसे आर. एण्ड डी. अर्थात् शोध एव विकास के बीच सम्प्रेषण की क्षमता।

● अन्तर्वैयक्तिक प्रेरण की अभीवर्धित शक्तिया।

इस प्रकार के सम्प्रेषण में प्रमुख मूल्य इस प्रकार है–

● सामूहिक क्रियाओ में सहभागिता के प्रति सहमति।

● लेखन मे अधिकाधिक सुगमता तथा स्पष्टता।

● परामर्श देने मे आत्मविश्वास।

● कार्य को सम्पन्न करने के लिए बने समूहों या समितियों की प्रभाविता मे सुधार।

● लोगो के सामने प्रभावी रूप से बोल सकना आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना करना।

अच्छे सम्प्रेषण के दस मूल-मंत्र

अमरीकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अच्छे सम्प्रेषण श्रेष्ठतम, मुख्यतम तत्व इस प्रकार प्रस्तुत किए

● सम्प्रेषण से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना।

● सम्प्रेषण के वास्तविक प्रयोजन की जाच क

● भौतिक तथा मानवीय सम्पूर्ण परिवेश को विचा लेना।

● सम्प्रेषणीय सामग्री के नियोजन में जब भी : हो दूसरों से परामर्श प्राप्त करना।

● संदेश की मूलभूत विषय-वस्तु के साथ-साथ उ अतिरचना के प्रति सावधान रहना।

● जब भी सम्भव हो उपयोगी सूचना प्रदान क

● सम्प्रेषण पर पृष्ठ-पोषण।

● भविष्य तथा वर्तमान को ध्यान में रखते हुए सम करना।

● शब्दों को कार्यों से आधार प्रदान करना।

● एक अच्छा श्रोता बनना।

सम्प्रेषण के उद्देश्य

● मानव सम्बन्ध–सम्प्रेषण के बिना पारस्परिक विकसित नहीं हो सकती तथा मानव सम्बन्धों में पारस समझ सम्प्रेषण द्वारा ही सम्भव है।

● एम्पाथी– अन्य व्यक्ति के साथ उस जैसा ही अ करना एम्पाथी है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किय सके। सहानुभूति, दूसरों के लिए दुःख का अनुभव है जिसे शब्दो द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकत

● प्रेरित करना– परसुएशन एक ऐसी प्रक्रिया है ि कार्य करने के लिए तर्क द्वारा सन्तुष्ट करना व करना होता है। एक व्यक्ति को तैयार करने के त मे एक भाषण देना है। जिस व्यक्ति को प्रेरित होता है उसमें मानव रुचि की भावना उत्पन्न उसे अपने कार्य के कारण और प्रभाव को सम जा सकता है।

● सूचना–संगठनों मे सूचना लेना और सूचना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

● प्रभावित करना–सूचना सम्प्रेषित करने का उद्देश्य प्राप्त करने वाले के व्यवहार को परिवर्तित करना है। सम्प्रेषण का लक्ष्य वाच्छित लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, प्रभावित करना तथा सक्रिय बनाना है।

● समझ–अन्तर्वैयक्तिक स्थिति मे संघर्ष का प्रमुख कारण पारस्परिक समझ का अभाव है। समझ के इस अन्तराल को पाटने (दूर करने का) सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रकार्य सम्भवतया सम्प्रेषण है। जिसके बिना पारस्परिक समझ को विकसित नहीं किया जा सकता।

● गलत सूचना को हतोत्साहित करना– सम्प्रेषण का उद्देश्य न केवल नीतियो, नियमो, आदेशों, पद्धतियो तथा उद्देश्यो का हस्तान्तरण एवं विनिमय है अपितु सम्प्रेषण मे विकृति से बचना भी है। सम्प्रेषण का उपयोग गलत सूचना या अफवाह, गप्प के प्रसार को हतोत्साहित करना है और कर्मचारियो के भावनात्मक तनावो से उन्हें मुक्त करना है।

● सुझाव तथा शिकायतें–सम्प्रेषण का एक अन्य उद्देश्य उत्पादन तथा कार्य स्थितियों मे सुधार के लिए मातहतों से सुझाव तथा विचारों को प्रोत्साहन करना है। इससे समय तथा लागत में कमी हो सकती है और कच्चे माल के अपव्यय से बचा जा सकता है।

● उन्मुक्त विनिमय–सम्प्रेषण का द्विपक्षीय मॉडल सूचना तथा विचारों के उन्मुक्त आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है जो सभी कर्मचारियों को संदेश समझने और स्वीकार करने का अवसर प्रदान करते हैं।

अच्छे सम्बन्ध

● *संरक्षण प्रदान करने की प्रवृत्ति*

संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा, सहयोग तथा कार्य से सन्तोष अधिक आवश्यक है। सम्प्रेषण का प्रयोजन एक ऐसी प्रवृत्ति को संरक्षण देना है जो प्रेरणा, सहयोग तथा कार्य सन्तोष के लिए आवश्यक है।

सम्प्रेषण का प्रयोजन

प्रकार्य

अनुदेशनात्मक प्रकार्य– अनुदेशनात्मक प्रकार्य कमोबोश निर्देशात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसके अन्तर्गत सम्प्रेषण आवश्यक निर्देशों तथा मार्गदर्शन सम्प्रेषित करता है। जिससे कार्य को सम्पन्न किया जा सके। इसमे अनुदेश ऊपर से निचले स्तरो की ओर प्रवाहित होते हैं।

समाकलन प्रकार्य– सम्प्रेषण का समाकलन प्रकार्य मुख्यत. विभिन्न प्रकार्यों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करना होता है। यह प्रबन्धन प्रकार्यो के एकीकरण मे मदद करता है।

सूचना प्रकार्य– किसी भी संगठन में सम्प्रेषण का प्रयोजन का कार्य व्यक्ति या समूह को विषय के बारे मे जानकारी देना है। शीर्ष स्तर का प्रबन्धन, मध्य स्तर के बाद निम्न स्तर पर नीतियों की जानकारी प्रदान करता है। सम्प्रेषण का मुख्य प्रयोजन जानकारी पाना या दूसरों को जानकारी देना है।

मूल्यांकन प्रकार्य– सम्प्रेषण व्यक्ति को जानकारी देने का उपकरण है। इससे स्वयं के द्वारा संगठन में जानकारी देना उसका मूल्याकन करना, स्वय अपने आगत या दूसरों के निर्गत का मूल्यांकन अथवा किसी वैचारिक योजना का मूल्यांकन एक व्यक्ति तथा प्रभावी सम्प्रेषण प्रक्रिया की मांग है।

निर्देशात्मक प्रकार्य–सम्प्रेषण शीर्ष प्रबन्धन द्वारा निर्देश जारी करने के लिए या मैनेजर द्वारा निचले स्तर पर दूसरो को निर्देशन देने या स्वय निर्देशित होने के कार्य, सम्पूर्ण सम्प्रेषण प्रक्रिया बिना नही किए जा सकते। दूसरों को निर्देशित करना मौखिक या लिखित रूप से सम्प्रेषित किया जा सकता है, एक आदेश एक सामान्य प्रार्थना हो सकती है या अन्त.निहित आदेश हो सकता है।

प्रभावित करने के प्रकार्य– दूसरों को प्रभावित करने या स्वयं प्रभावित होने के लिए एक सम्पूर्ण सम्प्रेषण प्रक्रिया आवश्यक है। इसमें पृष्ठ-पोषण का प्रावधान अन्त.निहित है जो सम्प्रेषण के प्रभाव के विषय मे बताता है।

आकस्मिक तटस्थ प्रकार्य– सम्प्रेषण अनेक आकस्मिक तथा तटस्थ प्रकार्य सम्पन्न करता है किसी सगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए गए सम्प्रेषण के बहुत से टुकड़े प्रत्यक्षत. जुड़े हुए नही होते। सम्प्रेषण बहुधा संगठनात्मक लक्ष्यो की पूर्ति मे अप्रत्यक्ष रूप से योगदान

देता है। उदाहरण के लिए सम्प्रेषण संगठन के भीतर सामाजिक सम्पर्क प्रदान करता है।

शिक्षण प्रकार्य– विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए पूर्ण सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी व्यवस्था अथवा संगठन के श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भी सम्प्रेषण आवश्यक है जिसमें उन्हें कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा के विषय में सिखाया जाता है। यह सम्प्रेषण श्रमिको को दुर्घटना या जोखिम आदि से बचने में मदद करता है और कार्यशैली सम्बन्धी लागतों को दूर करता है।

आमुखन प्रकार्य–सम्प्रेषण लोगो को सहकर्मियो से, उच्चाधिकारियो से उनकी नीतियो, उद्देश्यो तथा संगठन के नियमों से परिचित होने मे मदद करता है।

साक्षात्कार प्रकार्य– साक्षात्कार के सम्प्रेषण के लिए फ्रासिस जे. बेटगिन के 'सैवन सी' बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस बात की वकालत करते हैं कि मौखिक सम्प्रेषण मे 'सी' से प्रारम्भ होने वाले सात शब्द स्मरणीय है–

- ☐ क्लैवर – चतुर
- ☐ क्लियर – स्पष्ट
- ☐ कम्पलीट – पूर्ण
- ☐ कनसाईज – सारभूत
- ☐ काक्रीट – ठोस
- ☐ करेक्ट – शुद्ध
- ☐ करुटियस – विनम्र

साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप है जिन्हे साक्षात्कारकर्त्ता, साक्षात्कारदाता कहते हैं। ये दोनों एक-दूसरे के साथ अन्त.क्रिया करते है।

निर्णय देने वाला प्रकार्य– प्रभावी निर्णय करना तभी सम्भव है जब आवश्यक हो और पर्याप्त जानकारी निर्णयकर्ता को उपलब्ध हो। मौखिक अथवा लिखित सम्प्रेषण निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। सामान्य रूप से सगठन में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होती है। जिससे वे अपना कार्य प्रभावी व दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें।

सम्प्रेषण की बढ़ती हुई महत्ता के लिए उत्तरदायी घटक

बड़े आकार का संगठन– बड़ी संख्या मे व्यक्ति संगठन के अन्दर तथा बाहर कार्य करते हैं। यह आकार सगठन में पद सोपान के विभिन्न स्तर उत्पन्न करता है। निर्देशन तथा समन्वयन समस्याए उत्पन्न करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो सम्प्रेषण की बढ़ती हुई महत्ता के लिए भी उत्तरदायी है। यह केवल बहु माध्यम अथवा बहुचैनल के साथ घटित होता है। इसमें सम्प्रेषण, निर्देशन, समन्वयन तथा प्रेरण करना सम्भव हो जाता है। इस प्रकार प्रबन्धन, शिक्षण, व्यवस्थापन की प्रक्रिया में सम्प्रेषण एक महत्वपूर्ण कडी है।

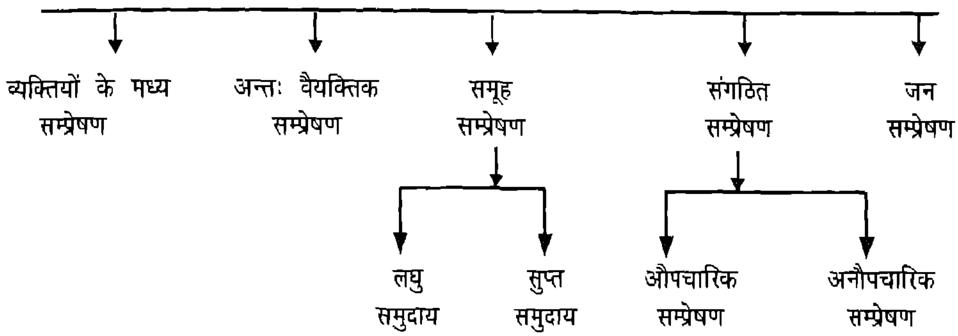
तकनीकी विकास– सम्प्रेषण के बढते महत्व के लिए उत्तरदायी एक अन्य महत्वपूर्ण घटक तकनीकी प्रगति या विकास है। तकनीकी विकास के कारण बडी सख्या में मौखिक एव लिखित सम्प्रेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली आन्तरिक युक्तिया विकसित हो गई हैं। सम्प्रेषण तकनीक में सम्प्रेषण युग्म के अन्दर सप्रेषण क्राति के कारण बहुत तेज रफ्तार से संप्रेषण तकनीक मे परिवर्तन हुए है। जिनके हम साक्षी हैं इसलिए एक जटिल आधुनिक व्यावसायिक संगठन को आज के प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व मे सफल होने के लिए स्वय को अधुनातम उपलब्ध तकनीक के साथ समायोजित कर लेना चाहिए।

- ट्रेड यूनियन गतिविधियों में वृद्धि
- मानव सम्बन्धो पर बल
- जन सम्बन्ध

सम्प्रेषण का महत्व

- समन्वय
- कार्य सम्पन्न करने मे सरलता
- प्रभावी निर्णय लेना
- प्रबन्धन क्षमता
- सहयोग
- प्रभावी नेतृत्व
- कार्य से सन्तोष
- उत्पादकता मे वृद्धि
- नैतिकता उत्पन्न करना
- प्रबन्धन भूमिकाओ को उपलब्ध कराना
- अधिगम को सरल बनाना।

सम्प्रेषण का वर्गीकरण



चस्टर आई बरनर्ड कहते हैं कि कार्य निष्पादन का प्रथम फलन सम्प्रेषण प्रणाली को विकसित करना तथा बनाए रखना है।

सम्प्रेषण का वर्गीकरण

- दो व्यक्ति एक साथ सम्पर्क करते है और प्रतीको को साझा इस्तेमाल करते है तथा एक-दूसरे से अपेक्षाए विकसित करते हैं।
- अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण से अभिप्राय स्वय के अन्दर या एक व्यक्ति के भीतर सम्प्रेषण से है। साक्षात्कार, बैठक, विचार-विमर्श अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण है। अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण की श्रेष्ठ विधियां हैं—एक पक्षीय सम्प्रेषण, द्विपक्षीय सम्प्रेषण। एक पक्षीय सम्प्रेषण जो सदैव नीचे की ओर होता है जबकि द्विपक्षीय सम्प्रेषण ऊपर की ओर होता है।

मीडिया चैनल तथा सम्प्रेषण का नेटवर्क– मीडियम शब्द एकवचन का तथा मीडिया शब्द बहुवचन है। अत मीडिया चैनल का अर्थ है—कोई वस्तु जिसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, या जाहिर किया जाता है मास मीडिया या जन माध्यम कहलाता है।

जनमाध्यम अभिव्यक्ति सम्प्रेषण के वे उपकरण दर्शाता है जो बड़ी सख्या मे लोगों तक पहुंचे जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार-पत्र, सिनेमा आदि। सम्प्रेषण के सम्बन्ध मे मीडिया से अभिप्राय सम्प्रेषण के उपकरणों से है।

इनका अर्थ है कि – एक संदेश को उनकी प्रवृत्ति तथा महत्व के निरपेक्ष सम्प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण या बहुत से उपकरणो से है।

मीडिया की मुख्य भूमिका या उत्तरदायित्व सन्देश के संग्राहक को जानकारी देने की है। सन्देशों का सवहन सम्प्रेषण है। मास मीडिया जनसाधारण तक सूचना प्रसारित करने का प्रयत्न करता है। मास मीडिया न केवल सूचित करता है अपितु प्रेरित भी करता है। मीडिया का प्रयोग मनोरंजन तथा व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक भी हो सकता है। मीडिया के अभाव में कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं होगी।

मौखिक सम्प्रेषण के माध्यम–

- आमने-सामने
- दूरभाष यंत्र
- गोष्ठिया
- प्रेस-कॉन्फ्रेन्स
- प्रदर्शन
- रेडियो
- रिकार्डिग
- डेक्टा फोन
- बैठक
- अफवाह
- ग्रेप वाईन (नेटवर्क)

एक पक्षीय सम्प्रेषण

नीचे की ओर सम्प्रेषण

↘ उच्च स्तर प्रबंधन ↘

↘ मध्य स्तर प्रबन्धन ↘

↘ निम्न स्तर प्रबन्धन ↘

द्विपक्षीय सम्प्रेषण

ऊपर की ओर सम्प्रेषण

↖ उच्च स्तर प्रबधन ↖

↖ मध्य स्तर प्रबन्धन ↖

↖ निम्न स्तर प्रबंधन ↖

- माईक
- सामूहिक विचार-विमर्श
- मौखिक-प्रतिवेदन
- बन्द परिपथ दूरदर्शन

लिखित सम्प्रेषण के माध्यम – लिखित संदेशो के सम्प्रेषण में प्रयुक्त उपकरण–

- पत्र
- पत्रक
- पुस्तिकाएं
- स्मरण-पत्र (मेमोरेन्डम)
- कार्यालय-आदेश
- विनिर्देशन
- मैनुअल्स
- कार्यालय टिप्पणी
- स्पष्टीकरण
- मैगजीन
- सरकुलर
- पोस्टर
- पर्चे
- प्रपत्र
- बुलेटिन
- ब्रोशर
- संघीय-प्रकाशन
- शिकायत एवं सुझाव
- हाऊस जरनल्स
- हैन्ड-बुक
- हैन्ड-आऊट (पत्रक)
- हैन्ड-फाईल्स
- वार्षिक प्रतिवेदन
- समाचार-पत्र
- डायरेक्ट्री
- प्रस्ताव
- सहमति (एग्रीमेंट)
- कर्मचारियों की हैन्डबुक
- पे-पैकेट-इन्सर्ट
- विशेष सरकुलर आदि।

दृश्य सम्प्रेषण माध्यम

- दृश्य सहायक उपकरण
- चार्ट्स
- ब्ल्यू प्रिन्ट्स
- मॉडल्स
- पोस्टर
- स्लाइड
- नीयॉन (चिह्न)
- होर्डिंग्स
- चित्र
- फ्लैनल बोर्ड्स
- फैसीमाईल (सील)
- मैग्नेटिक बोर्ड
- इलेक्ट्रो-राईटर्स
- टेली लेक्चर्स
- वीडियो कैसेट्स
- तालिका
- नक्शे

- व्यंग्य चित्र
- बैनर
- डिसप्ले आदि।

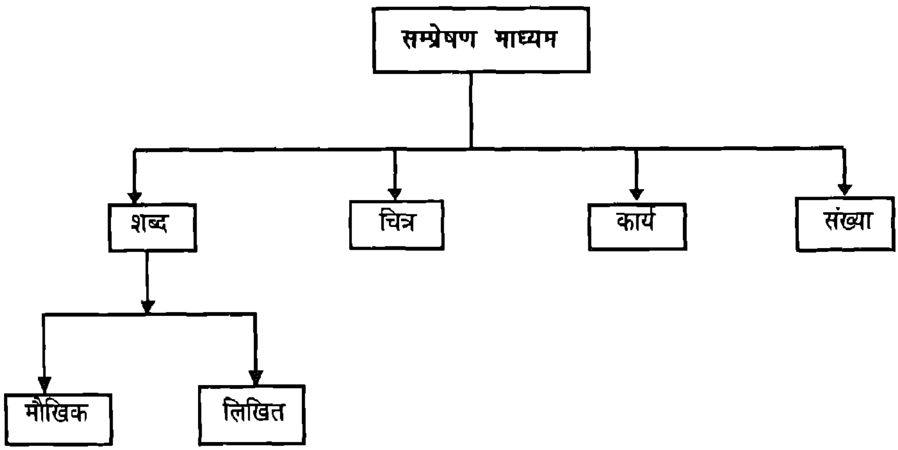
अशाब्दिक सम्प्रेषण माध्यम

- हाथ मिलाना
- मौन
- मुस्कान
- त्यौरियां चढ़ाना
- सकेत
- स्वीकृति (सिर-हिलाना)
- उपभाषा (पैरा-लेंग्वेज)
- शारीरिक भाषा (बॉडी-लेंग्वेज)

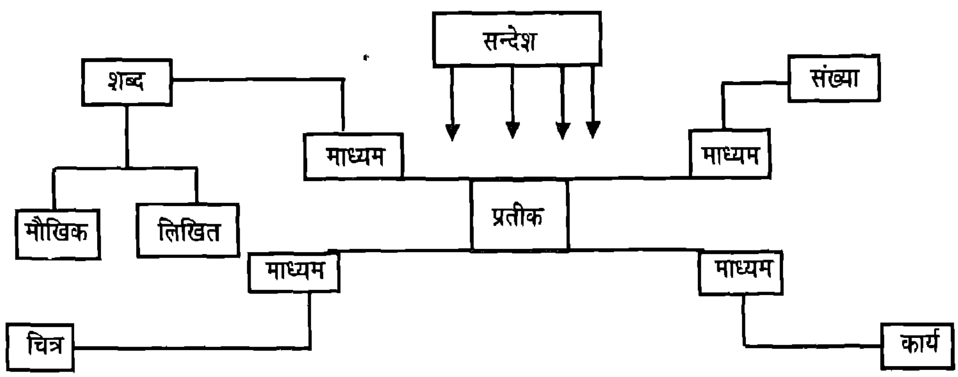
संख्यात्मक माध्यम

- आकडे
- सांख्यिकी आकड़े

बहुमाध्यम – बहुमाध्यम या मल्टी मीडिया में बहुत से माध्यम होते हैं और प्रत्येक के अपने गुण व दोष होते हैं। एक से अधिक माध्यम का अन्य के संयोजन में प्रयोग बहुमाध्यम कहलाता है। इसमें एक विशिष्ट स्थिति में प्रत्येक माध्यम की उपयोगिता व उपयुक्तता को ध्यान में रखकर बहुत से माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।



बहु-माध्यम



वाहिका (चैनल)—वाहिका या चैनल विभिन्न विधियों और साधनों को अपनाकर प्रेषक द्वारा संग्राहक तक संदेशों को सम्प्रेषित करने के लिए अपनाया जाता है। दूसरे शब्दो में चैनल वह मार्ग या पथ है, या माध्यम है जिसके द्वारा सूचना को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। सन्देश अपने गन्तव्य तक केवल तभी पहुंच सकता है जब उसे सम्प्रेषित करने के लिए सही चैनल का चुनाव किया जाए। अतः चैनल सम्प्रेषण के किसी भी माध्यम मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भले ही चैनल के द्वारा शब्दों, संख्या, चित्र अथवा कोई अन्य संदेश को सम्प्रेषित करना हो। हमारे व्यापक सम्प्रेषण के ससार में सम्प्रेषण के कई माध्यम हैं। लिखित तथा मौखिक संदेश सम्प्रेषण के विविध माध्यम व साधनों से भेजे जा सकते है।

सम्प्रेषण के माध्यम का निर्णय लेते समय निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए—

- संसाधन
- गति
- लागत
- दूरी
- क्षमता
- परिशुद्धता
- गोपनीयता
- प्रभाव
- सुनिश्चितता
- आग्रह
- उद्देश्य
- प्रभावी रखरखाव
- प्रशिक्षण तथा शिक्षा
- सन्देशो की सुरक्षा
- पृष्ठ-पोषण

औपचारिक सम्प्रेषण के लाभ

- सही सूचना
- सत्ता की विद्यमानता
- प्रभावी सम्प्रेषण
- संगठनात्मक दक्षता
- सम्प्रेषण की एकरूपता

औपचारिक सम्प्रेषण के दोष

- विलम्ब
- केवल आन्तरिक साधनों का होना
- सूचना का अत्यधिक भार
- धीमी गति से सम्प्रेषण
- शीघ्र प्रत्युत्तर का अभाव
- पृष्ठ-पोषण का अभाव

सम्प्रेषण में बाधाए—बाधा शब्द का अर्थ, रुकावट या अवरोध या कठिनाई या समस्या होता है। सम्प्रेषण के सन्दर्भ में बाधा से अभिप्राय अवरोधों या समस्याओ से है जो मार्ग मे आती हैं और जो प्रेषक से संग्राहक तक सूचना के सम्प्रेषण को विपरीत रूप से मार्ग में प्रभावित करती है। मार्ग में विभिन्न प्रकार की समस्याए आ सकती है जिनसे संग्राहक तक सदेश के सम्प्रेषण में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है या यह भी हो सकता है कि संदेश पहुचे ही नहीं। बहुधा ये बाधाएं सन्देश को विकृत करने की प्रवृत्ति रखती हैं और संगठन के सदस्यों के मध्य भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। साथ ही ये कर्मचारियो के मनोबल को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं और टीम-रूप में कार्य करने के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अवरोधो के विभिन्न वर्ग जो सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न करते है इस प्रकार है—

सगठनात्मक अवरोध— • नीति, • नियम, • स्तर तथा स्थिति, • जटिल, • सुविधाएं

भाषागत अवरोध— • बुरी तरह से अभिव्यक्त सन्देश, • त्रुटिपूर्ण अनुवाद, • अवर्गीकृत मान्यताएं, • शब्दाडम्बर युक्त भाषा

व्यक्तिगत अवरोध— • उच्चाधिकारियो के प्रति अवरोध, • आदत तथा प्रवृत्ति, • सत्ता को बनाए रखना, • आत्मसन्तोष, • उपयुक्त चैनल का सिद्धान्त, • पूर्वाग्रह, • अविश्वास, • हां में हां मिलाने वाले उच्चाधिकारी, • जटिल, • समय का अभाव, • बोझिल सन्देश

मनोविज्ञान अवरोध— • सम्प्रेषण मे अविश्वास, • ध्यान का अभाव, • अपरिपक्व मूल्यांकन, • सम्प्रेषण की विफलता, • सम्प्रेषण द्वारा हानि, • लिखित सन्देश पर आग्रह

अन्य अवरोध— • परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, • बोझ, • मन्द मस्तिष्क, • भय, • सम्प्रेषण की योग्यता का अभाव, • अपर्याप्त समायोजन अवधि, • दूरी तथा समय

सम्प्रेषण के अवरोधों को दूर करने के उपाय— ● आमुखन, ● उपयुक्त भाषा, ● अच्छा स्रोत, ● ग्रेपवाइन का प्रयोग, ● कार्य, ● स्पष्टता, ● संग्राहक को जानना, ● अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, ● पृष्ठ-पोषण

कक्षा-कक्ष में सम्प्रेषण

कक्षा-कक्ष में सम्प्रेषण बहुधा मौखिक अथवा लिखित भाषा द्वारा किया जाता है। इसमें मौखिक सम्प्रेषण तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ी भूमिका निर्वहन करता है जीनपियागेट के अनुसार बच्चो का प्रारम्भिक मौखिक सम्भाषण अह केन्द्रित होता है। वे शब्दो कि व्याख्या व उनका उपयोग अपने चारों ओर के अनुभवों के आधार पर ही करते है। इसका कारण यह है कि इन बालकों की विचार शक्ति अभी तक एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। अतः प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षक को प्रत्येक शब्द का अर्थ (वस्तु) के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित कर अपने सम्प्रेषण को प्रभावी बनाना होता है।

अच्छा शिक्षण मात्र सम्प्रेषण नहीं है, अपितु उससे अधिक है। बालक सम्प्रेषित किए गए शब्द को उसी प्रकार दोहराएगा यह पर्याप्त नही है। शिक्षक का प्रयोग यह है कि बालक उस शब्द को पहचाने, उसका अर्थ समझे और भावी परिस्थितियों में उसका प्रयोग सही वर्तनी सहित उपयुक्त रूप से कर सके। वास्तविक अधिगम केवल तभी घटित होता है जब सम्प्रेषण का कार्य विद्यार्थी के सम्प्रेषण कौशलो में सार्थक तथा स्थायी अभिवृद्धि करने में सफल हुआ हो। कक्षा में सम्प्रेषण केवल मात्र तथ्यों का एकतरफा प्रस्तुतीकरण नहीं है इसके लिए छात्र तथा शिक्षक के बीच अन्त· सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है। शिक्षक को सम्प्रेषण के विषय मे बहुत-सी बाते जाननी चाहिए। कक्षा इसलिए स्थापित की जाती है कि सम्प्रेषण के उद्देश्यों की प्रर्ति हो न कि युवा और विकासशील मस्तिष्कों पर शिक्षक के विचारो को आरोपित करें। पाठशाला का मूलभूत प्रयोजन बालको में सम्पूर्ण कौशलो का विकास करना है। अत· शिक्षक को इन कौशलों को विकसित तथा परिष्कृत करने की विधिया और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षक को छात्र के ऊपर कक्षा से बाहर अनेक सम्प्रेषण माध्यमो के निरन्तर पडने वाले प्रभाव को महसूस करना चाहिए। वे शब्द जिनका प्रयोग बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व करते हैं, बालको द्वारा ये शब्द पूर्व मे विभिन्न माध्यमों से सीखे गए थे। शिक्षक को इस प्रकार से सीखे गए शब्दो को पाठशाला की गतिविधियो से जोड़ देना चाहिए। सम्प्रेषण केवल तभी घटित हो सकता है जबकि शिक्षक और उसका शिष्य सामान अर्थ तथा अनुभवों का साझे रूप से उपयोग करें।

वर्तमान समय में विद्यालय में आने वाले छात्र व्यापक रूप से विभिन्न पृष्ठभूमियो तथा क्षमताओ तथा अभिरुचि वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक को भी ज्ञान मे हुए व्यापक प्रसार को दृष्टिगत रखना होता है। विद्यार्थियों को बहुत कम साधन और बहुत कम अवसर मिलते हैं, उनके पास उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय-वस्तु का साधन अन्वेषण करने के लिए बहुत थोडा समय होता है।

आधुनिक तकनीक ने फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, मेगनेटिक टेप, स्टीरियोस्कोपिक आदि सम्प्रेषण की अनेक युक्तिया उपलब्ध करा दी है जिनका सम्प्रेषण में व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। इन्हे दो वर्गो मे बांटा जा सकता है।

- ❑ जो विभिन्न क्षमताओं वाले युक्तियो से बने समूहों में प्रयोग किए जाने के लिए प्रभावी हों।
- ❑ दूसरे वर्ग मे ऐसी युक्तियां आती है जिन्हे शिक्षक की मूलभूत सहायता के साथ व्यक्तिगत अनुदेशन में व्यापक रूप से प्रयोग मे लाया जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्प्रेषण हमारा विकास करने, सिखाने, जागरूक रखने और समायोजन करने योग्य बनाता है।

यह सम्प्रेषण कई प्रकार के माध्यमों से किया जा सकता है जिससे संग्राहक तक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। ❑❑

एजुकेशनल हैराल्ड
महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर, राजस्थान

हिन्दी भाषा साहित्य : शिक्षण और समस्याएं

❑ जयपाल तरंग

भाषा और साहित्य शिक्षण की समस्याओं का उल्लेख करने से पहले यह भी तय है कि गुणात्मक शिक्षा के विचार का प्रमुख केन्द्र शिक्षक ही है। यद्यपि शिक्षण से जुड़े हुए शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, पूरक पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, शिक्षण साधन, दृश्य-श्रव्य सामग्री, अभिनय, प्रदर्शन कलाएं और परिभ्रमण आदि शिक्षण का अंग हैं, लेकिन हमारी शिक्षण समस्याओं की चर्चा के अन्तर्गत इन सबका स्थान गौण ही रहेगा, प्रमुख रहेगा शिक्षक। परिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा प्रबन्ध भी फिलहाल मुख्य नहीं हैं।

आज के विषय पर चर्चा को सीमित समय के अनुसार अनुशासन मे रखते हुए निवेदन है कि उन मुद्दो और समस्याओं को चर्चा का विषय न बनाए, जिनमें हिन्दी शिक्षकों की भागीदारी नही है। भाषा शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य और मूल्यांकन संबंधी दस्तावेजों में हम हिन्दी अध्यापको का कोई दखल नहीं है। इनका नीति-नियोजन और निर्धारण कक्षा आठ तक राज्य सरकारे करती है तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड करते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों और अन्य निजी संस्थानों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करते हैं। कहने की आवश्यकता नही कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य-सामग्री के निर्माण में सरकारी वर्चस्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन उसकी चर्चा हम शिक्षको के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारी दृष्टि मे हमारे कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है और हमारा कर्मक्षेत्र ही प्रमुख है।

इस सम्बन्ध मे एक बात और स्पष्ट कर लें। हिन्दी भाषा-शिक्षण की दृष्टि से मातृभाषा/प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में सीखी-सिखाई जाती है। भाषा-शिक्षण की समस्याओं पर चर्चा में हमारा ध्यान तीनो स्तरो पर अलग-अलग केन्द्रित नही रहा है बल्कि सामान्यीकृत रूप से हिन्दी भाषा-शिक्षण पर केन्द्रित है।

भाषा और साहित्य शिक्षण की समस्याओं का उल्लेख करने से पहले यह, भी तय है कि गुणात्मक शिक्षा के विचार का प्रमुख केन्द्र शिक्षक ही है। यद्यपि शिक्षण से जुड़े हुए शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, पूरक पुस्तके, अभ्यास पुस्तके, शिक्षण साधन, दृश्य-श्रव्य सामग्री, अभिनय, प्रदर्शन कलाएं और परिभ्रमण आदि शिक्षण का अंग है, लेकिन हमारी शिक्षण समस्याओ की चर्चा के अन्तर्गत इन सबका स्थान गौण ही रहेगा, प्रमुख रहेगा शिक्षक। परीक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा प्रबन्ध भी फिलहाल मुख्य नही हैं।

आइए, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि शिक्षण है क्या? इसके उत्तर में अंग्रेजी और अंग्रेजियत समर्थको के वागजाल में पड़ने की जरूरत नही है क्योंकि इन विद्वानों के शब्दाडम्बर इतने बवडरपूर्ण होते हैं, जिनमें

सम्पूर्ण सम्प्रेषणीयता का घनघोर अभाव रहता है। सरल शब्दों में शिक्षण कार्य एक क्रिया है, प्रयोग है, एक कला है, जो अवसर, स्थिति और प्रकरण के अनुकूल अध्यापक द्वारा रूप धारण करता है। यानि हिन्दी भाषा और साहित्य को सीखने-सिखाने मे शिक्षक का कार्य ही शिक्षण है। शिक्षण-सिद्धान्त, विधियां, युक्तियां अपने आप में साध्य नही हैं, बल्कि साधन हैं, जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य को सरल, सुग्राह्य और रुचिकर बनाता है। इससे भाषा शिक्षक की इस योग्यता पर प्रकाश पड़ता है कि वह बालकों की स्थिति के अनुकूल यथाप्रसग, शिक्षण-सिद्धान्तो और विधियों का प्रयोग करने की दक्षता रखता है।

शिक्षण-विषयक ज्ञान शिक्षक को यह मानने की प्रेरणा देता है कि शिक्षण-शास्त्र एक विकासवान विद्या है। नवीन शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धान्त और युक्तियां प्रयोग के धरातल पर परिवर्तित होते रहते है। भाषा और साहित्य-शिक्षण के सम्बन्ध मे भी यह सही है। भाषा-शिक्षण सिद्धान्तों और विधियों आदि में परिवर्तन होता रहता है। भाषा शिक्षकों को और अन्य शिक्षको को भी स्वर्गीय राजीव गांधी की शिक्षा नीति-क्रियान्वयन से एक बडा लाभ यह मिला है कि शिक्षण सम्बन्धी विविध और नवीनतम जानकारियों से सुपरिचित रहने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, विचार-गोष्ठियो, कार्य गोष्ठियों, नवाचार और क्रियात्मक अनुसंधान के पर्याप्त साधन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण सस्थान आदि के माध्यम से उपलबध हैं और सचालित किए जा सकते हैं।

भाषा और साहित्य शिक्षण को लेकर जिन अभावों को समस्या के रूप में उठाया जाता है उन पर उंगली उठाने वालो मे परीक्षा-प्रबंधक, शिक्षा-विभाग, शिक्षा-मंत्रालय, राज्य-सेवा-संघ और लोक-सेवा-संघ, विश्वविद्यालयो के प्राध्यापक, प्रशासक और अभिभावक प्रमुख हैं। उच्चारण, अनुतान, मौखिक अभिव्यक्ति, वर्तनी, विराम आदि का प्रयोग, लिखित अभिव्यक्ति आदि के संदर्भ में अशुद्ध भाषा-व्यवहार के लिए भाषा शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हिन्दी भाषा-शिक्षण की आलोचना मे हम अध्यापक भी बड़े सक्रिय हैं, प्राथमिक स्तर के अध्यापक-अध्यापिकाए बच्चो के भाषागत अज्ञान को कोसते हैं। माध्यमिक स्तर के अध्यापक भाषा कौशलों, सम्प्रेषण और चितन की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक अध्यापक-अध्यापिकाओ पर दोष मढ़ते हैं। इस समस्या से उबरने की जरूरत है और इससे तभी उबरा जा सकता है जब हम शिक्षण कार्य की शैक्षिक दक्षता पर खरे उतरें।

शिक्षण के लिए शिक्षक सूत्रधार है, निदेशक है, अभिनेता है, कक्षा-प्रबधक है। भाषा और साहित्य का ज्ञाता है। उद्देश्य प्राप्ति के शिक्षा दर्शन और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से वाकिफ है। उद्देश्यो के अनुरूप प्रश्न निर्माण और परीक्षण मूल्याकन के कायदो का जानकार है। यदि इस सामर्थ्य मे हम शिक्षको की कोई कमी है तो उसे समस्या के रूप मे माना जा सकता है। इन अपेक्षाओं के सदर्भ मे कुछ मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा के ज्ञान की समस्या

हिन्दी शिक्षक का सबसे पहला काम और कर्तव्य है कि उसका हिन्दी भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। भाषा तत्वो का ज्ञान—ध्वनिया, शब्द-भंडार, वाक्य रचना और वाक्य-विज्ञान, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों और सम्प्रेषण कौशलो से पूर्ण परिचय और चिंतनपरक अभिव्यक्ति के विकास की व्यावहारिक और शास्त्रीय जानकारी हो। हिन्दी एक जीवन्त भाषा है। उसकी जीवन्तता उस भाषा के लोक प्रचलन में है। बोलिया, मातृभाषा और मानक हिन्दी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे समस्या कहां है? समस्या वहा है जहा शिक्षक इस ज्ञान के अभाव से ग्रस्त है।

हिन्दी साहित्य ज्ञान की समस्या

हिन्दी भाषा के साथ शिक्षक को उसके साहित्य पक्ष का भी अधिकारी विद्वान होना चाहिए। शिक्षक के पाठ्यपुस्तक में वर्णित साहित्यकारो और उनकी कृतियों के सदर्भ, विधागत विकास, प्रमुख साहित्यकारो, कवियों, निबन्धकारों, कहानीकारो, उपन्यासकारों, एकाकी और नाटककारो आदि की जीवनी और उनकी साहित्यिक

पृष्ठभूमि से पूर्ण परिचित होना चाहिए। साहित्यालोचन और काव्य शास्त्रीय अनुप्रयोग से साहित्यिक अध्ययन के प्रति विद्यार्थियो मे अभिरुचि, अन्तर्दृष्टि और व्याख्या सामर्थ्य विकसित करने में सहायता मिलती है। इस साहित्यिक दक्षता/योग्यता का अभाव भी एक समस्या है।

साहित्यिक अभिरुचि की समस्या

साहित्य शिक्षक के लिए भाषा और साहित्य का ज्ञान ही अपेक्षित नही है, बल्कि उसमे साहित्यिक अभिवृत्ति, रुचि और सृजनात्मक शक्ति का होना भी जरूरी है। कहना न होगा कि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन और शिक्षण में अनुप्रयोग शिक्षण के कार्य में हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाओं का सृजन-प्रदर्शन आदि-आदि साहित्य शिक्षण के रचनात्मक रूप है। साहित्यिक अभिरुचि से ही पाठ्यपुस्तको में दी हुई पुरानी और घिसी-पिटी सामग्री तक को भी जीवन्त और तरुणयुगीन बनाया जा सकता है। इसका अभाव भी शिक्षण की ही एक समस्या है।

हिन्दी के प्रति गौरव और दायित्व की भावना की समस्या

अग्रेजी भाषा और पश्चिमी सस्कृति की नकल के नौटंकियों की झकझोर में हिन्दी के प्रति गौरव और गरिमा की अनुभूति और अभिव्यक्ति और प्रभावी प्रदर्शन भाषा शिक्षक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। सांस्कृतिक दायित्व है। क्रियाकलापों की संचार-भाषा के रूप में अंग्रेजी पिछाड़ प्रदर्शनों से हिन्दी को गौरवान्वित किया जा सकता है। इसका अभाव भी हिन्दी शिक्षण की प्रमुख सांस्कृतिक समस्या है। कहना न होगा कि अन्ताक्षरी जैसा कविता का साहित्यिक खेल सिनेमा गीतो के खेल में बदल गया है। रंगीन प्रचार-प्रसार तन्त्र से हिन्दी साहित्य की सुरक्षा भी हिन्दी शिक्षण से जुड़ी है। आपसी संवाद में हिन्दी भाषा को लोकप्रिय बनाया जाए।

भाषा-शिक्षण तथा साहित्य-शिक्षण विधियों/युक्तियों के ज्ञान और प्रयोग की समस्या

हिन्दी भाषा शिक्षण और साहित्य शिक्षण की आधुनिक विधियों का सम्यक ज्ञान होना हम हिन्दी शिक्षको के लिए आवश्यक है। शिक्षण विधि या युक्ति नामकरण-अनुकरण की मोहताज नही है, बल्कि यह जानने की प्रक्रिया है कि भाषा या साहित्य मे जो सिखाने जा रहे हैं उसे किस प्रकार प्रस्तुत करें कि विद्यार्थियो को वह रुचिकर, आकर्षक और ग्राह्य हो सके। पाठ-प्रस्तुति की तैयारी, पाठ-विकास मे विद्यार्थियो का सक्रिय सहयोग, रचनात्मक प्रश्न चर्चा आदि आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होती है। साहित्यिक शिक्षण में समन्वित शिक्षण का स्वरूप विकसित नहीं हो पाया है यानि यह प्रयोग मे नही है। कवि, कविता, कवि-जीवनी, हिन्दी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र को अलग-अलग सीखने-सिखाने और अलग-अलग ही परीक्षण मूल्याकन एक समस्या है। कविता-शिक्षण में समन्वित शिक्षण के तहत इनके एकीकृत शिक्षण का प्रचलन किया जाना चाहिए, जिससे कविता की सर्वस्व ग्राह्यता की दिशा खुले।

कक्षा-भाषा-प्रबन्ध की समस्या

शिक्षण कार्य की कक्षा एक रंगभूमि है। कक्षा को सुनने-सुनाने, पढ़ने-लिखने, सम्प्रेषण और चिन्तनपरक गतिविधियों में अनुशासित रखने के लिए जिस भाषा प्रबंध की आवश्यकता है, उसके संकेत नाट्यशास्त्र से मिलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या के कारण शिक्षण-युक्तियों का प्रयोग न कर पाने की दलील उचित नहीं है। क्रिया-प्रतिक्रिया की यदि हमारी भाषा तत्समी है तो वह प्रायः सम्प्रेषणीय नहीं होती। हम अपने उपदेशों, निर्देशों की शब्दावली पर गर्व कर सकते हैं और विद्यार्थियो के मौन को 'सीख गए' समझ सकते है। जबकि यह कई बार सही नही होता। हिन्दी भाषा के सामान्य स्वरूप को तत्सम-बोझिल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अर्थ-सम्प्रेषण की दृष्टि से प्रचलन प्रधान बनाने की जरूरत है। निश्चय ही यह एक समस्या है। हिन्दी और साहित्य के शिक्षण में नाट्यशास्त्र, लोकवार्ता विज्ञान और समूह-शिक्षण के अनुशासन की सहायता ली जा सकती है।

हिन्दी-संस्कृतिगत सौंदर्यबोध की समस्या

मानक हिन्दी भाषा जिस बहुभाषिकता का प्रतिनिधित्व

करती है उसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय संस्कृति की शब्द संपदा सम्मिलित है। नगर, महानगरों को कंकरीट सभ्यता, गावों से चरागाह और वन-उपवन की अनुपस्थिति, वृक्ष, लता और झाड़ियों के दुलर्भ दर्शन होने के कारण आज के व्यक्ति की आंखों मे प्रकृति की सजीव छवि नही रही है। व्यक्ति और प्रकृति की दूरी के कारण उनका सौदर्य बोध अभावग्रस्त है। इस अभाव की आपूर्ति ऐसे चित्रों व चलचित्रों से संभव है जिनमें सभी द्रुम, लता, झाडी, पुष्प, झील, ताल, कुज आदि के संग्रहालयों की व्यवस्था की जाए। कर-कमल, कंठ-कमल, नयन-कमल आदि के सौंदर्य बोध की अपेक्षा है कि नेत्रों में वह छवि रमे तभी साहित्य के अर्थ में फलीभूत हो सकती है। प्रकृति छवि-संग्रहालय का न होना भी साहित्यिक सराहना की समस्या है। अत. हिन्दी-संस्कृति सग्रहालय पर विस्तार से विचार की आवश्यकता है।

निदान और उपचार-शिक्षण की समस्या

शिक्षण अधिगमोन्मुख होता है यानि शिक्षण की संप्राप्ति विद्यार्थियों में घटित होती है, उनका सीखना ही अधिगम है। शिक्षण का परीक्षण या मूल्यांकन नहीं किया जाता किन्तु अधिगम की संप्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों ने उद्देश्यानुसार क्या सीख लिया है? और क्या नहीं सीखा है। यद्यपि इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि हमारे शिक्षण से क्या सीखा जा सका और क्या नहीं सिखाया जा सका। जो नहीं सिखाया जा सकता उसके निदान की आवश्यकता होती है और निदान शिक्षक के लिए वह ज्ञान है, जिससे वह त्रुटियों का सर्वेक्षण, त्रुटियो का विश्लेषण और उस आधार पर उनके कारणों की पहचान करता है। शिक्षण कार्य मे त्रुटियों को ही निदान मान लेना गलत है। निदान तो त्रुटियों के कारण जानने से होता है। इन त्रुटियों के कारण ज्ञान पर आधारित निवारणार्थ शिक्षण को उपचार शिक्षण कहते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों के उपचार शिक्षण बहुत उपलब्ध हैं लेकिन चिन्तनपरक, रचनात्मक, अभिव्यक्ति के निदान और उपचार शिक्षण का अभाव हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक है।

भाषा और साहित्य शिक्षण के क्षेत्र में अध्ययन-अनुसंधान के निहितार्थ की समस्या

हिन्दी भाषा और साहित्य शिक्षण के क्षेत्र मे गत पचास वर्षो मे कई उपयोगी अध्ययन और अनुसंधान हुए हैं, जो भाषा शिक्षण और साहित्य को चार चांद लगा सकते है। लेकिन वे अनुसंधान कार्य भाषा और साहित्यकर्मियों के पास नहीं पहुचते। इसके दो कारण हैं–

- शिक्षकों में अनुसंधान पुस्तकों और पत्रिकाओं की जानकारी का अभाव और उनके अध्ययन के प्रति उपेक्षा।
- अनुसधान अध्ययन में प्रयुक्त भाषा का कठिन स्तर जो अनुसंधानकर्ताओ को समर्पित होता है।

आवश्यकता है कि इन अध्ययन-अनुसंधानों के आधार पर शिक्षकों को शिक्षण की जानकारी के मोनोग्राम उपलब्ध कराए जाएं और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्य आयोजित प्रशिक्षण और विचार-गोष्ठियों में शिक्षकों को उपलबध कराए जाएं।

परीक्षण-मूल्यांकन की दक्षता संबंधी समस्या

भाषा साहित्य शिक्षक के लिए सीखने वालों के पूर्व ज्ञान की परख-पहचान आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा सिद्धान्त के अनुसार ज्ञात से अज्ञात को युक्तियों से सिखाया जा सकता है। पूर्व ज्ञान-परीक्षण और मूल्यांकन के औपचारिक और अनौपचारिक उपकरणों का निर्माण, प्रयोग और विश्लेषण हमें जानना चाहिए। समस्या है कि हमारा शिक्षण विद्यार्थियों की पहचान से प्रारम्भ होता है।

विषय-वस्तु-शिक्षण साधन और पाठ्यपुस्तकों की बोधगम्यता की जाच भी जरूरी है, जिसके अभाव में सामग्री के काठिन्य का वैज्ञानिक बोध नहीं होता तथा कठिनाई निवारण की विधियां और युक्तियां तैयार नहीं की जा सकतीं। पाठ्यपुस्तकों की बोधगम्यता की मूल्यांकन विधियां हैं। भाषा-साहित्य शिक्षको के लिए वे उपलब्ध हो या उनका निर्माण, प्रयोग और विश्लेषण जान लेना चाहिए।

शिक्षण-उपयोगी बहुआयामी सूचनाओं का अभाव– एक समस्या प्रधान अभाव

सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में शिक्षण को प्रभावी बनाने

के लिए पुस्तकालय, इन्टरनेट, सी.डी., वैबसाइट आदि के योगदान को हम स्वीकार तो करते है किन्तु उनका लाभ नही उठा रहे। उनके विषय मे हमारा अज्ञान भी रुकावट है। अध्यापक कक्ष में सूचनापट जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नही है जो होनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'पुस्तकालय ऋण' चुकाने की बात कही है। समस्या है हम उस ऋण को दो स्तरो पर नहीं चुका रहे–

- ☐ पुस्तकालय को ताजातरीन पुस्तकों से लैस करना।
- ☐ पुस्तक पठन के लिए विद्यार्थियों मे उसकी आदत डालना।

आचार्य का कथन है– "पुस्तके परीक्षित सन्त है। पुस्तकालय ऋण चुकाने का प्रयत्न कीजिए", विद्यालय खोलकर, पुस्तकालय खोलकर जिस प्रकार से भी हो इसकी रक्षा करो और इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, नही तो इतना तो तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है कि यह नष्ट न हो पाए और अगली पीढी के लिए सुरक्षित रहे। (आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा-साहित्य और देश पृ. 154)

हिन्दी भाषा और साहित्य शिक्षण की समस्याओ का शिक्षक ही आधारभूत अंग है। भाषा और साहित्य को प्रदर्शन कला न मानना, दूसरे हिन्दी भाषा और साहित्य शिक्षकों द्वारा यह मान्यता कि शिक्षण की उपाधि विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षण मे कोई योगदान नहीं करती। पाठ्यचर्या शिक्षा के लक्ष्यों को रेखाकित करती है जिसकी समझ शिक्षा दर्शन और अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बिना समझी-समझाई नही जा सकती। पाठ्यक्रम में वर्णित कौशल और योग्यता के उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ग्रहण करने में पाठ्यक्रमो के उद्देश्यों की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के लिए– कक्षा आठ प्रथम हिन्दी भाषा मे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबन्ध संकलित है– "क्या निराश हुआ जाए" यही निबन्ध सैकेण्डरी स्तर पर दसवीं कक्षा के विद्यार्थी बी कोर्स में पढ़ते हैं। आप सब जानते है कि पाठ को पढाने का उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ति के लिए पाठ के बाद में प्रश्न और अभ्यास दिए जाते है, जिससे तय होता है कि इस पाठ से क्या, कितना और क्यों सीखना है। दोनों पाठों के बाद जो प्रश्न अभ्यास दिए गए है उन प्रश्नों में पाठ्यचर्या के लक्ष्य, व्यक्तित्व मे नागरिकता के गुण, मानवीय अधिकार और कर्तव्य का बोध और आचरण तथा पाठ्यक्रम के उद्देश्यो के अनुरूप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संप्रेषण कौशल और सृजनात्मक योग्यता के अन्तर्गत प्रश्नो के अभ्यासो का नितात अभाव है। कारण–पाठ्यपुस्तक और परीक्षण के तहत हिन्दी भाषा और साहित्य का शिक्षण अपेक्षित माना जाता है। नीति नियोजन, क्रियान्वयन के दस्तावेज, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम खूंटी पर टांग दिया जाता है। और हम शिक्षक अपनी व्यावसायिक दक्षता के लिए उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। यहां तक कि पाठ्यपुस्तक के प्राक्कथन और भूमिका में जो सीखने-सिखाने के दिशा-निर्देश दिए जाते हैं वे हिन्दी भाषा और साहित्य शिक्षण के लिए हमारी व्यावसायिक दक्षता को विकसित करने वाले होते हैं लेकिन हममे जाने क्यो ये धारणा घर कर गई है कि ये हमारे लिए बेकार हैं। शिक्षण संदर्शिकाएं भी या तो बनाई नही जातीं या उनका कोई व्यावसायिक उपयोग नही होता है।

शिक्षण को धारदार और प्रभावी बनाने के लिए हम शिक्षकों को भाषा और साहित्य से जुड़कर राष्ट्रीय हित और लोक मंगल की कामनाओं से सोचने-समझने और प्रयत्न करने का सकल्प लेना चाहिए। विश्वास रखकर आशान्वित रहिए और याद रखिए आचार्य द्विवेदी का यह परामर्श–

"हम प्रयत्न करते रहें ताकि... कोई बालक तुलसीदास के समान, रवीन्द्रनाथ के समान और विवेकानन्द के समान नई ज्योति दे सके, और देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने मे बड़ी भारी सहायता कर सके। असंभव कुछ भी नहीं है, होगा अवश्य, क्यो नहीं होगा"...(वही)

हिन्दी भाषा और साहित्य-शिक्षण की समस्याओ का आकलन, विश्लेषण तथा शिक्षणधर्मी समाधान हिन्दी शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता के विकास और विद्यार्थियों में अधिगम-सिद्धि के लिए प्रभावी प्रयास होगा। इसी उत्तरदायित्व के साथ नवाचार की पहल भी संभव है। ☐☐

एच-2/53, महावीर इन्क्लेव
पालम, नई दिल्ली

माध्यमिक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता

❑ कुंवर पाल सिंह

प्रत्येक विद्यालय में प्रातः अथवा सायं विशेष ट्यूटोरियल कक्षाओं का आयोजन करके छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन के अभिशाप से, घर-घर जाने के अभिशाप से बचाया जा सकता है। इसके लिए अल्प मात्रा में अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है। भारतीय शिक्षा की महान परम्पराओं को समर्पित कुछ शिक्षक रविवार या अन्य अवकाशों में अतिरिक्त कक्षाएं लेकर आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। नालन्दा, तक्षशिला और उज्जैन के शिक्षा केन्द्र हमारे प्राचीन आदर्श हैं। डाक्टर अमर्त्य सेन ने शिक्षा और समाज कल्याण के विषय में जो उद्‌गार प्रकट किए हैं उनसे राष्ट्र को प्रेरणा लेनी चाहिए। साधन सम्पन्न विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में एक महीने तक विशेष ट्यूटोरियल कक्षाओं का आयोजन करके कमजोर छात्रों को राहत दी जा सकती है।

हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा जटिल परीक्षा पद्धति छात्रो तथा छात्राओ के सर्वागीण विकास में तथा उनके चरित्र का निर्माण करने में असफल रही है। छात्रों तथा छात्राओ को राष्ट्र के सहकारी उत्पादन मे भागीदार बनाने में भी हमें सफलता नहीं मिली है। माध्यमिक शिक्षा मे सुधार के लिए कई आयोग तथा समितियां गठित की जा चुकी हैं। कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। किन्तु माध्यमिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए कोई क्रान्तिकारी योजना लागू नही की गई। आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके है। अत' सभी शिक्षाविदो, शिक्षकों, राष्ट्रनेताओ तथा विद्वानों को गभीरता से विचार करना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा में कैसे परिवर्तन किए जाएं जिससे राष्ट्र प्रगति, विकास और एकता के पथ पर अग्रसर हो सके। अच्छे नागरिक, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, शासक, प्रशासक, लेखक, वक्ता, समाज सुधारक, राजनेता, सैनिक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, तकनीशियन सबका प्रारम्भिक निर्माण शिक्षण संस्थानो से ही होता है। राष्ट्रीय मशीन के सभी पुर्जे वही पर ढलते है।

हमे ऐसी शिक्षा प्रणाली तथा परीक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो छात्रो को वर्ष भर नियमित रूप से काम करने की प्रेरणा दे। उन्हें भाग्यवादी तथा अवसरवादी न बनाए। उन्हें सादगी और श्रम के संस्कारों से दीक्षित करके आत्मनिर्भर बनाए ताकि वे निर्भीक होकर राष्ट्रीय जीवन मे आगे बढ़ सकें। भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता के विरुद्ध आवाज उठा सकें। वे ट्यूशन, सिफारिश तथा अनुचित साधनों की ओर लोभित न हो। सफेदपोश रोजगारो के मोहताज न बने। माध्यमिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें एक क्रान्तिकारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें, राष्ट्रीय मूल्याकन पद्धति, राष्ट्रीय गणवेश तथा शिक्षको के लिए राष्ट्रीय चयन एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण की आवश्यकता है। युवको तथा युवतियो में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, वे जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे की दीवारो से ऊपर उठकर नए प्रजातांत्रिक समाज तथा पंथनिरपेक्ष भारत का

निर्माण कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

छात्रो तथा छात्राओ के सर्वागीण विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास, प्रतिरक्षा तथा एकता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता है। सस्ती सुलभ माध्यमिक शिक्षा का प्रकाश भारत के प्रत्येक कुटीर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देश में लगभग 90 हजार माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के होते हुए भी करोड़ों युवको तथा युवतियों को हाईस्कूल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अत. माध्यमिक शिक्षा को (कक्षा 6 से 10 तक) निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

जो दानवीर अपना धन तथा धरती भारत के बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करते हैं उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। नए हाईस्कूलों को मान्यता तथा आर्थिक सहायता देने में सरकार द्वारा उदारता की नीति अपनाई जानी चाहिए। हमारा लक्ष्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर निवेश करना होना चाहिए। शिक्षा के सरकारी बजट मे 70 प्रतिशत तक की राशि को शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छात्रों/छात्राओं को आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति इत्यादि पर व्यय करना न्याय सगत होगा। किन्तु कम से कम 30 प्रतिशत राशि शिक्षा के अन्य संसाधनों के विकास पर, शिक्षा के भावी विकास पर व्यय करना आवश्यक होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के साथ पर्याप्त भवन, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, वर्कशॉप, फ्लश शौचालय, पेयजल, वाचनालय, पुस्तकालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने के लिए छात्रों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ अस्थायी शिक्षक नियुक्त किए जा सकते है। गैर-सरकारी स्कूलों को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिया जाना चाहिए।

कक्षा 6 से 10 तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। किन्तु लगभग 100/- रुपए वार्षिक सामान्य शुल्क सभी छात्रों से प्रवेश के समय लिया जा सके तो विद्यालयों के चहुंमुखी विकास में सहायता मिलेगी। सत्र के अन्त में भी लगभग 100/- रुपए विकास शुल्क लेना न्याय सगत होगा। सभी भूमिहीन, सम्पत्तिहीन तथा स्थायी रोजगार से वंचित परिवारों के छात्रों को जिनकी पारिवारिक आय तथा जीवन स्तर निर्धारित सीमा से नीचे है इससे मुक्त रखना भी न्याय संगत होगा। सभी वार्षिक शुल्क विद्यालय के कार्यालय द्वारा दो किस्तों मे सत्र के आरम्भ तथा अन्त में लिए जा सकें तो शिक्षको तथा छात्रों का पूरा समय शिक्षण कार्यो में प्रयुक्त किया जा सकेगा। सभी सामान्य आर्थिक दण्ड, विलम्ब दण्ड तथा अनुपस्थिति दण्ड समाप्त किए जा सके तो कागजी काम पर्याप्त सरल हो जाएगा।

विद्यालय का दैनिक कार्य समय 6-30 घण्टे होना चाहिए जिसमें लगभग 40 मिनट का समय मध्यावकाश के लिए दिया जा सकता है। छात्र अपना लेखन कार्य विद्यालय में ही पूरा कर सके तो उनकी लेखन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकेगी।

आठ पीरियड का समय चक्र निर्मित किया जाना चाहिए। एक अतिरिक्त शून्य पीरियड दैनिक प्रार्थना, सामूहिक व्यायाम, भाषण, प्रवचन, राष्ट्र गान, योग शिक्षा इत्यादि के लिए निर्धारित होना चाहिए।

मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता

कक्षा 6 से 10 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन पद्धति का प्रसार किया जाना चाहिए जिससे अधिकांश छात्रो को प्रोन्नत किया जा सके तथा उसके योग्य भी बनाया जा सके। उन्हें वर्ष भर नियमित रूप से कार्य करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए जिससे वे ट्यूशन, सिफारिश तथा अनुचित साधनों की ओर लोभित न हों। भाग्यवादी अथवा अवसरवादी न बनें। हमे यह जानकर निराशा होती है कि भारत में कक्षा 1 मे प्रवेश लेने वाले 100 छात्रों मे से 10 वर्ष पश्चात् 10 छात्र ही कक्षा 10 में उत्तीर्ण हो पाते हैं। शेष 90 छात्र मार्ग मे ही भटक जाते हैं। कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ पढ़ाई मध्य में ही छोड़

देते है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है।

प्राईवेट ट्यूशन के रूप मे एक समान्तर शिक्षा प्रणाली का विस्तार हमारे देश मे तेजी से हो रहा है। विद्यालयों में छात्रों की भीड कम और अध्यापकों के घरों मे अधिक होती जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिए विद्यालयों मे शैक्षिक वातावरण मे सुधार, प्रमाणिक पाठ्यपुस्तकें, उपयोगी सहपाठ्यकर्मीय पुस्तकें, उच्च स्तर के मॉडल प्रश्न-पत्र तथा शिक्षा को समर्पित शिक्षकों की आवश्यकता है। मॉडल प्रश्नोत्तर तथा गाईड पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाकर हम गरीब छात्रों की शिक्षा को ही प्रतिबन्धित करते हैं। इससे प्राईवेट ट्यूशन को प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालयो में शिक्षक कठिनाई से पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। छात्रों को प्रश्नों के मॉडल उत्तर लिखने-लिखाने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। घरों में प्राईवेट ट्यूशन में भी छात्रो को उत्तरों की कार्बन कॉपी ही मिलती है। किन्तु अप्रमाणित पॉकेट पुस्तकों तथा निम्न स्तर की गाइड पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

प्रत्येक विद्यालय में प्रात. अथवा सायं विशेष ट्यूटोरियल कक्षाओ का आयोजन करके छात्रो को प्राईवेट ट्यूशन व घर-घर जाने के अभिशाप से बचाया जा सकता है। इसके लिए अल्प मात्रा में अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है। भारतीय शिक्षा की महान परम्पराओं को समर्पित कुछ शिक्षक रविवार या अन्य अवकाशों में अतिरिक्त कक्षाएं लेकर आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। नालन्दा, तक्षशिला और उज्जैन के शिक्षा केन्द्र हमारे प्राचीन आदर्श है। डाक्टर अमर्त्य सेन ने शिक्षा और समाज कल्याण के विषय में जो उद्गार प्रकट किए है उनसे राष्ट्र को प्रेरणा लेनी चाहिए। साधन सम्पन्न विद्यालयो में ग्रीष्मावकाश मे एक महीने तक विशेष ट्यूटोरियल कक्षाओं का आयोजन करके कमजोर छात्रो को राहत दी जा सकती है।

कक्षा 6 से 10 तक प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक 15 प्रतिशत निर्धारित कर दिए जाएं तो परीक्षाओं के विषय में राष्ट्रीय धारणा बदलेगी। राष्ट्र के समय, संसाधन तथा शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। शिक्षा का लक्ष्य छात्रों / छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। 15-33-45-60-100 के अन्तराल से ग्रेड निर्धारित किए जा सकते हैं। जो छात्र किसी विषय मे या सम्पूर्ण योगफल मे 15 प्रतिशत से अधिक और 33 प्रतिशत से कम अक प्राप्त करते हैं, उन्हें उत्तीर्ण के स्थान पर प्रोन्नत घोषित किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र का ग्रेड सभी विषयों के प्राप्तांकों के योगफल की प्रतिशत संख्या के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र का ग्रेड सभी विषयो के प्राप्तांकों के योगफल की प्रतिशत संख्या के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्रत्येक विषय में 10 प्रतिशत अंक वार्षिक लिखित कार्य, उपस्थिति, कक्षा मे अनुशासन तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर विषय अध्यापक द्वारा किए गए मूल्याकन के माध्यम से प्रदान किए जा सकें तो छात्रो/छात्राओ को वर्षभर नियमित रूप से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। कक्षा 9 तक सभी परीक्षाएं गृह परीक्षा के रूप मे आयोजित की जा सकती हैं। कक्षा 10 की विभागीय परीक्षा राज्य या केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। इस परीक्षा में कक्षा 9 तथा 10 का दो वर्षो का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए। कक्षा 10 की बोर्ड द्वारा सचालित परीक्षा में प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा के लिए 90 प्रतिशत अंक निर्धारित किए जा सकते है। शेष 10 प्रतिशत अंकों का आंकलन प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित कक्षा 10 के विषय अध्यापकों की एक समिति द्वारा किया जा सकता है। प्राइवेट छात्रों के लिए इन 10 प्रतिशत अकों का आंकलन प्रत्येक विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रो के आधार पर किया जा सकता है।

कक्षा 11 में उन्ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो हाईस्कूल परीक्षा में प्रत्येक विषय मे न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की श्रेणी में आते है। शेष छात्रो को प्रोन्नत की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसी भी विषय में 15 प्रतिशत से कम अक प्राप्त करने वाले छात्रो को अनुत्तीर्ण की श्रेणी मे रखा जा सकता है। इन्टरमीडिएट स्तर पर प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए। एन.सी.सी. प्रत्येक छात्र तथा छात्रा के लिए आवश्यक होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक युवक तथा युवती को राष्ट्र का सशक्त अनुशासित सैनिक बनाना इन्टरमीडिएट शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। जिन छात्रों को इन्टरमीडिएट स्तर पर प्रवेश नहीं मिलता वे पत्राचार पाठ्यक्रमो तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

कक्षा 11 तथा 12 में परीक्षाए बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। 33-45-60-100 के अन्तराल से यथावत 3 ग्रेड निर्मित किए जा सकते हैं। कक्षा 10, 11, 12 में जहां बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त करना उचित होगा। बोर्ड की परीक्षा से एक मास पूर्व प्रत्येक विद्यालय में एक पूर्व परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

सरस्वती के प्रांगण मे बालकों के कोमल मस्तिष्कों मे जात-पात, हरिजन-गैरहरिजन, सवर्ण-दलित, शूद्र-अभिजात्य, अगडे-पिछड़े, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक, आर्य-द्रविड़ इत्यादि शब्दों का भेदभाव प्रवेश न होने दे तो प्रजातान्त्रिक समाज तथा पंथ निरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए आधार तैयार किया जा सकेगा। हमे मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सभी धर्मो, सम्प्रदायों, जातियों, वर्गो तथा क्षेत्रों के लोग एकता, प्रेम और विश्वास के वातावरण मे रह सकें। कन्धे से कन्धा मिलाकर राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ सके। मिलकर भारत की पवित्र सीमाओ की रक्षा कर सकें।

शिक्षण संस्थाएं राष्ट्र की भावनात्मक एकता के प्रारम्भिक केन्द्र हैं। सभी विद्यालयो मे देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यदि सभी माध्यमिक विद्यालयो के मुख्य द्वार के साथ निम्न अभिलेख अंकित किए जाएं तो राष्ट्र की भावनात्मक एकता सुदृढ़ बनाई जा सकेगी–

"हमारे विद्यालय ही पंथ निरपेक्ष भारत के राष्ट्रीय पूजा स्थल है जहां विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायो, जातियों तथा वर्गो के बच्चे मिलकर एक साथ अध्ययन करते हैं। मिलकर खेलते, खाते और गाते हैं। मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढते हैं।

जब तक भारतीय विद्यालयों मे विभिन्न सम्प्रदायों, जातियों, वर्गो तथा क्षेत्रो के बच्चे मिलकर अध्ययन करते रहेंगे, मिलकर खेलते, खाते, गाते रहेंगे और एक साथ मिलकर प्रार्थना करते रहेगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे–तब तक संसार की कोई भी शक्ति भारत की एकता, अखण्डता और आजादी को चुनौती नहीं दे सकेगी।"

देश 21वीं शताब्दी मे आगे बढ़ रहा है। समय की आवश्यकता है कि एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में सुधार के लिए, उसे राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एक कार्यकारी राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत कर सके। यदि यह आयोग राष्ट्र की शिक्षा समस्याएं हल करने मे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सके तो राष्ट्र के भावी निर्माण में ऐतिहासिक सहायता मिलेगी। शिक्षा सुधरेगी। लोकतन्त्र सुधरेगा। देश सुधरेगा।

यदि हम सम्पूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करें, राष्ट्रीय जनसख्या नीति लागू करें, मेहनत, ईमानदारी और एकता से काम करें तो हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत के सभी समुदायों को सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन की बेड़ियों से मुक्त किया जा सकेगा। देश को जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता की राजनीति से मुक्त किया जा सकेगा। इसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्रो मे जातीय आधार पर आरक्षण तथा विशेष सुविधाए देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तदोपरान्त राष्ट्र के सभी धर्मो तथा सभी जातियो के सामान्य छात्रो को जातीय आरक्षण के स्थान पर राष्ट्र का आर्थिक सरक्षण देना न्याय सगत होगा। उस स्थिति में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक किसी भी छात्र की जाति अंकित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी सरकारी रिकार्ड में जाति का स्तम्भ समाप्त किया जा सकेगा। तभी हम भारतीय सविधान की निम्न आकांक्षा पूरी कर सकेगे–

"भारतीय गणराज्य में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग अथवा उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।" ❑❑

एच.ए.वी. इंटर कालेज
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

गृह-वातावरण के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन

❑ विभा निगम

उच्च एवं निम्न गृह-वातावरण के छात्र एवं छात्राओं के सन्दर्भ में अलग-अलग अध्ययन करने पर उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में अन्तर सार्थक नहीं पाया गया। जबकि निम्न स्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मध्यमानों में अन्तर सार्थक पाया गया अर्थात् निम्न स्तरीय गृह-वातावरण में जैसा वातावरण छात्रों को मिलता है वैसा छात्राओं को प्राप्त नहीं होता है। उच्च वर्गीय परिवारों की अपेक्षा मध्यमवर्गीय एवं निम्न वर्गीय गृह-वातावरण वाले परिवारों में सामान्यतः आज भी लड़कों को ही परिवार का भविष्य समझा जाता है।

व्यवसाय मानव जीवन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पक्ष है। बाल्यावस्था से उत्तरोत्तर प्रत्येक बालक अपने भावी जीवन के सन्दर्भ मे अनेक धारणाएं बनाने लगता है, जिसमें उसके भावी जीवन की व्यवसाय सम्बन्धी कल्पनाएं एवं धारणाएं सर्वोपरि होती हैं। बालक की इन कल्पनाओं की सरिता को इसी समय उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि अनुसार उचित प्रवाह / दिशा प्रदान किया जाना आवश्यक है क्योकि उसका भविष्य उसके वर्तमान पर निर्भर करता है।

वर्तमान युग व्यवसाय की दृष्टि से विशिष्टीकरण का युग है। नवीन तकनीकी और औद्योगिक विकास ने व्यावसायिक जगत को नूतन आयाम प्रदान कर अनेक व्यावसायिक क्षेत्र उपलब्ध करा दिए है। अत व्यवसाय का चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सभी व्यक्तियो के लिए स्व-निर्धारित प्रत्यय है। वे अपने भावी व्यवसाय का चयन अपनी भावी व्यावसायिक रुचियों के आधार पर करते हैं। वैसे तो बालक की व्यावसायिक रुचियों एवं भावी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं किन्तु विभिन्न शोध कार्यो से यह उद्घाटित होता है कि व्यावसायिक रुचियों के निर्धारण में बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं गृह-वातावरण की भूमिका सर्वोपरि होती है। गोयल (1967), देसाई (1974), सिन्हा (1978), हॉलैंड (1985), मौन्टगोमरी (1993) तथा फुलिग्नि (1996) आदि, जब कि कुछ शोध कार्य इसके विपक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध करते हैं कि वर्तमान समय में व्यावसायिक रुचियां आवश्यक नहीं कि अभिभावकों या पारिवारिक पृष्ठभूमि के व्यवसायों से प्रेरित हो। पसरीचा (1942), ग्रेवाल (1971), जोशी (1972), तथा साकानिका (1994)।

अत. ऐसी ही कुछ संशयात्मक परिस्थितियों के फलस्वरूप शोधार्थिनी के मस्तिष्क में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि विद्यालयों में छात्रों को समान शैक्षिक सुविधाएं, अधिगम अनुभव तथा समान वातावरण प्राप्त होने पर भी उनकी व्यावसायिक रुचियों एवं क्षमताओ मे भिन्नता का क्या कारण है? तथा बालकों के गृह-वातावरण एवं उनकी व्यावसायिक रुचियों के मध्य कैसा सम्बन्ध है? किस प्रकार का गृह-वातावरणीय प्रभाव बालकों में कैसी व्यावसायिक रुचियो का बीजारोपण करता है? उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में ही निम्न समस्या पर शोध कार्य किया गया है।

समस्या कथन

'गृह-वातावरण के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन'

अध्ययन के उद्देश्य

- विद्यार्थियों के गृह-वातावरण का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियो की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन करना।
- गृह-वातावरण के परिप्रेक्ष्य मे विद्यार्थियो की व्यावसायिक रुचियो का अध्ययन करना।
- गृह-वातावरण के परिप्रेक्ष्य मे छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

- छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों मे कोई अन्तर नहीं होता है।
- छात्र एव छात्राओं की व्यावसायिक रुचियो पर उनके गृह-वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यादर्श का चयन

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु आगरा जनपद के बारहवीं कक्षा के 300 छात्र एवं छात्राओं को यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चयनित किया गया है।

अध्ययन-उपकरण—विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण को ज्ञात करने हेतु बीना शाह द्वारा निर्मित 'पारिवारिक परिवेश मापनी' तथा उनकी व्यावसायिक रुचियो का मापन करने हेतु एस. पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित 'व्यावसायिक रुचि प्रपत्र' का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय प्रविधियां—प्रदत्त विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग किया गया है। छात्र-छात्राओं को निम्नस्तरीय एवं उच्चस्तरीय गृह-वातावरण के अन्तर्गत वर्गीकृत करने हेतु प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश (Q_1 and Q_3) की गणना की गई है।

परिणाम एवं व्याख्या—वर्तमान अध्ययन में जिन उद्देश्यो को लेकर प्रदत्तो का विश्लेषण किया गया उनसे प्राप्त उपलब्धियां एवं निष्कर्ष निम्न हैं—

विद्यार्थियों के गृह-वातावरण का अध्ययन— गृह-वातावरण मापनी पर प्राप्त छात्रों का औसत मान (M = 122), छात्राओ का औसत मान (M = 123) से अधिक है तथा दोनो में गृह-वातावरण के अन्तर की सार्थकता की जांच हेतु ज्ञात किया गया क्रान्तिक अनुपात मान (CR = 2.43) 0 05 स्तर पर सार्थक पाया गया।

अत. कहा जा सकता है कि आज भी व्यावहारिक रूप मे परिवारों में लडकियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक स्नेहपूर्ण, प्रोत्साही एवं सुरक्षापूर्ण पारिवारिक वातावरण प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए भी सम्भव है क्योकि भारतवर्ष में आज भी अभिभावक लडकों को व्यावसायिक एव आर्थिक रूप से व्यवस्थित करने की दिशा मे अधिक चिन्तित रहते है।

उच्च एवं निम्न गृह-वातावरण के छात्र एव छात्राओं के सन्दर्भ में अलग-अलग अध्ययन करने पर उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र एवं छात्राओ मे अन्तर सार्थक नही पाया गया (CR = 1.38)। जबकि निम्न स्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मध्यमानों में अन्तर सार्थक (CR = 25.66) पाया गया। अर्थात् निम्न स्तरीय गृह-वातावरण मे जैसा वातावरण छात्रों को मिलता है वैसा छात्राओं को प्राप्त नहीं होता है। उच्च वर्गीय परिवारों की अपेक्षा मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय गृह-वातावरण वाले परिवारों में सामान्यतः आज भी लड़को को ही परिवार का भविष्य समझा जाता है।

विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन—प्रतिदर्श मे सम्मिलित विद्यार्थियों के व्यावसायिक रुचि प्रपत्र द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में प्रबन्धक क्षेत्र (M = 11 8) में सर्वाधिक रुचि प्रदर्शित करते हुए इसे वरीयता क्रम में प्रथम स्थान तथा वैज्ञानिक (M = 11.5), सामाजिक (M = 11 04), कला (M = 10 7) क्षेत्रों को क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान तथा हृदयग्राही, (M = 9 98), गृह-निपुणता (M = 9 97), वाणिज्य (M = 7 29) तथा साहित्यक (M = 7 25) क्षेत्रों में विद्यार्थियो की रुचियां सामान्यतः औसत स्तर की पाई गई जबकि कृषि (M = 6 28) एवं रचनात्मक (M = 5 79) क्षेत्रो के सदर्भ मे विद्यार्थियो की रुचियां अति निम्न पाई गई।

छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों के मध्य अन्तर देखने पर मुख्य रूप से गृह-निपुणता एवं कला क्षेत्रों के मध्य क्रान्तिक अनुपात मान क्रमश. 10 76 तथा 2. 76 प्राप्त हुआ। जिसमें 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया तथा वाणिज्य, रचनात्मक एवं सामाजिक क्षेत्रों के मध्य क्रान्तिक अनुपात मान क्रमश. 2.47, 2 02 तथा 1.98 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया जबकि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में दोनों वर्गो की

व्यावसायिक रुचियां लगभग समान स्तर की थी।

छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों में जिन क्षेत्रो में सार्थक अन्तर ज्ञात हुआ है उनमे छात्र और छात्राओ के मध्यमान मानों से स्पष्ट होता है कि छात्राओ ने जहा गृह-निपुणता, सामाजिक, कला एवं रचनात्मक क्षेत्रो के व्यवसायों को छात्रों की अपेक्षा अधिक मान्यता दी है वहीं छात्रो ने वाणिज्य क्षेत्र के व्यवसायों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया है।

अत. यह स्पष्ट होता है कि छात्र एवं छात्राएं व्यावसायिक रुचियो के दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर रखते है। अत' प्रथम परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

गृह-वातावरण के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन

उच्च स्तरीय गृह-वातावरण के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियां— उच्च स्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के विद्यार्थियों के व्यावसायिक रुचि प्रपत्र पर प्राप्त प्राप्तांको मे सर्वाधिक मध्यमान (M = 12.93) कला क्षेत्र के सन्दर्भ में प्राप्त हुआ। अत. कला क्षेत्र को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान तत्पश्चात् सामाजिक प्रबन्धन एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रमशः द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान तथा अन्य क्षेत्रों मे विद्यार्थियों की रुचिया औसत स्तर की हैं जबकि कृषि (M = 7.29) एवं रचनात्मक (M = 6 47) क्षेत्र के व्यवसायों में उच्चस्तरीय गृह-वातावरण के छात्रों की रुचियां निम्न स्तरीय पाई गई।

उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र एवं छात्राओ की व्यावसायिक रुचियों के मध्य अन्तर देखने पर सर्वाधिक अन्तर गृह-निपुणता क्षेत्र स्तर पर (C R. = 4 24, 0 01 स्तर पर सार्थक) के मध्य पाया गया। इसके अतिरिक्त कृषि, कला, एव प्रबन्धक क्षेत्र के मध्य भी छात्र एव छात्राओ की रुचियों में 0 05 स्तर पर अन्तर सार्थक पाया गया। जिसमें गृह-निपुणता एवं कला क्षेत्र के व्यवसायों मे छात्राएं तथा प्रबन्धन एवं कृषि क्षेत्र के व्यवसायो को छात्र अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्रदान करते हैं। शेष अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में छात्र एव छात्राओ की व्यावसायिक रुचियां लगभग समान स्तर की पाई गई।

निम्न स्तरीय गृह-वातावरण के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियां— निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के विद्यार्थियों के व्यावसायिक रुचि प्रपत्र पर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रो में प्राप्त प्राप्तांको में सर्वाधिक मध्यमान (M = 11 96) गृह-निपुणता क्षेत्र के सन्दर्भ मे प्राप्त हुआ। अत. इसे वरीयता क्रम के प्रथम स्थान प्रदान किया गया तथा सामाजिक, कला एव प्रबन्धक क्षेत्र के व्यवसायो को क्रमश. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रो में इनकी रुचिया लगभग सामान्य स्तर की पाई गई जबकि न्यूनतम मध्यमान रचनात्मक (M = 6.2) एवं वाणिज्य (M = 6.43) क्षेत्र के व्यवसायो मे प्राप्त हुए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्रो के व्यवसायों में विद्यार्थियों की रुचियां निम्न स्तरीय हैं।

निम्नस्तरीय गृह-वातावरण के छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों के मध्य अन्तर देखने पर सर्वाधिक अन्तर गृह-निपुणता (C R = 7 6) तथा साहित्य (C R = 3 33) सम्बन्धी क्षेत्रो मे पाया गया जो 0 01 स्तर पर सार्थक था। इसके अतिरिक्त कला क्षेत्र (C.R = 2.01) मे यह अन्तर 0.05 स्तर पर सार्थक पाया गया। इन तीनो ही क्षेत्रो के व्यवसायों को छात्रों की अपेक्षा छात्राए अधिक वरीयता प्रदान करती है जबकि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में दोनों वर्गो की रुचिया लगभग समान स्तर की पाई गई।

उच्च एवं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियो का तुलनात्मक अध्ययन—उच्च एव निम्नस्तरीय गृह-वातावरण के विद्यार्थियो की व्यावसायिक रुचियो मे हृदयग्राही, प्रबन्धन, वाणिज्य एवं वैज्ञानिक क्षेत्रो के सन्दर्भ मे दोनों समूहों में सार्थक अन्तर पाया गया। इन सभी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के विद्यार्थी अपेक्षाकृत उच्च रुचि रखते हैं।

उच्चस्तरीय तथा निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्रों की व्यावसायिक रुचियों में हृदयग्राही कृषि, वैज्ञानिक, एवं प्रबन्धन क्षेत्र के सन्दर्भ में दोनों समूहों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। इन क्षेत्रो के मध्यमान मानों से यह भी स्पष्ट हुआ कि इन चारों ही क्षेत्रो मे उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वाले छात्र अपेक्षाकृत अधिक रुचि रखते हैं।

छात्राओ की दृष्टि से उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय दोनों ही वर्गों की छात्राओं की व्यावसायिक रुचियो में प्रबन्धन (C R = 2 04), वैज्ञानिक (C.R = 2 02) गृह-निपुणता (C.R = 2 02) तथा कला (C R = 2 01) क्षेत्रों के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों के मध्यमान मानों से भी यह स्पष्ट होता है कि जहा प्रबन्धन, वैज्ञानिक एव कला क्षेत्र में उच्चस्तरीय

गृह-वातावरण वाली छात्राए उच्च रुचि रखती हैं वहीं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वाली छात्राएं गृह-निपुणता क्षेत्र के व्यवसायों को अधिक वरीयता प्रदान करती हैं।

अत. निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि गृह-वातावरण की दशाए विद्यार्थियो की व्यावसायिक रुचियो को प्रभावित करती हैं जिसका प्रमाण है उच्च स्तरीय एव निम्नस्तरीय गृह-वातावरण के छात्र एवं छात्राओ की विभिन्न व्यावसायिक रुचि क्षेत्रों के मध्य विद्यमान सार्थक अन्तर। अत॰ इस आधार पर द्वितीय परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष

उपर्युक्त शोध उपलब्धियों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए--

- ☐ छात्र एवं छात्राओ की गृह-वातावरणीय परिस्थितियों में अन्तर होता है जिसमें छात्रों की स्थिति परिवार में अधिक स्वीकारात्मक होती है।
- ☐ विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियो की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रबन्धन, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं कला क्षेत्र के व्यवसाय सम्मिलित है।
- ☐ छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों मे अन्तर पाया जाता है। जिसमे छात्र जहां मुख्य रूप से प्रबन्धन, वैज्ञानिक एव वाणिज्य क्षेत्र के व्यवसायों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान करते हैं। वही छात्राए गृह-निपुणता, सामाजिक एवं कला क्षेत्र के व्यवसायों को अधिक पसन्द करती हैं।
- ☐ उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचियो में अन्तर पाया जाता है।
- ☐ उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र जहा प्रबन्धकीय वैज्ञानिक एव हृदयग्राही जैसे उच्च व्यावसायिक क्षेत्रो में अधिक रुचि रखते हैं वहीं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग के छात्र मुख्य रूप से कला एवं सामाजिक क्षेत्रों के व्यवसायों मे अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं।
- ☐ उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग की छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों में भी अन्तर पाया जाता है। उच्चस्तरीय गृह-वातावरण वर्ग की छात्राए जहां आधुनिकता का परिचय देते हुए प्रबन्धकीय एव वैज्ञानिक क्षेत्रों के व्यवसायों को अधिक महत्व देती हैं वहीं निम्नस्तरीय गृह-वातावरण वाली छात्राए परम्परागत रूप से गृह-निपुणता, सामाजिक एवं कला क्षेत्रो के व्यवसायो में अधिक रुचि रखती हैं।

अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता

अभिभावकों हेतु महत्व एवं सुझाव— आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को भावी जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पक्ष जैसे परिवार, समाज तथा व्यवसाय आदि में स्वस्थ समायोजन हेतु तैयार किया जाए। इस सन्दर्भ मे सुझाव है कि वे अपने पारिवारिक वातावरण को स्वस्थ बनाएं तथा लड़के और लड़कियो को समान स्नेह, अवसर, प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करें। अभिभावक बाल्यकाल से ही बच्चो के व्यवसाय के सन्दर्भ में स्वय ही योजनाएं न बनाएं और न ही अपनी अपूर्ण व्यावसायिक आकाक्षाओं की पूर्ति अपने बच्चों के माध्यम से करने का प्रयास करें वरन् बच्चो की रुचियो, क्षमताओं और कौशलों को पहचानें, इनका विकास करें तथा इससे सम्बन्धित शैक्षिक और भौतिक सुविधाएं प्रदान करें तभी बालक की अन्तर्निहित क्षमताओं और योग्यताओं का ईष्टतम उपयोग हो सकेगा तथा बालक भविष्य में पूर्ण रूप से समायोजित हो सकेगा।

शिक्षकों हेतु महत्व एवं सुझाव— इस शोध से यह आवश्यकता अनुभव होती है कि वर्तमान समय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उपयुक्त व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए जिसके अन्तर्गत उन्हें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रो की कार्य प्रकृति, उनमें अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता एवं प्रशिक्षण आदि से परिचत कराया जाए जिससे वे अपनी रुचि के अनुसार अपनी भविष्यगत शैक्षिक योजनाएं निर्धारित कर भविष्य मे उपुक्त व्यवसाय का चयन कर सके। शिक्षक भी बालको की रुचियों और क्षमताओं को जानकर उनकी योग्यताओं और कौशल को पहचाने तथा उनका समुचित विकास करने का प्रयास करें। ☐☐

शिक्षा संकाय
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश

विद्यालयी प्रार्थना की आवश्यकता एवं इसके प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

❑ सुनील कुमार सिंह
❑ मुकेश कुमार

दिन का काम प्रार्थना से शुरू कीजिए और उसमें इतनी आत्मा उंडेलिए कि वह शाम तक आपके साथ बनी रहे। दिन का अन्त भी प्रार्थना के साथ कीजिए ताकि आपकी रात शांतिपूर्ण तथा स्वप्नों और दुःस्वप्नों से मुक्त रहे। प्रार्थना के स्वरूप की चिंता न कीजिए। स्वरूप कुछ भी हो, वह ऐसा होना चाहिए, जिससे भगवान के साथ हमारे मन की लौ लग जाए। इतना ध्यान रखिए कि स्वरूप कैसा भी हो, मगर आपके मुंह से प्रार्थना के शब्द निकलते समय आपका मन इधर-उधर न भटकने पाए।

भारतीय परंपरा मे आत्मोन्नति हेतु परंपरागत मान्यता के अनुसार प्रार्थना का स्थान सर्वोपरि रहा है। अतः व्यक्तिगत एव सामाजिक हित हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो ही रूपो मे हमारे समाज मे प्रार्थना का प्रचलन प्राचीन काल से ही है। आधुनिक समाज में भी यह इसी प्रकार प्रचलित है। बीसवीं शताब्दी के शांति दूत महात्मा गांधी ने भी इसके महत्व का अनुभव किया। उनके अनुसार–

> "....दिन का काम प्रार्थना से शुरू कीजिए और उसमे इतनी आत्मा उडेलिए कि वह शाम तक आपके साथ बनी रहे। दिन का अन्त भी प्रार्थना के साथ कीजिए ताकि आपकी रात शांतिपूर्ण तथा स्वप्नों और दुःस्वप्नो से मुक्त रहे। प्रार्थना के स्वरूप की चिंता न कीजिए। स्वरूप कुछ भी हो, वह ऐसा होना चाहिए, जिससे भगवान के साथ हमारे मन की लौ लग जाए। इतना ध्यान रखिए कि स्वरूप कैसा भी हो, मगर आपके मुंह से प्रार्थना के शब्द निकलते समय आपका मन इधर-उधर न भटकने पाए।"

(भाषण साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में)
"सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय, 42.424-6, 17-1-1930"

अतः प्रार्थना के उपरोक्त महत्व को स्वीकार करके ही उसे विद्यालयो मे दैनिक क्रिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसे निर्विवाद रूप से प्रत्येक विद्यालय मे स्वीकार किया गया है चाहे विद्यालय राज्य, व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष द्वारा ही पोषित क्यों न हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने भी अपने प्रतिवेदन में यह सुझाया है कि "प्रत्येक विद्यालय की दिनचर्या का आरम्भ शिक्षको व छात्रो की असेम्बली से होना चाहिए जहां प्रतिदिन के कार्यों की घोषणा होती हो। इस सभा का सदप्रयोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रेरणास्पद वार्तालाप से किया जाना चाहिए।" श्री प्रकाश समिति (1956) ने प्राथमिक स्तर पर इसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहा कि "प्रतिदिन की सभा में प्राथमिक विद्यालयों मे समूह-गान, सरस कहानियां, महापुरुषों की जीवनी दर्शाने वाली दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि का प्रदर्शन

किया जाना चाहिए।" इन समस्त सुझावों के अनुरूप विद्यालयी प्रार्थना आयोजित की जाती रही है अथवा नहीं? यह स्पष्ट रूप से कहना तो कठिन है, परन्तु समस्त विद्यालयों में प्रार्थना का आयोजन अनिवार्य रूप में किया जाता रहा है। यह प्रार्थना विगत कुछ वर्षो में विवाद के घेरे मे अवश्य आई है, जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्टो से स्पष्ट होता है—

राष्ट्रीय सहारा (1998) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार—

".. ......वंदे मातरम् आवश्यक रूप से गाए जाने के कथित निर्णय के बाद ऑल इडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अब्दुल हसन अली नकवी ने मुसलमानो से अपने बच्चो को ऐसे स्कूलों से हटा लेने का अनुरोध किया जहा वदेमातरम् का गाया जाना अनिवार्य है।"

सहारा समाचारः राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 22 नवम्बर, 1998, पृ 1

जनसत्ता (1998) में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार—

"..... हरिद्वार के साधु-सन्तों ने फतवा जारी कर ऐलान किया है कि जिन स्कूलो में वंदेमातरम् और सरस्वती वदना नही होती है, उन स्कूल/कालेजो मे हिन्दू सम्प्रदाय अपने बच्चो का दाखिला न कराए और अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों मे पढ़ने भेजे जहां भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दी जाती हो।"

जनसत्ता ब्यूरो— जनसत्ता, नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1998 पृ. 2।

उपरोक्त सन्दर्भो से यह स्पष्ट होता है कि समाज में प्रार्थना के स्वरूप को लेकर एक मत नहीं है। प्रार्थना के स्वरूप एवं इसके प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुमार (1975) के अनुसार अधिकांश प्रचलित प्रार्थनाओं में, ".....आजाद भारत की स्तुति इस तरह नहीं है कि बच्चे पुराने और नए भारत का अतर जान सकें— यह स्तुति मातृभूमि के नाम से है या भारत की शाश्वत कही जाने वाली सास्कृतिक धरोहर के नाम से। ..." प्रार्थना के बिन्दु को केन्द्र में रखकर किए गए अन्य अध्ययन सारंगी (1994) व दिनमान दैनिक (1975) का है। अन्य अध्ययन नहीं है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों में प्रचलित प्रार्थना के दार्शनिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओ का विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। अतः प्रस्तुत अध्ययन को निम्न समस्या कथन के रूप में निर्धारित किया गया।

समस्या अभिकथन

चूकि प्राथमिक एव माध्यमिक कक्षाओं मे अध्ययनरत समस्त छात्रो को प्रार्थना हेतु निर्देशित किया जाता है, अतः वे अनुशासन भाव से उसमें भाग लेते हैं। परन्तु किशोरावस्था मे प्रविष्ट अधिकांश विद्यार्थी जो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनमें प्रार्थना के प्रति अवबोध एवं दृष्टिकोण का भी विकास हो जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन निम्न निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत किया गया—

"विद्यालयी प्रार्थना के प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति"

अध्ययन के उद्देश्य

उपरोक्त के सन्दर्भ में अध्ययन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए—

- उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओ को विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दू व मुसलमान विद्यार्थियों को स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दू विद्यार्थी व हिन्दू बहुल विद्यालयो मे पढ़ने वाले मुसलमान विद्यार्थियो की स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दू बहुल विद्यालयों मे पढ़ने वाले मुसलमान विद्यार्थियों व मदरसों में पढ़ने

वाले मुसलमान विद्यार्थियों को स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।

- उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला, विज्ञान व वाणिज्य के विद्यार्थियो को स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अंतर ज्ञात करना।
- उच्च्तर माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के एकल व संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियो की स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम व निम्न आय वर्ग की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की स्कूल प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे अन्तर ज्ञात करना।

प्रमुख पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

विद्यालयी प्रार्थना—इसका तात्पर्य विद्यालयों मे होने वाली प्रतिदिन की सामूहिक प्रार्थना से है।

अभिवृत्ति—प्रस्तुत अध्ययन मे इसका आशय थर्स्टन (1946) एव शेरगंज (1970) की अभिवृत्ति की परिभाषाओं से है। थर्स्टन (1946) के अनुसार, "अभिवृत्ति किसी एक मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति संबंधित धनात्मक अथवा ऋणात्मक भाव की मात्रा व्यक्त करती है।" शेरगंज (1970) के अनुसार, "अभिवृत्ति अनुभवो पर आधारित है और इसका विषय सदैव विशिष्ट रहता है...। अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को विषय-वस्तु की ओर प्रेरित करती है और प्रतिकूल प्रवृत्ति उससे दूर जाने के लिए प्रेरित करती है।"

आय स्तर—निर्धारित स्तर के अनुसार तीन आय समूह है— ● निम्न रु. 60,000 वार्षिक से नीचे, ● मध्यम रु. 60,000 से रु. 1,20,000 एवं ● उच्च रु 1,20,000 से अधिक।

अध्ययन की परिकल्पना

अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यो के सन्दर्भ में सांख्यिकीय परिपुष्टि के लिए क्रमश· आठ शून्य परिकल्पनाओं (Ho1, Ho2, Ho3, Ho4, Ho5, Ho6, Ho7, और Ho8) का निर्माण किया गया।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु "विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि" का प्रयोग किया गया। इसमें प्रयुक्त उपकरण, जनसख्या, प्रतिदर्श आदि का वर्णन नीचे दिया गया है।

उपकरण

प्रदत्तो के सग्रह हेतु सिह एस. के. (2001) के निर्देशन मे कुमार एम. (2001) द्वारा, "विद्यालय प्रार्थना अभिवृत्ति मापनी" विकसित की गई। यह "लिकर्ट मापनी" के आधार पर तैयार की गई। इसमें प्रार्थना सम्बन्धित पाच आयामो ● चरित्र-निर्माण, ● आस्था, ● अनिवार्यता, ● राष्ट्रीय एकता व सद्भाव एवं ● रुचि एव प्रेरणा से सम्बन्धित कुल 25 कथन सम्मिलित हैं, जिनको 52 कथनों के प्रथम प्रारूप से पद विश्लेषण के पश्चात् चयनित किया गया। 25 कथनो में 13 विधेयात्मक एवं 12 निषेधात्मक कथन है। स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफैसी सूत्र द्वारा प्राप्त इस मापनी का विश्वसनीयता गुणांक 0.86 है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या वाराणसी शहर के सत्र 2000-2001 में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी थे।

प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में "यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि" द्वारा प्रतिदर्श का चयन किया गया। इसमें वाराणसी शहर के, सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल (कमच्छा); सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल (कमच्छा); गुरुनानक खालसा बालिका इण्टर कालेज, गुरुबाग; मानवीय शिक्षा निकेतन, सकटमोचन; केन्द्रीय विद्यालय बी.एच.यू., हमीदिया रिज्विया, मदनपुरा एवं महमूद-उल-मजारिश मदनपुरा नामक 7 विद्यालय

सारणी 1

क्र.स.	उद्देश्य संख्या	शून्य परि-कल्पना सं.	विद्यार्थी अभिवृत्ति वर्ग	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर सार्थकता
1	1	1	छात्र	80	60.95	7 598	4 0842	सार्थक
			छात्रा	70	65 071	4 589		
2	2	2	हिन्दू	120	64 05	5 4961	6.959	सार्थक
			मुसलमान	30	58.166	3 728		
3	3	3	हिन्दू	120	64 05	1.036	169.31	सार्थक
			मुसलमान (हिन्दू बहुल विद्यालय मे)	11	47.272	0 9958		
4	4	4	मुसलमान (हिन्दू बहुल विद्यालय मे)	11	47 27	3 77	13 6833	सार्थक
			मुसलमान (मदरसो मे)	19	64.47	2 347		
5.	6	6	शहरी	119	62.394	8 754	1.848	सार्थक नहीं
			ग्रामीण	31	64.709	5.354		
6	7	7	एकल परिवार से	86	63 488	5.365	1 550	सार्थक नहीं
			संयुक्त परिवार से	64	62.046	5 829		

सारणी 2

क्र.स.	उद्देश्य संख्या	शून्य परि-कल्पना स.	प्रसरण स्रोत	डी एफ	वर्गों का योग	माध्य	एफ मान	.05 स्तर पर सार्थकता
1.	5	5	एस एस एम.	2	239 62	119 81	2.875	सार्थक नहीं
			एस एस डब्ल्यू	147	6247 58	42.54		
2.	8	8	एस एस.एम	2	229.97	114.985	2.308	सार्थक नहीं
			एस एस डब्ल्यू	147	7320.58	49.80		

चयनित किए गए। अध्ययन के विभिन्न आधारो के अनुसार विश्लेषण करने पर पाया गया कि प्रतिदर्श में कुल संख्या इस प्रकार थी— छात्राएं (70), छात्र (80), हिन्दू (120), मुस्लमान (30), मदरसा के मुसलमान विद्यार्थी (19), हिन्दू बहुल विद्यालयो में मुसलमान विद्यार्थी (11), कला विद्यार्थी (75), विज्ञान (56), वाणिज्य (19), शहरी विद्यार्थी (119), ग्रामीण (31), एकल परिवार के विद्यार्थी (86), संयुक्त परिवार के (64), उच्च आय वर्ग (26), मध्यम आय वर्ग के (46) एव निम्न आय वर्ग के 78 विद्यार्थी थे।

अंकीकरण

मापनी के कथनो पर प्राप्त उत्तरों के अंकीकरण हेतु, कथनों को क्रमशः सहमत, अनिश्चित व असहमत के सातत्य पर 3, 2 व 1 अंक प्रदान किए गए। निषेधात्मक कथनों को सहमत, अनिश्चित व असहमत के सातत्य पर क्रमश- 1 2 व 3 अंक प्रदान किए गए। इस आधार पर अंकीकरण किया गया एव उनके योग द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुल अभिवृत्ति प्राप्ताक ज्ञात किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित शून्य परिकल्पनाओं की साख्यिकीय परिपुष्टि हेतु अभिवृत्ति प्राप्तांको के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी एव एफ टेस्ट का प्रयोग किया गया। प्राप्त टी एवं एफ मान को उद्देश्यों एव उनसे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना के सन्दर्भ मे सारणी 1 एव 2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1 एवं 2 के आधार पर टी मान "एफ मान" एवं अभिवृत्ति अंक मध्यमान के विश्लेषण करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए जो क्रमश· उद्देश्यों एव शून्य परिकल्पना के आधार पर दिए गए है—

- ☐ उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति छात्रों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
- ☐ उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दू विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मुसलमान विद्यार्थियों से अधिक सकारात्मक है।
- ☐ उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिन्दू विद्यार्थियो की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति बहुल विद्यालयो के मुसलमान विद्यार्थियो से अधिक सकारात्मक है।
- ☐ उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसो के मुसलमान विद्यार्थियों की हिन्दू बहुल विद्यालयों के मुसलमान विद्यार्थियो की तुलना में विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक है।
- ☐ उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला, विज्ञान व वाणिज्य के विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विद्यालयी प्रार्थना के प्रति इनकी अभिवृत्ति समान है।
- ☐ शहरी व ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विद्यालयी प्रार्थना के प्रति इनकी अभिवृत्ति समान है।
- ☐ एकल और संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियो की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विद्यालयी प्रार्थना के प्रति इनकी अभिवृत्ति समान है।
- ☐ उच्च, मध्यम व निम्न आय वर्ग की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वियालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विद्यालयी प्रार्थना के प्रति इनकी अभिवृत्ति समान है।

निष्कर्ष एवं निहितार्थ

प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित परिणाम 1 के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि—

निष्कर्ष 1—लैगिक स्तर पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है। छात्रों की तुलना मे प्रार्थना के प्रति छात्राओ की अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक है।

निहितार्थ—छात्राओ का अभिवृत्ति मापनी पर आस्था सम्बन्धित कथनो के प्राप्तांकों के अवलोकन से यह ज्ञात

होता है कि छात्राओ को सामाजिक परम्पराओ के प्रति छात्रों की अपेक्षा अधिक आस्था है। सम्भवतः यही कारण है कि छात्राओं की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति छात्रो से अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति है।

द्वितीय एव तृतीय उद्देश्य से सम्बन्धित परिणाम 2 एवं 3 के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि–

निष्कर्ष 2–धर्म के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है। मुसलमान विद्यार्थियों की तुलना में प्रार्थना के प्रति हिन्दू विद्यार्थियों की अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक है। अभिवृत्ति के अन्तर का यही प्रतिरूप (पैटर्न) हिन्दू बहुल विद्यालयों के हिन्दू व मुसलमान विद्यार्थियों के भी मध्य है।

निहितार्थ–उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक (हिन्दू) विद्यार्थियों को विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति अल्पसंख्यक (मुसलमान) विद्यार्थियों की तुलना मे अधिक सकारात्मक है। अतः "धर्मनिरपेक्षता" के संवैधानिक मूल्य के अनुरूप राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में विद्यालयी प्रार्थना के शब्द, स्वरूप एवं पद्धति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अध्ययन के चौथे उद्देश्य से सम्बन्धित परिणाम 4 के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि–

निष्कर्ष 3–मदरसा के उच्चतर माध्यमिक स्तर के मुसलमान विद्यार्थियों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति हिन्दू बहुल विद्यालयो मे पढ़ने वाले मुसलमान विद्यार्थियों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।

निहितार्थ–उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय की प्रकृति का विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति के निर्धारण में अहम् योगदान है। अतः विशेषकर अल्पसंख्यक विद्यालयों में कराई जाने वाली प्रार्थना का संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में, प्रार्थना के शब्द, स्वरूप एवं पद्धति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

अध्ययन के पाचवे, छठे, सातवें एवं आठवें उद्देश्य से संबंधित परिणाम संख्या पाच, छ, सात एव आठ के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि–

निष्कर्ष 4–उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन विषय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार का स्वरूप तथा पारिवारिक आय का स्तर इत्यादि उनकी विद्यालयी प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित नहीं करते है एवं इन सभी चरो से स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों की प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति एक समान है।

निहितार्थ–उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न विषयो, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्वरूप व पारिवारिक आय वाले उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी भी विद्यालयी प्रार्थना के प्रति एक समान अभिवृत्ति रखते है। अत. इन सभी चरों की विद्यालयी प्रार्थना के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति निर्धारण में मुख्य भूमिका नहीं है।

मुख्य निहितार्थ

उपरोक्त समस्त निष्कर्षो एव निहितार्थों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी दिनचर्या की प्रारंभिक व आवश्यक क्रिया "विद्यालयी प्रार्थना" के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को लिग, धर्म व विद्यालय की प्रकृति जैसे चर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अत· आधुनिक भारत में यह आवश्यक है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राष्ट्रीय हित को केन्द्र में रखकर सभी विद्यालयों में कराई जाने वाली प्रार्थना को विषय-वस्तु, शब्द, स्वरूप व पद्धति का पुनर्मूल्यांकन करके ही उसे लागू किया जाए। ❑❑

शिक्षा संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
कमच्छा, वाराणसी

बाल अपराध–कारण व निवारण

❑ एकता भाटिया
❑ ज्योति भाटिया

बाल अपराध समाज का जटिल व्यवहार है। भारतवर्ष में बाल अपराध कोई आज की समस्या नहीं है। कानूनों का उल्लंघन चाहे बालकों द्वारा हो या वयस्कों द्वारा एक राष्ट्रीय समस्या है। समाज विरोधी कार्य करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की आयु अब 7 वर्ष से 16 वर्ष के बीच और बालिकाओं के लिए यह आयु 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

बाल अपराध समाज का जटिल व्यवहार है। भारतवर्ष में बाल अपराध कोई आज की समस्या नही है। कानूनो का उल्लघन चाहे बालको द्वारा हो या वयस्कों द्वारा एक राष्ट्रीय समस्या है। समाज विरोधी कार्य करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियो की आयु अब 7 वर्ष से 16 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है बालिकाओं के लिए यह आयु 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

सयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय प्रोबेशन समिति ने बाल अपराधी की परिभाषा निम्न रूप में की है–

- ❑ वह बालक जिसने राज्य के किसी कानून या धारा अथवा राज्य के उपविभाग के किसी कानून को तोडा हो।
- ❑ वह बालक जो आवारा होने अथवा आदतन अनाज्ञाकारी होने के कारण अपने माता-पिता या संरक्षक के नियत्रण से बाहर हो।
- ❑ वह बालक जो आदतन रूप से स्कूल या घर से भागने वाला हो।
- ❑ वह बालक जो अपने को आदतन इतना बिगाड़ता है कि अपने या दूसरे के स्वास्थ्य अथवा नैतिकता को खतरा अथवा चोट पहुचा सकता हो।

मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक गतिकी के आधार पर बाल अपराधियों को पाच समूहों में वर्गीकृत किया है–मानसिक रूप से दोषपूर्ण, मानसिक रूप से पीडित, नाड़ी रोग से पीड़ित, परिस्थितिजन्य व सांस्कृतिक। भारत में आज कुल सज्ञेय अपराध का लगभग 2 प्रतिशत बाल अपराध हैं तथा 1988 से पहले यह प्रतिशतता लगभग चार थी। बाल अपराध 1978 और 1988 के बीच लगभग 25 प्रतिशत बढा परतु 1988 में आई. पी. सी. के अन्तर्गत यह 1987 की तुलना में 53 प्रतिशत कम होकर स्थानीय व विशेष कानूनो के अन्तर्गत यह 70 प्रतिशत घट गया।

भारत में बाल अपराध की दरें लड़कियों की अपेक्षा लड़को में बहुत अधिक है। इसी प्रकार अपराध की दरे प्रारम्भ की किशोरावस्था (12-16 वर्षो की आयु समूह) में सबसे ऊंची है। राज्यवार विवरण मे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाल अपराध 3396 (आई.पी.सी) दर्ज किए गए, दूसरा स्थान 2806 बाल अपराध संख्या के साथ मध्य प्रदेश का था। स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत सर्वाधिक बाल अपराध तमिलनाडु में 63.5 प्रतिशत हुए थे। 6 राज्यों व 5 केन्द्र शासित प्रदेशो व 4 नगरो

में कोई बाल अपराधी नही पाया गया। बाल अपराध एक ग्रामीण तथ्य होने की अपेक्षा नगरीय तथ्य अधिक है। इसी प्रकार अधिकांश बाल अपराधी निरक्षर व कम शिक्षित होते है। लगभग 42 प्रतिशत निरक्षर, 52 प्रतिशत प्राथमिक, मिडिल व सैकेन्डरी कक्षाए पास किए हुए होते हैं व बहुत ही कम सख्या 6 प्रतिशत हाईस्कूल व उसके आगे तक शिक्षित होते हैं। निम्न वर्ग मे बाल अपराध अधिक घटित होते है।

बाल अपराध विभिन्न ढग के आचरण या व्यवहार के तरीके प्रदर्शित करता है। हावर्ड बेकर (1966) ने बाल अपराध के चार प्रकार बताए हैं प्रथम—व्यक्तिगत बाल अपराध जो दोषपूर्ण, अनुचित, रोगात्मक, पारिवारिक अन्तःक्रिया के समरूपो से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओ के कारण होता है। द्वितीय श्रेणी, दूसरों की संगति में किए जाने वाले अपराधों की है। तृतीय, संगठित बाल अपराध औपचारिक रूप से संगठित गुटों को विकसित करके किए जाते हैं। चतुर्थ, परिस्थितिवश अपराध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, यह अवधारणा अविकसित सी है।

बच्चों के अपराधो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक दो समूहो मे विभाजित किए जा सकते हैं—व्यक्तिगत कारक और परिस्थिति सबंधी कारक। बाल अपराध के विकास मे परिवार को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

काफमैन (1959), बर्मन(1964), आमस्ट आईहार्न(1969) जैसे मनोवैज्ञानिक अपराधो के कारणो में मुख्यतया बचपन के अनुभवों, भावात्मक वचनो, बच्चे के पालने की प्रक्रियाओ—जो व्यक्तिगत निर्माण को प्रभावित करते हैं, महत्व देते हैं।

छिन्न-भिन्न परिवार, पारिवारिक तनाव, माता-पिता द्वारा अस्वीकृति, माता-पिता का नियंत्रण और पारिवारिक आर्थिक स्थिति, बाल अपराध उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले क्षेत्र, जहां मनोरंजन का अपर्याप्त सुविधाएं होती हैं, बच्चों के खेलने की प्राकृतिक प्रबल इच्छाओं का दमन करते हैं और अपराधी गिरोहों के बनने को प्रोत्साहित करते हैं। सिनेमा व कॉमिक पुस्तकें बच्चों व किशोरों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते है। हमारे देश के विभिनन भागों से कई बच्चे साधारण चोरी, सेध लगाकर चोरी और अपहरण करने के लिए उन्हीं शैलियों का उपयोग करने पर गिरफ्तार किए जाते हैं। इन चलचित्रों से ऐसी मनोवृत्तिया बन जाती हैं जो सरलता से पैसा बनाने की इच्छाओ को जागृत करके, उसकी प्राप्ति के लिए सदिग्ध तरीके सुझाकर अपने को जोखिम में डालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, काम वासनाओ को भड़का कर व दिवास्वप्न देखने की आदत बनाकर अपराधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं।

समाधान में परिवार, समाज व विद्यालय की भूमिका

बाल अपराध ऐसी समस्या नही है जिसे हल न किया जा सके किन्तु इस समस्या के समाधान मे परिवार, समाज, विद्यालय—इन सभी वर्गो का सहयोग अपेक्षित है। परिवार बच्चों को अच्छा वातावरण दे, उनमें अच्छी आदतो का विकास करें, उनकी उपेक्षा न करे, उचित स्तर तक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। साथ ही पारिवारिक अनुशासन के सबंध में सतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

समाज का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों के खेल, पठन-पाठन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करे ताकि बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके साथ ही बच्चो के लिए सामाजिक सगठनों का भी आयोजन किया जाए। छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए। बच्चो को आदर्श जीवन की प्रेरणा देने वाले चलचित्रो के प्रदर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विद्यालयो में बच्चो की आयु व रुचि के अनुसार मनोरंजन का प्रबध हो। अध्यापक का व्यवहार उनके प्रति पक्षपात रहित, सहानुभूति, प्रेम, दया से परिपूर्ण हो। व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन द्वारा बच्चों को बाल अपराधी बनने से रोका जा सकता है। निर्देशन के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। कर्नल थॉमस के शब्दो में कहा

जा सकता है–

"We must have systematic character training for the children Every child wants to be good but then the child must have a good guide "

साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण इस ढंग से किया जाए जिससे वह जीवन के साथ संपर्क कराने में उपयोगी सिद्ध हो सके। अध्यापक को चाहिए कि आत्म नियंत्रण द्वारा कक्षा में उत्पन्न समस्याओं को हल करे। बाल-अपराधी बालक की भावना का ध्यान रखकर उसके साथ उसी स्तर से व्यवहार करना चाहिए। क्लीनिकल सुविधाओ का लाभ उठाकर भी अध्यापक ऐसे बालको का सुधार कर सकता है। बाल अपराधियो की रोकथाम के लिए यदि इन कदमों को उठाया जाए तो निश्चित रूप से बाल अपराध की दर घटायी जा सकती है।

उपचार की विधियां

अपराधी के उपचार के लिए कई उपागमों व तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। किशोरों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक, मनश्चिकित्सक, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यक्तिगत उपचार का तरीका अपनाते हैं। यद्यपि मनोवैज्ञानिक सामूहिक तरीके का भी कई बार उपयोग करते है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का उपचार करते हैं व अन्तर्वैयक्तिक गतिकी पर बल देते हैं। मनचिकित्सा भावात्मक और व्यक्तित्व की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार करती है। इसी तरह यथार्थ चिकित्सा का उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को जिम्मेदार तरीके से काम करने में सहायता प्रदान करना है। व्यवहार चिकित्सा अपराधी के सीखे हुए व्यवहार में नई सीखने की प्रक्रियाओ के विकास द्वारा परिवर्तन करना है; क्रिया चिकित्सा बालक की दबी हुई भावनाओं को उपयुक्त मुक्ति प्रदान करती है परिवेश चिकित्सा ऐसे वातावरण को बनाने का प्रयत्न करती है जो कि अर्थपूर्ण परिवर्तन और सतोषजनक समायोजन में मदद करे। इन तरीकों के अतिरिक्त तीन और तरीकों का उपयोग बाल अपराधियों के उपचार में किया जाता है–

- सामाजिक प्रकरण कार्य अर्थात् असमंजित बच्चे को उसकी समस्याओ का सामना करने में सहायता करना।
- व्यक्तिगत परामर्श अर्थात् अपराधी को उसकी वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराना और उसकी समस्या के समाधान के लिए पुनः शिक्षित करना।
- व्यावसायिक परामर्श अर्थात् अपराधी के जीवन के विकल्पो, नौकरी के विशेष विवरण और योग्यताओं तथा सफल रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी को बढ़ाना।

निष्कर्षतः बाल अपराध की रोक व नियत्रण के सभी पहलुओं के बारे में एक सही सरकारी नीति के लिए सूक्ष्म अन्वेषण पद्धतियों के द्वारा योजना एवं मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी एजेन्सियो, विश्वविद्यालयों, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओ के बीच समन्वय भी आवश्यक है। बाल अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे समूल नष्ट करने की दिशा मे प्रयास आवश्यक है क्योंकि ये बच्चे ही राष्ट्र के भावी निर्माता हैं तथा इनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाना सभी का सम्मिलित दायित्व है। ◻◻

(1) गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद
(2) एम.जे.पी., रुहेलखंड यूनिवर्सिटी
बरेली, उत्तर प्रदेश

राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा

❐ मुन्नेश कुमार

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं से वंचित बालिकाओं/बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया, जिसका लक्ष्य वंचित वर्ग को प्राथमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा उनकी सुविधा के समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने बंद कर ई.जी.एस. एवं ए. आई. ई. कार्यक्रम नवीन रूप में प्रारम्भ किया है जो वर्तमान में लागू 'सर्व-शिक्षा अभियान' का प्रारम्भिक ढांचा था।

राजस्थान राज्य शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ राज्य है, जहा औपचारिक शिक्षा सुविधाओ की सतत् वृद्धि एवं इनकी हजारो गांवो मे उपलब्धता के उपरान्त भी लाखों बालिकाए/बालक सामाजिक, आर्थिक एव अन्य कारणो से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं/बालको, जिनकी आयु 6-14 वर्ष की थी, को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया।

राजस्थान सरकार ने प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का सूत्रपात सन् 1974 में किया। आबू में प्रशासनिक एवं शैक्षिक अधिकारियों की एक गोष्ठी की गई, जिसमे अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओ पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार ने आबू गोष्ठी के आधार पर 6 जिलों– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा– के शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया। राजस्थान के 26 जिलों में से 16 जिलो में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 1977 के अन्त तक प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष 1984-85 में बालिका वर्ग के 3000 एव बालक वर्ग के 7400 अर्थात् कुल 10400 केन्द्र स्वीकृत किए गए थे, परन्तु बालिका शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रों की सख्या में परिवर्तन करते हुए बालिका वर्ग के 6000 तथा बालक वर्ग के 4400 केन्द्र स्वीकृत किए गए। सितम्बर 1989 में इन सभी केन्द्रों का समूहीकरण करते हुए पंचायत समिति स्तर पर परियोजना का स्वरूप दिया गया और 165 पंचायत समितियों में 104 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। वर्ष 1994-95 मे 3200 एव 1995-96 में 4000 और नए केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की। इस प्रकार वर्ष 1995-96 मे समस्त केन्द्रो की संख्या 17600 हो गई, जिसमें से 8900 केन्द्र बालिका वर्ग एवं 8700 केन्द्र बालक वर्ग हेतु निर्धारित किए गए। 31 मार्च, 2001 को अनौपचारिक शिक्षा को नए रूप में प्रस्तुत करते समय राज्य की 205 पंचायत समितियो में कुल 161 परियोजनाएं स्वीकृत थीं, जिनमें 82 परियोजनाएं बालिका वर्ग व 79 परियोजनाएं बाल वर्ग की कार्यरत थीं। इन समस्त केन्द्रों पर अनुदेशको द्वारा बालिकाओ / बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनुदेशकों की शैक्षिक योग्यता पुरुष अनुदेशक की आठवीं पास रखी गई। चयन करते समय महिला को प्राथमिकता दी जाती थी।

उद्देश्य

अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के बालिकाओं / बालकों को प्राथमिक स्तर तक की नि-शुल्क शिक्षा उनकी सुविधा

के समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराना था।

- ☐ 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के अशिक्षित एवं वंचित वर्ग की बालिकाएं / बालक।
- ☐ ऐसी बालिकाएं / बालक जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणो से औपचारिक विद्यालयो में प्रवेश नहीं ले पाए या जिन्हें अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा।
- ☐ ऐसी बालिकाए / बालक जिनके माता-पिता मजदूरी करते हो, जिससे उन्हें घर पर कार्य करना पड़ता हो या वे स्वयं मजदूरी करते हो।
- ☐ ऐसी बालिकाएं-बालक जिन्हे विद्यालयो की दूरी के कारण औपचारिक विद्यालयों में नहीं भेजा जाता हो।
- ☐ ऐसी बालिकाएं / बालक जिनके माता-पिता विद्यालय की फीस, पठन-पाठन सामग्री आदि उपलब्ध नहीं करा पाते।

वित्तीय प्रबन्ध—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनो के सहयोग से संचालित हो रहा था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अशदान बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा बालक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो के लिए क्रमश. 90.10 एव 60'40 था, प्रबन्ध हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अशदान 60:40 का था।

प्रशासनिक व्यवस्था—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु निदेशक साक्षरता एव सतत् शिक्षा जयपुर उत्तरदायी थे। कार्यक्रम का प्रबन्ध, क्रियान्वयन, परिवीक्षण तथा मूल्याकन का कार्य भी यही निदेशालय करता था।

जिला स्तर पर सहायक निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा तथा परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, परिवीक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य करते थे।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु शैक्षिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर द्वारा किया जाता था। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रशिक्षण तथा अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास भी सस्थान द्वारा किया जाता था।

लाभान्वित वर्ग—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त जाति वर्ग के ऐसे परिवारों के बालिकाएं / बालक लाभान्वित होते, जो अपने आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से अपने बच्चो को औपचारिक विद्यालयों में नही भेज सकते थे।

योजना प्रारम्भ करने का वर्ष—राजस्थान राज्य में वर्ष 1975 में 230 केन्द्रों से अनौपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1984-85 में केन्द्रों की संख्या 10400 जो बढ़ाकर 1995-96 में 17600 की गई और 31 मार्च, 2001 तक यही केन्द्र स्वीकृत थे।

योजना की अवधि—राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को 31 मार्च, 2001 में भारत सरकार के निर्देशानुसार बन्द कर इसके स्थान पर नवीन योजना "शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचार शिक्षा योजना" (ई.जी.एस एवं ए.आई.ई) दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से प्रारम्भ की गई, जो वर्तमान मे संचालित सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानी जा रही है।

योजना का लाभ—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के केन्द्रों पर सभी वर्गो के लोग, जो अपने बच्चों को अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से औपचारिक विद्यालय नहीं भेज सकते, उन्हे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देकर लाभान्वित किया जाता। पिछले पांच वर्षों के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के केन्द्रों पर कुल नामांकित बालिकाओं / बालकों को निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री वितरण करते हुए औपचारिक विद्यालय मे प्रवेश दिलाकर औपचारिक शिक्षा से जोड़कर लाभान्वित किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत छोटे एवं वंचित आवासीय इलाकों में रहने वाले बच्चों सहित अन्य श्रेणी के बच्चो जैसे कामकाजी बच्चे, घुमन्तू (प्रवासी) बच्चे, गलियों में एव फुटपाथों पर रहने वाले बच्चे, किशोरियों आदि स्कूल से बाहर रहने वाले 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चो के लिए 1 किमी की परिधि में शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलकर प्राथमिक शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य माना गया।

स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से भी शिक्षार्थियो को लाभान्वित किया गया। प्रदेश मे 37 संस्थाओं को 2686 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने की स्वीकृति जारी की गई। इनके माध्यम से मार्च 2001 तक 61307 शिक्षार्थियों को लाभान्वित किया गया। इन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे ही शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया।

वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक कक्षा पांच में नामांकित बच्चों में से इसकी परीक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कक्षा 6 औपचारिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या

वर्ष	1994-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-01
कक्षा 5 की परीक्षा में बैठने वाले बच्चो की संख्या	कक्षावार न होकर इकाईवार नामाकन की व्यवस्था थी	28871	33060	25427	22320	20753	30285
कक्षा 5 मे उत्तीर्ण बालक/बालिकाओं की संख्या	–वही–	22760	25917	20556	18701	16821	केन्द्र बीच मे बन्द कर बालिका / बालक को औपचारिक विद्यालय से जोड़ने के कारण सही डाटा प्राप्त नहीं।
उत्तीर्ण मे से कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले बालिका / बालको की सख्या	–वही–	10598	9795	9537	8812	8000	–वही–

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य व उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत केन्द्र	भौतिक लक्ष्य	कुल लक्ष्यो के विरुद्ध उपलब्धि	अनु. जाति की उपलब्धि	अनु जन जाति की उपलब्धि	वित्तीय प्रावधान (रुपए मे)	व्यय राशि (रुपए में)
1994-95	13400	3 35	3 19	0 35	0.46	317 81	157 51
1995-96	17600	4 40	4.29	1.09	0 92	609 41	439 41
1996-97	17600	4.40	4.62	1 08	0 95	726 75	566 22
1997-98	17600	4.40	4 34	1 04	0 89	866 41	518 26
1998-99	17600	4.40	4.40	1.05	0 89	808 45	504 98
1999-2000	17600	4 40	4 15	1 00	0 86	600.00	545 99
2000-01	17600	4 40	3.52	0 88	0 72	665 70	848 18

□□

द्वारा– क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
अजमेर, राजस्थान

परिषद् की "भारतीय आधुनिक शिक्षा" एवं "प्राइमरी शिक्षक" त्रैमासिक पत्रिकाओं के ग्राहकों, पाठकों तथा लेखकों से निवेदन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की उपर्युक्त उल्लेखित दो त्रैमासिक पत्रिकाएं शिक्षा जगत मे राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर हो रहे अनेक प्रयोगों, अनुसंधानों, कार्यक्रमों व गतिविधियों को पाठकों तक पहुचाने के सुगम माध्यम है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाविदो, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षको तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को समर्पित है। इनके प्रत्येक संस्करण में ऐसे नवीनतम लेखों के प्रकाशन को प्राथमिकता दी जाती है जो शैक्षिक नीतियों से संबंधित हो, गुणात्मक सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रयोग हो, अधिगम को सुरुचिपूर्ण तथा ग्राह्य बनाने की दिशा में निजी अनुभव अथवा शोध कार्य हों, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमो के विवरण हो, शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी प्रभावी सामग्री हो। शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से ये पत्रिकाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा परिषद् इन्हें मूल लागत से भी बहुत कम कीमत पर पाठकों को उपलब्ध कराती है।

इन पत्रिकाओं के लिए उत्कृष्ट स्तर के शिक्षाप्रद प्रभावी लेख सहर्ष स्वीकार किए जाते हैं तथा उनके प्रकाशन के उपरांत समुचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख की विषय-वस्तु 2500 से 3000 शब्दों या अधिक टंकित रूप में होना वांछनीय है। कृपया अपने लेख निम्न पते पर भेजें :

विभागाध्यक्ष (पत्रिका प्रकोष्ठ), प्रकाशन विभाग,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली–110 016

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली -110 016 के लिए प्रकाशिन तथा जैन कम्प्यूटर, शकरपुर, दिल्ली द्वारा लेजर टाईपसैट होकर शगुन आफसेट प्रेस, 92–बी, गली न 4, कृष्णा नगर, सफदरजग एन्कलेव, नई दिल्ली–110 029 द्वारा मुद्रित।

10. Should the board give publicity to the names of the candidates for the superintendency?

Since publicity is usually, if not always, embarrassing to unsuccessful candidates and serves no purpose except to satisfy idle curiosity, it should not be given to unsuccessful candidates. Publicity should be given only to the *successful* candidate The same procedure regarding publicity should be followed in filling all school positions. The public will not resent this policy if it is consistently and honestly carried out, because the policy is in the public interest.

11. Should a board member promise a candidate his vote for the position of superintendent?

Since such a promise closes the door against any further information and against all other candidates, it should not be given to any candidate by any board member, moreover, no candidate should request or expect such a promise. When a board member sponsors a certain candidate without having full information on all candidates, he is apt to create obstructions to obtaining the best superintendent; such a board member gives evidence of having a closed mind and of being more interested in the desires of a certain candidate than in the welfare of the schools. The board meeting at which the superintendent is to be elected is the only appropriate time and place to come to a final decision regarding one's vote. The interests of the public can best be served through this practice A board member should not mortgage his final decision by making an early promise to any individual or group.

12. For what length of term should a superintendent be employed?

Most of the larger school systems contract with their superintendents for terms of two to five years, three years being

the usual term. In the small school systems, one-year contracts are usually found. Provided the superintendent has amply demonstrated his ability in other educational positions, most students of school administration favor giving him a contract term of two to five years for the first contract in order that he may have sufficient time to demonstrate his worth; after that contract has expired, they favor keeping him in office as long as his services are acceptable. Of course, many states have laws which govern the length and other features of contracts of school employees, and such laws must be followed. If the contract is not clear and not in accordance with state law, the board may become involved in litigation. This is always embarrassing to all concerned and demoralizing to the school system.

13 How should the board determine the salary of the superintendent?

When the board is seeking a superintendent, it should set the salary range which it will pay, then attempt to find the candidate best qualified for that range. It should not request the candidates for any school position to compete on salary. In fact, the Code of Ethics of the National Education Association prohibits members of the teaching profession from engaging in such competition.

In setting the salary to be paid the superintendent the board should, provided it has sufficient funds, establish an amount at least as large as the average salary of superintendents in similar school systems of the state and nation, especially the forward-looking ones. Unless it can and does compete in salary with excellent school systems, the board risks the danger of obtaining a poorly qualified superintendent or of losing a well-qualified one to a community which pays a larger salary The selection of a poorly qualified super-

intendent, at even a small salary, is the worst investment which a school board can make. The salary paid to such a superintendent is likely to be largely or entirely wasted, and the decisions which he makes or fails to make are likely to waste much more than his salary. The best superintendents are by no means plentiful, and they are in competition for the best salaries in their profession

The superintendent should be paid on a twelve-months' basis. He should be given a vacation of two to four weeks during the summer months, and he should be expected to have adequate time for recreation, self-improvement, and home life

When he is on school board business inside or outside the school district, the travel expenses of the superintendent should be paid by the board. Most of the large school systems provide an automobile for the superintendent to use while on business for the schools, and, of course, they pay the expenses of the upkeep of the automobile.

One of the best ways by which the board may show the superintendent its valuation of his services is to relieve him of time-consuming details as much as possible. In school systems having at least twelve to fifteen teachers the superintendent should be provided with a full-time clerk who can assume much of the office detail, thus freeing much of the superintendent's time for planning and leadership.

WORKING WITH THE SUPERINTENDENT

14 How may the school board help the superintendent to give the schools a successful administration?

Since he must obtain practically all his powers and duties from the school board, the best qualified superintendent in the world cannot succeed without the cooperation of the

The state laws give practially all powers and duties ning to the management of the schools to the board, ve few of them to the superintendent. The board can, ore, "hamstring" him, or it can permit and help him to e real leader which he should be. Assuming that the ntendent is properly qualified, the board can help him ny ways to succeed

t of all, the school board should regard the superintend- the leader of the school forces of the community and l seek his recommendation on all school matters under isdiction. This does not mean that the board should ie a "rubber stamp" for the superintendent. Rather, oard should seek and carefully consider all such recom- ations, but should reserve for itself the right to approve eject them. An intelligent and fair-minded superintend- ill not object to having his recommendations rejected onally. If he does object, he deserves to be criticized for himself too seriously and for perhaps wanting to be a or of the educational destinies of the community.

erintendents should realize that practically all school members are honest and public-spirited, and that they to do everything possible for the schools. A superin- nt should never forget that he is an *employee* of his l board, and that he must cooperate with the members board if he desires to continue to hold his position To arize, the school board must know how to work with perintendent, and the superintendent must know how ork with the school board The school board must be the benefit of any disagreement.

he second place, the board should make an early agree- with the superintendent regarding his duties and the of the board This agreement should preferably be *in writing* as a part of the rules and regulations of the

board. An excellent example of such rules and regulations was given in answer to question 19, Chapter I, pages 23 to 26 of this book. But a good school system can be conducted for a long time without the superintendent "erupting" and foolishly *demanding* a statement of his powers and duties. There must be "teamwork" on the part of the board and the superintendent.

In the third place, the board should give the superintendent the task of executing all decisions of the board and support him in all reasonable and efficient performance of the task It should not, however, request or expect him to execute unreasonable decisions, but the board should have the benefit of the doubt on whether its decision is reasonable or unreasonable

15. Should a school system have more than one head or chief executive?

Most school systems have only one head or chief executive, namely, the superintendent. A few of the larger school systems, however, have two or more heads, consisting usually of a superintendent who directs the instructional program and a business manager who looks after finances, school buildings, supplies, and other business matters. The one-headed plan of administration is called the *unit* plan, while the many-headed plan is known as the *multiple* plan. Most multiple plans are dual

All rural, village, and small-city school systems make the superintendent the only head or chief executive Although a few school systems of the large cities have more than one head or chief executive, these are rapidly adopting the plan of having only one; they are more and more appreciating the fact that the business and financial side of school administration cannot be separated from the educational side. As Figure

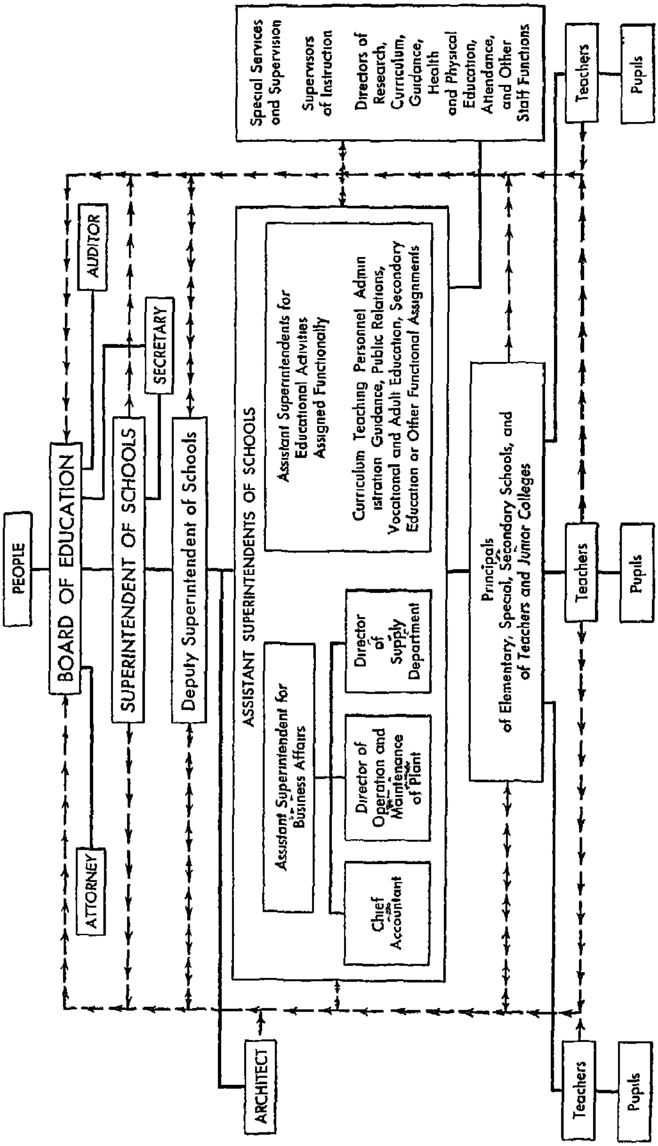


Figure 4 An administrative organization and staff recommended for a large city school system (From *A Report of a Survey of the Public Schools of St Louis, Missouri,* p 276 Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University)

4 indicates, large school systems may have one or more assistant superintendents who serve under the one head or superintendent

Practically all students of school administration believe that a school system should have only one head, namely, the superintendent. They favor the one-head plan for the following reasons:

1 The plan provides for centralized control, and such control is found to be working successfully in all other endeavors. It fixes responsibility. A school system needs only one head, as a company of soldiers needs only one captain or a corporation needs only one president

2. The plan prevents friction and duplication of effort which frequently exist when the school system has two or more heads It obtains better schools at a smaller cost

Where there is more than one head, the board members should insist that the plan give way to the one-head plan, even when the change is opposed by the heads themselves, as it sometimes will be.

16. When should a school board dismiss its superintendent?

The superintendent should be retained in office only as long as he is efficient, possesses high character, and desires to remain. If he has become inefficient, has stolen school funds, is guilty of immoral conduct, or for some other reason is a handicap to the welfare of the schools, he should be dismissed. Unless the charges against him are very severe, such as those involving immoral conduct, he should be dismissed at the end of his contract, not during the contract, and he should be given at least a month's notice that his contract will not be renewed. During the life of his contract an employee

cannot be dismissed except for the causes stipulated in the contract or in the laws of the state. These causes must always be acceptable to the courts, provided the superintendent questions his board's decision, when they are not acceptable, the dismissed employee may claim and collect any back salary as well as the salary for the remainder of his contract.

The dismissal of the superintendent should be based only upon the board's dissatisfaction with his accomplishments in the school system or with his personal conduct, and such dissatisfaction should be based upon facts rather than upon rumors and unsupported opinions. It should not be based upon personal grudges against the superintendent either from within or without the board Such grudges are often the result of small shortcomings in the superintendent, although he may have unusual gifts in all other respects. Before decision is made to dismiss the superintendent his strengths should be balanced against his weaknesses, and he should be given an opportunity to defend himself before the board When these actions have been taken, the board should courageously make its decision, with the welfare of both the schools and the superintendent in mind Its first loyalty should, however, always be to the schools rather than to the superintendent or to any other school employee.

School boards should realize that even the best superintendents sometimes make mistakes. The best will make many home runs, but they will also sometimes strike out Sympathetic appraisal of the superintendent's *whole record* should be made when his retention is under consideration.

Unless the superintendent has committed a serious civil offense or is grossly inefficient, it will be advisable to offer him another position in the school system rather than to dismiss him from the system, the laws of many states require this procedure. He will often have the ability and energy to per-

form efficiently the duties of a teaching position, a principalship, or some other school position, but be unequal to the more arduous duties of the superintendency. Just as humane farmers lighten the work schedules of old and faithful horses or mules, so school boards should, if feasible, lighten the loads of old and faithful school employees until the retirement age has been reached Although outright dismissal of an employee from the school system is sometimes necessary, it should usually be taken only as a last resort. The long-range interests of the schools and of the public will be served best through boards of education following the humanitarian policies just recommended.

Most superintendents who fail of reappointment fail because of not demonstrating one or more of the qualities listed on page 48.

17. Should the superintendent "fight" the decision of his board not to renew his contract?

When the school board has notified the superintendent that his services as superintendent are no longer wanted and that his contract will not be renewed, he should make up his mind that he will probably have to accept the decision as final. He has the privilege, of course, of "fighting" the decision, or of permitting his friends to "fight" it, but he and his friends will almost always find that the board will not change its mind on the matter. Such "fights" usually injure the standing of the schools and the prestige of the superintendent, and wise superintendents will not become a party to them.

Why some superintendents have not known, for at least several months, that they are no longer wanted, and why some of them want to remain when they know they are not wanted, is difficult to comprehend.

4

Financial Support of the Schools

PUBLIC RESPONSIBILITY FOR SCHOOL SUPPORT

1. What is the policy of the people of the United States regarding school support?

The faith of the people of the United States in education has been called by a European visitor our "national religion." This faith has led our people to develop the best school system in the world and to make it almost entirely free to all the people. In most foreign countries only elementary school education is free, whereas in this country high school as well as elementary school education is entirely free and college education is chiefly free

The foreign school systems, especially on the high school and college levels, are designed to select and to prepare leaders, whereas our school system is designed to raise the educational level of the whole population Our people have the firm belief that by raising the educational level of all the people they will obtain both intelligent leaders and intelligent followers. In a democracy the people deem themselves to be competent to select their leaders and to prescribe the powers and duties of those leaders And in a democracy, also, the best leaders deem the people competent to perform the duties just mentioned

In the United States the ideal has been to give every person who desires it, and who has the intelligence to obtain it, an education extending from the elementary school to and through the graduate school of a university. Our leaders have followed this ideal because they have believed that the welfare and progress of the nation and of each person in the nation could best be assured through the education of all the people. They have believed that equality of educational opportunity is the best single assurance of equality in economic, political, and all other opportunities The greatest wealth of a nation exists in the amount and the quality of the education of its people.

2 What is the responsibility of the school board for financing the schools?

No organization can be run on thin air or on the good wishes of its friends All organizations must be adequately financed, and schools are no exception to the rule. One of the largest responsibilities of the school board is to make certain that the finances of the school system are adequate and properly administered, in fact, it must perform in person many of the duties of finance because some of these duties cannot be delegated to the superintendent, the clerk, or any other employee In the administration of the finances of the school system the board has the following responsibilities

1 It must see that sufficient revenue is obtained, at least in terms of the financial ability of the school district. If the present sources of revenue are not sufficient, it must try to find new ones When occasion demands, it must request additional funds from the voters of the school district and must justify these requests It must occasionally cooperate with other school boards in requesting the state legislature to make changes in the school finance laws.

2. It must make certain that all funds of the school district are spent without waste. In other words, it must endeavor to obtain 100 cents worth of education for each dollar expended.

3. It must adopt efficient accounting and auditing procedures for all funds of the school district What constitutes such procedures will be discussed in a later section of this chapter.

THE INCREASING SCHOOL EXPENDITURES

3. How much have school expenditures increased during recent years?

It is common knowledge that school expenditures have increased tremendously during recent years. Since 1870, the expenditures for public elementary and high schools have increased more than forty fold During the same period, the total population of the nation has increased only two and one-half fold, or one-sixteenth as rapidly as school costs. According to the United States Office of Education,[1] the total expenditures per pupil in average daily attendance in the United States have increased from almost sixteen dollars in 1870 to more than two hundred dollars at present. Of course, these expenditures per pupil have always varied widely among the states.

4. What are the explanations for the increases in school expenditures which have occurred during recent years?

All intelligent and honest persons will readily admit that the increases in school expenditures in the United States have been very large. All these persons will also admit that merely

[1] The United States Office of Education collects financial and other school statistics every two years, and these statistics may be consulted by anyone desiring the most recent data for the whole nation, for any state, or for any large city The reports are published by the United States Government Printing Office, in a volume entitled *Biennial Survey of Education in the United States*

to point out these increases without attempting to explain them is likely to give the schools a reputation for extravagance. School board members and superintendents should know the reason for the increases and should be able to explain them when school costs are unjustly attacked. The explanations are listed herewith

1. The increase in school enrollment is the most obvious explanation This increase in enrollment has been particularly rapid in the high school, where the per pupil expenditures has usually been almost twice that in the elementary school During the years immediately preceding and following World War II, the birth rate of the nation rapidly increased This has brought into the elementary schools a tremendous increase in enrollment, and this increase is beginning to hit the high schools It probably will continue for several years.

2 During recent years, especially during and following World War II, the purchasing power of the dollar has been much less than it was in former years, and this situation has required a larger expenditure to purchase the same amount and quality of education as formerly

3 Much of the increase may be charged to the larger amount and the better quality of education provided the pupils From the time of their establishment, the schools have constantly been improved. School terms have been lengthened, better qualified teachers and other employees have been obtained, better and more adequate school plants and supplies have been provided, more enriched curricula have been offered, and numerous school conveniences and services, such as pupil transportation, school libraries, free textbooks, and health services have been introduced. All these improved and increased services and conveniences have required the expenditure of more money

Only when the public is convinced that increased expenditures are necessary, will it willingly pay the bills. These explanations, therefore, must be kept before the public in order

that it may understand that it is getting its money's worth The fact that by far the majority of school board requests for increased school taxes have always been approved by the voters is convincing evidence that the people are interested in their schools.

5. Has the ability of the people to pay for schools kept pace with their expenditures for them?

There are two measures of ability to finance schools or anything else These measures are the amount of (1) *wealth* and (2) *income*. In terms of their wealth and income, school expenditures have not kept pace with ability Although the total school expenditures have increased rapidly, the percentage of the wealth and of the income devoted to the schools during recent years has declined The percentages of the national income devoted to national defense and to old age pensions, during recent years, have far outstripped the percentage devoted to the schools. We, as a nation, in terms of our ability are tending to spend less for schools

6 What have the schools accomplished which would justify the large expenditures for them?

This question has always been difficult to answer because of the impossibility of separating the influence of the school from the influence of other educational agencies such as home, church, theater, radio, television, newspaper, travel, work, and library Much progress has been made in improving individual and social well-being, and it is reasonable to conclude that the schools have been a vital force in bringing that progress Some of the improvements which the schools have helped to bring in American life are the following

1 Since 1900, the death rate per inhabitant has decreased one-third and life expectancy has increased one-fourth

2. Illiteracy is now only one-third as frequent as it was in 1900. The typical United States citizen (25 years old and over) has had approximately eight and one-half years of schooling, and the amount of schooling is increasing every year. It is unfortunate, however, that four persons in every one hundred persons have not received any schooling whatever

3. Our total national wealth has increased more than tenfold since 1900. And the per capita income of our people has also increased tremendously.

4. The per inhabitant circulation of newspapers, magazines, and library books has increased several fold since 1900 We have become by far the greatest "reading" people on the earth. And the development of radio and television has made us also the greatest "listening" and "seeing" people on earth.

5. The average worker now produces and consumes much more than his parents and grandparents Moreover, his standard of living is much higher Education develops tastes for the better things of life. The uneducated person is not apt to have those tastes, and he will therefore be content to live without the comforts and conveniences which characterize gracious living.

7. What are the chief sources of revenue which school boards now use?

The average school district in the United States now receives approximately 95 per cent of its revenue from *local* and *state* taxation of such things as property, income, sales, inheritances, and natural resources. The remaining 5 per cent of the revenue comes from such sources as income from endowments and other permanent funds, tuition of non-resident pupils, rental of school property, and federal aid.

The chief source of school revenue in all states is the property tax, especially on real estate, approximately 60 per cent coming from it, however, the tendency is toward using the property tax less and other types of tax more. Most au-

thorities are agreed that the property tax has many shortcomings and that it will soon have to be largely supplanted by other types of tax Much of the wealth of the nation is now of an intangible sort (stocks, bonds, commodities, machinery, merchandise, etc.); it is this intangible property which the property tax cannot easily reach and which other forms of tax such as income, sales, and corporation are being rapidly adopted to reach. The income tax is the best measure of ability to pay and should be used more widely than it is today in most states.

Unfortunately, the federal income tax is now so high that most states hesitate to adopt a state income tax. High federal income taxes will probably continue for a long time to deter the adoption of state income taxes; although that may be necessary to maintain our national security, it will be unfortunate for the schools in their search for more funds.

8. What are the governmental units of school support today, and what is the tendency regarding the use of these units for school support?

In most states there are now three governmental units of support for the elementary and high schools. (1) federal, (2) state, and (3) county and local In the average state slightly more than one-half of all revenue is now being furnished by the county and local districts, chiefly the local districts in all states except the southern ones The federal government furnishes approximately 2 per cent, practically all of which goes for vocational education in agriculture, home economics, industry, and the distributive occupations such as retail selling. The state government provides the remainder, which is slightly less than one-half of the total in the average state. The percentages provided by the various units of government are shown in Figure 5.

In order that there may be greater equality in educational opportunity and in tax burden among the school districts of the state, the tendency is toward having the state furnish a larger percentage of the revenue for the public schools of the state. Every state now gives a large amount of state aid for schools, and the tendency has been to increase the amount. In several states more than one-half of all school revenue is furnished by the state, and in Delaware more than 90 per cent is provided by the state When the state provides too large a percentage of the revenue, there is danger that local districts will lose interest in their schools because they do not have enough of the responsibility for supporting them. Just as parents must be on guard lest they pauperize their children by doing too much for them, so the state can pauperize school districts through giving too much state aid

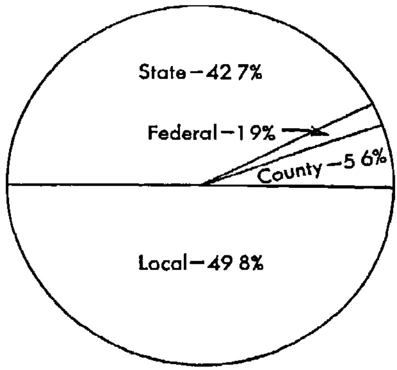


Figure 5 The units of school support in the United States and the approximate percentage of revenue provided by each unit These percentages vary, of course, in different states

The same arguments which are made for providing state aid for schools may also be made for providing federal aid for them Large differences in per-pupil expenditures for schools are found among the states. Some of the states spend almost twice as much per pupil as the average state, and some of them spend five times as much per pupil as other states. These large inequalities in expenditures result in large inequalities in educational opportunities among the states, and they have called forth the suggestion from many of our citi-

zens that federal funds for elementary and high schools be regularly granted to the states, especially to the states which have low financial ability. Many of our citizens, however, are opposed to federal aid for the schools because of the dangers of pauperizing the states and of obtaining federal control of the schools

At present, federal aid is given only for *vocational* (agriculture, home economics, trades and industries, and *distributive*) education. By distributive education is meant education which prepares a person for engaging in retail selling and in other occupations concerned with the distribution of goods and services. For classes in vocational education the federal government pays approximately one-half of the cost, while the state and the local school districts pay the remainder. School boards wishing to establish such classes should request their superintendent to make application for funds to their state department of education.

9. How may the school board meet a financial stringency in the school system?

Owing to business depressions, to large increases in enrollment, or to poor financial management, practically every school system faces hard times or a financial stringency from time to time. The three following steps may be taken by the school board to meet such a stringency, and the first two steps should always be taken whether there is a stringency or not

1 The board should make all financial economies that are reasonable. In attempting to obtain economies, false ones should not be mistaken for real ones When money is saved and the educational oportunities of the pupils are not harmed, a *real* economy is effected When money is saved through the curtailment or the elimination of a school service, and the educational opportunities of the pupils are injured more than they would have been harmed

through the curtailment or the elimination of some other school service, a *false* economy is practiced. If the expenditures of a school system must be decreased, services which make the least contribution to the welfare of the smallest number of pupils should be curtailed or eliminated first

2. It should see that all moneys to which the schools are legally entitled come in. To obtain that result, it should do such things as the following· make sure that all nonresident pupils pay their tuition or have it paid for them by their home school district or the state; obtain the highest rate of interest, consistent with safety, on all funds in depositories, obtain all state aid and federal aid to which the district is entitled; make sure that the city council, mayor, county budget commission, or similar authority deals justly with the schools; and see that all miscellaneous funds, such as rentals, fines, income from permanent funds and endowments, and proceeds from the sale of sites, buildings, equipment, and supplies, are forthcoming

3 If taking the two steps just mentioned does not provide sufficient revenue, the board has the two following alternatives First, it may attempt to obtain additional revenue through such means as requesting the people to vote an additional tax, second, it may curtail expenditures, starting first on those items which make the least contribution to the educational welfare and progress of the smallest number of pupils.

KEEPING FINANCIAL ACCOUNTS

10. Why should the board arrange for proper records to be kept of every important school transaction?

School records must be kept in order that ample, accurate, and meaningful information will always be available as the basis for all opinions and decisions of school officials and employees on the finances of the school system Every school system which desires to be efficiently administered must systematically collect, file, and use information which will show the operation and the efficiency of the school system

as a whole and in each of its parts. Records must be kept which will provide information on the efficiency of every employee, every pupil, and all important equipment. Among the records which must be kept are those of teachers, principals, supervisors, janitors, bus drivers, nurses, attendance officers, pupils, budgets, repairs of buildings, insurance of buildings, school bonds, school expenditures and receipts, cafeteria and other internal accounts, books, supplies, and equipment inventories. The school board should expect and require its superintendent to take the lead in placing in operation a system of records adequate for the school system. Moreover, it should give him authority to require all school employees to keep any necessary records and to make any necessary reports. These matters, however, are policies, and like all policies should be submitted to the board for amendment, approval, or rejection.

11 What are the purposes of school financial accounting?

Efficient accounting of school funds has the following purposes: (1) it aids in preparing the budget for the succeeding year, (2) it helps in making studies of cost and efficiency, (3) it shows the amount of funds at all times and thus helps to make sure that expenditures will not exceed appropriations, and (4) it makes possible the auditing of accounts to ascertain whether school officials and employees have been honest

12. What characteristics should a school financial accounting system possess?

In many states the accounting forms for all school systems are prescribed by the state department of education, the state auditor's office, or some other division of state government. An accounting system should combine *simplicity* with *adequacy*. Simplicity is necessary because many school clerks

are not well trained in financial accounting procedures; however, simplicity should not be carried so far that the system becomes inadequate to meet the purposes of financial accounting which were mentioned in the answer to the preceding question.

In addition to having simplicity and adequacy, an efficient accounting system should follow the best practice in its classifications and definitions. The income ledger should make provision for all sources of revenue which the state laws provide The expenditure ledger should follow closely the headings found in the school budget form which is shown in Figure 7, pages 86 to 89. Such classification of expenditures is recommended by the United States Office of Education, the United States Census Bureau, the National Education Association, the Association of School Business Officials of the United States and Canada, and many other national and state agencies and authorities. Accounting forms which follow these classifications may be obtained at small cost from various stationary firms and school-supply houses. The following advantages would be obtained if school systems used a uniform accounting system of the sort just described:

1. A uniform system would make possible a comparison of the financial practices in one school system with those in other school systems. Those comparisons are particularly helpful in budget making and in studies of costs

2. The training of school clerks, superintendents, and other school employees in financial accounting procedures would be easier because there would be only *one* financial accounting system with which these employees would need to become acquainted.

3. Reports could be made more easily by local officials to the United States Office of Education, the state department of education, the county auditor, or similar agencies

4 The income and the expenditures of each school system could be audited more quickly and accurately, and a meaningful report of the audit could be more readily made to the people of the school district

If a uniform accounting system is not now in effect, a school board should direct its superintendent and its clerk to install such a system as soon as it is practical to do so. But the board should require the system that is recommended to be submitted to it for its approval or rejection.

13. How may school boards obtain more efficient clerks?

One of the greatest needs in school administration has always been better qualified clerks to keep the financial records and accounts In many school districts, especially in those of the rural and village communities, the school clerk has little knowledge of the purposes and the procedures of school financial accounting. This shortcoming results from various factors. It frequently results from the clerk being elected on a "political" or some other unjustifiable basis, it sometimes results from the fact, especially in small school districts, that persons qualified for the office do not live in the school district, or if they do live there, they refuse the office because of the small salary offered In practically all rural and village school districts, the position of school clerk is a part-time one and pays only a small salary.

The school clerk should be selected only on the basis of his ability to perform efficiently the duties of the office of clerk. Small and adjoining school systems could obtain more efficient clerical service if several of them went together and employed a full-time and trained clerk who would work for all of them. Small school systems should also consider the feasibility of

employing a person full time to serve as clerk and to perform some other school service or services such as acting as school librarian, secretary to the superintendent, attendance officer, or commercial teacher. Since full-time employees usually give better service than part-time ones, either one of these moves would make for economy.

If the clerk collects and disburses the funds of the school district, he should be required to give an adequate bond to guarantee his financial honesty and to protect the district against any possible dishonesty; most states have laws which make this requirement. In fact, all officials and employees who handle school funds should be required to give such a bond. The cost of the bond should be paid from school funds, and the amount and type of the bond should be approved by the school board. A bond written by a reputable bonding company is to be preferred over a personal bond

14. What procedure should the school clerk use in filing bills and other financial documents?

As soon as the bills are received, the clerk should file them in chronological order and in a special place, so that none will be lost or misplaced. Before presenting any bill to the board for authorization of payment, the clerk should examine it carefully to make certain that it is accurately itemized If any discounts are offered for payment of bills within a specified period of time, arrangements should be made to take advantage of them. Efficient business procedure demands that bills be presented promptly and not allowed to run for more than a month or two before being paid.

No payment should ever be made on the basis of a mere oral statement A bill should always be required If the original bill has been lost, another copy of it should be obtained before payment is made.

When payment of a bill has been allowed by the board, the clerk should prepare a voucher. Copies of all invoices, payrolls, and purchase orders and certificates should be attached to the voucher jacket. The vouchers and all pertinent material pertaining to them should then be filed in numerical order and placed in a convenient file for reference until audited. After they are audited, they should be filed permanently by years in a convenient place in order that they may be available for reference if needed. File boxes or other filing equipment should be furnished the clerk for such purposes.

The clerk should also keep all paid warrants for auditing. When these are returned from the bank, they should be sorted and placed in numerical order and then checked to see whether they correspond to the checks issued Following this, the record of the returned checks should be filled out in the cash book. The paid warrants should be filed for reference and kept for a few years The laws of most states permit the paid warrants to be destroyed after five years

All other valuable papers such as enumeration reports, the annual budget, financial statements, contracts of all kinds, paid bonds and interest coupons, bond of the depository, deeds for school property, and insurance policies should be filed separately in the manner suggested for bills. Most of them should be kept several years for reference. All the more valuable papers, such as deeds for property, insurance policies, and contracts, should be kept in a locked box in the safe-deposit vault of a convenient and responsible bank. Every school district should also have a vault or safe for keeping its other records, such as those pertaining to pupils and employees, in fact, if the school safe or vault is large enough, it may be used for keeping all school records and other valuables

15. What financial reports should the school board make?

The importance to the public of financial reports made by school boards can hardly be overestimated. Such information should be presented regularly by every board, because the faith of the public in the financial honesty and competence of the board is determined largely by it. Care should, therefore, be taken to make certain that such reports are prepared and presented accurately and clearly. Unless they are thus prepared and presented, they will not be read and are likely to be misleading.

The financial report which school boards most frequently make is the "income and expenditure" statement, which indicates the amount of money received from each source and the amount expended for each school service or purpose Practically all states require such a statement to be made at the close of each fiscal year, and many states prescribe the type of information which the statement shall contain. Most states require that the statement be published at least once in a newspaper of general circulation in the community, other states, especially those of New England, permit or require the board to publish it in bulletin form. Whether required by law or not, such a statement should be published annually in some form, and wide circulation should be given it among the residents of the school district A good annual report contributes to good public relations

16 What audit should be made of school funds?

The laws of most states provide that the accounts of all financial officials of the public shall be audited at least once every two years The laws usually require also that this auditing be done by representatives of the state auditor's office or of some other designated branch of state government. The

chief purpose of the audit is to make sure that public officials do not violate the laws of the state in the handling of their funds. For the protection of the public and of itself, every school board should provide for an audit of its funds at least once every two years, although the state laws may not require it; an annual audit would be even more desirable than a biennial one. The board should also see that ample publicity is given to the outcome of all audits. This publicity may be best given through the local newspaper or newspapers.

17. What supervision should the school board give to the funds of cafeterias, athletics, the book and supply store, and similar departments?

The school board should make certain that efficient practices are followed in the collection and expenditure of these private funds. It should protect such funds and the reputations of all pupils and employees who have the custody of them by establishing certain rules and regulations for their management. Among other provisions, these rules and regulations should provide for an annual audit of all such funds and for proper publicity for the audit.

18. What provision should the school board make for equipment inventories?

The board should arrange for an annual inventory, usually at the close of the school year, of all equipment belonging to the schools. Such a check can be made by principals, teachers, janitors, and other school employees It should be supervised by the superintendent of schools or by someone appointed by him. It should include a listing or a checking of all items of movable equipment such as desks, chairs, bookcases, filing equipment, maps, globes, typewriters, tools, laboratory ap-

paratus, and pictures. It should be taken for the following reasons:

1. It helps to prevent the loss or misplacement of equipment by giving school employees and pupils a greater feeling of responsibility for these school possessions

2 It aids the school board in determining the amount of insurance to carry on school equipment It also aids the board in settling claims for losses, because it shows the equipment that was damaged or destroyed.

3. It facilitates the replacement or the repair of destroyed, damaged, or stolen equipment

4 Since it shows the amount of equipment on hand, it assists in preventing the purchase of unnecessary equipment

5 By showing the amount, the cost, and the date of purchase of equipment on hand, it aids in calculating the amount of depreciation on the equipment, since depreciation is an element in cost, the amount of depreciation must be known before school costs can be accurately determined

5

Making the School Budget

DEFINITION AND IMPORTANCE OF A BUDGET

1. What is a school budget?

A school budget is a statement which analytically lists (1) the anticipated *revenues* and (2) the predicted *expenditures* of the school system for one year. This year is known as the *fiscal year*, which is not always the same as the calendar year or the school year. In most states, however, the fiscal year is the same as the school year. It usually extends from July 1 to June 30, but many other dates for its beginning and its ending are in use in the various states.

The school fiscal year should be the same as the school year, because the fiscal year should serve the school year Making the fiscal year serve two school years contributes to much more difficult school budget-making.

2. Why should every school system operate under a budget?

In most states school boards are required by state laws to make a school budget for each fiscal year. Moreover, the laws usually prescribe, at least partly, how and when the budget shall be made.

The budget should be regarded as a financial and educational plan for the school system, and like all good plans it should be carefully made. As will be seen by a glance at Figure 6, such a plan consists of three parts—*educational, income,* and *expenditure.* The budget affects the school system in all its parts. The proposed expenditures should be based upon the educational needs and the financial ability of the school district. Preparing, defending, and using the budget is one of the most important as well as one of the most difficult tasks which the school board has to perform.

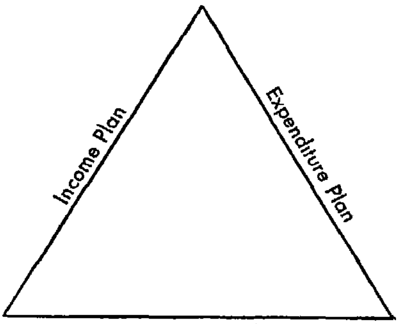


Figure 6 The three plans necessary in school budget making The foundation should be an educational plan for the school system, upon this the income and expenditure plans should be based, and all three must coordinate

PREPARATION OF THE BUDGET

3. What is the responsibility of the board for preparing the budget?

The school board should prepare the budget in cooperation with the superintendent and other members of the administrative staff of the school system. Since the superintendent knows, or at least should know, more about the needs of the schools than any other person, the board should delegate to him the task of drafting the budget and presenting it to the board. The board, of course, should always reserve the right to counsel, to amend, and to approve In considering the budget the board should not eliminate, increase, or de-

crease any item until the superintendent has been consulted. The school board should seek the people's help in determining the school needs and the community's ability and willingness to pay for the school program, *willingness* is especially important. Each board member should be presented a copy of the proposed budget by the person who drafts it.

4 In how much detail should the school board expect the budget to be analyzed?

The board should require the superintendent and his co-workers to analyze the budget in rather large detail. The budget should show the amount of money expected from each source of revenue and should indicate the proposed expenditures for each phase of the work of the schools. Moreover, the board should insist that pertinent information, which will help to explain and to justify each item, be collected and made available to it. A budget should be based on detailed information rather than on hunches and unsupported guesses. A lump-sum budget is of little value, because its estimates are likely to be either too large or too small; in fact, such lump-sum estimates are *not* a budget

5 How may the school board determine whether the budget is well proportioned?

The school budget should be well proportioned—that is, neither too large nor too small an expenditure should be made for any item. Those budgets are best which give as much as possible for instructional services (teachers' salaries, educational supplies, textbooks, etc.) and as little as possible for other things without, of course, crippling the contributions of these things to instruction. It should be reiterated that the school exists only to provide instruction for its pupils; it does

not exist to furnish positions or profits to anyone, except as a reasonable payment for service to the schools.

An excellent means by which school officials may inform themselves on whether their budget is well proportioned is to compare the percentages spent for the several items of the budget with the percentages spent in former years, and with the percentages spent for the same items in the budgets of similar communities. Of course, such a comparison merely helps to make school officials better acquainted with their former and their present practice and suggests that they further examine the practice, it does not necessarily tell them whether their present practice is what it should be.

According to regularly published statistics of the United States Office of Education, the percentage distribution of expenditures for current purposes in the average school system does not vary much from year to year. The following percentages went to the large items of *current* expense in the average school system of the United States during the most recent year for which data are now available from the United States Office of Education:

General Control	4.8
Instruction	69.4
Operation of School Plant	10.4
Maintenance of School Plant	3.4
Auxiliary Agencies	7.4
Fixed Charges	4.6
Total Current Expense	100.0

A glance at Figure 7 will give the reader an acquaintance with the more detailed items which are included under the large divisions of current expense, those large divisions are General Control, Instruction, Operation of School Plant,

I RECEIPTS

Items	*Receipts Last Fiscal Year (1953)*	*Receipts This Fiscal Year (1954)*	*Estimated Receipts Next Fiscal Year (1955)*
1 Unemcumbered balance			
2 Local-tax levy			
3 County-tax levy			
4. General state aid			
5 Section 16 and other permanent funds			
6 Depository interest			
7 Non-resident tuition			
8 Evening-school tuition			
9 Rentals			
10. Sale of sites, buildings, or supplies			
11. State aid for vocational education			
12 State aid for deaf			
13 State aid for blind			
14 State aid for crippled			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23 Miscellaneous			
Total			

	1953	1954	1955
Tax Duplicate	______	______	______
Tax Rate for Schools	______	______	______

Name of School System ______________________________

Fiscal Year for this Budget ______________________________

Figure 7 Suggested form for the final school budget

II. EXPENDITURES

Items	Expenditures for 1953	Appropriation for 1954	Estimated Needs for 1955	Increase or Decrease of 1955 Request over 1954		Percentage Increase or Decrease
				In-crease	De-crease	
1 General Control						
a Board of education—secretary's office						
b. School census						
c Operation and maintenance of general offices						
d Salary of superintendent of schools						
e Salary of superintendent's clerk						
f Enforcement of compulsory-education laws						
g. Expense fund						
h						
i						
j Other expenses of general control						
Total expenses of general control						
2 Instruction						
a Salaries of supervisors of grades and subjects						
b Other expenses of supervisors						
c Salaries of principals and their clerks						
d Other expenses of principals						
e Salaries of teachers						
f Textbooks						
g Stationery and supplies used in instruction						
h Commencement						
i						
j						
k Other expenses of instruction						
Total expenses of instruction						
3 Operation of School Plant						
a Wages of janitors and similar employees						
b Fuel						
c Light and power						

II. EXPENDITURES (*Continued*)

Items	*Expenditures for 1953*	*Appropriation for 1954*	*Estimated Needs for 1955*	*Increase or Decrease of 1955 Request over 1954*		*Percentage Increase or Decrease*
				In-crease	*De-crease*	
3 Operation of School Plant (*Cont*)						
d Janitors' supplies						
e Care of grounds						
f						
g						
h Other expenses of operation of plant						
Total expenses of operation of plant						
4 Maintenance of School Plant						
a Repair of buildings						
b Repair of grounds						
c Repair and replacement of equipment						
d						
e						
f Other expenses of maintenance of plant						
Total expenses of maintenance of plant						
5 Fixed Charges						
a Employees' retirement						
b Workmens' compensation						
c Building insurance						
d Rent						
e						
f						
g Other fixed charges						
Total expenses of fixed charges						
6 Debt Service						
a Payment of bonds (direct)						
b Payment of bonds (sinking fund)						
c Redemption of short-term loans						
d Interest on bonds						
e Interest on short-term loans						
f						
g						
h Other expenses of debt service						
Total expenses of debt service						

II EXPENDITURES (*Continued*)

Items	*Expenditures for 1953*	*Appropriation for 1954*	*Estimated Needs for 1955*	*Increase or Decrease of 1955 Request over 1954*		*Percentage Increase or Decrease*
				Increase	*Decrease*	
7 Capital Outlay						
a Land						
b New buildings						
c Alteration of old buildings						
d Equipment of new buildings and grounds						
e Equipment of old buildings exclusive of replacement						
f						
g						
h Other outlay expenses						
Total expenses of outlay						
8 Auxiliary Agencies and Miscellaneous						
a. Libraries						
(1) Salaries						
(2) Books						
(3) Other expenses						
b Promotion of health						
(1) Salaries						
(2) Other expenses						
c Transportation of pupils						
(1) Salaries						
(2) Other expenses						
d Board and lodging of pupils in lieu of transportation						
e Provision for lunches						
f Recreation and playgrounds						
g Social centers						
h Indigent children						
i Pupil tuition						
j						
k						
l Other expenses of auxiliary agencies, etc						
Total expenses of auxiliary agencies, etc.						
Grand total						

Maintenance of School Plant, Auxiliary Agencies, and Fixed Charges. Because expenditures for Debt Service and Capital Outlay vary so much in most school systems from year to year, they should not be included in a percentage distribution of current expense for any year. Expenditures for Debt Service and Capital Outlay should be regarded as *permanent*, or *non-current*, expenditures, not as current ones. A further glance at Figure 7 will indicate the kinds of expenditures which are listed under Debt Service and Capital Outlay (items 6 and 7.)

6. Should the budget be padded?

By padding a budget is meant asking for more revenue than is needed or expected. Some school officials prepare their budget with the expectation that it will be cut a certain amount, and they therefore pad it up to the amount which they estimate it will be cut. They try to outguess, if not mislead, the person or persons who must approve the budget.

Padding the budget should not be practiced. It is a species of dishonesty and is certain to result in suspicion and distrust of the budget makers on the part of the reviewing or approving authorities. School officials should make their budget requests on the basis of educational needs and reasonable expectations of revenue, then be ready to take off their coats and fight for these requests if necessary. In the long run, the personal fortunes of school officials, as well as budget requests, are certain to fare better if a policy of strict honesty is followed in making the budget.

7. During what time of the year should the budget for the next year be made?

Most states have enacted laws which prescribe that the budget shall be prepared and adopted at least sixty days before

the beginning of the fiscal year for which it is made Authorities agree that this is the best way. If it is made earlier that this, the task of estimating school needs will be too difficult. If it is made later, there may not be sufficient time for holding necessary conferences on it and for making any needed revisions, moreover, if the time is too short, contracts for services and materials will have been made and obligations incurred before the budget has been adopted. It is not good practice to mortgage funds until they are certain to be available, "Deficit financing" can be used only by the federal government, and it has been used entirely too much there.

PRESENTATION OF THE BUDGET

8. How should the budget be presented to the authority which must review or adopt it?

Unless the laws of the state require the use of a particular budget form, a form similar to the one shown in Figure 7 may be used in presenting the budget to the reviewing or adopting authority. This particular form meets the recommendations of the United States Office of Education, of state departments of education, and of other school agencies and authorities. It works hand in glove with the financial accounting system recommended in the preceding chapter. Furthermore, it is not difficult to understand and to use.

School officials should be expected to be able to explain and to justify every request for funds and every estimate of income made in the budget If an increased appropriation is requested, a justification for it should be especially given, and the wherewithal to meet the increase in expenditures should be shown. When the budget has been made on the basis of detailed information, such justification may be more easily made A lump-sum budget is always difficult to justify and

should be avoided. Making a good school budget is more than a "guessing game"; it involves the highest type of educational statesmanship, and must, in the final analysis, largely determine the merit of a school system

9. What publicity should be given the budget?

Ample publicity should be given the budget, because the public is always extremely interested in how its money is being spent. This publicity may be given through the newspapers, through holding a public hearing on the budget, or through printing or mimeographing the budget in a small bulletin and presenting a copy to each home, in a few states the use of one or more of these methods is required by law. The major features of the budget can be presented in such a manner that public interest in and support of the budget will be obtained. With such interest and support the budget can hardly fail of adoption, and the public will be given greater confidence in its officials and its institutions. Budget publicity is effective public relations.

ADMINISTRATION OF THE BUDGET

10. How closely should the approved budget be followed?

It has already been stated that a budget is a *plan*, and plans are made to follow. This does not mean, of course, that the budget should be followed blindly, irrespective of needs At best, a school budget is an *estimate*, and estimates of revenues and of expenditure needs cannot always be accurately made, especially several months in advance of the beginning of the fiscal year. Although revenues and expenditures may have been estimated with the greatest care, later events may prove the estimates to have been too high or too low

Often the school board will find it advisable to transfer funds from one item to another, provided the funds have not already been mortgaged for some other purpose, any such transfers, however, should be made only upon the recommendation of the superintendent and only with the school board's approval. To meet emergencies, such as might be caused by unexpected enrollments, unusually cold weather, floods, and cyclones, many school boards carry in every budget an unappropriated emergency fund amounting to from 5 to 15 per cent of the total budget, such a fund should be carried when the amount of revenue in the school district is sufficient to permit the establishment of the fund. Any emergency funds that are not needed in the year for which they were budgeted should, of course, be carried over to the next year, they should not be wasted on useless enterprises. They have, though, sometimes been largely wasted.

11. Should the budget be balanced?

Authorities in school budget-making agree that appropriations and expenditures should balance at the end of the year. Of course, a surplus is much more justifiable than a deficit. Borrowing money to pay current expenses is regarded as bad practice in school administration, particularly when continued over a long period, in fact, temporary financial disaster is likely to happen to a school system which pursues such a policy. The people of a school district expect the school board to provide the best schools possible with the money available, they are opposed to running the school district into debt to meet current expenses.

In order that the school board may know at any moment how much money remains in each fund, it should require its clerk or other financial officer to keep a system of accounts which will provide this information Moreover, the board

Month	Income								Expenditure								Budget		
	Local Taxes	*State and Federal Aid*	*Rentals*	*Sale of Property*	*Tuition*	*Depository Interest*	*Other Sources*	*Total Income*	*General Control*	*Instruction*	*Operation of Plant*	*Maintenance of Plant*	*Fixed Charges*	*Auxiliary Agencies*	*Debt Service*	*Capital Outlay*	*Total Expenditure*	*Amount of Budget*	*Balance Available*
July																			
August																			
To Date																			
September																			
To Date																			
October																			
To Date																			
November																			
To Date																			
June																			
To Date																			

Figure 8. Suggested form for making a monthly financial statement to the school board (Enough copies of this form should be mimeographed for at least one school year, one copy for each monthly meeting will be needed for each board member and each executive of the board The form should include space for each month of the school fiscal year)

should require this officer to make to each board member a monthly statement which lists the sources of income per month and to date, the amount of the budget, and the budget available. A sample form for making such a statement is shown in Figure 8.

6

Planning and Financing School Buildings

DETERMINING THE BUILDING NEEDS

1 How serious is the building problem of the schools today?

Already there is a serious school building shortage in the United States, and this shortage will probably continue for several years because of the rapid increase in school enrollment. A recent nation-wide survey by the United States Office of Education found that by 1957-58 this country will need 600,000 additional classrooms—222,000 to meet the increased school enrollment, 126,000 for the replacement of obsolete buildings, and 252,000 to take care of the backlog of former years.

Of course, this shortage is much more acute in some communities than in others, it is an outgrowth of the national increase in population and especially of the large shifting of population from some communities to others that have had better employment opportunities.

Making the problem of supplying the additional classrooms more severe than ever before is the present high cost of school buildings—from $30,000 to $35,000 per average classroom, if the related facilities such as offices, gymnasiums, and

toilets are included, some of the wealthier school systems have recently spent $75,000 per classroom and their related facilities. To meet their school-building needs, many more communities will be required to have state or federal assistance.

2 Why should a thorough survey of school-building needs be ordered by the school board before a new school building is authorized or planned, and what information should such a survey obtain?

Such a survey should be ordered and made because school buildings are somewhat permanent and expensive, and it is possible to waste several thousand dollars through constructing a building that is improperly located, too large, or poorly adapted to the educational program of the community. And, worst of all, several hundred thousand dollars could be wasted in the erection of a large building that was not needed In making a school-building survey the following information should be obtained:

1. Since new buildings cannot be justified until all the present buildings are used to capacity, the extent of use of all the present buildings should be learned

2 The number, the type, and the residences of the pupils to be immediately accommodated, and similar data for the pupils to be accommodated within the next few years, should be ascertained

3. The probable building needs of the entire school system should be estimated for the next five, ten, twenty, or thirty years, and every new building should be planned and located in relation to this program. As a part of this long-time program, the present buildings should be carefully inspected to ascertain how many are satisfactory for further use in their present condition, how many can be repaired and made satisfactory for further use, and how many should be soon or immediately abandoned. For

the expenditure of a few thousand dollars an old school building can sometimes be modernized so that it will serve for many more years.

3. Who should collect the information on the school-building needs of the community?

In most instances the superintendent of schools and his staff should be held responsible for collecting this information. When, however, the school system is very large and the administrative staff does not have time to collect the information, the school board should consider the advisability of employing an outsider or outsiders to make or to assist in making the survey. This outside service may usually be obtained at small cost from the department of education of colleges and universities.

SELECTING AND PURCHASING SCHOOL SITES

4. When should a school site be selected?

As a rule, the site should be selected and purchased, or an option taken on it, a few years before it will be needed for building purposes This recommendation is made especially for cities, and particularly for those which are growing rapidly. Early selection, especially in the cities, is urged for the following reasons

1. It will assure a more desirable site, since there will probably be more vacant land from which to choose Moreover, it will enable the school board to protest the establishment in the neighborhood of any business which would be harmful to a wholesome school environment.

2 It will obtain the site desired at a much cheaper price Land values tend to rise rapidly in a growing neighborhood, especially when a new school building is contemplated for the area

To summarize, the selection of a school site is too important to be made at the last minute. The site will stand for years as a monument, good or bad, to the school board that selected it.

5. Who should select the school site?

Just as they should cooperate in all matters of school administration, the school board and the superintendent should work together in selecting the school site Of course, the school board must make the final decision, but should make it on the basis of adequate information collected chiefly by the superintendent and his staff. A good school site cannot be selected through guessing or dreaming, it can be selected only on the basis of many facts on school enrollments, safety, school environment, and other school matters.

6. How may community fights which often result from the selection of school sites be avoided?

Some of the most bitter community fights have resulted from the selection of school sites, and the scars of these fights have frequently remained for many years It is natural for each parent to desire, if not insist, that the new school building be located close, but not too close, to his home, and it is also natural for owners and sellers of possible sites to urge the selection of those sites and their purchase at the highest price possible Thus, it frequently happens that the "East End" becomes engaged in conflict with the "West End," or the "North Side" with the "South Side" These conflicts will often have to be compromised by the school board, but the conflicts are never *rightly* compromised unless the board has made its selection entirely on the basis of the best interests of the people of the whole community.

Although it is too much to expect that all community jealousies and rivalries can be eliminated and that all the

people of the community can be made happy over the site selected, these aims should be accomplished as nearly as possible. Greater public approval for the site which is to be selected may be obtained by the school board and superintendent using such procedures as the following.

1. Before selecting the site, formulate a list of standards which the site should meet, then follow that list (A suggested list of such standards will be found below, in question 7) Give these standards ample publicity through community newspapers, public meetings, and other available agencies. In brief, make all decisions with only the interests of all the children and the whole community at heart. Tell the people the bases on which the decisions were made and ask their help in improving the bases.

2 If several sites are under consideration, and if community factions are developing over the matter, consider the advisability of bringing in outside authorities to aid in the selecting, or to act as referees

Since the support of the community is necessary for a smoothly functioning school system, every possible effort should be made to avoid friction over the selection of a school site. It should be remembered, though, that there will be more friction over the selection of a *poor* site than will ever come from the selection of a *good* one.

7. What standards should a school site meet?

A school site should meet the following standards, or the best balance and coordination of these standards

1. The site should be centrally located to the pupils it is expected to serve. Elementary-school pupils should not be required to walk more than one mile and high-school pupils not more than two miles, of course, these distances should be decreased whenever possible. The direction in which the population is growing should be kept in mind, as well as the location of the present

population Spot maps locating both present and prospective enrollments should be constructed, such a map is shown in Figure 9 The direction in which the school population is growing may be obtained from a study of birth certificates, new factories, new residential districts, and extensions of public utilities. Getting such information is not difficult in most communities

The site should be located near, but not too near, streetcar lines, bus lines, and other public transportation facilities It should be located with convenience to the community interests (post office, church, lodges, stores, etc.) of the people

It should be located in a wholesome environment for the education of children It should be free from undue moral and physical hazards, unsanitary conditions, and similar influences. Nearness to such things as railroads, factories, dangerous bodies of water, airports, heavily traveled highways, bad odors, stone quarries, stockyards, cliffs, and forests which are likely to have ravaging fires, should be avoided

2 The size, shape, and topography of the site should meet proper standards. The *size* should be determined by such factors as the number of pupils to be accommodated, the availability of land at a reasonable price, and the type of school to be erected The site should be large enough to afford ample space for playgrounds, for placing the building, for landscaping, for experimental gardening, and for any probable growth in the enrollment of the school. In many states the size of sites for rural and consolidated schools is determined by state law The *shape* should be in dimensions of two by three, three by four, three by five, four by five, or of approximately one of these. The *topography* should not require too much expense for grading, it should be as level as possible.

3. The soil should be quick-drying, and should be free from decaying matter and artificial construction It should readily permit the development of a good lawn, landscaping, pupil gardening, and playgrounds

4. The drainage should be natural, or it should be possible to construct easily and cheaply an artificial drainage system The elevation should be proper, that is, neither too high nor too low

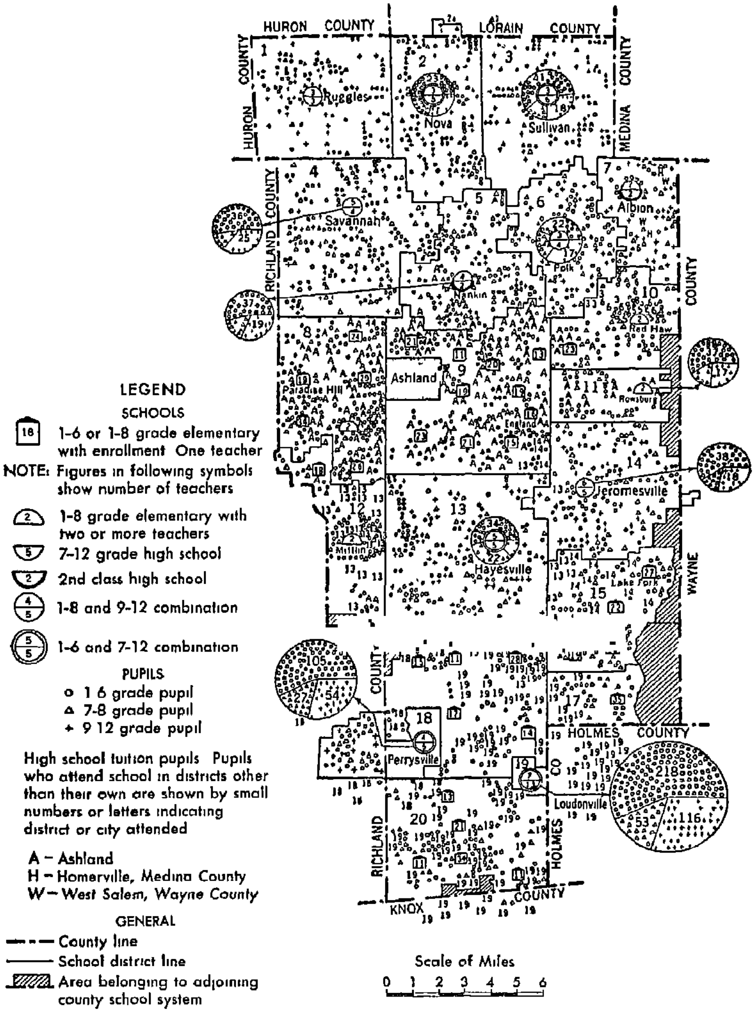


Figure 9 Spot map showing the number, types, and residences of pupils in Ashland County, Ohio (From T C Holy and John A McKnight, *Study of Local School Units in Ohio*, p. 196)

5. The water supply should be of a good quality and should be sufficient. This matter should be especially checked in rural communities, which must usually depend on wells for their water supply

6. Sunlight should be able to reach the site during the entire school day, or during as much of the school day as possible.

7. The cheapest site should be selected, provided it meets the other standards mentioned above. In rapidly growing districts the site should be selected and purchased a few years in advance of the erection of the school building.

All of these standards are very simple, but they are frequently forgotten by school boards and superintendents. They should be remembered and used.

8. After the school site has been agreed upon by the school board, how should it be purchased?

The method to be used in purchasing a school site should be determined by the local situation; there is no one best method which can be used under all conditions. However, one of the following methods should be followed

1. The school board may purchase the site *direct from the owner*, without the help of a third party. This method may be used when it is known that the owner is public-spirited and will therefore be likely to ask only a reasonable price for his property

2. The board may purchase the site through *the help of a third party*, without the owner knowing the identity of the purchaser This method may be used when it is known that the owner would be likely to request a higher price from the public than he would from a private purchaser

3 The board may acquire the site through *condemnation proceedings* In every state, the laws provide that property for public purposes may be acquired through this method. The method may be appropriately used in dealing with owners who

ask an unreasonable price for their property Moreover, the use of this method stops the cry of graft, which is occasionally raised when sites for public buildings are purchased

The tendency in practice is toward the use of the third method, because it seems to be fair to both buyer and seller

9 Should school boards purchase land with the sole intention of selling it sometime at a profit?

School boards are not justified in purchasing land, or anything else, for purposes other than present or future school use. They should not use public funds to purchase anything with the sole intention of later selling it at a profit, in other words, they should not "speculate" with public funds, because speculation is hazardous and is not fair to the public.

OBTAINING ARCHITECTURAL SERVICES

10 What qualifications should the school architect possess?

More than any other person, the architect determines the merit of the school building In planning and designing a building a well-qualified architect can save his salary manyfold, and a poorly qualified one can waste his salary manyfold The architect largely determines whether the building will meet the educational needs of the community, whether it will be constructed without waste, whether it will be safe and healthful, and whether it will be beautiful or ugly According to the Report of the Committee on Schoolhouse Planning and Construction of the National Education Association, a school architect should possess the following qualifications

1 Familiarity with modern educational practice and the activities conducted in a modern school

2. Open-mindedness to suggestions and willingness to revise plans so long as they can be improved .

3 Originality and extended experience in school architecture. .

4 Professional spirit shown by his desire to secure the solutions that are best for the community and its children

5. Executive ability to keep all working harmoniously

11. How should the school board select the school architect?

He should be selected entirely on the basis of qualifications, not on the basis of local residence, "politics," "pull," or similar considerations The two following methods of selection are now being used

1. The method which is almost always used is to select the architect *without an organized competition* Under this method the board interviews the various applicants and non-applicants, inspects one or more buildings which each qualified candidate has designed, secures all other pertinent information on each candidate, then selects the person whom it believes to be the best qualified.

2. The other method, which is seldom used, is to select the architect on the basis of a formally announced and *organized competition* In this method each competitor is required to submit tentative plans and drawings for the building Most school authorities, as well as most architects, recommend that this method be used only when the first method fails They do not recommend the method because (1) it is expensive, and (2) many excellent architects refuse to enter a competition.

The board, of course, should not select an architect who is the friend of a board member or the superintendent, unless he is the best-qualified applicant It is always better to lose the friendship of an unqualified architect than to lose the respect of the whole community or any considerable part of it.

12. Under what conditions should the school board consider the employment of a full-time and salaried architect?

The employment of a full-time and salaried architect should be considered in large and rapidly growing school systems, because such systems always have sufficient new construction or major repairs under way to keep such an employee busy. Investigations in large cities, such as Philadelphia, St. Louis, and Cleveland, show that architects are obtained at much less cost on a salaried and full-time basis than in other large cities which employ their architects on a percentage basis.

When architects are employed on a percentage basis, the fee usually amounts to 6 per cent of the cost of the building, this fee covers the drawing and writing of plans and specifications and the supervision and inspection of construction. The drawing and writing of plans and specifications are usually allotted 4 per cent of the fee, while the supervision and inspection of construction are usually allotted 2 per cent

13 Why should a schedule of the rooms to be contained in the building be made by school officials for the architect before he begins drawing the building plans?

A schedule of the rooms to be contained in the building is necessary before the architect can begin drawing the plans for the building. This schedule should be based upon the educational needs of the community at the present time and for a few years ahead. It should be prepared by the superintendent of schools and his staff with the cooperation of the school board, and it should be approved by the school board.

The schedule of rooms should contain for each room the following information· (1) the grade or subject to be taught

in the room, (2) the location of the room in the building, (3) the pupil capacity of the room, and (4) the type and location of each large item of equipment to be used in the room. Any changes made in the information contained in this schedule should be approved by the school board upon the recommendation of the superintendent. The architect should be encouraged to suggest needed changes in the schedule, but he should not make any changes except with the approval of the school board and upon the recommendation of the superintendent.

PREPARING AND APPROVING PLANS AND LETTING CONTRACTS

14 What objectives should school officials and the architect keep in mind in preparing and approving the plans and specifications for a school building?

According to the Report of the Committee on Schoolhouse Planning and Construction of the National Education Association, the following objectives should be kept in mind in planning a school building

1. It should be adapted to the educational needs of the community.

2 It should make proper provisions for the safety of its occupants.

3. It should be healthful

4. It should be convenient

5 It should be so planned that it may be readily expanded and otherwise changed to meet future needs

6. It should be beautiful.

7. It should be constructed without waste

15. Why should the preliminary floor plans and the equipment plans for a school building be carefully inspected and approved by school officials?

Even the best architects are not *perfect;* therefore, careful inspection by the school board and its administrative staff of the preliminary plans will often bring suggestions for the improvement of the plans. After the plans have been approved by the school board, the architect may begin making the working drawings and writing the specifications for materials and workmanship, these, though, may often have to be revised before they are in final form.

16. What are working drawings and specifications, and why should they also be carefully inspected and approved by school officials?

The working drawings and the specifications may be regarded as the final plans for the building As stated above, they are made by the architect, and he or his helpers must usually spend hundreds of hours in preparing them They are the guide to the contractor of the building, and they are also the basis for the bids which prospective contractors make They specify the kind and the quality of materials and workmanship which are expected to be used in each part and in each detail of the building. They should be inspected carefully and approved by the school board and its executive staff before bids from contractors are requested.

17. How may the best bids possible be obtained on building contracts?

An attempt should be made to obtain bids from as many contractors as possible, and this requires that the letting of the contract be properly advertised Before a contractor can

place his bid, he must see the plans and specifications for the building and must know the conditions of the bidding, and sufficient copies of these materials must be provided by the school board.

Most states prescribe by law the manner in which building contracts shall be advertised and let Circular letters to contractors, and advertisements in newspapers and builders' magazines, are regarded as excellent ways in which to advertise for such bids The successful bidder should be required to give adequate bond to guarantee the satisfactory completion of the building within a specified period of time

SUPERVISING AND INSPECTING CONSTRUCTION

18 Why is it necessary to provide proper supervision and inspection when school buildings are being constructed?

Such supervision and inspection must be provided in order that the school board may know that it is obtaining the materials and workmanship for which the contract calls The board should make certain that all phases of the construction meet exactly the plans and specifications stipulated in the contract made between it and the contractor.

19 What methods of supervising and inspecting the construction of school buildings are being used?

The following methods are now being used Each school board should select the method which would seem best to meet the needs of the local situation.

1. By far the most frequently used method is for the school board to make the architect responsible for the supervision and inspection

2. The next most frequently used method is for the school to employ someone other than the architect to do the supervising and inspecting

3. The least frequently used method is for the supervision and inspection to be provided jointly by the architect and an employee of the school board It has merit, but sometimes leads to disagreement

PAYING FOR SCHOOL BUILDINGS

20. Should new school buildings be financed through the sale of bonds or from the proceeds of current taxes?

The usual practice has been, and still is, for school boards to finance new school buildings through the sale of bonds, that is, through borrowing. The chief argument advanced for this plan is that it distributes the payment over the years of use of the building and does not place an undue strain in any year upon the taxpayer; this argument applies particularly to school districts which have only one or a small number of school buildings

The chief argument advanced against the bonding plan is that it requires a large interest charge, which in long-term bonds may amount to as much as the principal of the bonds. It is argued further that such debt is usually created in good times, but that the bonds must be retired and interest on them paid in bad times as well as good Many financial authorities have begun to view with alarm our debt for schools and other public purposes

21. What are the two plans of bonding, and which is better?

The two plans of bonding and their relative merits are as follows:

1. The *serial-bond plan*, which makes provision for retiring a specified part of the total debt each year This plan is required by state law in most states, and the tendency everywhere is toward its use. The plan should be used whether it is or is not required by the state.

2. The *straight-bond plan* (sometimes called *term-bond plan*) of retiring all the debt at one time, for example, in five, ten, twenty, or some other number of years. This plan is not recommended because the interest charges on such bonds often amount to more than the face of the bonds when they come due. When straight bonds are issued, a sinking fund should be created to pay off the bonds upon maturity.

22 What is a sinking fund and how should it be administered?

Webster's International Dictionary defines a *sinking fund* as "the aggregate of sums of money, set apart usually at fixed intervals, and deposited or invested to extinguish a debt, or for other purposes" Although the theory back of such funds is excellent, authorities in school administration are usually opposed to them because most school systems do not administer them efficiently. The funds are frequently used for other purposes, and at other times they are not properly invested.

23. In issuing and selling school bonds what further steps should the school board take?

The following further steps are suggested

1 See that all details of the bonds are in agreement with the laws of the state.

2. Advertise the sale of the bonds in ways which will obtain the best possible bids The state laws usually prescribe the manner in which such advertising shall be conducted The state laws must be followed.

3. Sell the bonds at a public sale rather than at a private one. Public sales obtain more and better bids, and they are fairer to all concerned.

4. Do not make the term of the bonds any longer than necessary, and never make it longer than the life of the improvement for which the bonds are issued Bonds for equipment should be limited to ten-year terms; those for buildings and sites could be for longer terms, depending on their estimated lives.

5 Consider the advisabilty of having a recall provision in the bonds This provision is especially recommended when interest rates are high But bonds having a recall provision do not sell as well as those not having such provision

6. Keep a record of pertinent information on all bonds. The information which should be kept is as follows. the total outstanding bonded indebtedness of the schools, the amount of bonds maturing each year, the improvements obtained by each bond issue, the time and place for paying the interest on each issue, and the name and address of the purchaser of each issue.

7

Use of School Buildings

PUPIL USE OF THE BUILDINGS

1. How much waste results when school buildings are not used to capacity?

A school building is used to capacity when every desk, or other pupil station, of every classroom is used during every period of the school day. The largest waste in school buildings is caused by the failure to use them, up to the standard just mentioned. When it is considered that the school buildings of the United States have cost more than $15,000,000,000, and when it is remembered that they are used only eight, nine, or ten months of the year, only five days of the week, only six, seven, or eight hours of the day, and that thousands of classrooms are not used to capacity during the school day, the large waste in the unused buildings is brought forcibly to attention Investigations have shown that a large number of school buildings, especially high school buildings, are used at less than two-thirds of their capacity during the school day, in other words, many school buildings are larger than they need to be

Of course, the percentage of use varies from school to school and from school system to school system As a rule,

the elementary schools make more complete use of their space than the high schools do, partly because their schedules are less complicated. In fact, because of recent large increases in school population, which were described in the preceding chapter, many classrooms, especially in the elementary schools, now have *too many* pupils in them.

2. What are the causes of the waste in unused buildings and how may they be eliminated?

Since failure to use school buildings to capacity results in a waste of several million dollars annually in the United States, the causes of the waste should be sought and eliminated. Much of the waste in unused buildings is the result of poor planning of the buildings before they are erected; this poor planning is evidenced by failure to estimate accurately the attendance in the whole school and the enrollments in the various subjects and classes. Much of the waste is also due to the inefficient scheduling of classes, especially in the high school. The waste in many communities has resulted from a decrease in school population, caused by many families moving to other communities.

The largest waste in school buildings is found in the small use of *special* rooms such as the auditorium, the gymnasium, the cafeteria, the shops, and the laboratories. In many schools these rooms are used only one or two periods per day. Modern school officials are taking two steps to eliminate this waste. First, in the erection of buildings, they are planning and equipping these special rooms in such a manner that they can be used for classes in English, history, and other subjects, second, they are adopting new types of school programs, such as the platoon program, which have as their chief purpose the making of capacity use of all parts of the plant throughout the school day.

3. When a school system has a shortage of school buildings, what may the school board do to relieve the situation until additional buildings can be provided?

The following procedures may be used to relieve such shortage

1. See that the present plant is used to capacity. Investigations have shown that, even in communities which claimed to have a school-building shortage, many buildings had classrooms which were not used throughout the school day When these rooms were used to capacity, many more pupils could be accommodated, and more classrooms were not needed.

2. If feasible, change school zones or boundaries in order that pupils from crowded schools may attend schools which are not crowded.

3. Consider arranging for two shifts of pupils, one shift to attend school during half of the day and the other shift to attend during the other half. This suggestion, however, should not be acted upon unless absolutely necessary, because at best it is a poor makeshift for full-day school advantages, half-day school sessions handicap the pupils and "slave" the teachers who must care for two different groups of pupils

4. Consider the use of portables and other temporary structures. Temporary structures, however, should not be permitted to become permanent provisions as has been the case in many communities.

The last two procedures will provide only makeshift facilities, while the first two will give permanent relief.

4 What action should school boards take to make certain that school property is not unnecessarily damaged when it is used?

Under even the best conditions, all the wear and tear of usage of school property cannot be prevented In many

schools, however, school property is not treated with proper respect by pupils, employees, and other persons who use it. Sometimes the desks and other furniture have been whittled by pupils' knives; paper wads stain the walls; finger or shoe marks mar the walls, pencil, ink, and chalk marks are found almost everywhere, and window glass is frequently broken. These are only a few of the examples of misuse, and occasionally of downright vandalism, on the part of many pupils and other users of the building.

These depredations make the building unsightly and less useful, and they shorten its life, they result in millions of dollars in damage annually to the school buildings of the nation, and worst of all they teach pupils a disrespect for property, both public and private. These depredations can and should be prevented They can be prevented if the school board and superintendent use such procedures as the following

1 Put all property in a respectable condition by cleaning, painting, and making all repairs as soon as needed Run-down property is always a greater invitation to vandalism than well-kept property "A stitch in time saves nine"

2 Request, and even *require*, school employees to see that proper respect for property is taught to pupils If they are given a small amount of guidance, pupils will cooperate with school officials and employees in keeping the buildings spick and span, they are not vandals born and bred, they like to live in beautiful surroundings, and they abhor ugly surroundings.

3. Instruct janitors and other school employees to make sure that all doors and windows of buildings are kept locked during the time that the buildings are not in use. All offices, and perhaps all other rooms, should also be kept locked when not in use

4 See that a janitor or some other responsible person is in charge of the building when it is used during evening and other out-of-school hours

5. Try to arrange for each building to have a janitor or some other type of custodian during the summer months. The tendency is toward the employment of school janitors on a twelve-months basis, of course, they should usually be given a vacation of two to four weeks during each year of employment.

6 Require malicious destroyers of school property to pay for the damage, and in extreme cases have them prosecuted. However, the legality of requiring pupils to pay for damaged property is extremely doubtful, because pupils are minors and therefore do not have any money of their own

COMMUNITY USE OF THE BUILDINGS

5. What is the tendency regarding the use of school buildings by community organizations?

Since the time of the founding of the first schools in the United States the school building has been regarded as the "community capitol." This tendency toward making the school an important center of community life continues to grow, and it will undoubtedly go much further. Today, school buildings are being opened for the educational and recreational use of the general public during the evenings, and at other times when the work of the day-school pupils will not be hindered. Adult education is being emphasized almost everywhere today, because it is realized that only a beginning in education can be obtained in the eight, twelve, or sixteen years of the school and college Many states now give special financial aid to school systems which establish classes for adults.

In addition to being used as a meeting place for adult classes, the school plant is being used by dozens of welfare, civic, and other community organizations for evening meetings. Some of the organizations which make frequent use of the school plant are parent-teacher associations, mothers'

clubs, Red Cross, people's forums, welfare organizations, health organizations, farmers' institutes, Boy Scouts, Girl Scouts, Chambers of Commerce, labor organizations, political parties, Americanization clubs, and lyceums.

6 For what purposes should school boards grant the use of school property?

The statutes and court decisions of each state determine, at least in general terms, the purposes for which school boards may or shall grant the use of school property. These statutes and decisions vary from state to state, but most of them prescribe that school buildings shall be open to community organizations which have the purpose of promoting the public welfare. The statutes of many of the states enumerate these organizations that must be granted the use of school property

In practically all states the statutes and court decisions give school boards much discretion in determining the purposes for which they may or shall grant the use of school property. The courts have not interfered with the exercise of this discretion unless there is evidence that it has been abused The following principles should be kept in mind by school boards:

1. The statutes and court decisions of the state should always be followed, especially when they are explicit

2. Since schools are maintained first of all for the pupils, community use of school property should not be permitted to interfere with pupil use Moreover, school money should not be spent for keeping school buildings open for community use, when the money is needed to maintain school for the day-school pupils

3. After the demands of pupil use have been met, community organizations which definitely contribute to public welfare should be served in the order in which they contribute to that welfare.

If a school board follows the foregoing principles, a great deal of misunderstanding will be avoided, and the interests of both the community and the pupils will be best served.

7. What organizations should be required to pay a fee for the use of school property, and on what basis should the amount of the fee be determined?

Whether a fee should be charged should be determined by the condition of the finances of the school system and by the purpose for which the property is to be used In many communities the school funds are barely sufficient to keep the buildings open for the regular pupils, and when this is true the use of any of the funds for even the most worthy community use should be opposed by school board members. As a rule, the small school systems do not charge fees as frequently as the large systems.

Three practices regarding fees are found among the smaller communities. These are (1) to give free use of buildings, (2) to charge a fee for janitor services only, or (3) to charge a fee for heat and light as well as for janitor services

Most city school systems charge a fee sufficient to cover the expenses of janitor services, heat, and light. Whether a charge shall be made, and the amount of the charge, are usually determined by the purpose of the use and by the expense incurred in the use Thus, organizations such as the Boy and the Girl Scouts and parent-teacher associations, which are closely allied with the work of the school, should be excused from the payment of fees or should be charged a smaller fee than organizations which are not so closely related to the regular work of the school.

Although school systems should always strive to provide sufficient funds for an adequate use of school buildings and grounds by the civic and welfare groups of the community,

they should always recognize that the children of *today*, rather than the children of *yesterday*, have the first claim to the interest and support of the public. And they should recognize it, although the children of today are not yet old enough to vote; they will find that following such a practice will not be difficult to defend to the voting population of the community.

8. How may the danger of community friction over granting the use of school property be decreased?

Some of the most bitter school and community fights have been caused by wobbly policies of school boards in granting the use of school property to certain groups and refusing its use to similar groups. For example, the use of a school building has sometimes been granted to one political party for a public meeting and refused to another political party for a similar meeting. School boards that make their decisions on such a basis are sure to be accused of partiality and highhandedness, and friction will be engendered in the community.

Such friction may best be prevented by every school board adopting a fair, clear, and written set of rules and regulations which it will follow in the letting of school property for community use. These rules and regulations should prescribe the method of obtaining permission to use the property, the conditions of use, and any fees which must be paid. As a part of the rules and regulations, there should be an application blank which organizations seeking the use of school property would be required to fill out. A set of rules and regulations, together with an application blank, reduce to routine much of the work of letting school property, moreover, such a set gives greater assurance that all community organizations will be treated fairly, and thus it leads to better public relations. The

school board should request its superintendent or his representative to formulate a set of such rules and regulations and to submit it to the board for its approval, amendment, or rejection.

9. In the planning of school buildings what care should school boards take to see that the buildings are better adapted to community use?

Since school buildings are being used more and more by community organizations, this tendency should be kept in mind when the buildings are being planned and erected. It should be especially kept in mind in the rural communities, because there the school building is often the only building which is available for use as a community center.

The parts of school buildings which are most often used by the community are the auditorium, gymnasium, lunchroom, library, and toilets. These facilities should, therefore, be planned with that use in mind. In planning them, an attempt should be made to locate them at such a place in the building that the general public will not have access to the remainder of the building, and they should be located on the first floor, if possible. In every case, however, it should be remembered that school buildings are erected for the education of children, and any conflict between community use and pupil use should be decided primarily in favor of the latter.

8

Repairing and Insuring School Property

REPAIRING SCHOOL PROPERTY

1. What are the causes of the depreciation of school property?

By *depreciation* is meant a wearing out or deterioration This wearing out or deterioration goes on constantly in everything and leads to the need, in due time, of repair and of replacement. Nothing can be made to last forever. What nature and man provide, they also constantly damage and eventually destroy.

There are four causes of the depreciation of school property. The first and usually the largest cause is the *wear and tear of usage*. A second cause is *physical decay* A third cause is *obsolescence*, that is, a growing out of up-to-dateness. The fourth cause is *accidents*. All these factors are constantly at work on every school site, every school building, and every item of school equipment.

2. How may school boards decrease the depreciation of school property?

Depreciation is a waste, and although it cannot be entirely prevented, its rate and its amount can be reduced. School

boards should take, or should see that the superintendent takes, the following steps to decrease the depreciation of school property.

1 Require school employees to make certain that the employees, pupils, and other persons do not misuse school property. In any campaign to teach respect for school property a first step to take is to place the property in a "respectable" condition; when that has been accomplished, pupils and other users are likely to cooperate in keeping the property "respectable" All civilized people respect well-kept property Keeping school property in good repair is a part of good public relations.

2. Arrange for all repairs to be made as soon as practicable after the need for them has been discovered. An early making of the repairs is recommended because (1) an unrepaired school plant is a temptation to vandalism, (2) postponed repairs are likely to cost more to make, and (3) the school may have to be closed temporarily if the making of the repairs is delayed too long.

3. What types of repairs on school buildings are most frequently needed?

Although heating systems, roofs, doors, and windows need frequent repairs, most school buildings are in greater need of painting, floor finishing, desk finishing, and other types of decorations than any other type of repair. Because of failure to obtain these improvements on time, many buildings are dirty and otherwise run down and fail to possess an attractive and homelike appearance. Since paint and other types of decoration are cheap, and soap and water are even cheaper, there is little excuse for permitting any building to continue to resemble a "pigpen"

Most school buildings have wood floors, and keeping them

in good condition presents an almost endless problem for school officials and employees. The problem is especially large in rural schools, because the gravel, sand, and cinders which pupils "track in" are certain to damage the floors. The usual treatment recommended for wood floors is to clean them thoroughly, then to apply a good grade of floor seal, of course, if the floors are badly marred, they should be sanded before applying the seal to them.

Wood floors which have become eyesores can often be covered with good linoleum or block tile to make them serve for several years longer. Since the floors of the school corridors have the most severe traffic, special attention should be given to their upkeep and repair.

4 How may the need for repairs be regularly ascertained?

In order that needed repairs shall not go undiscovered for more than a few months, an annual inspection should be made before school closes in the spring that plans may be made for doing the repairing during the summer vacation. When the inspection has been completed, the repair schedule for the summer may be made It is a good plan to classify the repairs into the two following groups first, those that cannot be postponed, and second, those which, while not absolutely necessary, are desirable. Repairs in the first group should be made immediately, and those in the second should not be postponed longer than absolutely necessary

Of course, some repairs are of an emergency nature and cannot be postponed for even one day. For example, the heating, lighting, or water systems won't work, or a door to the entrance of a school building can't be closed Provision for such repairs must be made as soon as the need for them is discovered.

5. When should a school building be abandoned rather than repaired for further use?

Although repairs may have been carefully and promptly made, it is impossible to keep a school building entirely up-to-date and in its original condition. The time finally comes when a decision must be made for every school building on the question of whether it should be abandoned immediately or repaired for further use. In making this decision, the educational utility of the building and the health and safety of the pupils and employees should be the deciding factors. The financial condition of the school system must also be considered. The cost of repairing and operating an old building is often greater than would be the charges for repair and interest on a new building of equal capacity

When school buildings are abandoned because of being in a dilapidated condition, they should usually be torn down or otherwise disposed of as soon as possible. Sometimes an abandoned building may be remodeled and used for a shop and storehouse for the school system; sometimes, too, it may be used as an administration building for the system. If they are not soon put to use again, or torn down, abandoned school buildings become community eyesores. Moreover, abandoned buildings are a constant temptation to vandalism. When good school buildings are abandoned because of decreased enrollments, they should not be disposed of immediately; they should be kept a few years, until it is definitely known that they will not be needed again for school purposes of any kind.

6. To what extent, if any, should school janitors be expected to make repairs?

School janitors can, and should be expected to, make many repairs of an emergency, a minor, or a nontechnical nature

During the summer months many of the larger school systems organize the janitors into work gangs for the making of repairs. For example, those who can paint are placed in the painting gang, and those who can do carpentry, masonry, plumbing, electrical work, window cleaning, or other work are placed in appropriate gangs. Over each group is usually placed a foreman who is especially competent in the type of work which he will supervise This plan gets needed work done and makes it more possible to give janitors year-round employment

7 Should school-building repairs be made by full-time repair workmen, or should they be made on a job basis?

Since the amount of repairs which they have is not sufficient for full-time employees, most of the rural, village, and small-city school systems employ workmen on a contract or a per-hour basis for repair jobs. The larger school systems may practicably employ, on a regular salary, full-time repair workmen; for example, they may employ one or more full-time carpenters, plumbers, painters, masons, electricians, and landscape gardeners. A carpenter should probably be the first full-time employee, and a painter should probably be the second.

8. To what extent, if any, may the time of pupils be used in making repairs?

Educators are agreed that some of the time of pupils may be used in making repairs, provided the pupils are sufficiently skilled and provided the work has educational value for them They are agreed, however, that after a pupil has done a certain type of repair so long that it has ceased to have educational value, he should not be permitted or required to con-

tinue it For example, the refinishing of a few school desks would probably be educational to a pupil in industrial-arts classes and could therefore be justified, but the refinishing of several dozen desks could probably not be justified as an educative experience. Pupils are sent to school *to learn,* and school officials and employees should never be guilty of profiteering upon their time.

Of course, pupils of proper age may be paid to make repairs during school vacations. Teachers also can be found who like to help with school repairs during vacations

9. When should a school system have its own repair shops?

School systems which have more than approximately 20,000 population should consider the advisability of establishing a shop in which repairs to equipment may be made and in which certain items of equipment may be constructed. School systems of this size which have established repair shops, and which employ one or more repair workmen, have usually found that such an organization obtains financial economies and gets the repairs made more quickly and competently.

INSURING SCHOOL PROPERTY

10. What is the purpose of school insurance?

Insurance has the purpose of softening the blow of accidents and other misfortunes. It is a contract whereby one party, in consideration of a stipulated premium, promises to pay a stipulated sum upon the occurrence of a stipulated contingency, such as injury to one's person or destruction of one's property

11. What types of insurance do school boards carry, and what types should they carry?

The types of insurance which school boards most frequently carry are listed and briefly explained herewith.

1. *Fire.* Pays for loss consisting of injury to or destruction of school property by fire. This is by far the most frequently carried type of school insurance

2. *Tornado, cyclone, or other type of windstorm.* Pays for loss occasioned by any type of windstorm.

3. *Boiler.* Pays for loss to school property occasioned by an explosion of the boiler which is insured, it also usually pays for personal injuries caused by the explosion.

4. *Liability.* There are two types of liability insurance, namely, (1) *bodily injury*, and (2) *property damage* Bodily injury liability pays on behalf of the insured all sums which the insured shall become obligated to pay by reason of the liability imposed upon him by law because of bodily injury, caused by accident and arising from the ownership, maintenance, or use of the property insured. Most policies set a financial limit for each accident.

   Property damage liability pays on behalf of the injured all sums which the insured shall become obligated to pay by reason of the liability imposed upon him by law for damages to or destruction of property. It should be emphasized that this type of insurance pays for damages to the *other* person's property, not for damages to the property of the person insured.

   These two types of insurance are coming more and more to be carried on school buses, delivery trucks, and other types of school vehicles. They are carried espe-

cially by the rural school districts, which usually have pupil-transportation programs.

Since the courts of most states have stated that school boards are not *liable* for accidents, there is considerable doubt about the legality of spending public funds for protection against a liability which they do not legally have.

5. *Collision* There are two types of collision insurance, namely, (1) *full,* and (2) *deductible.* Full collision insurance pays for the full loss consisting of damage to or destruction of the transportation vehicle and its equipment, caused by accidental collision with another object, either moving or stationary, or by upset, or while the vehicle is parked or unattended.

   Deductible collision insurance pays for loss consisting of damage to or destruction of the transportation vehicle and its equipment, caused by accidental collision with another object . . . , but only for the amount in excess of the deductible sum stated in the policy. The deductible sum may be stated at any amount, but the usual amount ranges from $25.00 to $50.00

   Full collision, of course, costs more than *deductible collision* insurance, because the insurance company is liable for the entire cost of the full collision type of insurance

6. *Accident.* Pays the amount stated in the policy for certain types of injury and for death; this amount is paid whether the school or its employees were responsible for the accident or not. In many states all school employees are insured under state-wide workmen's compensation laws, and in thousands of other school districts accident insurance is carried on all pupils transported.

Many state athletic associations and numerous local athletic associations carry group accident policies on all athletes. These policies are financed by non-public funds, not by public funds.

7. *Theft, robbery, or pilferage.* Pays for loss consisting of the theft, robbery, or pilferage of the items insured. This type of insurance is often carried on motion-picture projectors, music instruments, typewriters, microscopes, and similarly valuable equipment, it is also often carried on the contents of school vaults. In some states, however, the courts have decided that public funds cannot be used for such insurance, because in those states the courts have reasoned that "no person is supposed to steal."

The types of insurance, if any, which should be carried by the school district will be determined first of all by the statutes and court decisions of the state. The carrying of certain types of insurance is permitted or required in certain states, but is prohibited in other states. If the expenditure of public funds for it is legal, a given type of insurance should be carried when the risk of loss is too large for the district to assume. Because their risks are not as widely distributed, small school systems are in much greater need of most types of insurance than large systems. Since the fire hazard is the main one with which school officials are concerned, and since fire insurance is carried by practically all school boards, the discussion of the remainder of the chapter will emphasize fire insurance Since transportation insurance is coming to be carried more and more, it will be discussed in Chapter 11, which deals with the problems of pupil transportation Several types of transportation insurance are recommended in that chapter.

12. How frequent are school-building fires?

According to the National Board of Fire Underwriters, approximately 2500 school-building fires occur annually in the United States Of course most of these fires are small, and only in the rural districts, which are frequently without fire protection, do school-building fires often result in complete losses.

All these school fires result in an annual loss of more than $10,000,000 in the school systems of the whole nation Practically all school-building fires are preventable; in fact, it may be logically argued that *all* of them are preventable. It is the obligation of school boards and school employees to do everything possible to reduce the number of school-building fires to a minimum, or to eliminate all the fires.

13. What care should school boards and employees take to prevent and to extinguish school-building fires?

School boards and employees should make certain that such procedures as the following are used in preventing and controlling school-building fires

1. Since the heating plant and the electrical system are known to be the most frequent causes of fires, great care should be taken to see that they are properly installed and kept in good repair Of course, similar precautions should be taken with all other parts of building construction and equipment

2. All fire hazards in and around the buildings should be removed. Rubbish, dead grass and weeds, and similar fire menaces should not be permitted to accumulate Matches, ashes from burning grates, waste paper, and similar materials should be kept in fireproof receptacles In shops and laboratories, which usually have highly combustible materials, special attention should be given to the storing and use of such materials

3. An inspection of all buildings should be made at least once each year to ascertain any fire hazards This inspection may be

made by a school official or school employee, or by a representative of the local fire department.

4 Ample and workable fire-fighting facilities should be provided for each building When fire hose and running water are not available on each floor of a building, chemical fire extinguishers should be provided, they should be provided especially for shops and laboratories These extinguishers should be inspected annually, and it should be known that school employees know how to use them

These precautions will not be found expensive, and they are certain to pay large dividends to the school system in fewer fires, in greater safety to all users of the buildings, and in reduced insurance premiums on the buildings

14. What precautions should school boards and superintendents take to protect the occupants of school buildings in case of fire?

In every school the principal and the teachers should be required to hold a fire drill at least once each month In practically every state a state law makes this requirement, school boards should make certain that the law is enforced. Fire escapes should also be provided for every building having more than one story, and it should always be known that they are in good working condition

15 Should school boards always carry fire insurance?

Just as many large corporations, such as railroads and chain stores, do not carry insurance on their property, likewise many of the large school systems do not carry it. These large organizations believe that since their risks are so numerous and so widely distributed in various communities and states, they are justified in taking this chance

Although the practice of not carrying fire insurance seems to be defensible in the unusually large school systems, it is not desirable in the small ones. The loss of one building in a small school system would usually mean a staggering blow if the building were not insured, moreover, the loss of one building in such a system would amount to as much as the insurance premiums for many years. Small school systems should always carry adequate insurance.

16. How does the amount of fire losses paid by insurance companies on school buildings compare with the amount of insurance premiums paid by school boards on their buildings?

State-wide investigations in several states show that the fire losses paid on school buildings amount to only approximately one-fourth of the premiums. Since it is known that the usual expense for overhead of fire insurance companies is approximately 40 per cent of the premiums, it is obvious that the profits on insuring the school buildings of these states are large even when the necessity which all fire-insurance companies have for building up large reserves is kept in mind. All the evidence indicates that school buildings, especially in the cities, are good insurance risks.

17 When school boards believe that fire insurance rates are too high, what may they do to obtain a reduction in the rates?

The following steps have been taken in many states, and may be appropriately taken in other states when needed

1. The school boards of the state may request the insurance companies doing business in the state to make a reduction in their rates on school property.

2. The school boards may recommend to the legislature that the state organize its own insurance system for school buildings. Such a system has been in operation for several years in North Dakota, South Carolina, and Wisconsin, and large economies are shown in each of those states. Several other states are now considering state insurance on school buildings

3. If a school system is large, the school board may carry its own insurance through setting up an insurance fund, or it may take the chance that a fire will not occur and not even create such a fund Most cities of more than 300,000 population have adopted one of these two plans. Both plans have been found to work very successfully, in that much unnecessary expense has been saved.

In several states, the state education association has cooperated with school boards in trying to obtain more reasonable insurance rates on school property throughout the state. Many associations have also cooperated in trying to obtain state insurance systems for the schools.

18. What further economies may school boards obtain in their expenditures for fire insurance?

Investigations show that in most school systems economies in fire insurance may be obtained through adoption of the following practices:

1. Purchase insurance policies for a three-year term, thus obtaining a lower rate than can be obtained for a shorter term.

2 Obtain a careful appraisal of the property insured Never insure for more than the value of the property, and never insure for less than the value, especially in the small rural systems Consider insuring the property under coinsurance for approximately 80 per cent of its insurable value

3 Reduce fire hazards by making minor changes in the construction of the building, under ideal conditions, these features would be included when the building is being erected

4. Provide fire-fighting equipment for the building

The adoption of these practices throughout the nation would result in the saving of millions of dollars annually in the insurance bills of the schools Of course, any savings to the schools increase the funds available for education of the pupils.

19 With what companies and agents should school boards place their insurance?

School boards face two problems in placing their insurance The first is to make sure that the insurance is placed only with the most reliable companies, the second problem is to apportion the insurance among the several local agents on a just and equitable basis. Some school boards divide their insurance business equally among the various agencies of the community, others award it to the various agencies according to the amount of local taxes paid by the agencies; still others permit the various agencies to help determine how it will be awarded Whatever plan of distribution is used, the school's insurance business should never be permitted to become a "political plum" to be awarded.

Whether school property should be insured with mutual companies is still a debatable question Some states prohibit public officials from insuring with "mutuals" because of the common belief that they do not carry adequate reserves and the uncertainty over the amount of the premium It should be stated, however, that many "mutuals" have established an excellent record for the full payment of losses, and the recent tendency has been to permit public property to be insured in them the same as in "stock" companies Of course, some mutual companies are better than others, just as some stock companies are better than others, and school officials must strive to select the best.

20. What insurance records should the school board keep?

The school board should instruct its clerk, secretary, treasurer, or another of its officers to keep a record of all insurance. This record should show for each policy such information as the following number of policy, name of company, name of agent, date of issuance, date of expiration, amount of policy, rate of premium, name of property covered, and kind of insurance. It goes without saying that all policies should be kept in a safe place, this place should be a fire-proof safe or vault in a school building or a safe-deposit box at a local bank.

9

Obtaining School Janitorial Service

IMPORTANCE OF THE SCHOOL JANITOR

1. What new title are many school systems now giving the school janitor?

Many school systems give the school janitor the title of school *custodian*, because they believe that the new title is more dignified. By far the majority of school systems, however, still use the title of school janitor, and it will be used throughout this book. The present writer doesn't know of any opinion poll on which title the present school janitors would prefer, but, he heard of one school "custodian" who didn't like his new title, because it seemed to mean that he could be "cussed" by the teachers and was to "toe to" the wishes of his principal. If the janitors of a school system express themselves as preferring the new title of *custodian*, the school board should probably approve the change. But, whatever the title of the position, the duties will remain the same; and there should be little controversy over titles, because "a rose by any other name would smell as sweet."

2. In what ways is an efficient janitor an excellent investment for a school?

Next to the teachers, school janitors constitute the largest group of school employees. They should be a concern of

every school board and superintendent. Contrary to the belief of many school board members, and a few superintendents, the janitor is an important school employee. He does much more than "build fires and sweep out." He is important because he performs, or should perform, the following necessary services for the school.

1. More than any other person, the janitor sets the housekeeping standards of the school He keeps, or should keep, the building and grounds spick and span, he believes, or should believe, that "cleanliness is next to godliness" Since the housekeeping standards of the janitor are likely to determine the housekeeping standards of the pupils and to carry over into their after-school life, these standards of the janitor should be raised to a high plane by every school system; examples are always potent in education

2. The janitor has custody of a building, equipment, and grounds which cost a large amount of money. He makes many repairs, and he reports all needed repairs which he is not qualified, or does not have the time, to make He keeps the building locked when it is not in use, and he protects the grounds, building, and equipment from unnecessary injury It would easily be possible for a janitor to cause a loss of hundreds or thousands of dollars to the school plant through only one act of carelessness on his part.

3 The janitor uses annually hundreds or thousands of dollars' worth of supplies in cleaning, heating, lighting, and other servicing of the building In a large school building he could easily waste or save an amount equal to his salary in the use of supplies

4. With the exception of the principal, the janitor has more to do with the health, safety, and comfort of the occupants of the school building than any other school employee He makes certain that the building is properly heated and ventilated, that it is clean, that it is fumigated after an epidemic of contagious disease, and that the water supply is ample and pure He sees that the fire escapes and the sidewalks are in good repair and are cleared of snow and ice He removes the fire hazards which often accumulate in the basement, under the stairways, and in other parts of the building and on the grounds

5. The janitor has an important educational influence in the school. The pupils hobnob with him at recess and at other school intermissions. Unless he is intelligent and is clean in mind and body, his influence upon the pupils is not likely to be the best Moreover, the janitor hears much, sees much, and often says much regarding the school, and all of this makes him an important public-relations agent; he can create good will for the school or he can thoughtlessly develop ill will for it.

A good school janitor, then, is not only versatile, but is intelligent, conscientious, industrious, and agreeable as well It bears repeating that he is an important employee.

3. How plentiful are well-qualified school janitors?

Most school boards and superintendents claim that well-qualified janitors are difficult to obtain for the salary offered, they claim that good janitors are much more scarce than well-qualified teachers. Unlike teachers, who always have had special preparation for their work, few janitors have had such preparation, and most of them are therefore a gamble. Of course, mere "coal shovelers and broom pushers" are fairly plentiful, but school janitors must, as was pointed out above, perform many duties besides the more obvious ones of shoveling coal and sweeping

SELECTION AND IMPROVEMENT OF THE SCHOOL JANITOR

4. Upon what basis should school janitors be selected?

Because of their importance in advancing the work of the school, janitors should be selected only on the basis of their qualifications to fill the position for the salary offered School boards and superintendents should not be guilty of selecting janitors or any other employees on the basis of "politics," of "the need for a job," of family relationship, or of some other

indefensible consideration. They should remember that the school janitor's position is both difficult and important, and that any "Tom, Dick, or Harry" cannot fill it.

In their attempt to eliminate "politics," "pull," and other types of favoritism, many of the more progressive school systems require all candidates for janitorial positions to take an examination on the duties which janitors are expected to perform This examination usually contains an oral as well as a written part In many cities school janitors have been placed under the civil-service laws of the city or the state and must pass an examination before they can legally be employed.

5. Who should select the school janitors?

School boards have the legal power to appoint janitors as well as all other school employees, and they should continue to exercise it. They should, however, make their appointments only after the qualifications of the available candidates have been carefully investigated by the superintendent of schools or his representative, and his nomination duly considered One of the largest handicaps to school-janitorial service today is the fact that in hundreds of school systems the janitors are being selected by the school board without consulting the superintendent, the business manager, or any other executive officer of the school, worst of all, they are sometimes appointed upon a "political" basis and, therefore, feel little or no loyalty to the superintendent, principals, or teachers of the school. School board members are not likely to be fully acquainted with the qualifications which school janitors should possess, or to have the time to examine the qualifications of the various candidates, they should seek the help which superintendents are qualified to give them in the selection of janitors and of all other school employees

6. Who should supervise and direct the work of the janitor of a school?

The chief executive of the school, that is, the principal, should be expected to supervise and direct the work of the janitor. He should not only supervise and direct the work, but he should obtain the cooperation of pupils and teachers in making the janitor's load no more burdensome than necessary. The janitor should be treated as a human being, rather than as a beast of burden or a slave, only employees who are treated thus will be happy and inclined to put forth their best efforts

7. What means may be used to prepare school janitors for their work?

The more progressive school systems are using such means as the following in better preparing school janitors for their work:

1. Many of the larger cities have organized janitorial schools which provide practical instruction on the janitor's work Many of the smaller school systems encourage their janitors to attend the janitorial schools which are sometimes held in neighboring school systems or colleges, many school systems pay the expenses of their janitors when attending such schools

2. Janitors' associations are frequently formed, and these usually hold regular meetings to discuss janitorial problems and the improvement of janitorial services and opportunities

3 In many school systems a set of rules and regulations covering the janitor's work is presented to him, preferably before he is employed. In small school systems this does not need to comprise more than a few pages, and these may be mimeographed at small expense

4. Many of the larger school systems appoint a supervisor of janitors who visits each building regularly and makes suggestions to the janitor for the improvement of his service to the school

5. The principal of the school frequently makes appropriate suggestions to the janitor on how he may improve his work or do it with the expenditure of less time and energy When these suggestions are reasonable and are tactfully presented, they will be appreciated.

The intelligent and ambitious janitor will see many ways of improving his own work. But no matter how good he is, he will need some instruction, especially when he is new. The spirit of the widespread movement for the in-service preparation of teachers should be carried over to the in-service preparation of janitors The in-service preparation of school janitors has been too much forgotten.

8. What provisions should school boards in rural districts make for janitorial services for one-room schools?

In one- or two-room schools, the teachers are usually required to perform some or all of the janitorial services. Many school boards pay the teachers of such schools a small sum for performing such services or permit the teachers to use the money to employ one or more of the older pupils to perform the services. The more progressive boards also employ someone to give the building, the equipment, and the grounds a complete cleaning before the opening of school in the fall.

PAY AND TENURE OF THE SCHOOL JANITOR

9. Upon what basis should school janitors be paid?

The amount of salary which school janitors are paid determines largely their qualifications If the janitors' qualifications in any school system are low, one of the first matters which the school board and superintendent should investigate is

whether the salary is sufficiently high to obtain and to keep persons of proper qualifications. An employee worth a salary of two or three thousand dollars annually can seldom, if ever, be obtained for a salary of one thousand dollars. No employee can live on thin air, and no one will even attempt to do so.

Salaries of public janitors in many communities, especially the large cities, are frequently set by civil-service commissions, and the salaries of school janitors are often under the regulations of these commissions. School boards whose employees are under such commissions must strive for changes in regulations which may be handicapping the obtaining of the best janitorial services for the schools.

The salary of every janitor should be determined by the amount of work to be done, the difficulty of doing the work, and the efficiency with which the work is performed. The more progressive school systems have designed a pay schedule for the various kinds of janitorial work to be performed. In such a schedule, the following matters are usually considered in determining the amount of pay: (1) cleaning, (2) heating and ventilating, (3) washing windows, and (4) care of lawns and sidewalks. Items 1, 3, and 4 are usually paid for on a *square-foot* basis, while item 2 is usually placed on a *cubic-foot* basis, especially when coal is used for heating. The rate of pay for each of these four types of service is usually determined in part by the type of building and in part by the age of the building Since old buildings are often more difficult to care for than new ones, a higher rate of pay is usually given for them.

Several states have already provided pension systems for all school janitors. These systems should be established by all the states. Sick-leave policies for janitors should also be provided

10. Should school janitors be employed during the whole year or during the school months only?

The number of months for which a school janitor is to be employed should be determined largely by the size of the building and grounds over which he has custody. In the small rural and village school systems he is usually employed during only the months of the school term. In the city schools he is usually employed during the whole calendar year Whenever possible, year-round employment is recommended for the following reasons

1 It gives the janitor employment and an income throughout the calendar year and thus results in the obtaining of a better qualified type of employee.

2. It makes someone responsible for the care and protection of the building, equipment, and grounds during the summer months

During the summer months the janitor can be occupied in giving the building a thorough cleaning, in making many repairs, in looking after the receipt and storage of fuel and other supplies, in caring for the lawn and playgrounds, and in opening the building for community meetings. In many school systems, during part or all of the summer vacation, the janitors are organized into small work gangs for doing certain repair jobs; a complete description of this plan of securing repairs was given in the answer to question 6, Chapter 8, and need not be repeated here.

Of course, when janitors are employed on a year-round basis they should be given a vacation, with pay, during the summer months The practice is to give two or three weeks' vacation each year with full pay. The amount of vacation is usually determined by the number of years' service in the school system

11. What should be the length of service of the school janitor?

He should be selected entirely on the basis of qualifications and should be retained for as many years as he performs his duties efficiently. The practice which many school systems have of changing the janitors every time the majority membership of the school board changes cannot be defended, it cannot be defended because it handicaps the obtaining of the best qualified persons and it does not place any premium on efficient service Many janitors who have worked several years in the same school have become school traditions, and some of them have become so revered that they have had school buildings named for them

10

Administration of School Supplies

SELECTION AND PURCHASE OF SUPPLIES

1 *How and by whom should the kind of supplies to be purchased for a school system be determined?*

The kind of supplies for a school system or any part of it should be determined by the use to be made of the supplies, by their cost, and by the amount of money available for them. The policies of progressive school systems usually require the school superintendent to appoint supply committees of school employees, and give to these committees the responsibility for investigating the supply needs and for making recommendations on the kind and the amount to be purchased. Most of the large school systems keep a standard supply list, and this list is revised, as needed, from year to year by the committees just recommended Since supplies are used only once, their quality should not be higher than is sufficient to meet that need.

The school board should not purchase supplies or equipment without consulting the superintendent, principals, teachers, janitors, and other employees who must use the materials. Persons who must use the materials should know best about the most appropriate kind and quality to be selected. When school boards do the selecting, there is danger that classrooms,

attics, basements, and other parts of school buildings will be cluttered with unused and unusable supplies and equipment. School boards are probably as unqualified to select proper supplies for a school as a board of trustees for a hospital is unqualified to select proper food, medicine, and other supplies for its institution. School boards should, of course, determine the general policies which shall govern the selection, purchase, and use of supplies, and they should see that full value is obtained from each dollar expended. But this should be the extent of their concern with supplies, they should assign all other phases of the administration of school supplies to the superintendent and other appropriate school employees.

2. How should the amount of supplies to be purchased for a school system be determined?

The amount of supplies to be purchased for the next school year should be based on accurate information which has been obtained from the various schools and departments of the school system. All estimates of needs for each supply item should take into account the amount used during the previous year and should also provide for any probable increase or decrease in school enrollment. The more progressive school systems standardize the amount of supplies to be allocated each pupil, they then purchase for the whole school system on the basis of the total enrollment. These school systems also distribute supplies, especially the instructional ones, to schools, to departments, and to individual teachers on a per-pupil basis

Since purchasing in large quantities will usually obtain cheaper prices for the school system, sufficient supplies, except in the case of perishable articles, should be ordered for one school year whenever possible. Of course, the amount of storage space available in the school system, and the amount of funds immediately available for supplies, will help to

determine whether the purchase of a quantity sufficient for one year is practicable or not. Making purchases sufficient for a period longer than one year, however, is not recommended, even when there is a belief that prices in the next year will go higher; public funds should not be used to gamble on future prices.

3 What instructional supplies should be furnished free to pupils?

The tendency everywhere is toward furnishing free instructional supplies to all pupils, this practice is followed especially in the elementary school. Since teachers, buildings, transportation, fuel, janitors, and other school services and facilities are furnished free, it would seem logical to furnish free pencils, paper, workbooks, and all other school supplies To furnish free supplies would seem especially desirable since pupil supplies constitute one of the smallest items in the school budget, moreover, free school supplies contribute to the equalization of educational opportunity, which has come to be accepted as an American ideal. If the condition of the school budget does not permit furnishing supplies to *all* pupils, they should be furnished to indigent pupils first. Moreover, they should be furnished to pupils of the elementary school before those of the high school. In other words, free supplies should be provided first of all for those pupils who are most in need of them or are least able to purchase them

4. How much special consideration, if any, should school officials give the local dealer in the purchase of supplies?

Since the local dealer is a local taxpayer, often has children in school, and has a special interest in the community, most

school authorities and the general public favor giving him the school's supply orders when his quality, prices, and services are equal to those of non-resident dealers They agree, however, that when his quality, prices, and services are *not* equal to those of non-resident dealers, he should not be favored The schools are run for the education of the pupils, they are not run to provide an unreasonable profit for anyone. When school officials extend an unjustified favor to anyone, they are certain to be condemned by other persons living in the community.

5. What advantages, if any, would there be in school systems engaging in cooperative purchasing of supplies?

In many neighboring school districts of the United States the local school boards purchase their supplies cooperatively. In California cooperative purchasing among the rural school districts of each county has been required by state law since 1928, and the practice has resulted in large savings there and in all other places where it has been tried

Cooperative purchasing obtains lower prices which usually come from large-scale purchases Investigations in California and in other states show that such purchasing results in an annual saving of three to five thousand dollars in the average county. In few instances school boards, county commissioners, city councils, and other public officials have cooperated in purchasing supplies for their respective divisions.

6. During what season of the year should supplies be purchased?

Since most school supplies may be purchased at a lower price during the spring and summer months, they should be

purchased then. Coal, which is the largest school-supply item, may usually be purchased from 10 to 20 per cent cheaper during the spring and summer months Purchase during those months is also recommended in order that the supplies may be delivered to the school, checked, paid for, and made ready for use at the opening of the school term.

7. How should bids for supplies be administered?

In most states the laws require that supplies which cost more than a certain amount, usually two or three hundred dollars, shall be purchased through bids Moreover, the laws usually outline the procedure which shall be followed in letting the bids. Whether the laws require this procedure or not, bids should be obtained on all supplies costing more than two or three hundred dollars. The adoption of such a procedure will usually save money for the school system, and it will protect the school officials from the charge of graft and partiality which is often made when bids are not obtained

In letting bids, specifications for each supply item to be purchased should be drawn carefully and other rules which are to govern the bidding should be made. In purchasing stationary, pencils, crayons, and similar materials, it will be found advisable to submit samples and to require that the supplies shall be of the same type or of an "equally good" type. The specification of only one "brand" will result in only one bid, which may be too high in price The specification of one brand should be avoided.

The letting of all bids should be advertised through desirable channels. School officials have found that the most effective method of advertising is to send a circular letter to all supply dealers who might be interested in bidding on the supplies to be purchased Newspaper advertisements are also effective and are required by law in many states

8. Why should supply deliveries be checked before payment is made for them?

When supplies are delivered, their quality, quantity, and condition should be checked before payment is made for them. Any school board which does not make provision for this check risks being cheated, either by accident or by intention of the seller. It should see that its superintendent, clerk, business manager, or other appropriate employee is delegated the task of making this check. The results of this check should be properly reported.

9. At what time should payment for supplies be made?

Since many supply companies provide a discount of 2 to 10 per cent for bills which are paid within ten, twenty, or thirty days, the school board should arrange its business procedures so that such discounts may be obtained. The board's rules should stipulate that when approval has been given for the purchase of supplies this approval also authorizes the payment of the bill as soon as the supplies and the invoices for them are received, checked, and found to be in accordance with the purchase order.

STORAGE AND REQUISITIONING OF SUPPLIES

10. What provisions should be made for the storage of supplies?

The following practices, or a combination of them, are used in the storage of supplies:

1. The supplies are placed immediately in a *storehouse* which serves the whole school system. Under this practice all supplies, except fuel, are placed in the central storehouse from which they are distributed as needed to the individual schools. Such a storehouse should meet the following standards: (1) be centrally

located; (2) be as near as possible to a railroad, and (3) be amply provided with fire protection, bins, and shelves Central storehouses are seldom feasible except in the large cities

2. The supplies are stored immediately in the *individual schools.* In some schools the educational supplies are stored in the principal's office, and in other schools they are stored in the rooms where they will be used. This plan of storage in the individual schools is universally used in the rural and village school systems, and is also used in most of the city systems

Each school system will, of course, use the plan which meets its own needs and takes into account its facilities. There is no *best* plan for every situation, because needs vary from school system to school system.

11. What provisions should be made for the requisitioning of supplies?

School officials should provide a definite plan by which supplies may be requisitioned by principals, teachers, janitors, and other employees. Such a plan is necessary in order that all supplies purchased may be accounted for and that waste may be prevented, the plan is particularly necessary in school systems which have a large number of employees. The school board should delegate to the superintendent and other administrative officials the formulation and the operation of the accounting system for supplies, the board should, of course, always reserve the right to inspect and to approve such system.

ECONOMIES IN USE OF PUBLIC UTILITIES

12 What economies should the schools attempt to obtain in their use of telephones?

All city school systems and most of the larger rural ones make regular use of various public utilities, such as telephones,

water, gas, and electric current. Much money is spent for these services, and many opportunities for effecting economies exist in the expenditures for each service For the more economical use of telephones, the following suggestions are made.

1. Telephones in many buildings may be disconnected during the summer months, thus saving the rental on them during those months.

2 Schools and departments which use a large number of telephones should consider the practicability of installing a switchboard Often the switchboard operator can serve also as information clerk and can do typing and other secretarial work

Many of the larger schools, especially the high schools, have installed pay telephones for the use of persons who have private business to transact.

13. What economies are possible in the school use of water, gas, and electric current?

Procedures such as the following may be used by school officials to effect economies in the expenditures for these utilities·

1 Every school building should be provided with a separate meter for each utility service in order that comparisons of costs for each building may be made. These comparisons should be reported periodically to the principal in charge of each building

2 When buildings are being erected, the lights of each room should be placed on different switches in order that the part of the room farthest from the windows may be lighted first. Lights should be turned off when not needed.

3. Commercial rates should be obtained from the utility companies whenever possible These rates usually permit a summary of the readings of the various meters and the submission of one bill for the whole school system at a reduced rate.

11

School Consolidation and Pupil Transportation

THE GROWTH OF SCHOOL CONSOLIDATION

1. What are consolidated schools, and what is the tendency regarding the establishment of such schools?

In rural school administration the outstanding development during recent years has been the consolidation of schools, that is, the abandonment of one or more small schools, usually one-teacher schools, and the bringing together of the pupils into a single larger, that is, *consolidated* school. During the last five decades, more that 100,000 one-teacher schools have become extinct, and in every state their number has been rapidly decreasing. What happens when schools are consolidated is shown in Figure 10 on page 156 The contrast between the present number of schools in the county illustrated and the number of schools in former days is revealing, contrasts as striking could be found in hundreds of other counties.

2. Why have consolidated schools had such a large increase in number?

The chief factors which have contributed to the large increase in the number of consolidated schools in recent years are the following.

1. The increasing evidence that consolidated schools provide broader educational opportunities than one-teacher schools

2 The migration of people from the rural districts to the cities and towns, this movement leaving thousands of rural schools with such small numbers of pupils that it has been deemed advisable to close them and to transport the pupils to larger schools On a per-pupil basis, the cost of maintaining small schools is very high. Since the teacher's salary is by far the largest item of school cost, a class having only 10 or 15 pupils costs almost as much as a class having 20 or 30 pupils, and small classes are not much more efficient in terms of pupil learning

3. The enlarging of school districts, thus making easier the consolidation of schools.

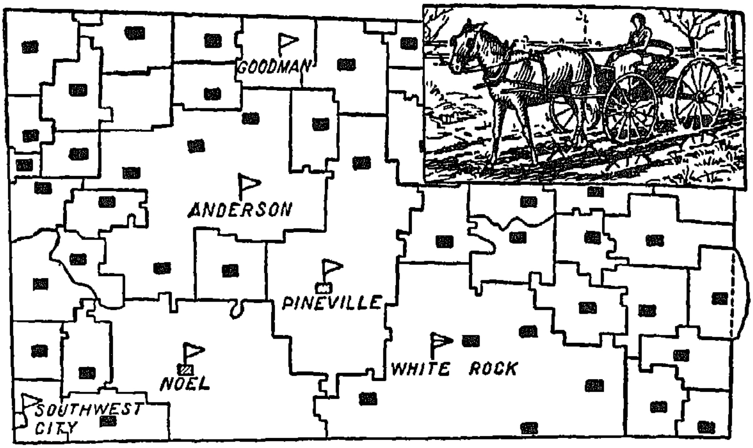
4. The development of the automobile and good highways, thus making it possible to bring pupils together quickly, economically, and safely over a distance of several miles

5. The enactment of state laws which require or permit school consolidation and pupil transportation and which sometimes give state financial support for them

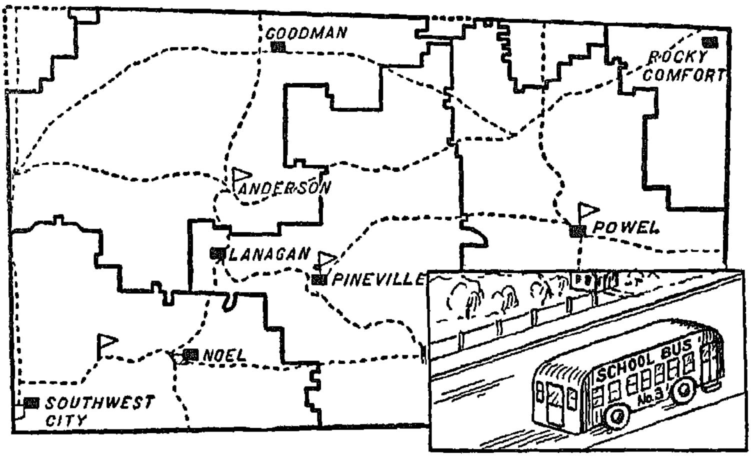
For these and other reasons rural education has been greatly improved in recent years through a widespread consolidation of small schools. The movement toward school consolidation will undoubtedly go much further, because there are still thousands of one-room schools and thousands of consolidated schools that should be merged to make larger schools. Small schools which have both the elementary and the high school grades may often merge two or more high schools while leaving the elementary school grades in their present locations.

3. Why is school consolidation sometimes opposed by a large portion of the people?

Seldom has a "little red schoolhouse" been abandoned without objections from many people These objections have



Small school districts served the small communities of pioneer days when travel was slow



But today this county has good highways, larger communities, and larger school districts.

Figure 10 The change from one-teacher schools to larger schools and pupil transportation (From Frank W Cyr, Arvid J Burke, and Paul R Mort, *Paying for Our Public Schools*, p 144 Reprinted by permission of the International Textbook Company)

come especially from the patrons of, and property owners located near, the school, and ocasionally they have come from the teacher or teachers of the school to be abandoned The chief objections which are frequently raised to the closing of small schools, and which progressive school boards and superintendents should always be prepared to meet, are the following.

1. The disinclination of parents to send their children to school very far away from home

2. The amount of time which pupils must spend on school buses, and the hazards of traveling on them

3 Jealousy over the location of the consolidated school It is natural for all parents to want the school located as close to their children as possible, though they do not want the school located *next door* to them

4 The inclination of many people to preserve the old landmarks and the old ways of education. To many people, "new ideas are as painful as new shoes," and most of us are much more conservative on educational procedures than on many other phases of life

THE NEED FOR PUPIL TRANSPORTATION

4 What relation has there been between growth of school consolidation and of pupil transportation?

School consolidation and pupil transportation have developed at about the same rate, both have grown very rapidly. The success of the transportation system has largely determined the success of the consolidation movement; without the other, neither one of them would have advanced very far. At present, there are approximately 20,000 consolidated

schools in the United States; to and from these schools more than 5,000,000 pupils are transported daily, in more than 100,000 vehicles, and at an annual cost of more than $100,-000,000, these numbers continue to increase appreciably each year.

5. Under what conditions should school boards provide transportation for pupils?

In most school districts, school revenues are so limited that if some of the pupils did not walk a reasonable distance to meet the bus, did not walk all the way to school, or did not undergo some other inconvenience, the school which they attend would have to be cheapened to meet the extra expense of transportation In many states, a maximum distance beyond which pupils may not be required to walk to school or to meet a bus is set by state law. This distance usually ranges between one and two miles for elementary school pupils and between two and four miles for high school pupils. In most states, however, school boards are given large discretion in determining for whom they shall provide transportation. In making its decision on this matter a school board should give first consideration to the health and safety of the largest number of children In addition to distance, the board should keep in mind the following factors· age and physical condition of the child, weather and road conditions, traffic hazards, and the school grade of the child.

Special provisions must often be made for the transportation of those pupils who have severe physical handicaps which prevent them from walking any distance to school. Rural schools usually route their buses so that these handicapped pupils can be picked up at and delivered back to their homes. City schools often use private taxicabs for these pupils

PLANNING TRANSPORTATION ROUTES

6. Why should transportation routes be carefully planned at the beginning of each school year?

If transportation routes are not carefully planned, there will be much criticism from the pupils and their parents Moreover, there will be financial waste. This waste will come from such practices as unnecessary traveling with empty buses, needless retracing of routes, and sending buses over poor roads. There is seldom a system of routes which cannot be improved, and the school officials and superintendents who spend extra time and effort in this endeavor are certain to be recompensed in the greater happiness, comfort, safety, and convenience of the pupils, in economy of operation, and in community support and good will. School officials and employees must learn to work better with highway officials

The most important step in route planning is the making of a transportation map of the school district. Such information as the name, age, grade, and residence of each child entitled to transportation must be known before the map may be constructed; moreover, this information should be present before the school buses can be purchased or contracted for. A map showing the school bus routes of a whole county is presented in Figure 11.

7. Under what conditions should the school board and superintendent consider the advisability of having a school bus make more than one trip?

Multiple routes, that is, the use of a bus on more than one route, are known to be much cheaper than *single* routes The board should, therefore, consider the feasibility of organizing multiple routes where the population is dense and where the highways are good enough to permit safety with a better

than average speed of the bus. Of course, single routes are usually to be preferred because of their greater convenience to pupils and teachers Multiple routes require that some of the pupils arrive at school and leave school before the other

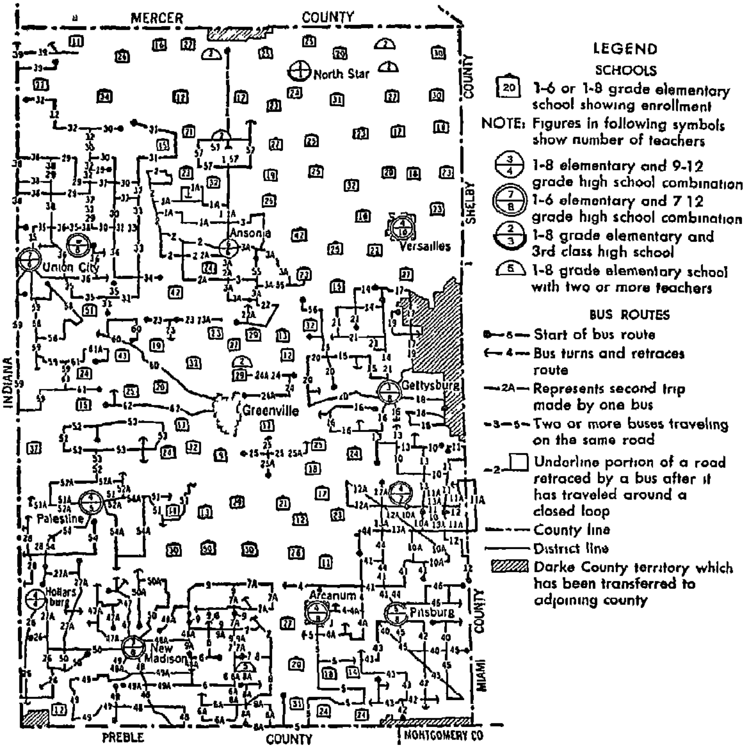


Figure 11. The School bus routes of Darke County, Ohio (From T C Holy and John A McKnight, *Study of Local School Units in Ohio*, p 64)

pupils, and this creates an extra problem of pupil supervision and discipline for the school. One school bus may often be readily made to serve two schools by opening and closing one of the schools earlier than the other.

8. Why should a time schedule be made for every bus route?

In many states all school buses are required by state law or by regulations of the state department of education to operate on a time schedule which shall be put into effect a few days after the beginning of the school term. Good practice requires that such a schedule be adopted for and followed by every school bus, because it is a guide to the bus driver and to every family which has children riding the bus A copy of the time schedule should be given to each parent who has a child to be transported.

THE SCHOOL BUS DRIVER

9. Why should the school bus driver be selected with great care?

He should be selected with great care because he must perform the following important duties

1. Transport the pupils safely and with proper regard for their health, happiness, and comfort He should be especially trustworthy in an emergency, and should try never to be in an accident.

2 Exercise a desirable moral and educational influence over the pupils whom he transports When pupils are on the bus, he serves in the relation of a parent to them and must enforce fair rules

3. Maintain proper custody over the bus which he operates. He must see that the bus is not unnecessarily damaged through usage or in any other manner.

Experience has proved the vital importance of choosing a thoroughly competent and trustworthy bus driver. Tragedies may result if incompetent and untrustworthy drivers are employed.

10. By whom should the school bus driver be selected?

Since the superintendent is more likely to know the relative abilities of the persons available for the position, the school board should delegate to him the responsibility of recommending all drivers. As in the case of the selection of all school employees, the board should always reserve the right to approve or reject such nominations. Many states now have laws requiring school bus drivers to have a license before they can be legally employed

11. Why should school boards have a set of operating rules for bus drivers?

Such rules should be provided every bus driver to help assure that the pupils will be transported safely, comfortably, and on time Many states now have statutes or rules of the state department of education which govern at least the safety phases of the operation of school buses.

THE MANAGEMENT OF SCHOOL BUSES

12 What standards should school buses meet?

Most of the states have enacted laws, or have regulations of the state department of education, which establish certain standards which school buses shall meet There are, of course, hundreds of specific standards which school buses should meet, but space limitations of this book prevent more than a listing and brief discussion of the general standards which should govern the more specific standards Those general standards follow

1. *Safety* is the first standard which school officials should keep in mind when purchasing a bus or approving a contract for a privately owned one Respect for this standard should continue

to lead to the adoption of steel construction, safety glass, emergency doors, standard colors, and innumerable other safety features

2 *Comfort* is second only to safety in its importance as a standard for school buses Such defects as poor ventilation, liability to extreme temperatures, and improper seating provision can injure health and thereby affect the safety of pupils as much as an accident A seat should be provided for each pupil

3 *Durability*, that is, the ability to stand the wear and tear of use, is another factor to be kept in mind in purchasing or renting a school bus Provided the finances of the school board permit, the extra money necessary to secure durability will usually be a good investment

4 *Economy*, especially in the chassis, is still another factor to be kept in mind in selecting and operating school buses

5. *Availability of repairs*, especially for the chassis, is a final consideration to be kept in mind.

13 What provisions should the school board make for the housing, regular inspection, and repair of its buses?

The board should adopt a policy to be followed in keeping its buses in condition for efficient service, and it must assure itself that privately owned ones are kept in the same condition. Many states require an annual inspection of all school buses, sometimes a state agency, such as the state highway patrol, has the responsibilty of making the inspections

School districts which own several buses, for example, more than six, have found that the most satisfactory plan for housing, repairing, and servicing is to own or to rent an equipped garage and to employ an automobile mechanic. In addition to keeping the buses in good repair and properly serviced, in many school systems the mechanic will have time to drive a bus on one of the shorter routes, or to drive an

emergency bus in case of an accident or a breakdown with a regular bus.

14. Should school boards own their buses or contract for them with a private owner?

The tendency is toward school-board ownership of school buses, although most boards still contract for them. Most authorities favor school-board ownership for the following reasons:

1. Practically all investigations have shown that board ownership is cheaper. School-owned buses are not run for profit, moreover, they are usually exempt from all forms of taxation, such as sales and income.

2 Board ownership provides better buses and better transportation service in general. A new school bus now costs several thousand dollars, which most persons as individuals are not able to guarantee.

3. Board ownership enables the school to use the buses for educational visits to factories, farms, institutions, and other places

Since school boards own school buildings, school sites, and all other school equipment, they should also own their school buses as soon as they can arrange to purchase them.

15. What should be the length of a transportation contract which the school board makes?

Since longer-term contracts usually obtain a better type of school bus and lower transportation costs, it is recommended that when the contract plan of transportation is used and the contractor is procuring new equipment, the contract be written for a period of at least three years, provided the state laws permit. After this initial contract, the contract may

be renewed for one year at a time so long as the old equipment is used and is satisfactory to the board. Of course, the school board should not contract with an owner who does not have a safe bus or a dependable bus driver

16. How may school boards finance the purchase of school-owned buses?

One of the following plans may be used, depending upon the provisions of the state laws and the condition of the school board's finances:

1 Paying cash for them This plan is recommended whenever the finances of the school district permit.

2 Issuing bonds for them Bonds, however, should not be issued for a term longer than the life of the buses

3 Obtaining them through a rental arrangement By this plan the board agrees to pay a stipulated amount of rent for a certain number of years with the understanding that it may have title to the bus at the end of the period The legality of this plan is doubtful in a few states

In a school district that has several school buses, a replacement program should be planned whereby all the buses will not have to be replaced during the same year. Experience shows that a good bus that is carefully used should last at least eight years.

17 What control should the school board give to the use of buses for purposes other than transporting pupils on the regular trips between their homes and school?

Because of the greater danger of damage to the buses and of injuries to passengers, the board's rules and regulations governing the use of school buses for other than strictly

school purposes should be even more rigid than those governing the use of buildings, grounds, and other school property for such purposes. All use of public-owned school buses should contribute to the education and well-being of pupils, in fact, they *must* make that contribution in order to be legal Such uses as the following contribute to the purpose just mentioned and should be approved by the board

1. To transport pupils to exhibits, museums, institutions, industrial plants, and similar places which the pupils are observing or in which they are participating

2. To transport ill or injured pupils to their homes, to a hospital, or to a physician.

3. To transport athletic, debating, and other groups representing the school in contests

TRANSPORTATION INSURANCE

18. What liability, if any, does a school board have for accidents?

The answer to this question is completely given under question 10, Chapter 15, of this book and need not be presented here

19. Why should every insurance policy be carefully read before the premium is paid?

Following accidents, many bus drivers and school officials have learned, often to their sorrow, that their insurance policy did not cover all the risks which they believed it did. They had not carefully read their policy. Liability insurance and accident insurance are frequently confused, and school officials should not pay for one of them in the belief that they are obtaining the other or both coverages. Definitions of these and other types of school insurance have been given in the

answer to question 11, Chapter 8, and may be read again if needed.

20 What kinds of transportation insurance, if any, should school boards carry?

The kinds of transportation insurance which should be carried by a school board will be determined first of all by the statutes and court decisions of the state. The kinds to be carried will be determined also by the finances of the board and by whether the board owns the school buses or contracts for them. When the statutes and court decisions permit, the following kinds of insurance are recommended under school-board ownership of buses (1) bodily injury liability, (2) pupil accident, (3) property damage liability, (4) fire, (5) tornado; and (6) either full collision or deductible collision. When the board contracts for its school buses, at least the following types of insurance should be required of the contractor (1) bodily injury liability, (2) pupil accident, and (3) property damage.

Since protection of the pupils should always be uppermost in the minds of school officials, the first type of insurance to be carried should be *pupil accident*, and it should be carried on both school-owned and privately owned school buses.

12

The Curriculum and Teaching Procedures

IMPROVING THE CURRICULUM

1. What is the curriculum?

In the early days the curriculum was regarded as a list of subject matter which pupils were expected to learn and to recite. Since this subject matter was usually limited to reading, writing, arithmetic, and the other school subjects, those subjects usually determined the curriculum In those days *book* learning was regarded as the most important if not the only type of learning, hence the textbooks used by a school determined its curriculum.

During recent years, the curriculum has come to have a much broader meaning than formerly. It has come to include not only textbook learning but all other types of learning in which the pupils engage under the direction of the school As Figure 12 indicates, it includes information, skills, and all other experiences which pupils receive from books, magazines, newspapers, movies, church, travel, play, and all other activities in which they engage under the direction of the school. It is as broad as life, and its purpose is to give the pupils experiences which will prepare them for life. The

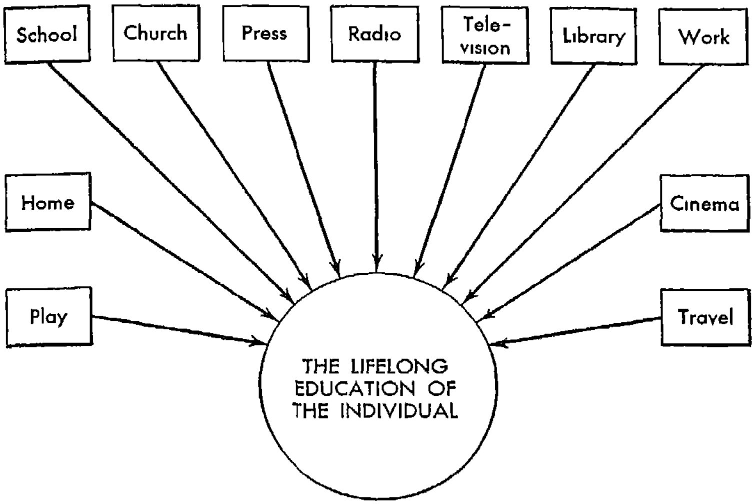


Figure 12. The chief agencies which now contribute to education of the individual. The experiences provided by all these agencies should be a part of the curriculum

merit of the curriculum largely determines the merit of the school.

2. How does the curriculum of today differ from that of earlier years?

Since the school subjects have usually determined the curriculum, the growth of the curriculum may be best seen from observing the increase in the number of the school subjects Because of the growing complexity of society and the tendency for the home to shift the responsibility of education to the school, the school subjects and the materials in them have had to be increased to meet the needs of the pupils The following columns give a bird's-eye view of the growth of the subjects in the elementary-school curriculum from the time of the first schools in the United States to the present

1635	*1775*	*1875*	*At Present*
Reading	Reading	Reading	Reading
Writing	Writing	Writing	Writing
Bible	Arithmetic	Arithmetic	Arithmetic
	Spelling	Spelling	Spelling
	Bible	Conduct	Character Education
		Language and Grammar	Language and Grammar, especially Language
		Geography	Geography
		History and Civics	History, Civics, and Current Events
		Drawing	Art
		Music	Music
		Nature Study	Science
		Physical Exercises	Health and Physical Education
			Safety Education
			Industrial Arts
			Home Economics
			Agriculture
			Consumer Education

The subjects of the secondary school (now usually called the high school) have increased even more rapidly than those of the elementary school (sometimes called the grade school). Whereas the subjects of the first secondary schools of the United States were usually limited to Greek, Latin, and higher arithmetic, most secondary schools of today, especially the larger ones, offer dozens of subjects including English, social studies, sciences, mathematics, homemaking, industrial arts, agriculture, commercial education, foreign languages, music, and health and physical education. For many years the chief purpose of the secondary school was to prepare its graduates for college, and little provision was made for the large number of students who did not desire to, or could not, attend college. During recent years, however, the secondary

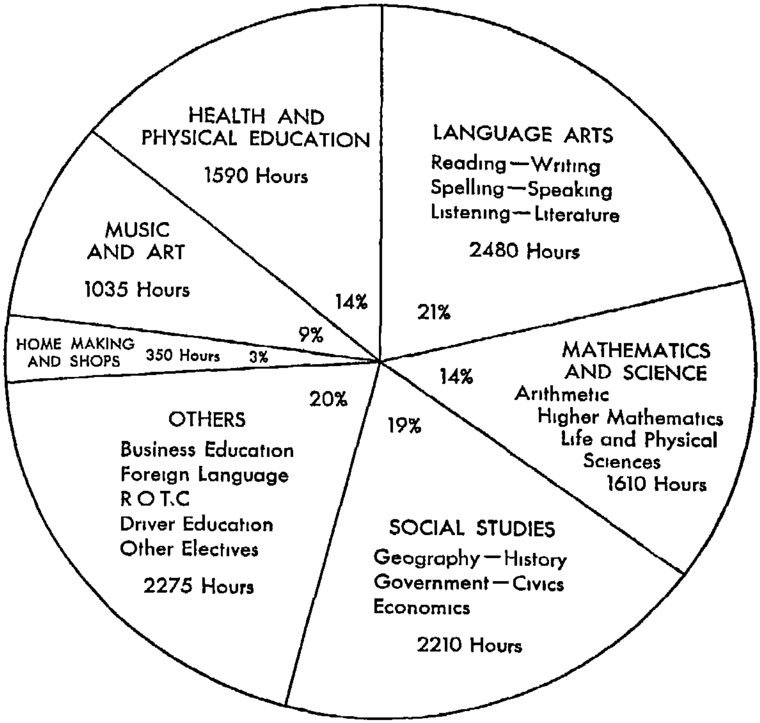


Figure 13 Distribution of pupils' time to the various school subjects A pupil attending school in Oakland from kindergarten through twelfth grade will spend approximately 11,550 hours in school (From *Oakland Public Schools*, Vol 2, p 1)

school has attempted more and more to better meet the needs of all its students, it has attempted to give preparation for life as well as for college.

3. How may the curriculum be kept up-to-date?

The chief criticism which has always been made of the schools has come from their failure to meet social needs, because of their use of an out-of-date curriculum New school subjects have been introduced slowly into the curriculum.

Moreover, when a subject has found a place in the curriculum, the tendency has been to keep it there long after the need for it has passed. Much "dead wood" has been kept in the curriculum largely because the school, like all institutions, has been conservative.

The only way by which the curriculum may be brought up-to-date and kept there is through a constant pruning of this "dead wood" by school officials and employees. Social needs are constantly changing and the school must keep itself informed concerning these changes in order that its curriculum may adequately prepare young people for the kind of life they must actually live. School officials and employees must realize, however, that all fundamental changes made in the curriculum must have the approval of the people of the community.

4. Who should determine what the schools shall teach?

In all states most of the subjects to be taught in the elementary school, and the number of minutes each week that they are to be taught, are prescribed by state law; and many of the subjects to be taught in the high school are also thus prescribed. Beyond these so-called *minimum essentials* each school board determines what shall be taught in the school system over which it has charge. A wise school board, however, will not take any action upon the curriculum until it has obtained the recommendations of the members of the instructional staff of the school system These recommendations should be organized under the leadership of the superintendent of schools and presented by him to the board. Moreover, each teacher should be given permission to make reasonable changes in the curriculum in order that the needs of her pupils may be more adequately met Any teacher who

cannot be trusted with this responsibility is not worthy of a position in the schools, and a school board must determine and enforce this responsibility of its teachers

5. How should the school deal with political, social, and economic questions over which there is a difference of opinion among the people?

There are few, if any, questions of today to which the final answer is known, and there are thousands of questions to which the final answer is *not* known. School boards should not only permit but should expect teachers and other employees to make the pupils acquainted with social, political, and economic questions which are appropriate to the age and understanding of the pupils These questions are resulting in too much conflict among our people and those of other countries, and the schools should give greater attention to them

Teachers should not be permitted to teach the pupils *what to think*, but should be expected to teach them *how to think* They should help the pupils to find and to use the facts and arguments on *all* sides of the questions being discussed, and they should expect the pupils to reach their own conclusions The most important contribution which teachers can make is to develop in their pupils greater respect for the *truth* and to give them preparation for *finding* the truth.

6 Should the schools undertake to prepare pupils for a vocation?

Because of the young age of its pupils, it is generally agreed that the elementary school should not undertake to prepare the pupils for a vocation but should emphasize general education, that is, preparation for citizenship. Since almost four-fifths of the high-school graduates are unable to attend college, the high school should offer as much vocational prepara-

tion as possible for those students who must start earning their living after high-school graduation.

The kind of vocational work to be offered should be determined by a survey of the vocational opportunities of the local community and other communities In rural communities the vocational departments most frequently needed will be agriculture and homemaking, while in the cities the departments most frequently needed will be homemaking, commercial, and various types of industrial arts Since no school can meet the vocational needs of all its students, its aim should be to offer those courses which will meet the needs of the largest number of students.

The chief purpose of the school is to prepare good citizens; therefore, the vocational program of the schools should not neglect to give the pupils preparation in citizenship as well as in the vocations which they wish to enter. It should be the aim of the school to produce well-rounded members of society, and every school should provide an educational and a guidance program which will aid in obtaining that result. Well-rounded individuals will not merely be docile followers, they will be able to think and decide for themselves

7. Why was religious instruction eliminated from the public schools, and how may these schools cooperate in the giving of such instruction today?

Until about 1825, instruction in religion was given in practically all public schools. After that date, it began to be taken from these schools because of the many conflicts among the various religious sects At present, every state prohibits the teaching of religious creeds in the public schools

Most states, however, permit the reading of the Bible in the public schools and will permit discussion of its historical and literary features as long as religious interpretations and creeds

are avoided. The United States Supreme Court recently ruled legal the New Jersey law which requires the daily reading of at least five verses from the Old Testament in the public schools, and allows any pupil to walk out if he does not want to participate.

Most states also permit the public schools to dismiss any or all pupils for a short period of time each week in order that the pupils may go to their respective churches to receive religious instruction. Although the public schools cannot give religious instruction, they should cooperate with other agencies which are organized for that purpose. By so doing they can help to raise the moral standards of their community and of the nation.

THE PLACE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

8. What is meant by extracurricular activities?

The term *extracurricular activities* includes all pupil activities which are not a part of the regular studies of the school Some of the more common of these activities are athletics, debates, clubs, dramatics, and student publications Since such activities have educational value, they should be regarded as a part of the curriculum rather than being outside it Although they are sometimes conducted outside the classroom, they are a part of the learning of the pupil; school officials and employees should give them supervision.

9. Are extracurricular activities receiving too much time and attention in the schools today?

The extracurricular activities have grown very rapidly during the last few decades, especially in the high schools and colleges They have also had a rapid development in

the upper grades of the elementary school. In the larger schools dozens of such activities are usually found, and practically all pupils participate in at least one of them.

In the early days school officials and employees took little or no interest in the extracurricular activities, and in most instances they considered them to be worthless. During recent years, however, forward-looking educators have come to believe that these activities, if properly directed by the school, have large educational value and are worthy of a place in the school program. If properly directed, many of the activities have larger educational value than some of the school subjects. Pupils like to take part in them, and through them valuable and unforgettable lessons in cooperation, sportsmanship, fairness, honesty, loyalty, and discipline may be taught. They also serve as constructive means of self-expression for many students.

10. Is there a tendency for the schools to neglect extracurricular activities of an intellectual type and to emphasize those of a physical type?

Many schools emphasize athletics too much and neglect the more intellectual extracurricular activities such as debates, dramatics, and musicales. In the long run overemphasis on athletics or any other extracurricular activity will be as injurious to the pupils of a school as too much pie or cake is to the human body. School officials and employees have the obligation of making certain that a proper balance is maintained among the various types of activities which their school offers, and they also have the obligation of seeing that each pupil who takes part in the activities does not pursue activities of one type to the exclusion of other types. The development of well-balanced pupils, rather than the production of winning teams, should be the aim of the school.

11. What supervision should the school board expect school employees to give the extracurricular activities?

The school board should delegate to the superintendent, the principal, and the teachers of a school the work of organizing, administering, and supervising all extracurricular activities in the school and should hold them responsible for efficient performance of this work. The board should not interfere in the management of such activities unless school employees prove themselves to be grossly incompetent in performing these duties. It should not interfere in such work as the arranging of school contests or the selection of students to take part in such contests Moreover, board members should not expect free admission to school activities which are not free to the general public, in fact, they should not expect *any* favor which is not given to the general public They should try to be an unselfish example for other public officials and for the members of the community.

12. What supervision should the school board give to the finances of the extracurricular activities?

A number of extracurricular activities receive and spend money, and some of them in the larger schools receive and spend thousands of dollars annually. Whether the amount of money be large or small the school must give supervision to it. No school activity can justly claim that since it has earned its money it should be permitted to spend it in any manner which it chooses. The school board should require school employees to organize an efficient accounting and auditing system for all extracurricular funds. It should also require regular reports to it of the status of all such funds.

School supervision of these funds should be provided for two reasons. In the first place, it will obtain a more eco-

nomical expenditure of the funds. In the second place, it will guarantee the financial honesty and will protect the reputation of all persons who handle the funds. All accounts should be so kept that no one could ever justly question the honesty and the efficiency of the persons who keep them

13. Should public funds be used to finance extracurricular activities?

At present, practically all extracurricular activities are financed through admissions, dues, and other private funds Public funds are seldom used for financing them Since such activities have educational value, public funds may be justly spent for them when the state laws permit and when other more important school work is not cheated. It should be kept in mind, however, that the expenditure of public funds for extracurricular activities is still illegal in many states.

TEACHING PROCEDURES

14. Should the school board prescribe the classroom procedures which teachers shall use?

So long as teachers obtain desirable results with the pupils, the school board should not concern itself with the methods of teaching or other classroom procedures used by them. There are many excellent methods of teaching, and teachers who are worthy of employment should, under the supervision of superintendents and principals, be permitted to select the method which is most appropriate for them and their pupils. In fact, since the *best* methods of teaching have not yet been determined, teachers should be not only permitted but encouraged to do some experimenting with the various methods. Not all teachers should be required or expected to use the same methods. Teachers who never do any experimenting

and who act as if they know "all the answers" are usually the poorest ones; they are apt to be like the Irishman's turtle—"dead and doesn't know it." Progress in any procedure or endeavor can come only through experimentation and a willingness to adopt new methods when they have good prospects of being an improvement over the old.

15. What changes have modern schools made in the old-fashioned recitation?

In the schools of former years the teacher made the same textbook assignment to all her pupils, and expected them to memorize and be able to *recite* the material at the next class meeting or "recitation." The old-time teacher was largely a "hearer of recitations." In modern schools, however, different assignments are often made to the various pupils, and these assignments are made from other books and sources as well as from textbooks. Moreover, during the recitation period the pupils are not only permitted but are expected to do more than recite what they have memorized, they are permitted and expected to discuss and to ask live questions and thereby to receive training in *thinking* as well as in memorizing.

16. Should the schools expect the pupils to prepare some of their school work at home?

Because most parents object to their children being required to do much of their school work at home, schools should adjust their programs in order that such homework may be reduced to a minimum. This recommendation is made especially for the elementary school. Teachers rather than parents, brothers, sisters, and other members of the family should be expected to help the pupils prepare their lessons.

17. What kind of discipline should the schools keep?

Discipline which is too severe, as well as no discipline, should be avoided by the school. The former tends to make pupils afraid of teachers and may give them the feeling that they are being treated unjustly. A lack of discipline tends to make pupils uncontrollable and to encourage them in believing that they should always have their own way. The school should steer a middle course between these extremes. The well-disciplined school does not resemble either "a cemetery or a riot"; it has the amount of freedom which pupils are able to use intelligently.

Discipline should make the pupils understand, and wish to accept, the regulations of the school; its basis is good education, a part of which is self discipline Moreover, the pupils should be given opportunity to cooperate in the making of the regulations. They should be taught to realize that with desirable personal *freedom* goes a large amount of *responsibility* to one's fellows Fear of physical punishment or of the loss of certain privileges is a poor substitute for understanding of and respect for desirable regulations.

18. What are reasonable rules for the punishment of pupils?

Pupils may be punished only for the violation of a reasonable rule of the school And they may be given reasonable corporal, that is, physical, punishment for the violation of a reasonable rule, provided the rules of the school board do not prohibit corporal punishment. What constitutes reasonable punishment is, of course, always a question for the courts to decide The courts have decided the following school rules to be reasonable and therefore legal

1. That pupils present a satisfactory excuse for absence or tardiness.

2. That pupils stay on the school premises during the noon period.

3 That pupils do home work not prohibited by their parents

4 That pupils participate in graduation exercises

The courts have also decided that the school may mete out reasonable punishment to pupils who have been guilty of the following conduct outside of school

1. Abusing other pupils on their way to or from school

2. Immoral conduct

3. Insulting a teacher.

4 Publishing derogatory remarks about the school or a teacher.

The courts have decided, though, that all punishment must be reasonable For inflicting unreasonable punishment, teachers may be fined by the courts. Types of unreasonable punishment that have been decreed by the courts are too severe corporal punishment, or the punishment of an entire group of pupils in order to find the guilty pupil or pupils.

19. Why should the schools do everything possible to reduce pupil failure?

In the whole United States approximately 10 per cent of the pupils fail to do successfully the work of their grade or subject, and are not promoted Such failure and non-promotion mean a large loss to the pupil and to society, and everything possible should therefore be done by the school to reduce them. In an ideal school each pupil would be given

the amount and the kind of work suited to his ability, and he would be helped in every way possible to complete the work assigned him. For the school to fail a pupil because of his inability to do more work than he is capable of doing is as foolish as trying to drive a five-ton truck over a bridge designed for a two-ton truck. The school should be more interested in adjusting itself to the pupil than in requiring the pupil to adjust himself to the school.

13

Administration of Textbooks and School Libraries

SELECTION AND USE OF TEXTBOOKS

1. How much emphasis is placed upon textbooks in the schools of the United States?

In the schools of the United States textbooks have always largely determined the materials and the methods of instruction. They have always been a sort of "educational bible" to be followed closely and carefully by teachers and pupils This emphasis upon the use of textbooks has been a powerful factor in making the people of the United States one of the largest groups of readers in the world. The ability to read has been the precious key which has enabled our people to unlock and to examine the world's greatest storehouse of knowledge—books, magazines, newspapers, and other reading materials.

In the schools of some foreign countries much larger emphasis is placed upon the lecture method of instruction than upon the textbook method This emphasis upon the lecture method is begun in the early grades and increases with each year of school life. Whereas our practice tends to develop good "readers," foreign practice tends to develop good "listeners," and each of these accomplishments is valuable.

2. What is the proper use to be made of textbooks?

The more progressive teachers in the United States are adapting the textbook to the needs of their pupils. Moreover, they are not limiting the materials of instruction to what is contained in only one textbook, because they realize that no textbook can contain all the information or all the viewpoints on a subject They are supplementing the materials of the textbook with materials found in other books, in magazines, in newspapers, on the radio and television, in motion pictures, in the life of the community, in travel, and in other sources. They know that the materials of education are not confined to any one source.

Just as there are many excellent methods of raising livestock, of selling merchandise, and of obtaining good results in all other endeavors, so there are many excellent methods of teaching Some teachers obtain good results from using one teaching method, while other teachers secure equally good results from using another School boards and superintendents should, therefore, hold each teacher responsible for obtaining desirable results, but they should not prescribe the methods to be used in obtaining those results. They should permit each teacher to determine the amount and the type of use which he shall make of textbooks. Teachers who cannot be trusted to make such decisions are not worthy of employment, and it is unfortunate to have to report that some teachers have proved themselves thus unworthy Some teachers must be dismissed.

3. How do our textbooks compare in quality with those of other countries?

The large use of textbooks in the United States has resulted in the development of the best textbooks to be found in any

country. Numerous private publishing companies have been organized to cater to the textbook business, and competition for the business is extremely keen This has resulted in a tremendous improvement in textbooks during recent years For most of the school subjects there are many textbooks from which school officials and employees may choose, and all these books are hopefully promoted by their publishers Companies have gone bankrupt because their textbooks could not compete with those of other publishers. Many publishing companies have had to combine with others.

Although the general quality of textbooks is excellent, it should be recognized that not all of them have the same quality. Some of the books are distinctly poor, and not even the best ones are perfect. Some are interestingly and accurately written, while others are dull and inaccurate. Some present fairly all sides of controversial questions and provoke thinking among the pupils, while others try to indoctrinate the pupils with only one point of view and thereby stifle thinking. Suggestions on how the *best* books may be selected and on how textbooks should not be selected are given in answer to questions 8, 9, 10, 11, 12, and 13 of this chapter.

4 How much do textbooks cost, and do they cost too much?

More than $100,000,000 is spent each year for textbooks in the elementary and high schools of the United States. This expenditure is surprisingly low when it is considered in relation to the importance and the quality of textbooks, and in relation to the total cost of the school. For each pupil, on the average, it is approximately four dollars per year and approximately three cents per school day, of course, per pupil costs are higher in the upper grades, because the pupils there must

have more and higher-priced textbooks Only approximately 2 per cent of the total expenditure for elementary and high schools goes for textbooks.

It is unpleasant to have to report that in thousands of schools the pupils are required to use out-of-date or worn-out textbooks, and that in thousands of other schools there are not enough textbooks to supply all pupils. In normal times probably nothing could increase the efficiency of the average school system more than additional expenditures for textbooks and for supplementary books. And in times of financial stringency the normal allocation for textbooks and for supplementary books is certainly one of the last items which the average school system should reduce in order to balance the school budget.

Of course, many persons complain about the "high cost" of textbooks. These complaints are often made by parents in school districts which do not provide free textbooks, and they become more understandable when it is realized that new clothing and other supplies for starting the children to school must be purchased at the same time that textbooks are bought. In school districts which provide free textbooks parents do not complain about the cost of textbooks This is another argument for free textbooks.

Criticisms of the "high cost" of textbooks also frequently come from "politicians" who claim that they could save "millions of dollars annually" through the state publication of textbooks, or through some other change in textbook policy. Such persons, of course, are merely "talking through their hats." Savings would be possible, and should always be striven for, but in any state or local school system they would probably be counted in the hundreds or thousands of dollars, not in the "millions." Of course, savings made by cheapening the quality of textbooks are false economies.

5. Should textbooks be furnished pupils through public funds, or should pupils or their parents be required to purchase them with their own funds?

More than half of the states now *require* school boards to furnish free, that is, public-owned, textbooks, and practically all of the remaining states *permit* school boards to furnish them. In several states, especially in the South and the Southwest, free textbooks are provided with state funds, but in most states they are provided with local funds. The tendency everywhere is toward the furnishing of public-owned textbooks for both the elementary and the high school. The tendency should continue

When public-owned textbooks cannot be furnished to both elementary and high-school pupils, they should be furnished to the elementary-school pupils, because elementary-school education is more important to the pupil and to society. The first obligation of school officials is to make sure that the elementary-school pupils are not handicapped by lack of textbooks; the welfare of high-school pupils, although extremely important, is a secondary obligation. The arguments most frequently advanced for public-owned textbooks are the following.

1. All pupils are placed upon the same plane, and poor children are not embarrassed by not having textbooks.

2. The cost to the community is less than under pupil ownership, and the cost is spread over the whole community through taxes.

3 The criticism of many parents concerning the cost of textbooks is eliminated This criticism comes especially from the less wealthy parents and is increased by the fact that these parents usually have larger families

4. Textbooks may be more easily changed when change is advisable.

5. On the first day of school each pupil is provided with his textbooks and is ready to begin work immediately When pupils purchase them, there are many delays in obtaining them and such delays handicap both pupils and teachers.

Education will be more attainable to all children when textbooks, workbooks, and all other school supplies are furnished pupils through public funds School boards and employees should work for this greater equality in educational opportunity for all children.

6. When the school board does not provide free textbooks for all pupils, what provision should it make for pupils who are unable to purchase them?

In states which do not require school boards to provide textbooks for all pupils, the laws usually require them to provide textbooks for those pupils who are not financially able to purchase them The laws also usually require that free school clothing shall be provided such pupils Such laws are in accord with the ideal of the United States that no pupil shall be prevented by poverty from obtaining at least a minimum amount of education, and school boards should willingly cooperate in their enforcement.

7. What provision should the school board require school employees to make for the care of public-owned textbooks?

The board should require school employees to organize an accounting system for all public-owned books, and to take precautions against loss and unnecessary damage, the superintendent should be expected to take the lead in organizing

such a system. A textbook that is carefully used should last at least three years, especially for pupils in the upper grades of the elementary school and in the high school. Ample shelves should be provided for the books when they are not in use, and teachers should be responsible for their care.

In large school systems, for example those having more than 300,000 inhabitants, school boards should consider the advisability of organizing a department for the repair of textbooks and library books, in fact, pupils in the fourth grade or above can often make simple repairs on their own textbooks The small school systems, however, will almost always be able to save money by having major repairs made by a private book bindery, moreover, they will usually be able to obtain a better quality of repairs from such firms

8. What should be the unit of selection for textbooks?

At one time more than half the states, mostly in the South and Southwest, provided for adoption of uniform textbooks. In recent years, however, most of these states have effected a compromise between state adoption and local adoption by requiring the state adoption of two or more (usually three) textbooks for each grade and each subject. From this multiple list, local school boards and educational employees are permitted to select the textbook which they desire to use in their school system. Most authorities in school administration favor local or county adoption for the following reasons·

1 Local or county adoption permits the selection of textbooks which are better adapted to the educational needs of the pupils. State adoption falsely assumes that educational needs throughout the state are the same

2 Local or county adoption permits school boards to obtain the help of their educational employees in selecting the textbooks.

Since these employees must use the books, they should have a large voice in their selection In state adoption the members of the selecting agencies frequently are not engaged in educational work, and many of them are "politically" appointed and are susceptible to "pull" and similar influences.

Certain southern states provide free textbooks out of state funds. Largely on this account a few state authorities still favor uniform state adoption, believing that it is cheaper and that it better accommodates pupils who transfer from one school district to another. However, most textbook publishers and most teachers prefer local adoption of textbooks.

9. For what length of term should textbooks be adopted?

Practically all states have enacted laws governing the length of term for which textbooks shall be selected The term varies among the states, but the one required is usually three, four, or five years. These laws have as their chief purpose the protection of the public purse from too frequent changes in textbooks. Many of the laws, however, must be criticized because they make it impossible to change to a much better textbook until the term of adoption of the present one is concluded. Local school officials should be permitted to select the textbooks for their schools, and they should be permitted to change them at any time they deem advisable just as they are permitted to change superintendents, teachers, or other services when change is deemed advisable; because of the cost, they should, however, avoid too frequent changes.

10 What are the duties of school boards and school employees in textbook selection?

The selection of the best textbook is a time-consuming and difficult task, and school boards do not have the time or

the technical knowledge necessary to perform it. They should therefore delegate this work to the superintendent, supervisors, principals, teachers, and other educational employees, because these employees have the time and the preparation to perform it The board should, however, always require the employees to explain and to justify their recommendations, above all, the board should see that the teachers who must use the books have a voice in their selection. In the more progressive school systems, committees of teachers, principals, and other educational employees are appointed by the superintendent to assist in the selection; this practice should be adopted by every school system.

11 What policies should be followed by textbook committees in doing their work?

One of the best contributions to desirable methods of textbook selection has been made by the American Textbook Publishers Institute in a six-page booklet entitled *Desirable Procedures for Selecting Textbooks.*[1] The policies of textbook selection recommended in that excellent publication are summarized and briefly supplemented herewith

1. The committee should not be secret

2. The committee should be small About five members are usually desirable, although the number may be increased in the larger school systems.

3. Since teachers are seldom experts in several subjects, their work on the committee should not include too many subjects.

4. The committee members should be given adequate free time to do their work.

[1] The American Textbook Publishers Institute, One Madison Avenue, New York 10, N Y.

5. A desirable time schedule for getting the work done should be set for the committee

6 Publishers should be notified by the superintendent of pending adoptions

7. Provisions should be made for interviews with textbook agents

8 Hearings with textbook agents may be desirable in the committee's work

9 Outside consultations should be prudent, if used.

10. Committees should be encouraged to study all aspects of the publisher's program

11 The development of a course of study and the selection of textbooks should go hand in hand

12 Individual judgment on a textbook's content and methods should be emphasized by the committee members

13. The superintendent should review the recommendations of a committee, and if he strongly disagrees he should state his reasons to the committee and request a second-choice recommendation. He should make all recommendations to the school board, committee members and textbook agents do not have any responsibility in presenting recommendations to the school board.

12. How may the frequent criticism of textbooks that are being used be avoided or reduced?

In many communities the textbooks that are being used are severely criticized by small or large groups of the community. Textbooks in the social studies (history, civics, current events, economics, etc) are most frequently criticized because their authors sometimes advocate political, social, or economic views that many citizens believe to be too "leftist," if not downright "red"

School boards and school employees should guard against the selection of textbooks that are too much to the "left" or too much to the "right" When the board and the superintendent find that a textbook which has been selected has come under severe attack, they should consider securing an evaluation of the textbook This evaluation can best be made by a small committee of intelligent and fair-minded citizens of the community that will report its recommendations to the school board, which makes the final decision. Of course in states which have state adoption of textbooks local boards must use the textbooks adopted by the state

13. What should be the business relationships between school people and textbook companies?

School boards and school employees are sometimes criticized for being under the influence of a certain textbook company. There is, of course, no easy way of ascertaining the truth of these charges, but persons in the best position to judge believe that there is "more smoke back of them than fire", practices which justify such charges are undoubtedly the exception rather than the rule Practically all textbook companies and their representatives, as well as school officials and employees, are honest.

It should go without saying that school officials and employees should select textbooks entirely on the basis of the quality and the cost of the books They should not select them on the basis of contributions of publishers to campaigns for school board membership, the need for business of the textbook agent or his company, expenditures for entertainment of school officials or employees, the promise of help in obtaining a better position, or for any other selfish reason School people who have anything to do with the selection of textbooks should discourage excessive entertainment of text-

book agents; in fact, they would usually be more correct to forego all such entertainment. Any sharp practice or carelessness in the selection of textbooks is bound to handicap the pupils and the teachers who must use the books, and it will mar the reputations of the school people or the textbook agents who have followed the practice.

IMPROVEMENT AND USE OF SCHOOL LIBRARIES

14. What contribution does a good library make to the efficiency of a school?

In the more progressive schools, the library is regarded, next to the teacher, as the most important feature of the school. As noted in a preceding section of this chapter, school officials and employees are rapidly changing their belief that the textbook is the only source of knowledge, and are striving to acquaint pupils with other books and other sources of information, in this attempt they find a good library an indispensable help. From all classes and departments of the school, teachers and pupils make constant visits to the library to use its books, magazines, newspapers, maps, and other materials. A library is as necessary to a good school as the heart is to the human body.

15. How many schools and communities are at present not provided with efficient library service?

The American Library Association estimates that 45,000,000 people in the United States are wholly without local library service, and that 40,000,000 others do not possess adequate library service. In other words, less than one-third of our people have access to adequate libraries. The deficiencies in libraries are found especially in the rural communities and in the small towns. Thousands of schools do not



Courtesy of Staten Island Advance

Figure 14. A mobile unit of the type that brings library facilities to rural communities and to outlying sections of large cities which lack a school library or a public library

have any kind of library, and thousands of others do not have an adequate one. Many school boards in the rural school districts are now cooperating with a central library in providing traveling-library services for the village and rural schools. A picture of such a library is shown in Figure 14.

16. What are the types of school-library control and administration, and which type is usually preferred by school officials and employees?

There are three types of school-library control and administration. These are as follows

1. Control by the school board. Under this plan the school board provides, and is in complete control of, all library facilities The plan is by far the most frequently used, it is always used in the small school systems.

2 Joint control by the school board and by the public library board Under this plan the public library board usually furnishes the librarian, and the school board usually provides equipment and other facilities for the library.

3 Control by the public library board Under this plan the public library board provides, and is in complete control of, all library facilities.

Although the other two types of control are known to be working well in various communities, most school officials and employees believe that the school library should be controlled and administered by the school board They argue that this plan gives greater assurance that the needs of the pupils will be met better than under joint control or under control by the public library. The alternative plans, however, should not be rejected without adequate study and consideration for a special situation.

17. When the community does not have library facilities should the school board try to make the school library available to all persons of the community?

Many school boards make the facilities and services of the school library available to the whole community. To serve better the community needs, many boards keep the library open during the summer months, during the evenings, and on Saturdays. Such arrangements would seem to be entirely commendatory, especially when the community does not have public library service and provided community use does not handicap school use.

18 Under what conditions should the school board consider the employment of a librarian for a school?

Under ideal conditions every school would have a librarian, either part-time or full-time This recommendation is made especially for high schools Because of lack of finances, however, a librarian's services usually cannot be provided in the smaller schools, say those having less than ten teachers. Full-time librarians are found today, as a rule, only in the large high schools. The small high schools and the elementary schools are usually not provided with a librarian, either part-time or full-time In the small high schools one of the teachers is sometimes employed to devote part of her time to the work of the library, this arrangement should be made by all small schools whenever the condition of the finances permits

19. What qualifications should a school librarian possess?

Just as the teacher largely makes the classroom what it is, so the librarian largely makes the library what it is In person-

ality, in college preparation, and in other respects, the librarian should be among the best qualified employees of the school. In fact, because she must serve the needs of all pupils and all teachers, she should probably have even higher qualifications than teachers Most authorities recommend that she possess the same amount of undergraduate preparation as the usual teacher, and that she have, in addition, at least one year of preparation in library science.

20. How may the school board assist in building up the school libraries and in encouraging their use?

A school library which is to serve the needs of the school best must be provided with adequate quarters and equipment, and above all it must constantly be supplied with proper and adequate reading materials. These reading materials are the lifeblood of a library. The chief contribution, therefore, which the school board can make to building up the school library and to encouraging its use is through making adequate funds available each year for the purchase of new materials. If funds are at all available, at least one dollar per high-school pupil and fifty cents per elementary-school pupil should be expended annually for library materials

14

Selection, Pay, and Tenure of Teachers

METHODS OF SELECTION

1. Why should great care be taken by school boards and superintendents in selecting teachers?

Teachers primarily determine whether the school will be efficient or inefficient, and therefore great care should be given to their selection. When the importance of education to society and to the individual is realized and when it is remembered that teachers largely determine the quality and the amount of that education, the importance of these employees is more clearly seen. Teachers can be among the real makers of history, because pupils both now and when they have become adults will probably do what they have been taught to do by their parents, their teachers, their clergymen, and all other persons close to them. Although well-qualified teachers must be paid good salaries, poorly qualified ones are much more expensive in the long run because they make little contribution to the pupil and to society, in fact, incompetent teachers may be a positive menace to their pupils and to society, and should not, therefore, be employed

2 What should be the responsibility of the school board and of the superintendent of schools in the selection of teachers?

Because of his educational preparation and teaching experience the superintendent best knows, or at least should best know, the qualifications needed for holding each teaching position in the school system, the school board should, therefore, delegate to him or to one of his representatives the responsibility for investigating the qualifications of and for recommending all teachers for appointment by the board The laws of a few states now make this requirement, and it would be helpful if all states would enact such laws. Progressive school boards have adopted such practices even before state laws have required them. Although most school board members are conscientious and intelligent, few of them have the time to investigate or are educationally prepared to judge the qualifications of the many candidates for teaching positions They are likely to consider every certificated teacher as adequately and equally qualified and to give too much weight to such matters as personal acquaintance, "good looks," "smooth talk," local residence, and economic needs, they are apt to forget the pupils for whom the teacher is being employed, especially when their own children are not to be among the pupils of the prospective teacher Most school board members are as poorly prepared to select teachers as superintendents of schools would be to select nurses and physicians for a hospital, clerks for a bank, or workers for a laboratory. The nomination of teachers is a responsibility of the superintendent.

To summarize, the superintendent should *nominate* all prospective teachers to the school board, and the school board should *appoint* them if the nominations are approved The actual *appointment* of school employees should, of course,

always be a prerogative of school boards, not of superintendents.

3 Should the school board ever reject a nomination of a teacher by the superintendent?

Although the school board should delegate to the superintendent the duty of nominating all teachers for appointment, or for promotion or demotion in rank, it should reserve the right to reject any nomination. Such a rejection, however, should always be based on accurate information concerning the nominee, and, if the board is not positive of its grounds for rejection, it would probably do well to postpone its decision until the next board meeting. When the school board does reject a nomination, it should request the superintendent to make another one; it should not substitute a candidate of its own selection. If the school board should be unfortunate enough to have a superintendent whom it cannot trust to make nominations on the basis of qualifications, it should release him at the termination of his contract and employ someone in whom it has complete confidence The superintendent should realize fully the responsibilities of his position

4. Should school board members interview candidates for teaching positions?

When the school system has a superintendent, the board should expect all candidates for positions to send their applications only to the superintendent and to promote their candidacies wholly with him. School board members do not have time to interview the dozens of candidates for positions; they will save themselves much annoyance by refusing to hold such interviews and by sending all applicants to the superintendent, and they can be more confident that the interviews

conducted by the superintendent will be more likely to result in the selection of better qualified teachers.

5. Should there be an age standard for the employment of new teachers?

Many school systems still have a rule requiring all new teachers to have passed a certain age before employment. Although such a rule was probably justified a few years ago when college preparation for obtaining a teacher's certificate was not always required, such preparation today is nearly universal, thus guaranteeing that practically all holders of certificates will be old enough to teach. Age of teachers is not a requirement for employment.

Many school systems also have a rule prohibiting the employment of new teachers who have passed a certain age, which is usually set at somewhere between 45 and 50 years. School systems which have this policy justify it primarily on basis of salary, since older teachers will usually require higher salaries; moreover, older teachers are closer to the retirement age and therefore will not have as many years of service remaining in the school system. In connection with the employment of older teachers each case should be considered on its merits. New teachers who have gone, or will soon go, "over the hill" should not be employed. Rules requiring the employment of *all* new teachers beyond a certain age should be frowned upon.

6. Should teaching experience in another school system be a requirement for the employment of new teachers?

Since the city school systems pay much larger salaries, many of them still require at least one year of successful teaching experience in another school system before employ-

ing new teachers. The tendency, though, is to abolish this experience requirement, because it requires the smaller school systems to "break in" all the new teachers in spite of the fact that these smaller systems usually do not have as many supervisors and other employees to help beginning teachers as the larger systems. Although school systems which pay larger salaries are probably justified in requiring experience, a hard and fast rule which always requires experience cannot be regarded as fair to the smaller school systems or to those inexperienced teachers with "blue-ribbon" prospects.

7. What is a desirable policy regarding the employment only of local residents or of non-residents as teachers?

Qualifications should be the only basis for selecting any person for a teaching position. If the best qualified candidate happens to be a non-resident, well and good, and if he happens to be a local resident, also well and good Any practice which prevents obtaining the most competent teacher is to be condemned because it ignores the welfare of the pupils and of the public. The schools do not exist merely to give positions to the "home boys and girls", they exist for the pupils and the public.

School boards which employ only local residents risk the dangers of inbreeding, and these dangers are particularly great in the small communities The dangers are also found when all or practically all teachers are graduates of the same college, especially when the college is located in the same community as the school system and draws most of its students from that community. Teachers who have not been away from their home community are likely to be provincial in their outlook.

School boards should not engage in the practice of employ-

ing only local residents, nor should they follow the equally indefensible practice of employing only nonresidents. To employ only local residents or only nonresidents is to levy a "high protective tariff" against persons with possibly the highest qualifications

8. Should married women be employed as teachers?

Many school boards do not employ married women as teachers Although there are arguments on both sides of the question of whether married women should be employed as teachers, most educational authorities are opposed to rules which prohibit the employment of any member of a certain group. It is possible for intelligent and courageous school boards and superintendents to select the competent married women teachers from the incompetent ones The evidence from former investigations shows that married teachers are as competent as those who are not married. Even though future investigations might show that most married women teachers are less efficient than the unmarried ones, a school board should not have a rule which would make it impossible to employ the *efficient* married ones Teachers should be normal persons leading normal lives, and marriage is a normal expectancy of most of all normal persons who expect to be teachers—at least in the public schools.

9. Should school board members employ their relatives as teachers or for any other positions in the school system?

Public officials are frequently criticized for employing their close relatives,[1] and many school boards also bring upon themselves this criticism In several states the practice of

[1] The employment of relatives, especially by public officials, is known as *nepotism*

school board members voting to employ their close relatives, especially a father or a mother, a son or a daughter, a brother or a sister, is prohibited by state law. Whether the state has such a law or not, a school board member should hesitate to vote for the employment of a relative, particularly a close relative. Although the relative may be well qualified for the position, there is always the danger that both he and the school board will be subjected to and handicapped by the charge of favoritism. Conscientious school officials will "lean over backwards" to avoid the appearance of evil, no matter how unselfish their motives actually are.

10 What provisions should the school board make for the employment of substitute teachers?

Since, because of serious personal illness, accidents, serious illness or death in the family, and many other reasons, teachers are sometimes unable to meet their classes, school officials should make arrangements for a list of capable and regularly certificated substitute teachers. All substitutes should be recommended by the superintendent; the school board should, of course, the same as for the regular teachers, approve or reject these nominations. Since substitute teaching is unusually difficult, the qualifications of persons employed for it should be even higher than those for regular teachers A teacher should never be permitted to employ his substitute without the approval of the superintendent and the board A list of substitute teachers equal in number to approximately one-tenth of the regular teachers will be found sufficient under normal conditions. Substitute teachers should be paid only for the days served, their rate of pay usually varies from approximately one-half to two-thirds that of regular teachers, and that rate should, of course, be set at the beginning of the school year by the school board

11 What should be the personal relations of school board members with teachers and with all other school employees?

The personal relations of school board members with teachers and with all other school employees should be on a businesslike and ethical plane. They should be calculated to make the employees happy and thereby better able to give their best service to the school and the community. The following more specific suggestions on improving personal relations of school board members with teachers are made.

1 Board members should be friendly and courteous toward school employees, and should strive to be helpful in every honest way. They should hesitate to listen to complaints and suggestions coming from employees without these matters being first submitted by the employees to the superintendent Of course, the board should always permit any employee to appeal to it when the employee believes that the superintendent has not dealt fairly with him

2 They should not use their positions for personal gain or for any other personal advantage They should not solicit to sell school employees anything or to secure any other favors from them School employees are not under greater obligations to school board members than to any other person or persons in the community.

3 They should not vote for the promotion of, or the giving of any other school favor to, an unqualified employee, and they should not recommend such a person to another school system On the other hand, they should be on the lookout for opportunities to help qualified employees to obtain deserved promotions or other rewards They should deal impartially with all employees who are on the same plane of merit, they should not play favorites The merit of any employee should determine their decisions concerning him

An uncompromising adherence to these policies will lead to greater harmony throughout the school system It will be best both for the school employees and for the system.

TEACHER'S CONTRACT

12. What standards should a contract between the school board and a teacher meet?

In practically all states the laws require school boards to make written contracts with teachers and with all other employees. According to the American Law Institute, "a contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty " Since a contract protects the interests of both the school board and the teacher, it is always recommended by students of contracts A contract should meet the following standards

1. It should be *mutual*, that is, all of its provisions should be acceptable to both the board and the teacher.

2. It should be *written*. When the state laws do not require a written contract, an oral one would be held legal, provided it could be substantiated by sufficient evidence Oral contracts, however, are usually difficult to substantiate and should be supplanted by written ones.

3. It should be *clear* and should cover all important details At least the following matters should be included in it (1) name of the school district, (2) name of the teacher, (3) amount of salary and term of employment, (4) time limit for acceptance, (5) signature of the authorized school officer, (6) agreement of the teacher to abide by the rules and regulations of the board; and (7) signature of the teacher. Some states require still further details, and these details must, of course, be known by school board members and their superintendent.

4 It must be *legal.* Among the practices which might make the contract illegal are failure to follow the form of contract prescribed by state law, failure of the teacher to have the proper certificate, and pecuniary interest of a school official in the contract

School boards which follow the preceding standards in making contracts with teachers have found and will probably continue to find that litigation and other misunderstandings are and will continue to be reduced to a minimum.

13. What are the most frequent violations of good contractual relations on the part of school employees and of school boards, and how may these violations be avoided?

Both employees and school boards are occasionally guilty of unfair practices in their contractual relations Employees sometimes treat their contracts as "scraps of paper," especially when a better position is offered them, likewise, school boards sometimes try to wriggle out of contracts A contract cannot be nullified except by the agreement of all parties to it, and any person breaking it is liable to have damages assessed against him by a court. Following are suggestions calculated to eliminate unfair practices of school employees and of school boards in their contractual relations.

1 School boards should not require school employees to sign and to abide by contracts which have unfair provisions. When an employee who is under contract receives another offer which he wishes to accept, he should be released from his contract as soon as someone can be found to take his place, and he should not expect to be released until that time

2. They should not employ persons already under contract elsewhere without securing the consent of the present employers

3. They should give all employees early notification of their reelection or of their dismissal; likewise school employees should give ample advance notice of their desire to be released from their contracts.

PAY OF TEACHERS

14. How do teachers' salaries compare in amount with the pay of workers in other vocations?

Teachers' salaries vary from state to state and from school system to school system in the same state. The average annual salary of the teachers, principals, and supervisors of the United States is approximately $3,300. In several states the average annual salary is less than $2,400, and in only a few states is the average more than $3,300. The salaries of teachers are much less than the incomes of members of other professions, and they are less than the incomes of most gainfully employed persons. They are less in the rural communities than in the urban areas. These are descriptions of conditions as they are, not of ideal conditions Teachers' salaries go up slowly in inflationary times, but they go down slowly in deflationary times.

15. Why should the school board attempt to keep teachers' salaries as high as possible?

Since the welfare of society and of the individual members of it is in the long run determined largely by the teachers of the children, the school board has the responsibility of seeing that teachers are the best qualified persons possible. In undertaking to obtain well-qualified teachers the board should remember that a close relationship between salary and qualifications is almost sure to exist, it should strive to pay the highest salaries which the district can afford. A low schedule of pay is not likely to attract the best teachers to the profession or to

any community. The teaching profession must constantly compete with other vocations, and if its standards of pay are too low there is danger that the profession will lose some of its best members to other vocations. Although the best teachers do not work for salary alone, they are apt to be like other persons in their desire to earn as much as possible. They require the same necessities and desire the same comforts as other persons, they must accumulate something for old age and the "rainy day", they cannot live on thin air.

16. What are the advantages of paying teachers according to a salary schedule?

As an aid to determining the amount of salary, most school systems, especially the city systems, have devised salary schedules The tendency in both large and small school systems is to devise and follow such schedules. Even the smallest systems have found them to be beneficial to both officials and teachers A typical salary schedule is shown in Figure 15.

A salary schedule for teachers has the following advantages.

1. It is helpful to school officials because it is a salary plan and assists in making the salary budget for the next year and for the years following.

2 It is advantageous to the teachers because it tends to assure that at least approximate justice will be given them. When there is no schedule, the determination of salaries often becomes a mad scramble in which each teacher is left to secure as much as he can and school officials are left to pay no more than they must, the best teachers will not take part in such a scramble, and they are usually the ones who are penalized because they are not "big requesters"

School officials who are planning to establish a salary schedule will be able to obtain a great deal of help from pub-

Years of Experience	Bachelor's Equivalent and Bachelor's	Master's Equivalent	Master's
0	$3150	$3350	$3350
1	3250	3450	3450
2	3350	3550	3550
3	3450	3650	3650
4	3550	3750	3750
5	3650	3850	3850
6	3750	3950	3950
7	3850	4050	4050
8	3950	4150	4150
9	4050	4250	4250
10	4150	4350	4350
11	4250	4450	4450
12	4350	4550	4550
13	4450	4650	4650
14	4550	4750	4750
15	4650	4850	4850
16	4750	4950	4950
17	4800	5025	5050
18			5150
19			5250

Figure 15 A Typical Single Salary Schedule for Teachers (Used in Indianapolis, Indiana)

lications of the National Education Association, Washington, D. C ; most of the state education associations are also prepared to give such help.

17. What is the chief weakness of teachers' salary schedules today?

Practically all teachers' salary schedules today give their rewards entirely on the basis of the amount of college preparation and teaching experience, they place too much emphasis on the accumulation of college credits and on "living another year." Few of them attempt to measure and to reward teaching efficiency, that is, what the teacher accomplishes with the pupils. Although the rewarding of teach-

ing efficiency is one of the most difficult problems confronting school officials, it should be kept in mind in making and administering salary schedules. Any salary schedule which automatically rewards all teachers on the basis of amount of educational preparation and number of years of experience cannot fail to pay many teachers more than they deserve and many others less than they deserve. Teachers do not deserve an automatic increase in salary for merely having "kept school" another year or for having accumulated a few extra college credits School boards should insist that principals, supervisors, and superintendents show more discrimination and courage in their recommendations of teachers for increases in salaries; in other words, no salary schedule should be automatic.

18. Who should prepare the teachers' salary schedule and determine individual salaries?

The salary schedule should be prepared cooperatively by the school board, the superintendent, and representatives of the teaching staff. The board of education should, of course, have the final voice of approval. The superintendent should always be expected to make his recommendations on individual salaries, but the board should always reserve the right to approve or to reject.

19. What is a single-salary schedule, and what are its advantages?

A single-salary schedule gives equal pay for equal qualifications and services. It does not make any distinction in pay for reasons of sex, race, or grades taught Although most school systems do not yet have such a schedule, the trend is properly and rapidly toward its adoption. Such a schedule permits ele-

mentary-school teachers to be paid as much as secondary-school teachers, provided their qualifications and services are equal. Teaching in the elementary school is coming to be recognized as being as difficult, if not more difficult, than teaching in the secondary school, moreover, the training received by pupils in the elementary school is probably more important than that received in the secondary school because it lays the educational foundation for the pupils. A typical single salary schedule was shown in Figure 15, page 210. Many cities pay higher amounts.

20. Should men teachers be paid larger salaries than women?

Recent investigations have shown that in most communities the men teachers usually receive from \$100 to \$300 more per year than the women teachers. This extra pay has been deemed necessary by many school boards if men are to be attracted to and retained in the teaching profession. Sometimes the extra pay is given for extra work, especially in the high schools. Whether this difference in pay is fair to the women teachers and in the public interest has not yet been determined. Although they may not be wholly logical, the usual arguments for paying men teachers more than women teachers are the following·

1. Although this situation is gradually and surely changing, many more vocations are still open to men than to women This means that there is much greater demand for the services of men, hence men command higher wages in the competitive market of most vocations

2. Men teachers have dependents, and they therefore have greater financial responsibilities than women It cannot be denied, of course, that many women teachers also have dependents, and it seems not unreasonable to urge that when dependents are a

consideration in determining salaries, women and men should be placed on the same basis.

3. The pupils, particularly those in the upper grades, need to come under the influence of men teachers At present, less than one-fifth of our teachers are men and practically all of them are found in the secondary school

The practice of paying men more than women has been strenuously opposed by many persons, especially by the women teachers. These persons argue that such a practice shows rank discrimination and injustice. They have adopted as their slogan, "Equal pay for equal work" They emphasize that women teachers, as well as men teachers, frequently have dependents; moreover, they state that no facts are available to show that the influence of the masculine personality is needed in the classroom. Many states have apparently accepted these arguments, because they have recently enacted laws which require employers to pay males and females the same amount for identical work. Teachers are sometimes paid more for extra work.

21. Should the teacher's salary be paid on a twelve-month basis or during the months of teaching only?

Most school systems pay their teachers monthly and during only the months of teaching. The trend, however, is definitely toward placing the salary on an *annual* basis and paying it monthly throughout the calendar year. Investigations show that teachers usually prefer the twelve-month basis of pay, although the annual salary may be the same, they can look forward to a salary check during each of the summer months as well as during each month of the school term Few teachers have employment during the summer months, in fact, most of them attend summer school and work for an advanced de-

gree. The arguments for paying teachers on a twelve-month basis seem to be indisputable.

22. What provisions, if any, should the school board make for paying teachers who are temporarily disabled?

To be disabled is a large handicap, but to have one's income cut off at that time is, or can be, almost a tragedy. Many school boards provide financial assistance to teachers who are disabled. Most boards which make such provision give a certain number of days of full pay or part pay each year as sick-leave

In providing assistance for disabled teachers, boards are confronted, on one hand, with the problem of trying to make sure that teachers are protected against undue worry and inconvenience which often come when their salary is stopped. They are faced, on the other hand, with the problem of seeing that no teacher takes unfair advantage of provisions for pay for disability. Teachers should be expected and required to give reasonable evidence of disability before being paid, and they should be permitted to carry over any unused disability leave to succeeding years.

TENURE OF TEACHERS

23. How long is the tenure of the typical teacher in the United States?

In normal times approximately one-fifth of the teachers of the United States are new to their positions each year, and approximately half of this one-fifth has not had salaried teaching experience. This turnover in employment among teachers is much larger in certain school systems than in

others, and it is much larger in the rural districts than in the cities.

24. What procedures may the school board use to increase the tenure of teachers?

The large turnover in employment among teachers is wasteful, and school boards should do everything possible to decrease it, especially when it is unreasonably high. To do this they must remove or reduce its causes, the chief of which are (1) low salaries compared with other communities and with other vocations, (2) "political" management of the schools, and similar conditions which the best teachers desire to avoid, and (3) the automatic dismissal, either immediately or at the close of the school year, of all women teachers who marry.

25. When and how should undesirable teachers be dismissed?

A few states, and hundreds of individual school systems, have adopted laws or rules and regulations which provide that teachers who are efficient and otherwise worthy shall be permitted to keep their positions until they reach the retirement age of the school district or of the state. Such practices are desirable, because teachers cannot do their best work if they are constantly haunted by the possibility of losing their position, especially for an unjustifiable reason.

Tenure laws and regulations should protect efficient teachers in every way possible; however, they should not make it impossible to dismiss inefficient or subversive teachers. Life tenure for all teachers is not desirable, neither are the too frequent conditions today which make it possible for teachers to be "fired" on the slightest excuse. School boards should support tenure laws and regulations which are fair both to the

teachers and to the public, and teachers should also support such laws

Under the famous Feinberg law of New York State, school boards have been given the proper duty of throwing out of the schools any teacher who is subversive or who belongs to an organization that has as its policy the overthrow of our Government.

New teachers should be appointed for a probationary period of one to three years and should be helped in every way to "make good" Those who are retained longer than three years should be given permanent tenure as long as their services are satisfactory. Except for criminal acts, teachers should be warned, and given an opportunity to improve their work, before they are dismissed They should also be given the opportunity of being heard in their own defense. The suggestions just given are usually incorporated in the teachers' tenure laws of each state When the state does not have such laws, the school board should state its tenure policy, according to such principles, in its set of rules and regulations.

26. Should all teachers be retired at a given age?

During recent years the tendency has been strongly toward the establishment of federal or state pension systems for all groups of workers. These pension systems make it more easy to retire all workers at a certain age, because at that age the workers will be eligible to a pension and will thus be less apt to be objects of charity. More than half of the states now have statewide pension systems for teachers, and in many of the remaining states some of the large school systems have organized their own pension plans. Although few of these provide for compulsory retirement of all teachers at a given age, many school boards have recently voted such an age regulation for their teachers, they have usually set the compulsory

retirement age somewhere between 65 and 70 Such a regulation has the advantage of more likely protecting the pupils from the incompetency of any worn out teachers, but it unfortunately assumes that *all* teachers become worn out at the same age. School boards should make few exceptions to such a state or local regulation, but they should reserve the right to continue in service by annual election any employee when the welfare of the pupils demands it and when the laws of the state permit it.

15

Health and Safety Work in the Schools

PROVIDING A SCHOOL HEALTH PROGRAM

1. Why is a program of health work needed in the schools?

Good health should be regarded by everyone as a most important aim of education and as a precious possession. Without good health, and especially if he had no chance of obtaining it, a person would be poor indeed—poor in opportunity for happiness and for the greatest success in life. If he did not have good health, the wealthiest person in the world would gladly exchange all of his worldly possessions for it.

In spite of its great importance in life, health work in the schools is sadly neglected. Thousands of schools are doing nothing in health education, they do not have the services of nurses, physicians, or other health employees—in fact, many of them do not spend one cent for the protection and improvement of health. The need for a health program in the schools is seen from the following facts. first, the importance of good health to the individual and to society; second, the large amount of illness and physical defects, most of which could be eliminated or corrected through an adequate health program; and third, the large loss in school attendance and

education which is suffered by pupils because of illness and physical defects.

2. What stages do the health programs of modern schools pass through?

The health programs of modern schools pass through three stages. Many schools, of course, have not advanced beyond the first stage, others are in the second stage, and still others have advanced through all stages and have complete health programs. The three stages are:

1 *Health protection* In this stage, everything possible is done to provide a healthful and safe school environment, to protect pupils and school employees from communicable disease, and to provide an educational program adapted to the body and mind of the pupil

2. *Remedial work* In this stage, physical and health examinations are given the pupils and steps are taken to correct the defects which the examinations have found. Of course, all the steps taken under the first stage are also taken under the second

3 *Health promotion.* In this stage, health is promoted through such means as instruction in health, safety, and physical education, the employment of nurses, and the providing of lunchroom facilities All the steps taken under the first and second stages are also taken in this stage

The three stages are necessary to a complete and effective health program. Their order of importance is probably the same as that used in the discussion above.

3. What health employees should a school system have?

The kind and the number of health workers which a school system can employ will be determined by the size of the sys-

tem and the amount of money available for health service. The larger systems will need and can afford a larger health staff; they can employ many different specialists such as nurses, physicians, dentists, and speech experts. The smaller systems, on the other hand, will often have to be content with the employment of only one part-time person; and, sometimes, because of the lack of revenue, not even one part-time health employee can be afforded.

School and medical authorities agree that when only one health employee can be afforded, that one should be a school nurse. They also agree that for the most effective results not more than approximately 1,000 pupils should be supervised by one nurse. Small neighboring schools may frequently cooperate in employing a school nurse, and by such cooperation other types of health specialists such as physicians, dentists, and speech workers may be employed. The rural and village schools should organize these cooperative movements more often than they have in the past. Hundreds of school systems are cooperating in health programs.

4. How may the school guard against and control the spread of communicable diseases?

Unless communicable diseases are guarded against and controlled, a great deal of suffering and death may befall pupils and employees, and it may become necessary to close the school for a few days Modern schools are adopting such procedures as the following to guard against and to control communicable diseases (1) daily inspection of the pupils by the teachers or the school nurse, (2) exclusion of all pupils who have been exposed to a serious disease from school until such time as there is no danger of their carrying the disease germs; (3) instruction to pupils and employees on methods to use in avoiding infection, and (4) immunization of

pupils and employees against particularly dangerous diseases such as smallpox, diphtheria, and scarlet fever.

In the case of particularly dangerous diseases which have become epidemic, it may be advisable to close the school for a few days, this step, though, should be avoided if at all possible, and should not be taken except upon the advice of the health officials of the school and community They will usually advise against such a measure, especially when the school have good health supervision. The advice of the health officials must be accepted

5 What provisions should the school make for medical attention, proper food, adequate clothing, and other school needs of indigent pupils?

A pupil who lacks any of the materials or services just mentioned will not be able to profit fully from school opportunities, in fact, without one or more of the materials or services he may not even be able to attend school. All states either permit or require school boards to use public funds to make such provisions for indigent pupils. When public funds are not adequate to provide the materials and services, an attempt should be made to obtain private funds for them from public-spirited individuals and organizations of the community, such attempts can be counted upon to be successful almost always.

6. What provisions should the school make for lunches of pupils and employees?

All modern schools, including even the one-teacher schools, provide special facilities and services for the lunch period, especially during the months of cold weather All try to provide at least one dish of hot food at the lunch period Most large schools are now planned to include lunchrooms which

serve meals at low and actual cost. In many schools, especially the smaller ones, mothers' clubs, parent-teacher associations, and similar groups, cooperate with the school in providing hot lunches; indigent pupils are provided such lunches free of charge. During recent years the federal and the state governments have provided funds for indigent pupils. These funds, though, have sometimes been criticized.

SAFETY EDUCATION

7. What is the tendency regarding the number of accidents in the United States?

According to statistics collected annually by the National Safety Council, the number of accidents has shown a tendency to increase because of the rapid development of machines and other accident-causing features of a bustling twentieth-century civilization In brief, hazards have increased much more rapidly than the accumulation of knowledge of the development of protective habits against them. According to the National Safety Council, in the whole United States more than 100,000 fatal accidents occur each year, and at the present rate six of every 100 persons are destined to meet a fatal injury. Motor vehicle accidents cause approximately one-third of these fatalities, home accidents, approximately another one-third, occupational accidents, approximately one-seventh, and miscellaneous accidents, the remainder.

Non-fatal injuries are, of course, several times as numerous as the fatal ones. The chief causes or instruments of both the fatal and the non-fatal types of injuries are the following. automobiles, falls, railroads, drownings, burns, poisonous gases, and firearms. Of course there are thousands of causes and instruments, and every day sees new ones added to the list.

These injuries befall all ages, although certain ages are more susceptible to them than others More than one-fourth of all accidents occur among school children, and the approximately 6,000 fatal injuries to school children each year constitute one-fifteenth of all fatal injuries These figures are significant because of their implication concerning the responsibility of the schools for the reduction of accidents to pupils.

8. How may the school reduce the number of accidents?

Accidents result in untold suffering, large expense, and other distress, and the school should do its part in a program to eliminate them Fortunately, all, or practically all, accidents are preventable "Accidents do not happen; they are caused." They may be prevented through removing as many hazards as possible and through the education of all the people in the causes of the hazards and in the ways and means of eliminating those causes.

In its program for the elimination of accidents the school has two responsibilities. In the first place, it must protect the pupils from injury, especially while they are on the school property and on their way to and from school. In the second place, it must see that while they are in school the pupils are given instruction on, and are helped to form habits against, accidents which may occur when the pupils are *not* in school and when they have become adults. Modern schools and school systems are using the following procedures to prevent accidents and have unanimously found them to be effective

1 Making school grounds, buildings, and equipment safer for work and play Since most accidents occur on the playground, in the gymnasium, in the shops and laboratories, and on the

streets, school officials and employees should take steps to prevent them first of all. During the summer months a careful inspection should be given to every part of the school plant to make certain that all hazards are removed, such inspection, however, should continue during the whole school year

2. Supervising the pupils while they are on the school premises and while they are on their way to and from school Traffic squads consisting of a few of the older pupils are almost universal, especially at school crossings which do not have traffic lights.

3 Providing instruction in safety. Most school systems now have separate courses in safety education or they give the instruction as a part of some other course.

4. Securing cooperation between the school and other public and private agencies for the reduction of accidents, especially traffic accidents. Newspapers and radio stations will help in this program

Extra effort put forth by school officials and employees in trying to prevent accidents is bound to pay dividends in lives saved and in injuries prevented.

9 How may school officials and employees protect all occupants of school buildings against fire?

The answer to this question has been given under question 14, Chapter 8, page 132, and does not need to be repeated here.

10. What liability do school districts have for injuries to pupils, employees, or the general public?

With few exceptions, practically all of which are found in the states of California, New York, and Washington, the courts have ruled that, in the absence of a statute imposing

liability, school districts cannot be sued or otherwise held liable for accidents. At present, only the State of Washington has a statute attaching such liability to school districts. The Washington statute says that "An action at law may be maintained against a county, incorporated town, school district, or other public corporation . . . for an injury to the rights of the plaintiff arising from some act or omission of such county or other public cooperation."[1] But no state has a statute negating such liability, although court decisions to that effect are frequent.

The argument most often given in support of the rule of non-liability for school districts is that school districts are agents of the state, and since the state cannot be sued without its consent, one of its agents cannot be sued without its consent. In addition to the reason just mentioned, the courts have stated that school officials do not have the power to use public funds to pay damages for injuries, because if they used them for that purpose, the welfare of the public would suffer. The courts have said that school funds are raised for the sole purpose of maintaining schools, and that the welfare of the public demands that they not be diverted to any other purpose.

Although only a few states make school districts *legally* responsible for accidents and injuries, school districts should always regard themselves as *morally* responsible for them. This moral responsibility attaches especially to school board members and to superintendents and other school employees. School officials and employees who fail to take all reasonable precautions against accidents may be risking disasters as awful as those which occurred in Collinwood, Ohio, and in New London, Texas, in those accidents, scores of pupils and employees lost their lives

[1] *Remington's Revised Statutes of Washington,* Section 951, p 561.

PROVIDING FOR PHYSICAL ACTIVITIES

11. Why are provisions for play and other physical activities more necessary in the school program today than formerly?

It is recognized by all intelligent people that a complete education requires exercise and training of the muscles as well as of the mind. Modern schools are making provisions for the education of the muscles through play and other physical activities Such provisions are more important today than formerly because (1) the individual has much more leisure time than formerly and he therefore needs guidance in its utilization, and (2) he spends much more time in "sitting" than formerly, and in consequence must be stimulated to engage in activities which bring the big muscles into use.

12. What provisions for play and other physical activities should the school make?

The first provision which should be made is for an adequate playground. It should be sufficiently large for all pupils to engage in games suitable to their ages. It should possess the proper topography, good drainage, and the proper type of soil; it should be free from hazards of all sorts and should be properly equipped with play apparatus and other facilities. Arrangements should be made for keeping it open during the vacation months as well as during the school term, and adequate supervision should be given it throughout the year; these provisions are especially needed in the urban communities

In addition to having a playground which is large enough and properly equipped, every school should make provision for indoor play of the pupils. Whether large or small, every school should have a gymnasium or some other type of play-

room. Every large school should have a gymnasium Most schools today have a combined gymnasium and auditorium, this combination of facilities is especially recommended for the smaller schools.

HEALTH OF SCHOOL EMPLOYEES

13. How important is good health for school employees, especially for teachers?

For the following reasons, good health is very important for all school employees.

1. It is necessary if the employees are to be happy, ambitious, energetic, and on duty regularly.

2 It is necessary for the physical and mental welfare of the pupils. If an employee possesses a communicable disease, the health of pupils and other employees may be endangered, or if he is nervous and irritable, there is danger that these characteristics will be transmitted to pupils and other employees

The above comments apply especially to teachers, because they are in closest and longest association with the pupils They apply with almost equal emphasis to school janitors, school bus drivers, lunchroom workers, and other employees who have frequent contacts with pupils and fellow employees. In fact, they apply in some degree to every school employee.

14. What responsibility does the school board have for making certain that all school employees have good health?

In view of the importance of good health in all school employees, the school board should adopt procedures which will assure that a good standard of health is met by all employees These procedures can be followed in such manner

that the rights of employees as well as those of the public will be protected, school employees have obligations to the public as well as individual rights It is not unreasonable to require a health examination of every *new* employee and periodic examinations of all others. These examinations should be given by a school physician or by another physician or physicians approved by the school board The nature of such examinations should be specified by the board, and the results of the examinations should be reported in a form approved by the board.

In addition to making certain that adequate health standards are met by all school employees, the school board should adopt a health program which will help employees to maintain and to improve those standards. Some of the features of such a program which the board can adopt, especially if sufficient school funds are available, are the following· a healthful school plant, salaries sufficient to enable employees to live comfortably and without worry; an adequate sick-leave policy for all employees; adequate retirement allowances for all employees, the requirement that employees remain at home when they are not able to work; and some provision to prevent overwork of employees.

16

The Administration of Pupil Attendance and Census

IMPROVING PUPIL ATTENDANCE

1. What increases in school enrollment have there been and what are the explanations for the increases?

Since 1870, the total population of the United States has increased approximately twofold, whereas school enrollment has increased approximately fourfold This increase in enrollment has occurred especially in the high school and the college. According to the United States Office of Education, the enrollment in public and private elementary schools has increased from approximately 14,000,000 in 1890 to approximately 25,000,000 today The enrollment in public and private secondary schools has leaped from approximately 400,000 in 1890 to approximately 8,000,000 today. The enrollment in public and private colleges has soared from approximately 200,000 in 1890 to approximately 2,500,000 today. At present, approximately 3,500,000 pupils are found in church schools (largely Roman Catholic), and approximately 500,000 are found in private schools.

These gigantic increases in school enrollment demonstrate a growing faith of the people in education Our people have

increasingly attended school because of their belief that education, more than any other factor, tends to make people equal in opportunity and able to accomplish most for themselves and for society. A second factor which has operated to increase school enrollment has been the enactment of more rigid compulsory attendance laws in every state. Likewise all states have enacted child labor laws which have directed thousands of children into school instead of into the mines, factories, shops, and other places of labor.

2. Is school enrollment likely to continue to increase?

Recent statistics from the United States Office of Education indicate that increases in school enrollment will probably continue in the future. Large increases have recently appeared in the elementary school, and within a few years they will probably be seen in all grades of the secondary school The increases which have occurred can be explained by the recent tendency of the birth rate to rise, and this means that there will be more children to educate.

It is in the secondary school and the college that the largest increases in enrollment may be expected in the future. Increase will probably continue there for at least several years because of the tendency of the states to regulate or to prohibit child labor and to raise the upper age limit of the compulsory attendance laws, and because of the ever growing desire of the people for more education. The peak enrollments, however, in the high school and the college are being approached. Many school systems have already reached their peak enrollments, and in the future they will not be compelled to meet the problems caused by rapidly increasing enrollments, they will, therefore, be better able to emphasize the *quality* of the educational output rather than the *quantity* of it Most school

systems, however, must prepare for an increase in enrollment for several years

3 How much non-attendance at school is there, and what loss results from it?

At present, according to the United States Census Bureau, approximately 85 per cent of the children five to seventeen years of age are enrolled in school.[1] Of those enrolled, approximately 85 per cent attend school every day. In other words, of each 100 children enrolled in school, approximately fifteen are absent daily. As would be expected, the amount of non-attendance varies from state to state, from school system to school system, and in other respects. As a rule, the northern states have less non-attendance than the southern states, and the cities have less than the rural communities, certain schools have less than other schools in the same county or city, and certain teachers have less than other teachers in the same building

This non-attendance constitutes one of our largest educational wastes, if not the largest one. It results in the following losses:

1 It results in a large *financial waste*, because the cost of running the school is practically the same whether all the pupils are present or not The teachers, janitors, bus drivers, and all other employees are under contract and must be paid for a part school the same as for a whole school

2. It results in a large *educational loss to the pupil*, and this loss cannot be measured in dollars and cents Non-attendance causes the pupil to fall behind in his work and to become discouraged,

[1] In interpreting this low percentage of children enrolled between the ages of five and seventeen, it should be remembered that most pupils do not have the advantages of a kindergarten and are not required to enter school until the age of six or seven

worst of all, it often results in the pupil's failure to be promoted to the next grade

3. It results in large *inconvenience to the teacher*, because when a pupil is absent the teacher feels obliged to try to help him make up the work missed. That effort on the part of the teacher is likely to take time from and to handicap the pupils who have not been absent

School officials and employees are being challenged to reduce these wastes and losses to a minimum. The challenge has already been met successfully in thousands of school systems.

4. What are the causes of non-attendance, and how may school officials and employees proceed to eliminate them?

In trying to decrease non-attendance, school officials and employees should ascertain first of all its *causes*. These causes are, of course, numerous, and they vary in number and in kind from school to school. Some of them are legal and others are illegal. The chief causes of non-attendance are. (1) illness of the pupil, (2) illness of some member of the family, (3) lack of proper clothing, (4) death in the family, (5) truancy, (6) walking distance to school too great, and (7) work Because of lack of school finances and of legal authority, and because of the necessity of keeping in mind the welfare of the child, school officials and employees cannot be expected to eliminate all these causes, however, the elimination of as many as possible should be kept in mind as the ideal.

The first obligation of the school officials and employees is to attempt to eliminate the *unlawful* non-attendance, following that, an attempt should be made to decrease or to eliminate the *lawful* non-attendance, such as illness of the

pupil. *Perfect* attendance, however, is seldom attainable, and unreasonable attempts to obtain it will harm and offend pupils and their parents.

5. Why does every state now have a compulsory attendance law?

All states now have compulsory attendance laws, and the tendency everywhere is toward making the laws more rigid and to enforce them more strictly These laws have been enacted because of the belief of the people that education is so necessary to the welfare of both the individual and society that it cannot be left to the whims of the child and his parents Although by far the majority of the people in the United States today would unquestionably attend school of their own free will and accord, some people would not attend if there were no compulsory attendance laws Laws are enacted for the control of the ignorant and the selfish few, not for the intelligent and the unselfish many.

6. What provisions should the school board make for enforcing the compulsory attendance laws?

The provisions for enforcement are determined in the main by state laws. The laws of most states provide that every county shall have an attendance officer for the rural schools, and that every city school system shall also have its own attendance officer Whereas the early attendance officer was merely an "officer" who had physical strength and plenty of courage as his chief qualifications, the modern attendance officer is regarded more as a social servant and teacher, and he must have more to recommend him than a "strong back"

School boards today, therefore, are looking more and more for attendance officers who have educational qualifications, and a few states have already enacted laws that establish

certain educational qualifications which they must possess. Many of the progressive school boards are delegating to a school nurse, or to a visiting teacher, the duties of the attendance officer. Such employees are well prepared for this work and thus are more likely to ascertain the causes of non-attendance, moreover, they are more likely to cooperate with parents and pupils and with school officials and employees in eliminating the causes.

7 May pupils be permitted to attend private and parochial schools instead of public schools?

Every state permits pupils to attend private and church schools instead of the public schools, and at present approximately 15 per cent of the children of the United States receive their education in such schools. The American policy has been to permit such schools to operate, provided they meet the standards prescribed by the state. The compulsory attendance laws apply, of course, to private and church schools just as to public schools Moreover, practically all private and church school officials and employees gladly cooperate with public school officials and employees in enforcing the compulsory attendance laws of the state.

IMPROVING THE SCHOOL CENSUS

8. What is a school census, and what are the purposes of taking it?

Every state now requires every school board to see that an annual census or enumeration of all children between certain ages is taken, the ages most often specified are five to eighteen. A school census usually includes such facts as the name, the date of birth, and the address of each child of census age residing in the school district. Its purposes are the following

1. Its chief purpose is to aid in the enforcement of the compulsory attendance laws of the state It gives this aid by listing the children who should legally be in school.

2. It aids in planning the educational program of the community. It does this by giving several months' or several years' notice regarding how many pupils must be cared for, thus enabling school officials and employees to provide necessary buildings, teachers, and other facilities and services.

3. In a few states, state funds are still distributed to the local school districts on a school census basis, and such a plan requires an accurate count of the children each year This purpose, however, is growing less important because of the realization that there are better bases, such as average daily attendance, on which to distribute state funds.

If these purposes are to be best served, the school census must be accurately taken and organized for ready use. It cannot be carelessly taken and merely "filed away."

9. How should the school census be taken?

The laws of each state outline the procedure to be followed by school boards in making provision for taking the school census, and this procedure must, of course, be followed. Most school boards employ a special census-taker or takers for a few days or weeks each year; other boards request the teachers to take the census, and most authorities in school administration prefer this plan.

An efficient school census will aid in accomplishing the purposes for which the census is required by state law. Its information should be useful, adequate, and accurate.

The tendency in practice is toward making the school census *continuous*. According to this plan, a continuous and permanent census card is provided for each child and the information on the card is kept up-to-date by school officials

and employees This plan makes unnecessary the annual head count of the old-fashioned census, moreover, the plan is cheaper and provides more accurate and useful information. If the state laws permit, each school board should request its superintendent to organize such a census for the school system

17

The School and Public Relations

PURPOSE AND IMPORTANCE OF PUBLIC SCHOOL RELATIONS

1. What is the purpose of public school relations?

Public school relations have the purpose of attempting to bring a harmonious working relationship between the schools and the public which the schools serve. They are a separate phase of school administration, but are also definitely related to *every* phase of school administration. Public school relations are sometimes called school publicity, school information, school public relations, school community relations, or school information. The public relations of the schools go on whether the school officials and employees are conscious of it or not, it is inevitable and goes on at all times. If school boards and superintendents are following the precepts of the preceding chapters, they are already largely meeting their public relations responsibilities.

2 What standards should the public relations program of the schools meet?

Public relations cannot be escaped by an individual or by an organization. Since the welfare of the schools will be

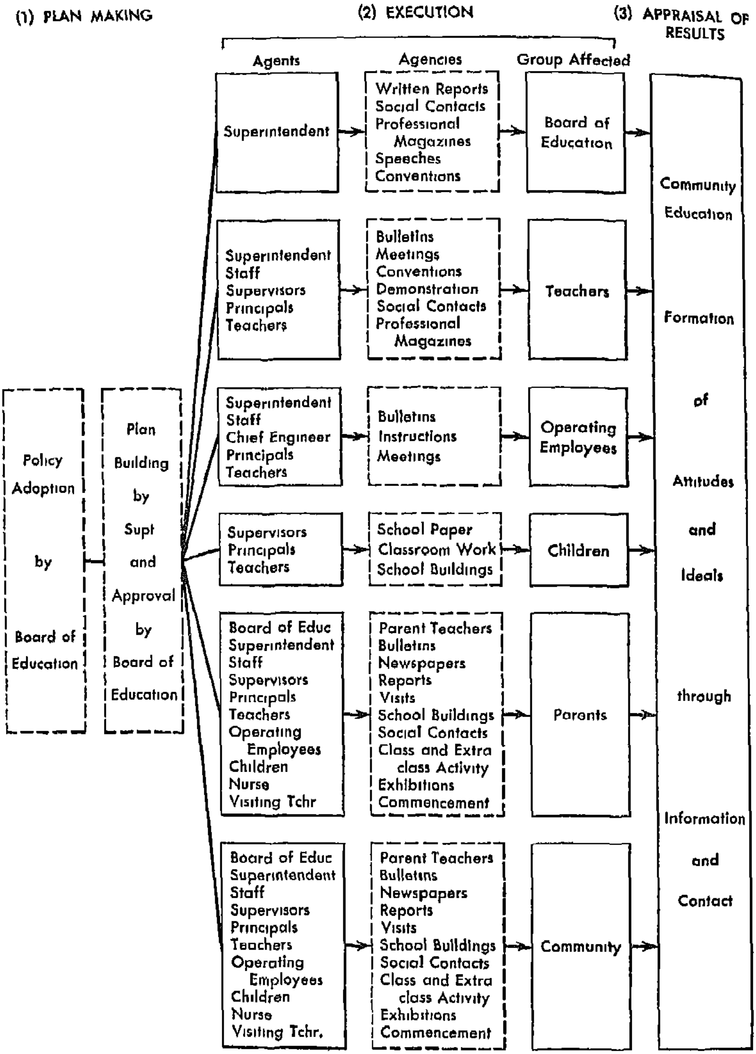


Figure 16 Organization of the public relations activities of a school system (From *The Public School Code of the Hamtramck, Michigan, Public Schools*, Research Series No. 2, p 252, Board of Education, Hamtramck, Michigan)

tremendously affected by the nature of the public relations program, school officials and employees should see that the program meets high standards. Those standards are

1. *The public relations program should be planned the same as every other phase of the work of the schools* At present, in many schools and school systems, too much of the public-relations program is incidental, and like most school work which is incidental it turns out to be "accidental."

2. *Every school official and every school employee must realize that he is a public relations agent of the school or school system* To be the best public relations agent he must meet at least three responsibilities In the first place, he must do his daily work as efficiently as possible, in the second place, he must practice good human relations both in school and out; and in the third place, he must be a good citizen, doing things that a good citizen does and avoiding unethical practices that would embarrass himself and the schools

3. *The public relations program of the schools should be based on public cooperation with the program.* School officials and employees should remember that the program is a "two-way street," not a "one-way street" Public cooperation should be welcomed by the school, in fact, the cooperation should be stimulated

4. *The public relations program should provide for proper information about the school* That standard will be explained in the answers to the next following questions

3. Why should the people be kept well informed about the work of the school?

In a democracy such as ours the people are the rulers. The school and all other public institutions belong to the people and are operated by them through their chosen representatives and their employees. Since the school is owned and

operated by the people, its welfare and progress will be determined largely by how the people regard it. How the people regard the school will be determined largely by what they *know about it.* It is the obligation, therefore, of school officials and employees to take the people into their confidence and to provide them with the information which they desire and to which they are entitled. No task of a school board and its superintendent is more important than making certain that such information is provided regularly. Abraham Lincoln, one of the greatest believers in democracy, once said "Public sentiment is everything. With public sentiment nothing can fail, without it nothing can succeed." An honestly informed people can be counted upon to follow intelligent and honest leadership.

STANDARDS FOR SCHOOL INFORMATION

4 Why should school information be truthful?

The first standard which school information should meet is *truthfulness.* The people are entitled to know the truth about the schools and they will not be satisfied with anything less. The people soon come to know whom they can believe and trust. In spite of Barnum's remark to the effect that the people like to be "fooled," the people really do *not* like to be "fooled"; and they will soon throw from office any of their representatives or employees who try to impose upon their intelligence and their good will

Of course, the truth does not need to be "shouted from the housetops." Often "silence is golden." Certain types of information pertaining to pupils and school employees should be regarded as confidential. Among these confidential types of information are the marks of individual pupils on their scholastic accomplishments, and the professional rating of in-

dividual teachers If presenting a given sort of information would injure any pupil or employee and would not serve any useful purpose, it should not be released, unless the laws require the release. The mere satisfying of idle curiosity does not justify the releasing of any item of information. "All the truth that is fit to tell" should be the guide of the school in its public relations policy, there is, of course, much information that is not beneficial and that is therefore not "fit to tell."

5 In providing school information, why should continuous information be emphasized rather than publicity campaigns?

Although publicity campaigns are occasionally necessary to obtain the approval of a new tax rate, a bond issue for buildings, or some other proposal, the emphasis should be on *continuous* or day-by-day school information. If the people are kept ignorant of their schools until something is wanted from them, they are likely to be suspicious not only of the request but of the persons who make it. It is unfortunate that many school officials and employees ignore the people until something is wanted from them Such a practice is neither helpful to the schools nor fair to the people; it does not promote good public relations between the schools and the people.

6 Why should school information be in the proper amount and be properly balanced?

Although most school officials and employees fail to provide the people with ample information concerning the school, some of them spend too much time and energy in providing it. The first obligation of school officials and employees is to run an efficient school, and such a school is almost sure to obtain favorable publicity through word-of-

mouth of the pupils and their parents. All the publicity in the world cannot change a poor school into an excellent one. Satisfied clients, constituents, or customers provide the best publicity which any service or product can have.

In addition to being in the *proper amount*, school information should be *balanced*, that is, no department or phase of the work of the school should receive more publicity than that to which it is entitled, and none should be slighted. In most schools, it is unfortunate that information on athletics and other extracurricular activities is emphasized unduly, while other phases of school work are neglected. Many investigations have shown that the people would like to have more information on these other phases of school work, it should, therefore, be provided them It should be provided by school officials and employees.

PUBLIC SCHOOL RELATIONS AGENTS AND AGENCIES

7. Who are the public relations agents in school affairs?

The public relations agents in school affairs are the *persons* who are responsible for planning and for carrying out the program of keeping the public informed about and cooperative with the school They include all school officials and employees, for example, school board members, clerks, the superintendent, supervisors, principals, teachers, attendance workers, janitors, and bus drivers. Although all these persons have a large responsibility for providing information regarding the school and for securing the good will of the public toward the school, many of them tend to forget the responsibility. It should be remembered that the starting point for a well-informed public is a well-informed school board and well-informed school employees

8 What are the duties of the school board in the public relations program of the school?

The first public relations duty of the school board is to approve, amend, or reject, upon the superintendent's recommendation, a public relations policy for the school system. This policy should state the general aims to be accomplished in the public relations program and should broadly outline the procedures to be followed in carrying out the program After the board has approved the public relations policy, it should, as in all other school policies, delegate to the superintendent the responsibility of executing that policy The board should, of course, appraise the efficiency with which the program is being carried out by the superintendent and should request any needed changes in the program.

The school board should realize that the way in which it performs its work has much to do with obtaining and keeping the cooperation and the good will of the public toward the school. The public recognizes and appreciates efficient services of its school board and its employees It is common observation that some school boards are constantly praised by the public, whereas others are regularly condemned. Boards and board members should avoid indulging in such practices as the following, which are particularly offensive to the public.

1 Giving the impression that they "own" the schools and are not responsible to the public

2. Voting for their relatives, especially close relatives, for positions in the schools Many states have enacted laws which prohibit this practice

3 Purchasing supplies, equipment, and similar materials and services from themselves, their relatives, or their friends, without asking for bids

4. Wasting school money in any manner.

5 Being unwilling to take the public into their confidence and to give publicity to discussions and decisions Too many boards insist on having many closed meetings and on ignoring newspaper reporters

6. "Firing" or demoting efficient employees without warrant; also retaining inefficient employees.

7. Playing "politics" and engaging in similar practices with the hope of receiving personal reward or gain

8. Indulging in "hobby riding" and "axe grinding"

9 Forming board factions. The harm which such factions do the schools was discussed under question 11, Chapter 1, pages 12 to 14.

10. Attempting to sell personal services or materials to school employees, or expecting school employees to patronize their businesses

There are, of course, many other offensive practices which are sometimes engaged in by boards and board members Public officials and employees should remember that only efficient and unselfish practices are pleasing to the people. Selfish practices are displeasing.

9. How may the school board make more certain that the schools are not used by selfish propagandists and similar interests?

One of the most difficult problems which school officials and employees meet is that of cooperating with individuals and organizations which make various requests of the school, in the average school system, hundreds of these requests are made annually. Some of the requests are unselfish while others are selfish, some of them, if granted, would help the

school while others would harm it It is always necessary, therefore, for school boards and superintendents to be on their guard against any individuals or organizations which would use the schools for selfish purposes

Many school boards have adopted rules and regulations governing the cooperation of the schools with outside agencies, and the adoption of such rules and regulations should become general. The rules and regulations might well be patterned after those recently formulated and adopted by the Rhode Island school officials and employees, quoted herewith

> 1. The tendency to promote various activities through the public schools has become excessive, and if not checked and regulated will seriously interfere with the progress of pupils in the regular work that the schools are expected to accomplish The fact that the schools belong to all of the people and are conducted for the benefit of all of the people renders it inconsistent to permit them to turn aside from their prescribed functions, unless in the judgment of the constituted authorities such a course is without question for the general welfare and not prejudicial to the interests of the pupils
>
> 2 No person should be permitted to address the pupils of a public school without the authority of the superintendent or the school board
>
> 3 There should be no advertising of any matter or exploitation of any cause in the schools through the distribution of circulars or articles or by announcements, unless it is related directly to the educational interests of the schools and also has the approval of the superintendent or the school board.
>
> 4 Requests for lists of the addresses of pupils should not be granted and permission should not be given to copy such lists from school registers

5 Soliciting agents should not be permitted to interview pupils or teachers in school buildings.

6. Photographers should not be permitted to take pictures of pupils or teachers on school premises without the authority of the superintendent or the school board. Such authority should not be given if the chief purpose relates to the financial interest of a photographer

7. The collection of money from pupils at school should be very carefully restricted and should be permitted only by authority of the superintendent or the school board. To place children under the necessity of either contributing or being publicly noted for failure to do so is unfair and inconsistent with the theory that the schools are entirely free

8. The practice of securing from pupils pledges to contribute definite sums of money for any cause should not be permitted

9. It is inadvisable to resort to methods that involve the recognition of special distinctions or privileges for groups of pupils, since such practices are a hindrance to the inculcation of the spirit of democracy that is based on equality. Membership in welfare organizations and participation in their work and privileges should pertain to entire schools rather than to individual pupils, and such activities should always be subject to the regulations of superintendents.

10 Teachers should discourage gifts from individual pupils or classes of pupils

11. The practice of offering children prizes or special rewards for essays or other accomplishments as a means for the promotion of any cause should be discouraged It involves unwise discrimination, and the intended benefits may be secured by less objectionable methods Moreover, the educational benefit that is sought by such prizes is usually included in the regular curriculum of school work as far as it is deemed advisable by school authorities.

12. Requests of either local or national organizations for the introduction of patriotic or philanthropic activities in the schools should be accepted with caution and discrimination, to prevent duplication or confusion and an unwarranted amount of interference with regular work

13. It is impracticable to make arrangements for special exercises in the public schools without a previous notice of at least one week.

10 What are the public relations agencies which may be used in school affairs?

The public relations agencies are the *means or instruments* which may be used in carrying out the program of public school relations The following agencies are widely used, though all of them are seldom found in one school system student newspapers, community newspapers, radio, television, employees' newspapers or magazines, pupils' and employees' handbooks, parents' handbooks, school exhibits, visiting days or nights at school, annual or special reports, citizens' committees, meetings of the parent-teacher association and of similar groups, and the day-by-day contacts of all school officials and employees with the pupils and the public.

School officials and employees should not forget that in the typical community approximately two-thirds of the homes do not have children in school, hence the usual public relations agencies of the school do not come in contact with these homes. Since the adults of these homes constitute the bulk of the voters on school tax levies and similar school questions, they should by no means be forgotten in the school's program of public relations All the adults in the community own the schools and are therefore entitled to adequate information concerning the schools Any school board which fails to see that ample information is provided the people is endangering the welfare of the whole school system

CONDUCTING A SCHOOL PUBLICITY CAMPAIGN

11. What is the purpose of a school publicity campaign?

The purpose of a school publicity campaign is to obtain the approval of the voters for a request made by the school board. Most school publicity campaigns are conducted to obtain public approval for an additional tax levy, or for a continuance of the present tax levy for the schools. In these days of mounting taxes a school publicity campaign is usually necessary even though the day-by-day, or continuous, publicity may have been well looked after over a period of several years.

12. What general standards should a school publicity campaign meet?

A publicity campaign for school purposes should meet the following general standards:

1. The purpose for which the campaign is conducted should be fully justified. The people do not like to purchase a "pig in a poke."

2. Before launching the campaign all factors likely to interfere with its success should be removed if possible.

3. The campaign should supplement continuous publicity, not take the place of it.

4. The aim should be to win the campaign, but to win it by fair means. The end does *not* justify the means.

5. As few enemies as possible and as many friends as possible should be made in the campaign. After the campaign, any enemies made must be "lived with" the same as one's friends. An old rhyme ascribed to Omar Khayyam says:

> He who has a thousand friends has not a friend to spare;
> But he who has one enemy shall find him everywhere

6. The campaign should be conducted, and the election held, preferably when the schools are in session, not during the summer Schools are nearer and dearer to the people, especially the parents, when they are in session

7. Persons who are not on the payroll of the schools should be chiefly responsible for conducting the campaign Likewise, little or no school time of the pupils should be taken to promote the campaign The school board should take the lead in seeing that a citizen's committee is organized to direct the campaign.

8 The campaign should be financed with private funds, not with public funds, the use of public funds for this purpose is illegal in all states Funds for the campaign may usually be obtained from the parent-teacher association and other public-spirited organizations.

If the people should refuse to vote the request made by school officials, they should not be condemned. When such is the outcome, school officials should wonder whether the request was really a justifiable one and whether it was well presented to the electorate. Wise school boards and superintendents will question their own intelligence, not that of the electorate, the voice of the people may not be "the voice of God," but the voice of the people is sovereign in this temporal world

13 What types of publicity material should be used in a school campaign?

The types of publicity material which should be used will be determined by the size and other characteristics of the community and by the purpose of the campaign There are dozens of types of materials, some of the more effective are the following:

1. Material in the newspapers, such as endorsing editorials, a sample ballot of the election, and reports of interviews with prominent citizens and leaders of community groups

2. Advertising folders, handbills, pamphlets, and circular letters. One or more of these might be sent to each home, and should be signed by each member of the school board

3. Short speeches by pupils and adults before the various community organizations such as churches, lodges, American Legion, Grange, Farm Bureau, labor groups, and the Chamber of Commerce.

4. Posters and stickers in windows, streetcars, buses, taxicabs, and similar places.

5. Pictures and graphs in the motion-picture houses

6. Telephone or house-to-house calls by members of the campaign committee or by representatives of groups such as the parent-teacher association

7. Street banners and floats

8. School exhibits

9 Radio talks and television programs

INDEX